(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम सत्र का 22 वां दिवस [संख्या 15

सोमवार

दिनांक 19 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री किशनसिंह भाटी।

राज्य में मेल व फीमेल नर्सों की कमी

356. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने अर्से से कितनी संख्या में मेल व फीमेल नर्सिंग स्टाफ की कमी है तथा इसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

(2) जैसलमेर जिले में विशेषत: उक्त प्रकार के कितने स्टाफ की कमी कितने अर्से से है तथा इसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

(3) उक्त स्टाफ की आज तक पूर्ति न होने के कारणों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? क्या इसकी कोई वैकल्पिक योजना बनाई है?

चिकित्सा मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) हर वर्ष नवीन पद सृजित होते रहते हैं। अत: सामान्यत: हर वर्ष नर्सिंग स्टाफ की कमी रहती आई है। वर्तमान में रिक्त स्थान इस प्रकार हैं :-

1. सिस्टर	4
2. मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	561
3. स्टाफ नर्स	39
4. ए.एन.एम.	605
5. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	600

उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर की जायेगी।

(2) दूसरा, जैसलमेर जिले में वर्तमान में स्टाफ की कमी इस प्रकार है :-

1. मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	17
2. स्टाफ नर्स	1
3. ए. एन. एम.	22
4. एल. एच. वी.	5

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर की जा सकेगी।

(3) जी हां। निम्न वैकल्पिक योजनाएं बनाई गई हैं :—

1 — नये आर. एन. आर. सी. सेन्टर्स की स्थापना।

2 — ए. एच. डब्लू. को मेल नर्स के पदों पर पदोन्नत करने की योजना।

3 - 17 ए. एन. एम. ट्रेनिंग सेन्टर्स पुनः सरकार के नियन्त्रण में लेकर पुनः चालू करना व प्रशिक्षण हेतु भर्ती की संख्या की बढ़ोतरी करना। एक नवीन केन्द्र की स्थापना करना।

4 — ए. एन. एम. के प्रशिक्षण को दो वर्ष से घटा कर डेढ़ वर्ष का करना।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले सवाल का पूरा उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा है कि कितनी संख्या में मेल और फीमेल नर्सिंग स्टाफ कम है, और इसकी पूर्ति कब तक कर देंगे ? इसका आपने पीरियड नहीं बताया। आपने यह कहा कि स्टाफ मिलने पर पूर्ति करेंगे तो क्या स्टाफ अपने जाने के बाद मिल सकता है, स्टाफ दो साल में भी नहीं मिला है। आप स्पेसिफिक पीरियड बतायें कि राजस्थान में इतने अर्से में नर्सिंग स्टाफ पूरा कर दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मन्त्री महोदय....

श्री किशन सिंह भाटी : दूसरा आप यह बतायें कि यह कमी क्यों है, लोग क्यों नहीं आते हैं, यह कमी रही है तो इसकी क्या वजह है ? क्या आप इनका स्टाइपेंड बढ़ा-कर या दूसरा कोई टेम्पटेसन देकर इनको नहीं बढ़ा सकते हैं। इनकी कमी से कितनी तकलीफ हो रही है। डाक्टर्स अपनी ड्यूटी इस वजह से ढंग से नहीं कर पाते हैं। नर्सिंग स्टाफ की कमी है तो डाक्टर्स तो नर्सिंग स्टाफ का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह बताइये कि किस स्पेसिफिक पीरियड में, 1 महीने में, 2 महीने में 12 महीने में या दो साल में या तीन साल में, यह कब तक पूरी करेंगे ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि 1100 नर्सिंग स्टाफ की कमी है तो यह कमी कब से हो गई ? दो साल पहले भी यह स्थिति थी और आज दो साल के बाद भी यही स्थिति है ?

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : यही स्थिति 20 वर्ष से है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय, बतायेंगे कि 20 वर्ष की कमी को साल भर में पूरा करने की कोई स्पेसिफिक व्यवस्था राजस्थान सरकार करने जा रही है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या मन्त्री महोदय नर्सिंग स्टाफ की कमी को देखते हुए उनकी रिटायरमेंट की एज को आगे बढ़ा रहे है ? जो नये केन्द्र आप

(3)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

खोल रहे हैं, लोग उनमें शिक्षित होकर आयेंगे 2-3 साल में, तब यह कमी नहीं होगी। इसलिए इनकी रिटायरमेंट की उम्र 58 कर दी जाय, तो निश्चित तौर से सुधार आयेगा।

श्री **जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ) : जब यह ट्रेनिंग सेन्टर बढाये जा रहे हैं तो यह कमी क्यों है ?

श्री **त्रिलोकचन्द जैन** : जो मेल नर्स की कमी है उसके लिए ए. एच. डब्ल्यू. पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको पदोन्नत करने के लिए प्रस्ताव डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के पास भेजा जा चुका है। और यह भी किया जा रहा है कि करीब 600 इस प्रकार के पद अगले वर्ष भर दिये जायेंगे। इस प्रकार कमी की पूर्ति हो सकेगी। खास तौर से जो ए. एन. एम. और एल.एच.वी. की जो कमी है वह छठी पंचवर्षीय योजना के पूरा होते होते पूरी हो सकेगी। लेकिन इसमें जो कम्पाउन्डर्स लगे हुए हैं तो कम्पाउन्डर्स ज्यों ही उधर चले जायेंगे, ज्यों ही पदोन्नत हो जायेंगे, 200 लोग ए. एच. डब्ल्यू. के हमें मिल सकेंगे। इसलिए काफी हद तक वह कमी पूरी हो सकेगी। इसलिए इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है और 17 नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं। दो प्रशिक्षण केन्द्र आर. एन. आर. सी. के खोलें जा रहे हैं। तो स्टाफ की कमी दूर हो जायेगी।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जितने लोग प्रार्थना पत्र देते हैं ट्रेनिंग के लिए उनमें से कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे पाते हैं ? जितने लोग ट्रेनिंग चाहते हैं और जो निर्धारित क्वालिफिकेशन रखते हैं, फिर भी आपने पिछले दो वर्षों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बिल्कुल ही नहीं बढ़ाई है। क्या यह सच है ?

श्री **अध्यक्ष** : श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : प्रश्न संख्या 357।

श्री **गुलाबचंद कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवाइये।

श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री **गुलाबचंद कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, लोग बेकार बैठे हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और सरकार के पास नर्सिंग स्टाफ की कमी है लेकिन सरकार उनको ट्रेनिंग नहीं देती है।

श्री **कौशल किशोर जैन** : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम् मसला है। इसका जवाब दिलायें।

श्री **किशन सिंह भाटी** : कितने वर्षों में यह कमी पूरी कर दी जायेगी ?

श्री **त्रिलोकचंद जैन** : मैंने यह निवेदन किया है कि जो 17 ए. एन. एम. के ट्रेनिंग सेन्टर्स पहले रेडक्रास के अधिकार में थे उनके लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अगले वर्ष से इन सारे केन्द्रों को अपने द्वारा संचालित किया जाय। 5 आर. एन. आर. सी. के ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं जिसमें 50-50 लोगों को ट्रेनिंग देने की केपेसिटी है,

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

उसको बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वह अगले वर्ष में बढ़ा दी जायेगी और दो नये आर. एन. आर. सी. के ट्रेनिंग सेन्टर्स खोले जायेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि ए. एन. एम. और ए. एच. डब्ल्यू. की छठी पंचवर्षीय योजना के पूरे होने तक कमी पूरी हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष, महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। कब तो छठी पंचवर्षीय योजना पूरी होगी और कब ए. एन. एम. की पूर्ति होगी ?

श्री किशनसिंह भाटी : आपने यह कहा कि आने वाले वर्षों में कमी पूरी करदी जायेगी तो इसका स्पेसिफिक टाईम बतायें कि कब तक पूरी कर दी जायेगी।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्ष, महोदय, मैंने यह सुना है कि सिरोही में ए. एन एम. ट्रेनिंग सेन्टर खोला गया है, क्या यह सच है ?

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है। अगर माननीय मंत्री जी सही जवाब न दें तो उनको आप ताड़ना दें। वह इसको इस प्रकार से मजाक में न लें। हम पूछ रहे हैं कि कमी कब पूरी होगी उसका जवाब नहीं नहीं आता है। मैं यह चाहता हूं....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अविलम्ब स्टाफ की पूर्ति के लिए नर्सिंग स्टाफ के रिटायरमेंट की ऐज 58 इयर्स को आप क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : वह कर दी गई है। इसी वर्ष से वह तीन वर्ष के लिए बढा दी गई है।

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, केवल इतना सा तो बता दें कि आपने दो वर्षों में अपने प्रयत्न से कितने पद अभिसृजित किये और कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दिलाकर पूरा करेंगे ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि आगामी वर्ष में 8 पद का ट्रेनिंग सेन्टर है उसको 20 पद तक अलग से बढ़ा दिया गया है। दो ट्रेनिंग सेन्टर्स को और खोला जायेगा। एक महिला सेन्टर भी खोला जा रहा है। 17 केन्द्रों को वापस राजस्थान सरकार लेगी और आगामी जुलाई से प्रारम्भ कर देगी। यह ट्रेनिंग सेन्टर्स और यह सारा ट्रेण्ड स्टाफ आ जायेगा। इनकी ट्रेनिंग अवधि भी दो साल से घटाकर डेढ़ साल की कर दी गई है। इस योजना की पूर्ति में इतना समय लगेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह जो ट्रेनिंग सेन्टर हैं......

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, कई पद खाली हैं, उनमें से कितने भरे गये ? 600 में से कितने भरे गये हैं।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन): सारे राजस्थान में बहुत खेद-जनक व्यवस्था है। जब तक ट्रेड क्वार्टर्स पर ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। महिलाएं आगे नहीं आ सकेंगी।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इन सर्वोदय मन्त्री को क्यों परेशान किया जा रहा है। इनका मकान भी बहुत दूर है। इनके यहां कोई टेलीफोन सुनने वाला भी नहीं है। इनको तंग नहीं किया जाये।

श्री किशनसिंह भाटी : यह ट्रेनिंग स्टाफ की कमी की पूर्ति कब कर दी जाएगी ?

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की व्यग्रता को देखते हुए·······

श्री किशनसिंह भाटी : कमी को पूरा कर दीजिए।

एक माननीय सदस्य : क्या मन्त्री महोदय, मेरे क्षेत्र में पूर्ति कर दी जाएगी।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की व्यग्रता को देखते हुए मन्त्री महोदय से उत्तर दिलाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ में अपनी भावनायें भी सम्मिलित करता हूं। जहां तक मन्त्री महोदय की ओर से प्रश्न का उत्तर देने का सवाल है, मन्त्री महोदय ने स्पष्टतया जानकारी दे दी है। मन्त्री महोदय ने सरकार की इच्छा को व्यक्त कर दिया है। इससे अधिक मेरे ख्याल से और क्या कहा जा सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कमी पूर्ति कब तक होगी, यह जानकारी दे दें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री) : बैठो, यार। बैठो बैठो।

श्री अध्यक्ष : एक साल के बाद फिर पूछ लीजिएगा।

श्री मूलचन्द डागा : इतनी दूर जाना पसन्द नहीं करते हैं।

माण्डल में आयुर्वेद औषधालय

357. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माण्डल में आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए जनता द्वारा निर्मित भवन दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां की आबादी एवं भवन की व्यवस्था को देखकर सरकार ने उस चिकित्सालय को 'ए' क्लास का घोषित कर दिया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि 'ए' क्लास का बना देने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है ? ऐसे चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधारने के लिये राज्य सरकार ध्यान देगी ? अगर हां, तो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

क्या-क्या सुविधायें व कब से प्रदान कर दी जायेंगी ?

राज्य मन्त्री आयुर्वेद (श्री भैरवलाल कालाबादल) : (1) मांडल के आयुर्वेदिक औषधालय हेतु पंचायत द्वारा भवन व्यवस्था की हुई है। किन्तु पूर्णतया विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है।

(2) जी हां। औषधालय 'बी' श्रेणी का ही है।

(3) जब 'अ' श्रेणी का घोषित ही नहीं किया गया है तो तदनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री मूलचंद डागा : शाबाश।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा निदेशक, आयुर्वेद विभाग को जल्दी ही बर्खास्त करना चाहिये। मन्त्री महोदय का गला तक साफ नहीं कर पाये अभी तक।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि ऐसे कितने तहसील हैड क्वार्टस हैं, जहां आयुर्वेद औषधालय नहीं है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्नकर्ता।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : झालरापाटन में औषधालय नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : अध्यक्ष महोदय, आज से 10 वर्ष पूर्व ही एक बड़ा भवन बना दिया गया है। दुर्भाग्य है कि वहां पर कोई सुविधा नहीं है। लेकिन यह भवन अभी सरकार को हैण्ड ओवर नहीं किया गया है। यह जनता के द्वारा दिया गया भवन है। क्या भवन की सुविधा देने के बाद भी 'ए' क्लास का घोषित नहीं किया जायेगा।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल से जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे अब तो घोषित करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मन्त्री महोदय जरा सुनेंगे। सुनने के बाद हजम करेंगे। फिर उत्तर देंगे।

श्री भंवरलाल कालाबादल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वह भवन आयुर्वेद विभाग के नाम रजिस्टर्ड करवा दें तो हम अवश्य दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत।

रेगिस्तानी क्षेत्र नागौर के समस्याग्रस्त गांवों के लिए योजना

358. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीलाल सारस्वत]

(1) नागौर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र के समस्याग्रस्त गांवों की कौन कौन सी योजना इस वर्ष राज्य सरकार हाथ में लेने की सोच रही है ?

(2) बाकी योजनायें कब तक बन सकेंगी ?

राज्य मंत्री जन-स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ज्यों–ज्यों धन उपलब्ध होता रहेगा, समस्याग्रस्त गांवों की योजना बनायी जाती रहेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के पश्चिमी उत्तरी भाग में जो कि बीकानेर जिले के पास है, क्या उसकी अन्य बातों की अपेक्षा इस समस्या की पूर्ति करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान सरकार वैकल्पिक रूप से यह ध्यान रखते हुये, राजस्थान केनाल जो कि बीकानेर तक आ चुकी है, वैकल्पिक रूप से राजस्थान केनाल से पानी लेकर पीने के पानी की समस्या हल करेगी ?

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान केनाल को पेयजल योग्य बनाने की योजना पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। जिन स्थानों पर अण्डर ग्राउण्ड वाटर उपलब्ध नहीं हुआ है। वहां के लिये राजस्थान केनाल की योजना बनाई जा रही है। जहां तक नागौर के लिये लिफ्ट योजनाओं का सवाल उठाया गया है, यह बात सरकार के विचाराधीन है। अभी बात फाईनल नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर) : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में पानी उपलब्ध नहीं हुआ है, वहां के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं तो कहां कहां योजनायें बनाई जा रही हैं ?

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि भू-जल स्त्रोत से जो पानी दिया जाता है जो अपेक्षाकृत अधिक व्यय वाला है, साथ ही साथ उपयुक्तता की दृष्टि से खर्चीला भी है ? क्या राजस्थान केनाल का पानी नागौर के लिये अधिक लाभप्रद नहीं है ? उसी से दिया जाना चाहिए। क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अगर आधा खर्च किया जाये तो समस्या की पूर्ति हो सकती है ?

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : दो हजार से अधिक आबादी वाले गांव में भी अभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं जहां तक राजस्थान केनाल को स्त्रोत बनाकर पेयजल की समस्या का समाधान करने का प्रश्न है, पेयजल अण्डर ग्राउण्ड वाटर टेप करके देने का जो प्रश्न

(श्री महबूब अली)

उठाया है, माननीय सदस्य ने जो कहा है, राजस्थान केनाल में पाईप लाईन ले जानी पड़ेगी। अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के विकल्प के लिये खर्चा बहुत है। राजस्थान केनाल में पाईप को बहुत बड़ा करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे.... ...

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि जहां ग्राउण्ड वाटर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पर ग्राउण्ड वाटर अवेलेबल है वहां पर आपने कितने गांवों में पानी पिलाने की योजना बनाई है ?

(व्यवधान)

श्री बहादुरसिंह (नोहर) मेरा प्रश्न है कि क्या बारानी गांवों को भी पानी पिलाने की व्यवस्था की जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं यह मानता हूं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एक माननीय सदस्य खड़ा होकर प्रश्न पूछे तो सरकारी उत्तर आ जाये। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछे तो प्रश्न का महत्व रह सकता है अन्यथा सदन का समय नष्ट होगा। कोई न कोई सामंजस्य होना चाहिए। धीरे-धीरे फर्क पड़ रहा है लेकिन और भी आपका सहयोग रहेगा तो प्रश्नोत्तर काल महान रुचिकर और सफल हो सकता है।

सप्लीमेण्टरी प्रश्न श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा अभी बताया कि पानी की समस्या को वे अहम् समस्या मानते हैं और साथ में यह मजबूरी भी बताई कि जहां पर ग्राउण्ड वाटर नहीं है वहां पर लिफ्ट केनाल ले जाने की बात की। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां रेगिस्तानी क्षेत्रों में ग्राउण्ड वाटर अवेलेबल है पहले से, कृपया यह बतावें मन्त्री महोदय की कुशलता को देखते हुए, इस अहम् और मानवीय समस्या को सुलझाते हुए कितने गांवों को पानी पिलाया गया है ? यह आंकड़े प्रस्तुत करें।

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य का अलग से प्रश्न है, इसको अलग से पूछेंगे तो मैं उनको विगत भी दे सकता हूं। मौजूदा प्रश्न सिर्फ नागौर से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य अलग से पूछेंगे तो निश्चित रूप से मैं जवाब दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले का प्रश्न है, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि सेवड़ा गांव में दो ट्यूबवैल्स हैं, क्या वे सील्ड कर दिये गये हैं ? उनको इलैक्ट्रिफाई करने से 100 गांवों को इसका लाभ मिल सकता है। क्या मन्त्री महोदय उस तरफ कोई प्रयत्न करना चाहते हैं ?

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मेरा एक पूरक प्रश्न है। वह यह है कि ग्राम चावडिया रुड, गाजू आदि गांवों में ट्यूब वैल्स लगे हुए हैं। उनको उपयोग में लिया जाय तो गांवों के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। क्या मन्त्री महोदय इस तरफ कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि नलों में खर्चा ज्यादा लगेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि बीकानेर से नागौर तक 36" का पाइप लगाने में क्या खर्चा पड़ेगा और राजस्थान सरकार ने विश्व बैंक की मदद से जो योजना बनाई है उसमें रेगिस्तानी क्षेत्र नागौर जिले में भू-जल के स्रोत से पानी पिलाने की क्या योजना है इसमें कितना खर्चा आयेगा ? ताकि यह मालूम हो सके कि कौन सी योजना लाभप्रद है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह । एक सप्लीमेंटरी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। हजारीमल सारण को समय दूंगा सप्लीमेंटरी के लिए। पहले सरकारी उत्तर आने दीजिए।

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, खर्चे का जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया कि राजस्थान केनाल से पानी लाने के लिए 36 इंच का पाइप या जितनी भी केपेसिटी का लिया जाय उसमें कितना खर्च होगा और अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्कीम से कितना होगा। इनके आंकड़े तो फिलहाल मेरे पास नहीं हैं। लेकिन मैं यह अर्ज कर दूं कि जितनी दूरी से पाईप लाया जायेगा उसका उतना ही ज्यादा खर्चा होगा, मोटे रूप में मैं यही कह सकता हूं लेकिन एग्जेक्ट आंकड़े में अभी बताने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि...

श्री अब्दुल अजीज : जो ट्यूब वैल्स खुदे हुए हैं उन पर क्यों नहीं आप शुरू करते ?

श्री महबूब अली : मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, आप मुझ को बता दीजिये, ट्यूब वैल्स अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल्स होते हैं। जो आप बता रहे हैं वे रेगूलर हैं या नहीं, आप मुझे बता देना, मैं इसकी पूरी सूचना दूंगा।

श्री बहादुर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नोहर तहसील में 1, 2, 3 गांवों में सीवेज की वजह से सारा एरिया खराब हो रहा है और गांव वाले प्यासे मर रहे हैं। क्या राजस्थान केनाल से बारानी गांवों को भी पानी दिया जायेगा और सरदारशहर, चूरू तहसीलों में भी दिया जायेगा ? क्या इस तरह की कोई योजना विचाराधीन है ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री हजारीमल सारण।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि भूमि का जल जहां पर उपलब्ध नहीं है वहां पर राजस्थान केनाल से व्यवस्था की जा रही है। मैंने यह प्रश्न किया है कि कौन-कौन से ऐसे स्थान हैं जहां के लिए राजस्थान केनाल से पानी पिलाने की योजना बनाई जा रही है और वह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) : अरे साहब बड़े मंत्री खड़े हुए थे।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक लेजिटीमेट प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : It is not a legitimate question.

अब आप स्थगित करिये।

श्री बहादुरसिंह : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेण्टरी स्थगित कर दिये या प्रश्न को स्थगित किया ?

श्री अध्यक्ष : आपके सप्लीमेण्ट्री को स्थगित किया क्योंकि वह सप्लीमेण्टरी नहीं बनता। सरकारी बेंचेज से बड़ा स्मार्ट उत्तर मिल चुका है।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले आप सुन लें। आप अलाउ करें या नहीं यह आपके डिस्क्रिशन पर है। मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि जहां भी स्कीम मन्जूरशुदा है वहां पर इसलिए पानी नहीं आ रहा है कि पाइप दो ही कम्पनियों से लिये गये हैं और पाइप लाइन नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को पत्र द्वारा जानकारी दे दीजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं देते हैं पत्र तो लिखकर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बहादुरसिंह।

कुंडला खुर्द से बाजना सड़क

359. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बहादुर सिंह)

(1) क्या कुण्डला खुर्द से बाजना सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां तो अब तक कितनी धनराशि किस किस विभाग से उस सड़क पर खर्च की जा चुकी है ?

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग इस सड़क को कितने समय में पूरा करने का विचार रखता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुण्डला खुर्द से बाजना सड़क मध्य प्रदेश की सीमा को मिलाती है ? यदि हां, तो सड़क निर्माण में देरी क्यों की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जय नारायण पूनिया) : (1) कुण्डला खुर्द से बाजना (मध्य प्रदेश) की सड़क राजस्थान सीमा के अन्तर्गत 16.85 कि. मी. है। इस पर कुछ वर्ष पूर्व माही परियोजना द्वारा कुछ कार्य किया था। इस विभाग द्वारा केवल सन् 78-79 में फेमिन कार्यों के अन्तर्गत 7 कि. मी. ग्रेवल व 9 छोटी पुलियाओं का कार्य किया गया और फेमिन के मद से 1.85 लाख रुपये व्यय हुए।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क के मद में इस सड़क पर कोई स्वीकृति नहीं है।

(3) यह सड़क छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है और इसकी व इस पर बनने वाले पुल-पुलियाओं की कुल अनुमानित लागत 40 लाख रुपये होगी।

श्री बहादुरसिंह : माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई और माही प्रोजेक्ट पर कितनी की गई ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सड़क पर मेटेरियल सारा पड़ा है और कम खर्चे में यह सड़क पूरी हो सकती है। माही बांध के बनने से रतलाम-बांसवाड़ा रोड़ जो डूब में जाने वाली है, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, इस सड़क को इस साल ही बनाया जाए ताकि आने जाने में कठिनाई न हो।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर माही परियोजना द्वारा करीब 19 लाख रुपये खर्च किए गए। पहले यह सड़क जहां पर बनी हुई थी वह माही परियोजना की डूब में आने की वजह से माही परियोजना द्वारा इसको अपने विभाग से बनाना शुरु किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस बात के लिए क्षतिपूर्ति चाही और पूछा गया कि हमारी सड़क के बारे में क्या किया। तब यह सामने आया कि इसे बनाना शुरु कर दिया। यह एलाइनमेंट का काम था। इससे नुकसान ज्यादा था इसलिए उसको पी. डब्ल्यू. डी. ने नहीं माना है। उस झगड़े में यह सड़क अभी भी पड़ी हुई है और उसके कारण हम अभी तक स्वीकृत नहीं कर पाए थे। अब छठी योजना में प्रस्ताव किया है और जहां से एलाइनमेंट किया गया है तालाब में कुछ पोर्शन आएगा। इस प्रकार यह बड़ी योजना है।

श्री जिथिंग (कुशलगढ) : इस रोड़ पर फेमिन में कितना खर्चा किया गया ? विभाग ने क्यों नहीं हाथ में लिया और जैसा प्रश्नकर्ता ने पूछा बांसवाड़ा—रतलाम रोड़ जो माही की डूब में जा रही है उस सड़क को सरकार कब तक कम्पलीट करने का विचार रखती है ?

श्री जयनारायण पूनिया : यह प्रश्न विचाराधीन है, इसका महत्व काफी है, इसको पंचवर्षीय योजना में हमने ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह दांता।

बाग्यवास से कुचामन तक जाने वाली बसें

360. श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में बाग्यवास कुचामन बसें बांय तक जाती थीं? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये बसें बंद कर दी गई थीं तथा मंत्री जी ने कितनी ही दफा डी. टी. ओ. सीकर को आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि सीकर से अजमेर जाने वाली बसों से बस स्टेण्ड तक आने के आदेश आयुक्त यातायात व आर. टी. ओ. जयपुर को दिए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां। बाजियावास-कुचामन मार्ग की बसें दिनांक 10-2-78 तक बांय तक जाया करती थीं।

(2) जी हां। तत्कालीन परिवहन मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आर. टी. ओ. जयपुर को इस मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था तथा आर. टी. ओ. जयपुर ने सम्बन्धित बस मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिए हैं।

(3) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किस बस स्टेण्ड के सम्बन्ध में सूचना चाही गई है।

श्री मदन सिंह दांता : दांता का जो बस स्टेण्ड है वह काफी दूर है, शायद आपसे बातचीत भी हुयी है और रघुवीर सिंह जी ने आदेश दिया था बस वालों को। दांता में पूरी चौपड़ है यहां जैसी. वहां भी बस नहीं जा रही है। मुसाफिर रात को बारिश में खुद माल उठा कर सिर पर ले जाते हैं, औरतें व बच्चे भी होते हैं। एक मील तक जाते हैं जबकि बांय तक परमिट है। उनकी जिद्द हो गई। या तो उनका परमिट कैंसिल किया जाए, नहीं तो जहां तक यात्री जाना चाहे वहां तक जाये या टेम्पो लगायें 2-4 गांवों में उनका माल ले जाने के लिए।

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य का कहना है कि बस बांय तक नहीं जाती है, हमको इसकी जानकारी है। वह जगह सकड़ी पड़ती है। जहां तक बस परमिट केन्सिल करने का सवाल है, यह कार्यवाही तो की जाएगी लेकिन इसमें माननीय सदस्य को ही परेशानी होगी।

श्री मदन सिंह दांता : मुझे कतई ही परेशानी नहीं होगी। बस तीन मिनट घूम कर दांता में एक चक्कर नहीं दे सकती। मैं ज्यादा बहस न करके आपको कन्विन्स कर दूंगा कि चौपड़ में ज्यादा तंगाई नहीं है। स्टेण्ड पर जगह कम है और दांता की

(श्री मदनसिंह दांता)

चौपड़ में अधिक है। कुछ मोटर मालिकों की जिद् हो गई है कि हम नहीं जायेंगे। बाकी और बसें क्यों जाती हैं, सीकर की बस क्यों जाती है, रींगस की बस क्यों जाती है, जयपुर की क्यों नहीं जाती ?

प्रश्न सख्या 361

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसों में शिकायत पुस्तिकयें

362.—**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत एक वर्ष में परिवहन की बसों के साथ रखी जाने वाली शिकायत पुस्तिकायें हेतु कुल कितना व्यय किया गया तथा कोटा, बूंदी, झालावाड़ डिपो के लिए गत वर्ष कुल कितनी शिकायत पुस्तिकायें सेंट्रल स्टोर से भेजी गई ?

(2) क्या यह सही है कि किसी भी बस में कोई शिकायत पुस्तिका न परिचालक के पास, ना ही शिकायत बाक्स में रहती है ? यदि हां, तो फिर क्यों कर बाक्स बस में लगाया गया है ? कोटा डिपो से चलने वाली बसों की शिकायत पुस्तिकाओं में कुल कितनी शिकायतें दर्ज हुईं ?

यातायात मंत्री(श्री हरिसिंह): (1) वर्ष 1978 में शिकायत पुस्तिका छपवाने हेतु 4472) रु. खर्च किए गए। कोटा, बूंदी व झालावाड़ आगार को वर्ष 1978 में क्रमश: 200, 100 व 50 शिकायत पुस्तिकायें स्टोर से जारी की गई।

(2) वर्तमान में निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शिकायत पुस्तिका टिकट बैग के साथ परिचालक को जारी की जाती है तथा परिचालक का यह कर्त्तव्य है कि किसी भी यात्री द्वारा मांगे जाने पर शिकायत पुस्तिका दी जावे। वर्ष 1978 में कोटा डिपो से चलने वाली बसों की शिकायत पुस्तिकाओं में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, परन्तु इस अवधि में कोटा आगार कार्यालय में 96 शिकायतें प्राप्त हुईं।

माननीय सदस्यों की बात सही है कि शिकायत पुस्तिका नहीं दी जाती है। हम इसको ठीक करने की व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री टीकमचंद कांत (जालौर) : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि शिकायत पुस्तिका के पास में ही फर्स्ट एड का बाक्स होता है ..

(व्यवधान)

श्री सूर्यप्रकाश (खेरवाड़ा) : निगम की बसों को चैक करने के अधिकार विधायकों को दिये गये हैं, विधायकों द्वारा कितनी बार चैकिंग की गई....

(व्यवधान)

श्री टीकमचंद कांत : शिकायत पुस्तिका के पास में ही जो फर्स्ट एड का बाक्स होता

(श्री टीकमचन्द कांत)

है और जिस तरह से शिकायत पुस्तिका का बाक्स खाली रहता है, क्या फर्स्ट एड बाक्स भी खाली रहता है ? अगर यह सही है तो उसको भी व्यवस्थित करने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : It is not a party. It is a gang of indiscilipine.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगज) : अध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्या की बगल में खड़े हुए क्या आप शोभायमान लगते हैं ?

श्रीमती नारंगी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जब कम्पलेन्ट लाज करते हैं तो उसका उत्तर नहीं मिलता है। दूसरा निवेदन यह है कि शाहबाद में बसें बिलकुल नहीं चलने दी गयी हैं....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : प्रश्न यह है कि सैन्ट्रल स्टोर्स से कम्पलेन्ट बुकें कोटा, बूंदी और झालावाड़ के लिए दी गयी हैं और मंत्री महोदय ने बताया कि वह 42 हजार रूपये की है और बसों में पुस्तकें नहीं हैं तो वह कहां गयीं ?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया मंत्री जी को निर्देश दें कि वह चश्मा उतार दें ताकि सच्चाई जाहिर हो सके।

श्री अध्यक्ष : शायद प्रश्न माननीय सदस्यों का एक है कि वह पुस्तकें क्या गायब हो गयी हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, यही बात है।

श्री टीकमचंद कांत : वह बसों में से गायब हैं। बसों में कम्पलेन्ट बुक्स नहीं होतीं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय से पूछें कि फिर वह कहां गयीं ?

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : एक सवाल और है कि कन्डक्टर लोग डुप्लीकेट पुस्तकें रखते हैं और उनको हटा लेते हैं शिकायत दर्ज करने के बाद में। इसका भी जवाब माननीय अध्यक्ष, दिलाया जाये।

श्री मदनसिंह दांता : सदस्यों को अधिकार है, उन्हें पकड़े।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी यह नये मंत्री आये हैं, पुस्तकें छपवा देंगे।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट एड बाक्स नहीं है उसके बारे में मंत्री महोदय ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : फर्स्ट एड के बाक्स डाक्टरों के पास गये हैं इलाज के लिए। बीमार हो गये हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : दवाइयां और बाक्स कहां गये इसका उत्तर दिलायें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस प्रकार की अनियमिततायें होती हैं इसका आभास इनको कब हुआ ? क्या यह विधायक थे तब से आभास था कि यह अनियमिततायें हैं या इनके मंत्री बनने के बाद इनको आभास हुआ है ? इन अनियमितताओं के रोकने लिए मंत्री बनने के बाद क्या कार्यवाही की है, यह बता दें।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही बताया था कि यह शिकायत पुस्तकें कन्डक्टर्स नहीं देते है। माननीय सदस्यों की बात सही है। दूसरे, मैंने यह बताया कि इस बारे में कार्यवाही की जा रही है।

इसके अलावा और भी अनियमिततायें हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : आज तक क्या एक्शन लिया, यह सवाल है ? बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपको यह आभास कब से हुआ कि यह अनियमिततायें हैं और उसके बारे में इन 6–7 महीनों में कितनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? दूसरा प्रश्न यह है कि पुस्तिकाओं को एम. एल. ए. को और दूसरे लोगों को यह परिचालक लोग नहीं देते हैं और इसके अलावा जिन शिकायतों को हमने डिपो में लिखा उनके ऊपर कितनों पर कार्यवाही पिछले 6-7 महीनों में आपने की ? हमको कहते हुए शर्म आती है कि डिपोज में शिकायत लिखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और आपको जानकारी होने के बाद भी आपने एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा उन कम्पलेन्टस को जो हमने डिपो पर लिखीं उनका आज तक हमें उत्तर नहीं मिला।

श्री किशनसिंह भाटी : आपने एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, यह बहुत रेलेवेन्ट क्वेश्चन है। इन्होंने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया ? लिया तो कितने लोगों के खिलाफ लिया इसका स्पेसिफिक जवाब दिलायें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यातायात मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन में....

श्री किशनसिंह भाटी : He is siding with the Minister and he wants to side track our question.

पहले हमारे क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए कि मिनिस्टर बनने के बाद से आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि आपको यह आभास कब हुआ कि यह अनियमिततायें होती हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : यह क्वेश्चन बहुत जरूरी है और इसको आधा घन्टे की चर्चा के लिए रखा जाये।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मैंने निवेदन किया था कि एक साल के अन्दर रोडवेज के सैन्ट्रल स्टोर्स से 42 हजार की पुस्तकें कोटा, बूंदी और झालावाड़ के लिए इश्यू हुईं वे कहां गयीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों की सेवा के लिए माननीय मन्त्री महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री किशनसिंह भाटी के सप्लीमेन्ट्री प्रश्नों का कृपया उत्तर दें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक मेरा और साथ ही साथ है'... '

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह भाटी : पहले हमारे सवाल का जवाब आना चाहिए। He should not try to side track our question.

पहले अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन कीजिए। आप इस तरह से बीच में बोलकर मन्त्री को डिफेण्ड मत कीजिए....

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप कृपा कर बैठ जायें। आप गलत कह रहे हैं। मैं आपकी तरह दोस्ती नहीं निभाता हूं। Would the Chair protect me from this disturbance ?

श्री किशनसिंह भाटी : He is attempting to side track our question.

श्री अध्यक्ष : You have caught my eye. I will give you time, but the hon. Member is arrogating to himself the duties and functions of the Speaker. What can I do ?

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री किशनसिंह भाटी ने जो सवाल पूछा है कि किन-किन के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है, यह सवाल अलग से है मैं इसकी सूचना भी उनको बता दूंगा अगर वह जानना चाहें तो।

श्री किशनसिंह भाटी : इसको आधा घण्टे की चर्चा के लिए रखा जाये अलग से।

श्री अध्यक्ष : मैं इससे अधिक प्रश्न का उत्तर नहीं दिला सकता। मन्त्री महोदय ने खड़े होकर उत्तर दे दिया बस। श्री बजरंग लाल शर्मा.

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कारपोरेशन में उनकी इसलिए नहीं चलती है कि वहां 50 साण्ड

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

छोड़े हुए हैं जो काम नही करते और कुछ होता है उसके बीच में अड़ंगा लगाते हैं ? क्या यह सही है कि 50 सांड वहां छोड़े हुए हैं ?

(व्यवधान)

श्री रघुनंदन व्यास : आधे घण्टे की चर्चा की जाये। 50 लोग कोन कौन है, उनके नाम आने चाहिये । इसकी पूरी जानकारी आनी चाहिये....

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था....

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : बहुत बड़ा एलीगेशन है इस प्रश्न के बारे में। बजरंगलाल जी नाम बतायें। मन्त्री महोदय जवाब दें। आधे घण्टे को चर्चा की जाये।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है। एक साल के अन्दर अन्दर 4200 शिकायत पुस्तकें यहां से रवाना हुई कोटा, बूंदी, झालावाड़ के लिये । परन्तु वहां की बसेज में नहीं हैं । मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रश्न संख्या 15....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : पहले भी रोडवेज का प्रश्न स्थगित हुआ था। आधे घण्टे की चर्चा के लिये रखा गया था लेकिन चर्चा नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : 50 सांडों का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री रघुनन्दन व्यास : बजरग लाल जी का महत्वपूर्ण सवाल है। 50 सांड कहां से घुस गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

मुझे विश्वास है, मन्त्री महोदय, कुछ न कुछ सुव्यवस्था लाने के लिये प्रयास गम्भीरतापूर्वक करेंगे।

स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

कृपया उत्तर सुनिये।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय अगर बजरंगलाल जी का मतलब कुछ × × से यह है कि रोडवेज में कुछ कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा दे रखी है तो मैं निवेदन करूंगा कि यूनियन से समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार यूनियन के पदाधिकारियों के काम नहीं करने का समझौता हुआ था और इस बात का समझौता हुआ था........

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 18

(18)

श्री श्योपत सिंह मकासर : फिर × × केटेगरी में आप भी आते हैं। उस यूनियन के साथ में आप भी आते हैं....

(व्यवधान)

श्री रघुनंदन व्यास : यूनियन के पदाधिकारियों से ड्यूटी लेनी चाहिये....

श्री एच. एन. शर्मा : यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है....

श्री श्योपत सिंह मकासर । यह × × खड़े हैं ।

श्री रघुनंदन व्यास : काम न लेना और तनख्वाह देना यह पाप है।

श्री एच. एन. शर्मा : × × × नेताओं के द्वारा....

(व्यवधान)

श्री रघुनंदन व्यास : इस भ्रष्टाचार के नंगे नाच का खुलासा होना चाहिये ।

(व्यवधान) ।

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसे आधे घण्टे की चर्चा के लिये रखा जाये ।

श्री रघुनन्दन व्यास : मुफ्त में तनख्वाह देना, उनको पालना, हड़ताल करने के लिए....

(व्यवधान)

यह जो रोडवेज कर रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : जिस प्रकार की सुविधायें ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सरकार से जानना चाहता हूं, इस प्रकार की सुविधायें ...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इमर्जेन्सी के नाम पर यह लाटरी का माल शोर मचा रहा है ।

श्री एच. एन. शर्मा : लड़कर लेने वाले बहुत देखे हैं ....

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह मजदूरों ने भेजा है । यह सरकारी सांड मजदूरों ने भेजा है ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो गाय है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, श्योपतसिंह जी बहुत पुराने सदस्य हैं। दूसरे विधायकों को सांड कह रहे हैं, इनको प्रताड़ना दी जाये ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो आपने समझौता किया है कि 50 आदमी महीने के महीने तनख्वाह लें और किसी प्रकार का काम न करें....

श्री श्योपतसिंह मकासर : लड़कर लिया है । समझौता किया है ।

(व्यवधान)

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

Page No. 19

(19)

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है ...

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जवाब सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मूलचंद डागा : प्रश्नकाल में इस तरह से उत्तर नहीं दे सकते हैं मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : इसका जवाब मन्त्री महोदय से दिलवाया जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कन्फ्यूजन में क्या पाइन्ट आफ आर्डर चलेगा। व्यवधान समाप्त होने दीजिए।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में भी अनियमितताओं के बारे में चर्चा रखी गई थी....

(व्यवधान)

इसलिए आधे घन्टे की चर्चा रखी जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन निगम की अनियमितताओं के बारे में पिछले सत्र में भी आधा घण्टे की चर्चा रखी गई थी लेकिन हो नहीं सकी थी। इसलिये मेरा निवेदन है सदन में इसके लिये आधा घण्टे की चर्चा रखी जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में आप मुझ से कक्ष में मिलें। मैं माननीय सदस्य, कई बार घोषणा कर चुका हूं कि प्रश्न समाप्त हुए। अब मन्त्री महोदय से उत्तर की अपेक्षा भी नहीं करता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंटरी पूछने का अधिकार है....।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी अव्यवस्था तो यह है कि इतने × × × बाद भी कोई कम्पलीट व्यवस्था नहीं है, बड़ी विडम्बना की बात है।

After this × × × the story is not complete.

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No. 20

(20)

श्री अध्यक्ष : यह स्टोरी कम्पलीट नहीं होगी। It is an un-ending stream of complications. The best thing is to give it up.

श्री कौशल किशोर जैन : दो करोड़ 53 लाख का घाटा है, आप व्यवस्था दीजिए।

(व्यवधान)

श्री हीरा लाल : यह खुला भ्रष्टाचार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि आपकी प्रश्न सूची में पांच स्थगित प्रश्न है। या तो हमेशा के लिए इन स्थगित प्रश्नों का समय ही समाप्त कर दिया जाये। एक घण्टा तो इसमें चला गया, इस पर क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित प्रश्नों के बारे में और भी विचार करूंगा और यदि महत्वपूर्ण स्थगित प्रश्न होंगे तो उस पर पुनः पूछने की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर सकता हूं। अभी मैं निश्चित रूप से कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : अध्यक्ष महोदय, सदन में साण्डों का मामला तो छेड़ दिया लेकिन सीमेन्ट की जो कमी है उसके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है..

(व्यवधान)

यहां × × को घण्टों हो गये। सीमेन्ट में कितना घोटाला है, यह भी बता दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नरेन्द्र पाल सिंह जी, आपकी आपत्ति से मेरी पूर्ण सहानुभूति है। इस विभाग में बड़ी अनियमितताएं हैं। कोई एक मिनिट में तो सुधारा नहीं जा सकता है, यह आपका सदन है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : ये जनता पार्टी के लोग शोर-शराबा ही शोर-शराबा करना चाहते हैं....

(व्यवधान)

जनता पार्टी के लोगों को किस तरह चलना चाहिये, जानते ही नहीं हैं।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के कोई सदस्य अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनता के हितों की बात करेंगे।

(व्यवधान)

आप पुराने होकर भी हल्ला मचाते हो। यह आम जनता के हित की बात है। कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

× × ×

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

× × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किए गए।

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नही किया गया।

अनुउपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर भरतपुर व सवाई माधोपुर में डकैत समस्या का उन्मूलन

361. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भरतपुर व सवाई माधोपुर जिले में कौन-कौन से डकैत गिरोह सक्रिय हैं ?

(2) इन जिलों में कब तक डकैती की समस्या का उन्मूलन कर दिया जायेगा ?

(3) क्या डकैतों के कारण ही पुलिस अधिकारियों को गेलेन्टरी मेडल मिलते हैं ?

(4) क्या कुछ सभ्य लोग भी डकैती को धन्धा मानकर इस कार्य में लीन हैं ?

(5) क्या डकैती की समस्या के समाधान की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालने की व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर

(1) भरतपुर तथा सवाई माधोपुर जिलों में उत्तर प्रदेश के चंदन डकैत का गिरोह सक्रिय है ?

(2) इस समस्या के उन्मूलन हेतु सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस समय इनकी गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण है।

(3) जी नहीं। किसी भी विशेष साहस-पूर्ण कार्य के लिए मैडल दिये जा सकते हैं।

(4) ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं है।

(5) यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अल्प आय वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आवासन मण्डल के मकानों का आवंटन

352. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में अब तक आवासन मंडल द्वारा कितने मकानों का निर्माण हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इसमें अल्प आय वालों के लिए कितने मकानों का निर्माण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों को कितने मकान आवंटित हुए हैं और कुल आवंटन में उनकी क्या प्रतिशतता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती दरों पर मकान आवंटित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आवासन बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 1978 तक 14950 मकानों का निर्माण

(नगर योजना मन्त्री)

किया गया है तथा 9066 मकान निर्माणाधीन हैं।

(2) दिसम्बर, 1978 तक अल्प आय वालों के लिए 11867 मकानों का निर्माण किया गया तथा 7710 मकान निर्माणाधीन हैं।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 596 व्यक्तियों को मकानों का आवंटन किया जा चुका है तथा कुल आवंटन में उनकी 4.68 प्रतिशतता है।

(4) ऐसा कोई विषय विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान शिक्षक संघ की मांगें

353. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान शिक्षक संघ की 71 सूत्री मांगों में से कई मांगों को शीघ्र पूरा करने का राज्य सरकार द्वारा लिखित आश्वासन मई, 1978 में दिया गया था ?

(2) यदि दिया गया था तो किन किन मांगों के सम्बन्ध में दिया गया था और कितनी अवधि में पूरा करने का दिया था ?

(3) किन किन आश्वासनों को पूर्ण कर राज्यादेश जारी कर दिये गये हैं तथा शेष मांगों को आश्वासन के अनुसार क्यों पूरा नहीं किया जाता तथा कब तक पूरा करेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुल 38 मांगों के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया था, परन्तु इन्हें पूरी करने की निश्चित अवधि नहीं बतलाई गई थी।

(3) इन 38 मांगों में से 15 के संबंध में निर्णय ले लिया गया है तथा आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं शेष 23 मांगें विचाराधीन चल रही हैं।

राज्य की शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या

354. श्री **बजरंगलाल शर्मा**(बनीपार्क): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है ? निम्न प्रकार से :—

(अ) प्राथमिक स्कूल तक,

(ब) उच्च प्राथमिक स्कूल तक,

(स) माध्यमिक स्कूल तक,

(द) उच्च माध्यमिक स्कूल तक,

(2) उपरोक्त में से सरकारी स्कूलों में उक्त वर्गानुसार कितने हैं और गैर सरकारी स्कूलों में कितने हैं ?

(3) उक्त सरकारी स्कूलों पर कुल व्यय कितना किया जाता है और गैर सरकारी स्कूलों को कितना अनुदान या अन्य सहायता दी जाती है ?

(4) बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों में कुल कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) राजस्थान में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालयों के स्तर अनुसार अलग से सलग्न की जा रही है।

(2) संलग्न प्रपत्र में ऐसी सूचना भी सम्मिलित कर दी गई है।

(3) संलग्न प्रपत्र में ऐसी सूचना भी सम्मिलित कर दी गई है।

(4) जो स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनकी सूचना विभाग द्वारा एकत्र नहीं की जाती है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नगरपालिका, नवलगढ़ की आय व खर्च

355. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका नवलगढ़ ने पिछले दो वर्ष में कौन कौन से निर्माण के कार्य और कितनी कितनी कीमत के कार्य करवाये हैं और उनमें कितनी धन राशि खर्च हुई है, कितने कार्य पूरे किये गये और कितने अधूरे हैं ? अधूरे कार्यों को अब तक किन कारणों से पूरा नहीं किया जा सका है ?

(2) नगरपालिका नवलगढ़ में कितने सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? नामावली मय नियुक्ति तिथि के सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) सफाई कर्मचारियों को पिछला एरियर कब दिया गया, किन किन को दिया गया और कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बकाया का भुगतान अब तक नहीं हो सका है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(4) नगरपालिका नवलगढ़ की कुल वार्षिक आमदनी कितनी है ? राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है तथा शेष आमदनी का स्रोत क्या है ? नगरपालिका का कुल कितना खर्चा होता है ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कुछ निर्माण कार्य व उन पर हुये व्यय की राशि का विवरण और अधूरे कार्यों का विवरण मय उन कारणों के, जिनकी वजह से कार्य पूरा नहीं हुआ, संलग्न है।

(2) सफाई कर्मचारियों की नामावली मय नियुक्ति तिथि के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) समस्त सफाई कर्मचारियों को पिछला एरियर मार्च, 78 से अक्टूबर, 78 तक दे दिया गया है। अब किसी भी सफाई कर्मचारी का कोई एरियर बकाया नहीं है।

(4) नगरपालिका की वर्ष 77-78 की आय व व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

सोजत नगरपालिका क्षेत्र में चुंगी की दरें

356. श्री खंगारसिंह चौधरी(खारची) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सोजत नगरपालिका क्षेत्र को वर्तमान चुंगी दरों का प्रकाशन कब से होगा ?

(2) उक्त प्रकाशन के पूर्व की नगर-पालिका की चुंगी दरों में मेंहदी पर चुंगी देय थी या नहीं ? अगर थी, तो क्या ?

(3) वर्तमान चुंगी दरों में मेंहदी पर क्या चुंगी लागू की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्या नगरपालिका उक्त चुंगी वसूल कर सकती है ?

(4) क्या यह सही है कि चुंगी वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार में नगरपालिका के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं और वे जिन पर चुंगी देय है उसे वसूल नहीं करते हैं व जिन पर देय नहीं है उन पर नाजायज वसूली करते हैं ?

(5) उपरोक्त वस्तुओं पर चुंगी देय थी जिन पर वसूल नहीं की गई उसे अब वसूल कब तक कर लिया जायेगा ?

(6) क्या यह सही है कि जिन वस्तुओं पर चुंगी देय है उसे वसूल न करने के लिये प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है व उसके ध्यान में नगरपालिका द्वारा यह तथ्य लाने पर भी अपने नाजायज लाभ हेतु अपने पद का दुरुपयोग कर उसकी वसूली के आदेश नहीं दिये ?

(7) नगरपालिका द्वारा कब कब प्रशासक को यह बताया गया कि कांकरी व कोयले की चूरी जो नगरपालिका क्षेत्र में खपत होती है, पर चुंगी की वसूली होती है ? इस चुंगी का प्रभाव किन किन पर पड़ता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नगरपालिका सोजत की वर्तमान चुंगी की दरों का प्रकाशन दिनांक27-3-75 को हुआ है।

(2) मेंहदी को किराना सामान मान कर इस पर चुंगी 50 पैसा प्रति सैकड़ा की दर से ली जाती है।

(3) किराने पर 1/- रु. प्रतिशत की दर के कारण मेंहदी पर भी इसी दर से चुंगी वसूल की जाती है।

(4) ऐसी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है।

(5) समय पर मेंहदी पर चुंगी वसूल की जाती रही है।

(6) ऐसा कोई मामला राज्य सर-कार के ध्यान में नहीं आया है।

(7) दिनांक 12-2-79 को बताया गया था। इसका प्रभाव मैसर्स सोजत लाइम कम्पनी के भट्टे पर पड़ता है।

भरतपुर शहर की मुख्य सड़कों का कार्पेट का ठेका

357. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर शहर के बाजार की मुख्य सड़क के कार्पेट का ठेका कब दिया गया ? कार्य पूरा होने की मियाद क्या है ? अब तक कितना काम पूरा हो चुका है ? क्या इस समय कार्य चालू है ?

(2) पूरा कार्य कब तक समाप्त हो जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि मैटीरियल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं लगाया जा रहा है ?

(4) क्या विभाग को यह जानकारी है कि सड़क के किनारे बंगलों से इतने ऊंचे बनाये गये हैं कि दुर्घटनाएं होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) ठेका दिनांक 7-12-78 को दिया गया था। इसकी मियाद 25-3-79 तक की थी। कार्पेट कार्य पूरा हो चुका है।

(2) दिनांक 4-3-79 तक कार्पेट कार्य पूरा हो चुका है।

(3) ऐसी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है।

(4) नगर परिषद द्वारा फुटपाथ को भी ऊंचा बनाये जाने की कार्यवाही चालू है।

राज्य में शिक्षा के विस्तार पर खर्च

358. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्ष 1978-79 में शिक्षा के विस्तार पर कितना कितना खर्चा किया गया ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा हुआ? तालिका जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 78--79 में शिक्षा पर व्यय का किया गया बजट प्रावधान जिलेवार संलग्न सूची में दिखाया गया है।

(2) बजट प्रावधान के अनुसार जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति का ब्यौरा संलग्न सूची में दर्शाया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की सूचना अलग से चिन्ह "अ" पर अंकित है।

वास्तविक व्यय का ब्यौरा दिनांक 31-3-1979 के बाद ही बताया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

नागौर जिले के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद

359. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में किस किस स्कूल में कितने कितने अध्यापकों के स्थान कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) लम्बे समय तक स्थान रिक्त रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। (क)

(2) कारणों का विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

चौकड़ी तोपखाना हुजूरी में भरने वाला वर्षा का पानी

360. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्षा काल में जयपुर शहर में चौकड़ी तोपखाना हुजूरी के पानी से चौकड़ी घाट गेट और चौकड़ी राम चन्द्र जी प्रभावित होती हैं ?

(2) यदि हां, तो नगर परिषद् इसके बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या चौकड़ी तोपखाना हुजूरी का 3/4 भाग कच्चा है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विकास कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्षा के पानी के निकास के लिए बांध बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) इस कार्य हेतु योजना है।

जैतारण और नियाज में महाविद्यालय की मांग

361. **श्री शंकरलाल** (जैतारण): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के जैतारण उप-खण्ड में जैतारण और नियाज में महाविद्यालय खोलने की मांग गत कई वर्षों से होती रही है ? परन्तु राज्य सरकार द्वारा दोनों स्थानों में से एक स्थान, किस स्थान को चुना जाय इसका निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है ?

(3) क्या जैतारण और नियाज के नागरिकों और विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त निर्णय लिया जाकर नियाज और जैतारण के बीच एक उपयुक्त स्थान को चुना जाय और आवश्यक सभी जन सहयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय तो राज्य सरकार महाविद्यालय खोलने का निर्णय लेने को तैयार है ?

Page No. 27

(27)

उत्तर

(1) ऐसी कोई मांग राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) यू. जी. सी. व केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अभी निश्चय तौर पर कुछ सम्भव नहीं है।

नगर विकास न्यास, जयपुर के क्षेत्र में हुए अनधिकृत कब्जे

362. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी-बाजार): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास के क्षेत्र जयपुर में कितने अनधिकृत कब्जे सन् 1978 तक हुए थे ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1978 में सबसे अधिक अनधिकृत कब्जे हुए ? ये कब्जे सरकारी भूमि पर किये गये या किसी अन्य की निजी भूमि पर ?

(3) क्या राज्य सरकार इन कब्जों को वैध मानती है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य-सरकार इन कब्जों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या राजस्थान सरकार अनधिकृत कब्जे करने वालों के लिए कानून में संशोधन करने का विचार रखती है ?

(5) अनधिकृत कब्जों के लिए राज्य सरकार की निगाह में कौन दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास जयपुर के क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 74-75 में 436, वर्ष 75-76 में 882, वर्ष 76-77 में 779, वर्ष 77-78 में 2524, मार्च, 78 तक तथा अप्रैल, 78 से दिसम्बर, 78 तक 5020 अनधिकृत कब्जे हुए।

(2) उपरोक्त आंकड़ों से स्थिति स्पष्ट है। अनाधिकृत कब्जे सरकारी व निजी दोनों प्रकार की भूमि पर हुए।

(3) सभी ऐसे कब्जे अवैध हैं, लेकिन घोषित नीति के अनुसार 21.8.71 से पूर्व के कब्जे नियमित किये जा रहे हैं।

(4) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(5) वर्ष 1978 में 8 फरवरी, 78 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एक निर्णय के अनुसार अवैध कब्जे हटाने के सम्बन्ध में न्यास अधिकारियों के अधिकार समाप्त हो जाने के कारण अवैध कब्जों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा नगर विकास न्यास अधिनियम में संशोधन जून, 78 में अध्यादेश जारी करके पुनः न्यास अधिकारियों को अधिकार प्रदान किये गये। इस संशोधन के पश्चात 1.9.78 से 31.12.78 तक 246 अवैध कब्जे हुए तथा 259 हटवाये गये तथा नये कब्जे रोके जाने की दिशा में इस भांति प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की गई।

खजूरी (जहाजपुर) का खेल का मैदान

363. श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा (मांडल): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खजूरी (जहाजपुर) में छात्रों के खेलने के लिए एक क्रीड़ा स्थल है जिस पर छात्र गत 20 वर्षों से अधिक समय से खेलते आ रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1966 में वहां के तत्कालीन प्रधानाध्यापक ने जिलाधीश, भीलवाड़ा को इस क्रीड़ा स्थल को छात्रों के लिये आवंटित कर सुरक्षित करने के लिए दरख्वास्त दी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1971 में एक जैन पटवारी ने तीन जैन आदमियों को यह जमीन अलाट करवा दी ?

(4) क्या यह सही है कि अलाटमेन्ट के बाद खेती आज दिन तक नहीं की है ? अगर हां, तो क्या सरकार छात्रों के उक्त क्रीड़ा स्थल को सुरक्षित रखेगी ?

उत्तर

(1) ग्रामवासियों द्वारा यह जानकारी मिली है कि ग्राम खजूरी में छात्रों का जो क्रीड़ा स्थल है उस पर गत 20 वर्षों से छात्र खेल रहे हैं। तहसील में इस सम्बन्धी कोई रेकार्ड नहीं है।

(2) 1966 के तत्कालीन प्रधानाध्यापक ने कोई प्रार्थना पत्र जिलाधीश को प्रस्तुत किया हो ऐसा तो कोई प्रार्थना पत्र जिलाधीश कार्यालय में उपलब्ध नहीं बताया गया है।

(3) इस भूमि का निम्न आदमियों को आवंटन हुआ है :—

1–श्री कन्हैयालाल महाजन निवासी खजूरी

2–श्री मूलचन्द महाजन निवासी खजूरी

3–श्री देवकरण निवासी खजूरी

4–श्री माणक चन्द महाजन निवासी खजूरी

इन चारों व्यक्तियों को सन् 1971 में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन किया था।

(4) इनके अलाटमेंट निरस्त करने हेतु राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत मामले जिलाधीश के न्यायालय विचाराधीन हैं। इस भूमि पर आज तक खेती नहीं हुई है।

तहसील कोटड़ा के भूतपूर्व जागीरदार की भूमि

364. श्री लालूदास (फलासिया): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटड़ा में इसी ग्राम के भूतपूर्व जागीरदार राणा मनोहर सिंह पिता मोहब्बत सिंह के नाम पर रेवेन्यू रेकार्ड के अनुसार कितनी भूमि है ?

(श्री लालूदास)

(2) पंचायत कोटड़ा के भूतपूर्व सरपंच और प्रधान ने कितनी भूमि उनकी गलत ढंग से कीमतन लोगों को आवंटित कर दी तथा उसका पैसा किस मद में जमा और खर्च हुआ ?

(3) इस भूमि में किस अधिकार से कांग्रेस भवन के लिए भूमि पंचायत ने दी और क्या पचायत के खर्च से उसका निर्माण कराया ?

उत्तर

(1) तहसील कोटड़ा के ग्राम कोटड़ा में भूतपूर्व राजा मनोहरसिंह पिता मोहब्बतसिंह के नाम पर राजस्व रेकार्ड में कोई भूमि अंकित नहीं है।

(2) भूतपूर्व जागीरदार के नाम कोई भूमि अंकित नहीं होने से गलत ढंग से आवंटन करने का व कीमत प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) कांग्रेस भवन निर्माण हेतु पंचायत द्वारा कोई भूमि नहीं दी गई और न ही पंचायत के खर्चे से निर्माण कराया गया भूतपूर्व जागीरदार के नाम भूमि नहीं होने से उनको भूमि देने का भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

गंगानगर के जिलाधीश तथा उनके परिवारजनों के नाम आवन्टित भूमि

365. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगानगर के जिलाधीश श्री गुमानसिंह तथा उसके भाइयों ने अपने पिता के जीवन काल में जागीरदार बनकर जमीन अलाट करवाई :—

(क) उनको किस अधिकारी ने जागीरदार घोषित किया ?

(ख) किस तारीख को घोषित किया गया ?

(ग) किस आधार पर जमीन अलाट की गई ?

(घ) श्री गुमानसिंह तथा उसके भाइयों की पिछले गांव बगोली तथा अन्य कितने गांवों में कहां-कहां जमीन है ? इन सबका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां।

(क) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत किसी अधिकारी द्वारा जागीरदार घोषित करने का प्रावधान नहीं है। अतः श्री गुमानसिंह व उनके भाइयों को किसी अधिकारी ने जागीरदार घोषित नहीं किया।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर के अनुसार इसका प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) श्री गुमानसिंह एवं उनके भाइयों ने राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत

Page No. 30

(30)

(राजस्व मन्त्री)

स्वयं को जागीरदार बतलाते हुए प्रार्थनापत्र फार्म नम्बर 3 में प्रस्तुत किये थे। तहसीलदार उदयपुर वाटी जिला झुन्झुनूं के समक्ष गवाह पेश किये जिन्होंने बहल्फ बयान किया कि इनको जागीर गांव बागोली मोजगढ़ व रघुनाथ पुरा गांवों में स्थित है। उदयपुर तहसीलदार ने खुद काश्त आयुक्त ने भूमि आवण्टन की सिफारिश की जिस पर खुदकाश्त आयुक्त ने सर्व श्री कल्याणसिंह, लक्ष्मणसिंह व भागीरथ सिंह को आवण्टन आदेश दिनांक 22.3.55 को तथा श्री गुमानसिंह को 3.4.55 को दिये।

श्री गुमानसिंह के इस आवण्टन को राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 40 ए के अन्तर्गत सिव्यू मोटो रिव्यू किया गया है। जिसकी जांच खुद काश्त आयुक्त के समक्ष चल रही है। सबूत आदि के लिए दिनांक 30.3.79 निश्चित है।

(घ) जिलाधीश झुन्झुनूं को प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न प्रकार के उनके पास खुद काश्त में भूमि है। (1) श्री गुमानसिंह की खुदकाश्त भूमि 17 बीघा 9 बिसवा चाही अव्वल डेड बीघा, अलिफ 4 बीघा 3 बिसवा बरानी अव्वल 5 बीघा 8 बिसवा बंजड़ 6 बीघा 8 बिसवा ग्राम बागोली में है।

श्री गुमानसिंह के भाई सर्व श्री कल्याण सिंह के पास 33 बीघा 8 बिसवा और भागीरथ सिंह व लक्ष्मण सिंह के पास 26 बीघा 11 बिसवा ग्राम बागोली में है।

तहसील खारची में ग्राम की भूमि का नामान्तरकरण का मामला

366. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नामान्तरकरण के अधिकार 1966 के पूर्व ही ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण कर दिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली तहसील खारची के ग्राम देवली आउआ के नामांतरकरण सं. 275 व 276 तहसीलदार खारची द्वारा स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार खारची ने उक्त दोनों ही नामांतरकरण अपने अधिकार क्षेत्र में न होते हुए भी स्वीकृत किये जो गैर कानूनी हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ही मामलों में अनुसूचित जाति के खातेदारों की खातेदारी एक स्वर्ण के खाते में यह जानते हुए कि इस तरह के खातेदारों का नामांतरकरण नहीं किया जा सकता, किया गया है ?

(5) सरकार उस व उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी जिन्होंने यह गैर कानूनी कार्य किया व उक्त नामांतरकरण को रद्द कराने की क्या कार्यवाही करेगी ? व कब तक करेगी ?

(श्री माधव सिंह दीवान)

(6) प्रश्न के भाग 2 में बताये गये नामांतरकरण सं. 2021 से 2024 की जमाबन्दी में खाता सं. 49 व 369 से सम्बन्धित है? यदि हां, तो क्या उक्त जमाबन्दी के खाता संख्या 5 में दर्ज इन्द्राज के आधार पर उक्त नामांतरकरण भरे जा सकते थे? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को अपने पद के दुरुपयोग हेतु दण्डित करेगी? जमाबन्दी की प्रतिलिपि कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। नामांतरकरण की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) नामान्तरकरण स्वीकृत करना तहसीलदार अधिकारी क्षेत्र में हैं परन्तु उक्त दोनों नामान्तरकरण तहसीलदार अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं।

(4) जी हां।

(5) उक्त नामान्तरकरणों के रद्द किये जाने की कार्यवाही जारी है। दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) नामान्तरकरण संख्या 275 व 276 का संबंध ग्राम देवली आउआ की जमाबन्दी सम्बन्ध 2021 से 2024 के खाता संख्या 149 व 369 से है। नामान्तरकरण तस्दीक करने के मामले में जांच के आदेश दे दिये गयें हैं। यह भी आदेश दिये गये हैं कि यदि किन्हीं अधिकारियों को गलत कार्यवाही का दोषी पाया जावे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

(नामान्तरकरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सुनेल से पाटन वाया सालोदिया सड़क

367 श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुनेल से पाटन वाया सालोदिया मार्ग पर पक्की सड़क कब तक बनने की संभावना है?

(2) उक्त सड़क पर अब तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है?

उत्तर

(3) पाटन से सुनेल सड़क 29 कि.मी. लम्बी है और जिसमें से 2 कि.मी. डामर व 18 कि.मी. मेटल रोड बनाई गई है का निर्माण प्रस्तावित है। बाकी 9 कि.मी. का निर्माण व बनी हुई सड़क का सुधार व डामर का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(2) उक्त सड़क पर अब तक 8,45,489 00 पैसे का खर्चा किया जा जा चुका है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की सड़कें

368. श्री ईश्वर चन्द, (पिड़ावा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

Page No. 32

(32)

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(1) पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र में 22 जून, 77 से 10 फरवरी, 79 तक विभाग ने किन किन मार्गों पर कितना रुपया व्यय किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1979-80 में पिड़ावा क्षेत्र की किन किन नवीन सड़कों के निर्माण व पुरानी सड़कों की मरम्मत की योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में निम्न सड़कों पर 22 जून, 77 से 10 फरवरी, 79 तक निम्न प्रकार से खर्चा किया गया है :—

सुधार कार्य पाटन रोड सुनेल	28,930/- रु.
नान प्लान	337
मार्ग व पुल	
पाटन आगार रोड	3,75,153-82
सुलिया सुनेल पिड़ावा सीयत रोड	4,16,876-79
पाटन सुनेल रोड	1,436-40
पिड़ावा सुनेल रोड (बाढ़ कार्य)	36,771-00

(2) राज्य में नवीन सड़कें जो 79-80 में स्वीकृत किये जायेंगी अभी विचाराधीन हैं। पुरानी सड़कों में से वर्ष 79-80 में पिड़ावा सुनेल सडक पर 4 पुलियाएं व 2 स्टाप वाल के बनाने की योजना बाढ़ग्रस्त कार्य के अन्तर्गत है।

तहसील तिजारा, किशनगढ़ एवं रामगढ़ की सड़कें

369. श्री अयूब खां (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. तहसील तिजारा, किशनगढ़ और रामगढ़ में कौन कौन से स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य अधूरे हैं? निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

1. तिजारा से घासोली वाया बिलासपुर,

2. भिडूसी से जयरोली, टपूकडा से नूंह (हरियाणा सीमा तक)

3. टपूकड़ा से धिवाना तथा हरियाणा सीमा तक।

4. कोट कासिम से धारुहेड़ा हरियाणा सीमा तक।

5. कोट कासिम से गैलपुर-हसनपुर वाया भौंकर, कतोपुर

(2) उक्त सड़क निर्माण कार्य कब स्वीकृत हुये तथा इनको पूरा कराने का कितना बजट प्रावधान रखा गया तथा कौन-कौन से वर्ष में इन पर कितना धन खर्च किया गया ?

उत्तर

(1) तिजारा किशनगढ़ तहसील में अधूरी सड़कें:-

1. टपूकड़ा से नूंह हरियाणा सीमा तक।

2, मक्कड़ वास से मित्तलवास बोछनी तक।

3. हसनपुर से गैलपर जोड़िया तक।

4. तिजारा से मद्दाना।

5. कोटकासिम से भगाना।

6. टपूकड़ा से भ्रडीबाना।

7. खैरथल से सिवाना।

8. खैरथल से कतीयाबाद।

9. खिदरपर अप्रोच रोड।

10. कोटकासिम से जोडिया।

रामगढ़ तहसील

11. केसरोली से साद्दोली।

12. मादरपुर से रामगढ़।

हां प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जावेगी।

1. इस नाम की कोई सड़क स्वीकृत नहीं है।

2. "क" इस नाम की कोई सड़क स्वीकृत नहीं है।

"ख" इस सड़क को स्वीकृति 1970-71 में 2 लाख तथा संशोधित स्वीकृति 1972 में 3.50 लाख प्राप्त हुई है।

उक्त सड़क का वार्षिक खर्चा निम्न प्रकार है :-

71—72	72—73	73—74	74—75
269928/—	26360/—	60106/—	32193/—

75—76	76—77	कुल योग
48175/—	15940/—	400189/- रु.

3. इस सडक की स्वीकृती सन् 1970 में हुई, वार्षिक खर्चा निम्न प्रकार है :-

71—72	72—73	73—74	74—75
11164/—	—	54810/—	10191/—

कुल योग = 76165/— रु.

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

4. इस नाम की कोई सड़क स्वीकृत नहीं है।

5. इस नाम की कोई सड़क स्वीकृत नहीं है।

(2) नं. 7,8 एवं 11 को मार्च 80 के अन्त तक पूर्ण की जावेगी। शेष सड़क स्वीकृति अनुसार पूर्ण है बाकी छठी पंच-वर्षीय योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर पूर्ण की जावेगी।

नादेसभा से पदराड़ा का सड़क मार्ग

371. श्री भूरालाल (गोगुन्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नादेसभा से पदराड़ा वाया ढोल कम्बोल कासी का गुड़ा, मादड़ी होकर जाने वाला मार्ग 10 मील है जो बिल्कुल कच्चा है इसका पक्का करना परम आवश्यक है? यदि हां, तो यह रोड कब तक पक्की हो जावेगी?

उत्तर

यह सही है कि नादेसभा से पदराड़ा वाया ढोल कम्बोल कासी का गुड़ा मादडी होकर जाने वाला मार्ग की लम्बाई लगभग 10 मील है जो कच्चा है। इसको पक्का करने के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

धोलपुर बस डिपो का स्थान

374. श्री जगदीशसिंह (धोलपुर)-क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धोलपुर में बस का डिपो कब खोला गया तथा इस डिपो को कितनी नई बसें दी गई थीं और कितनी बसें वापस ले ली गई? अगर ले ली गई तो क्यों? क्या आयन्दा नई व अच्छी बसें देने का विचार है?

(2) जो बस स्टेंड इस समय रोडवेज का है वहां की जमीन बसों के खड़े होने की कितनी है और क्या यह स्थान काफी है? अगर नहीं, तो आज तक बस स्टेण्ड के लिए क्या कार्यवाही की गई और क्या आयन्दा कोई जमीन एक्वायर की जा रही है? अगर हां, तो कब तक की जावेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि रोडवेज की बसें केवल जी. टी. रोड पर ही खड़ी की जाती हैं तथा इसके अलावा कोई स्थान नहीं है?

उत्तर

(1) धोलपुर आगार दि. 15.10.78 से प्रारम्भ किया गया था। इस आगार को 9 नई वाहनें आवंटित की गई हैं, जिसमें से कोई भी वाहन वापस नहीं ली गई हैं। आवश्यकता पड़ने पर और नई वाहनें उप-लब्ध कराई जायेगी।

(2) धोलपुर स्थित परिवहन निगम का बस स्टेंड का क्षेत्रफल 735 वर्ग गज है। वर्तमान में पार्किंग स्थान पर 2-3 बसें एक साथ खड़ी हो सकती हैं, जो अपर्याप्त

(यातायात मन्त्री)

है। फिलहाल अतिरिक्त भूमि अवाप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(2) जी नहीं। केवल ग्वालियर जाने वाली मेल सेवायें, जिसमें हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सेवायें भी हैं, प्राय: जी. टी. रोड पर रुक कर यात्री लेकर सीधी चली जाती हैं।

बसों में सीटों का निर्माण व संख्या निर्धारित करने का आधार

375. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदार शहर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बसों में सीटों का निर्माण और संख्या निर्धारण आराम दायक यात्रा के प्रतिकूल पाया जाता है ?

(2) सीटों की संख्या की निर्धारण प्रणाली क्या है तथा उसके लिये कौन कौन से बिन्दुओं का ध्यान रखा जाता है ? आराम दायक बनाने के लिये•:—1. दो सीटों के बीच की दूरी 2 फर्श से सीट की ऊंचाई 3. सीट प्लेन या कोण 4. बैंक प्लेन या कोण 5. अकेली सीट की चौड़ाई 6. दो सीट की चौड़ाई 7. एक सीट की लम्बाई 8. दो सीटों की लम्बाई 9. तीन सीटों की लम्बाई और बीच के रास्ते की चौड़ाई आदि क्या हो ? यदि नार्मस स्पेसिफीकेशन डिजाइंस और प्रचलित निर्देश हों तो विवरण सहित उनकी प्रतिलिपि कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) बसों की बोडी का निर्माण कितने किलोमीटर यात्रा करने योग्य माप तोल को ध्यान में रख कर किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सीटों की संख्या की निर्धारण प्रणाली निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित हैं :—

1. सीट का झुकाव

2. लेग डिस्टेंस (पैर रखने हेतु दूरी)

3. एक सीट से दूसरी सीट की दूरी (एक तरफ की)

4. सीट पुश्त एवं बैंक रेस्ट की माप

यात्री बस में सीटों आदि की दूरी मोटर व्हीकल रूल्स के अनुसार निम्न प्रकार रखी जाती है :—

1. दो सीट के बीच की दूरी 27"

2 फर्श से सीट की ऊंचाई $16\frac{1}{2}$" (साढ़े सोलह इंच)

3. सीट प्लेंक का कोण (सीट कुशन तथा बैंक रेस्ट के बीच) 100 डिग्री

4. अकेली सीट की चौड़ाई 16"

5. दो सीटों की चौड़ाई 15"

6. एक सीट की लम्बाई 16"

7. दो सीटों की लम्बाई 30"

8. तीन सीटों की लम्बाई 45"

(यातायात मन्त्री)

सीटों के बीच के रास्ते की चौड़ाई इस समय करीब 18" रखी जा रही है।

टाटा वाहन में 52 सीट हैं तथा लेलेण्ड वाइडिंग चेसिस में 57 सीट होती हैं, इसमें चालक परिचालक की सीट सम्मिलित नहीं है।

(3) बस बोडी की औसत उम्र चार साल आंकी जाती है तथा इस अवधि में वाहन द्वारा कम से कम 3,60,000 किलोमीटर दूरी तय की जानी चाहिये।

उदयपुर क्षेत्र में चलने वाली बसें

376. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जनवरी, 77 से जनवरी, 78 तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं और उनके स्थान पर कितनी नई बसें लगाई गई?

(2) क्या उदयपुर सिटी बस नाहर मगरा तथा हवाई अड्डा डबोक तक जाती हैं? यदि हां, तो यह स्थान शहर से कितने किलोमीटर दूर हैं।

(3) भीलवाड़ा से मांडल की दूरी कितने किलोमीटर है? क्या प्राइवेट बस चलने की अनुमति दे दी गई है जबकि उक्त मार्ग 10 कि.मी. से अधिक है?

(4) क्या नाथद्वारा से कांकरोली नगर पालिका की सिमा में सीटी बस चलाने का राज्य सरकार का इरादा है? क्या कांकरोली से 200 विद्यार्थी नित्य नाथद्वारा कालेज में पढ़ने जाते हैं? यदि हां, तो इनकी मारपीट के भय से कांकरोली स्टेन्ड पर दोपहर की बसें पिछले तीन माह से कितनी बार देरी से गई?

(5) क्या राज्य सरकार इस मार्ग पर प्राइवेट बसें चलाकर यात्रियों तथा छात्रों की समस्या हल करने का विचार रखती है?

(6) क्या नाथद्वारा बस स्टेन्ड बनाने का कोई विचार राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(7) क्या आमेट से राजनगर वाया केलवा प्राइवेट बस चलने देने में राज्य सरकार को कोई कठिनाई है? अगर केलवा से राजनगर 12 कि मी. है तो 10 किलोमीटर तक प्राइवेट बस चलने में राज्य सरकार को क्या कोई आपत्ति है? अगर हां, तो भीलवाड़ा से माण्डल तथा उदयपुर से नाहरमगरा प्राइवेट बसें किन नियमों के आधार पर चलती हैं?

उत्तर

(1) जनवरी, 77 से जनवरी, 78तक की अवधि में निगम की 473 वाहनें क्षतिग्रस्त हुई। प्रायः क्षतिग्रस्त वाहनों को निगम कार्यशाला में ठीक कर मार्ग पर भेज दिया जाता है।

(2) जी हां। उदयपुर से नाहर मगरा 25 कि. मी. डबोक 19 कि. मी. व हवाई अड्डा 21 कि. मी. है।

(यातायात मन्त्री)

(3) निगम के भीलवाड़ा बस स्टेण्ड से मांडल की दूरी 11 कि. मी. है। आर. टी. ए. उदयपुर ने निजी वाहन स्वामियों को भीलवाड़ा-मांडलगढ़ तक के राष्ट्रीयकृत मार्ग पर इस शर्त के साथ अनुमति दे दी है कि वे इस मार्ग पर यात्री नहीं उठायेंगे।

(4) जी नहीं। छात्रों द्वारा झगड़े फसाद करने से पिछले तीन माह में करीब 120 वाहनें कांकरोली से 15 से 30मिनट तक देरी से रवाना हुईं।

(5) जी नहीं। इस मार्ग पर निगम की बसें पर्याप्त मात्रा में चल रही हैं।

(6) जी नहीं। वर्तमान में निगम द्वारा नाथद्वारा में बस स्टेण्ड बनाने का विचार नहीं हैं।

(7) आमेट से राजनगर वाया केलवा मार्ग का केलवा से राजनगर तथा कांकरोली तक का भाग राष्ट्रीयकृत है जिसकी दूरी 18 कि. मी. है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर केवल 10 कि. मी. तक ही ओवरलेपिंग की अनुमति दी गई है। निगम द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण इस मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को वाहन संचालन की अनुमति नहीं दी गई।

सोजत व खारची तहसीलों को जल योजना

377. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत एवं खारची तहसील में कुछ गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सीमाट-भैसाणा रीजनल स्कीम तथा घुघंल पी. एण्ड टी. स्कीम बनाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला आयोजन समिति ने प्रायोरिटी फिक्स कर कुछ योजनाओं को रिकमण्ड किया था ? यदि हां, तो प्रायोरिटी वाइज उसकी सूची सदन की मेज पर रखें तथा चालू वर्ष में इन योजनाओं पर क्या प्रगति हुई उसका विवरण दें।

(3) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वन में प्रायोरिटी को नजर अन्दाज किया गया ? यदि हां, तो किसके आदेश से तथा क्यों तथा आगे राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय सीमाट-भैसाणा योजना बनाई गई है। घुघंल को पंप एवं टैंक योजना जिला आयोजना समिति के द्वारा प्रस्तावित नहीं होने के कारण नहीं बनाई गई।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं, निर्धारित मापदन्डों के आधार पर ही योजनाओं का चयन किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

Page No. 38

(38)

ग्राम बीलावर तहसील सोजत की जल प्रदाय योजना

378. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले को सोजत तहसील में ग्राम बीलावर जल प्रदाय योजना में कई सूखे ग्रामों में पेयजल पहुंचाया जाता है? यदि हां, तो ग्रामों की सूची मय उनकी आबादी के विवरण के सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत योजना के अंतिम छोर पर स्थित गांवों को पानी उनकी आवश्यकतानुसार कतई नहीं मिलता है जिसकी शिकायत पंचायत ने की और कई बार विभाग को की गई? यदि हां, तो उन गांवों को पानी उनकी आवश्यकतानुसार मिल सके इस हेतु क्या प्रयास किया गया?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि अंतिम छोर पर के गांवों को निर्धारित क्षमता का पानी हर हालत में उपलब्ध हो व इसका प्रमाण-पत्र हर हफ्ते पंचायत से विभाग प्राप्त करे ताकि मौके के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभा सकें?

(4) क्या यह सही है कि अन्तिम छोर के गांव 40 कि मी. दूर हैं तथा प्रेशर इतना कम है कि ग्राम लागोरा, भाणिया वगैहरा को तो तीन-तीन महीनों में कभी-कभी 1-2 दिन पानी उपलब्ध होता है? क्या यह इस बात को सिद्ध नहीं करता कि कि इस स्कीम की डिजाइन डिफेक्टिव है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ग्राम चाड़वास के पास एक बूस्टर-यूनिट कायम कर सकती है ताकि इन गांवों के साथ साथ उसी अंतिम छोर के पास आये 5 और गांवों को भी पानी उपलब्ध कराया जा सके?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, कई बार ग्रामवासियों द्वारा लाइनों की तोड़फोड़ करने एवं बिजली की कमी होने पर ग्राम धानिया एवं राजोला में पानी नियमित रूप से नहीं पहुंच पाता है। प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता प्राप्त कर इन ग्रामों में पानी की समस्या दूर करने के लिए विभाग प्रयत्नशील है।

(3) अंतिम छोर के ग्रामों को निर्धारित मात्रा में पानी मिले इसके लिए विभाग प्रयत्नशील है।

(4) जी हां, अंतिम छोर का ग्राम लगभग 40 कि. मी. दूर है लेकिन यह सही नहीं है कि तीन तीन महीनों में 1-2 दिन ही पानी उपलब्ध होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र का भू-जल सर्वे

379. श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : क्या भू जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र के भू जल का सर्वे कब कराया गया था एवं भू जल विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पिड़ावा पंचायत समिति का अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण 1970-71 में भू-जल विभाग द्वारा किया गया था। इस विभाग ने पंचायत समिति पिड़ावा, झालरापाटन तथा खानपुर जिला झालावाड़ एवं पंचायत समिति अटरू जिला कोटा के सम्मिलित सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किए थे। जिसके अन्तर्गत भू-जल विकास के लिए अतिरिक्त भू-जल भण्डार पाया जाना बताया गया था तदनुसार राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति पिड़ावा के लिए भू-जल विकास की लघु सिंचाई योजना कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम से स्वीकृत करा कर क्रियान्वित की जा चुकी है। जिसके अंतर्गत 282 कुओं का निर्माण, 249 कुओं को गहरा करना, 428 कुओं पर पम्प सेट्स एवं 9017 मीटर सिंचाई की पक्की नालियां बनायी गई थीं, इन मुद्दों पर 44.33 लाख रू. के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। पंचायत समिति पिड़ावा एवं झालरापाटन की एक सम्मिलित फल विकास एवं लघु सिंचाई योजना वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत 215 कुओं का निर्माण, 100 कुओं को गहरा करना, 265 कुओं पर पम्प सेट्स लगाना, 10,000 मीटर पक्की नालियों का निर्माण एवं 400 एकड़ भूमि में सन्तरा वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 44.70 लाख रु. ऋण वितरित होने का प्रावधान है।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में बस व्यवस्था

380. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में अभी तक कई पंचायत केन्द्रों तक यात्री बसों की व्यवस्था नहीं की गई है ? अगर हां, तो अब ऐसे कितने पंचायत केन्द्र बाकी हैं जहां यातायात की बसें नहीं जाती ?

(2) सब पंचायत केन्द्रों तक यात्री बस सेवा उपलब्ध करवाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ? क्या ऐसी नीति सरकार बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में सब पचायत केन्द्रों तक यात्री बसें कब तक चालू करवा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सांचोर पंचायत समिति के 17 पंचायत केन्द्र बस सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं।

Page No. 40

(40)

(यातायात मन्त्री)

(2) राज्य के सभी जिलों के लिए जिलेवार परिवहन योजना तैयार करवाई जा रही है। योजना तैयार होने पर राज्य के अधिकाधिक गांवों को बस सेवा से जोड़ने का प्रयत्न किया जायेगा।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दे दिया गया है।

जोधपुर से जालोर एवं सांचोर तक रात्रि बस सेवा

381. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर से जालोर, सांचोर तक रात्री बस सेवा चलाई गई थी? अगर हां, तो कब तक चलाई गई एवं फिर बाद में बन्द क्यों की गई?

(2) क्या यह भी सही है उक्त रात्रि बस सेवा आकोली एवं भरुड़ी नदियां आने से बस रूट बन्द होने का कारण देकर बन्द की गई? अगर हां, तो जब नदियों में पानी कम होने पर बस रूट खुलने तक उक्त बस सेवा पुनः चालू क्यों नहीं की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रात्री बस सेवा पुनः चालू करने के लिए कई प्रार्थना-पत्र राज्य पथ परिवहन निगम के आफिसरों को एवं सरकार को दिए गए थे? अगर हां, उन पर क्या कार्यवाही की गई? अब उक्त रात्री बस सेवा पुनः कब तक चालू करवा दी जावेगी? निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही हैं कि उक्त रात्री बस सेवा पुनः तुरन्त चालू करने के आदेश सरकार एवं महाप्रबन्धक राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा काफी अर्से पहिले दे दिए गए थे? अगर हां, तो उन आदेशों की अवहेलना क्यों की गई, एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी? अब तक उनके विरुद्ध कार्रवाही नहीं करने के क्या कारण हैं?

(5) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा सांचोर रोडवेज की एक अन्तिम बस रानीवाड़ा से 8 बजे रात्री को रवाना होकर सांचोर एवं सुबह 7 बजे सांचोर से रवाना होकर रानीवाड़ा प्रथम बस चलाई जा रही है जो बिलकुल खाली आती जाती है? अगर हां, तो खाली बस चलाने का क्या मकसद है? अगर उक्त बसों को सुबह सांचोर से 3.45 बजे रवाना होकर रानीवाड़ा से 5.30 बजे सुबह रवाना होकर सांचोर चलाई जाय तो रोडवेज की अच्छी इनकम हो सकती है? अगर हां, तो वह बस यात्रियों की सुविधा हेतु कब तक शुरू करवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 13-6-78 से जोधपुर-सांचोर वाया जालोर रात्रि वाहन सेवा प्रारम्भ की गई थी जिसे दिनांक 21-7-78 से आय में कमी की वजह से बन्द कर दी गई।

(यातायात मन्त्री)

(2) जी हां, परन्तु मुख्य कारण आय में कमी था।

(3) जी हां। ऐसे प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उक्त सेवा दिनांक 14.2.79 से पुनः प्रारम्भ कर दी गई है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में माह जनवरी, 79 में निर्देश प्राप्त हुये थे जिनकी अनुपालना में निगम द्वारा दिनांक 5.2.79 को संभाग प्रबन्धक, जोधपुर को उक्त वाहन सेवा को पुनः प्रारम्भ करने हेतु निर्देश जारी किये गये। जिनकी पालना में उक्त वाहन सेवा दिनांक 14-2-79 से पुनः प्रारम्भ कर दी गई है। अतः आदेशों की पालना में देरी अथवा अवहेलना का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(5) जी हां। उक्त सेवा रानीवाड़ा से रात्रि के 8 बजे रेल के यात्री लेकर सांचोर जाती है तथा सवेरे 7 बजे सांचोर से यात्री लेकर रानीवाड़ा में रेल कनेक्शन मिलाती है। उक्त वाहन सेवा अनार्थिक नहीं है। उक्त सेवा को सांचोर से सुबह 3-45 व रानीवाड़ा से सुबह 5-30 बजे चलाने बाबत सुझाव पर विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है।

भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी का प्रबन्ध

382. श्री सुरेशकुमार शर्मा (भरतपुर) —क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में जल पूर्ति के लिये चार इंच की पाइप लाइन डालने में प्रति किलोमीटर औसतन कितनी लागत आती है ?

(2) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के कौन-कौन से गांवों में वर्ष 1979-80 तक पीने के पानी का प्रबन्ध कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) सामान्य परिस्थितियों में लगभग 40,000/- रू. प्रति कि.मी. औसतन लागत आती है।

(2) वर्ष 79-80 तक ग्राम रारह, सहमावती, मोरलीकलां, धौरमियों मनुमान का नगला, अजान सेघरा, हथवारी व जमोना में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में टाटा ट्रक चैसिस के विक्रेता

383. श्री रामदेव सिंह (धोंद): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान में टाटा ट्रक चैसिस के कौन-कौन अधिकृत विक्रेता हैं तथा इनके यहां सितम्बर 1977 से स. इ., एल. पी. व एल. पी. टी. मोडल की कितनी चैसिस किस किस तारीख को बुक हुई थीं और इनमें से कितने को डिलीवरी दी जा चुकी है ? मय तारीख के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में ट्रक चेसिस, मोटर पार्ट्स व ट्रेक्टर पार्ट्स का भारी ब्लेक हो रहा है ? यदि हाँ तो

Page No. 42

42

(यातायात मन्त्री)

क्या राज्य सरकार इनके पार्ट्स को ब्लेक रोकने के लिये इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में शामिल करेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकार की सूचना संग्रहित नहीं की जाती। अतः प्रश्न द्वारा वांछित सूचना देना संभव नहीं है।

(2) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

राज्य में कार्यरत वैद्यों एवं उप वैद्यों के लिये स्थानान्तरण नीति

384. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के कितने-कितने वैद्यों एवं उप वैद्यों के स्थानान्तरण 1 नवम्बर, 1978 से 15 फरवरी, 1979 तक की अवधि में किये गये ? इन स्थानान्तरणों में से कितने स्थानान्तरण बाद में निरस्त कर दिये गये और क्यों ?

(2) बे मौसम (आफ सीजन) के इन स्थानांतरणों और निरस्तीकरणों का क्या औचित्य था ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रान्त के कई अन्य विभागों की भांति आयुर्वेद विभाग में कार्यरत वैद्यों और उपवैद्यों के स्थानांतरण की कोई निश्चित नीति निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) किन कारणों से आयुर्वेद विभाग के निदेशक का पद पिछले डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त पड़ा है ? विभाग के कार्यों के सुसंचालन तथा कर्मचारियों के असन्तोष को दूर करने के लिए सरकार आयुर्वेद निदेशक की नियुक्ति कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) 1 नवम्बर 1979 से 15 फरफरवरी 1979 के मध्य 450 वैद्यों एवं 284 कम्पाउण्डर धात्रियों के स्थानांतरण किए गए। इनमें से 37 वैद्यों व 26 कम्पाउण्डर धात्रियों के स्थानांतरण निरस्त किए गए। स्थानांतरण निरस्त करने के मुख्य कारण माननीय विधायकों की सिफारिश, प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखना व कर्मचारी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण है।

(2) प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने माननीय विधायकों की सिफारिश, मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए तथा कर्मचारी की स्वयं की इच्छा के कारण ही इस अवधि में स्थानांतरण व निरस्तीकरण किए गए।

(3) अन्य विभागों की भांति आयुर्वेद विभाग में भी वैद्यों और कम्पाउण्डर धात्रियों के स्थानांतरण करने के लिए नीति निर्धारित की हुई है।

(आयुर्वेद मन्त्री)

(4) निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति के अभाव के कारण आयुर्वेद विभाग के निदेशक का पद रिक्त पड़ा है। निदेशक के पद पर अतिरिक्त निदेशक कार्य कर रहे हैं। निदेशक के पद को भरने के लिए राज्य सरकार जागरुक है। इस पद को शीघ्र ही भरे जाने की सम्भावना है।

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में नये आयुर्वेदिक औषधालय

385. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) —क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष ज्यादा तादाद में आयुर्वेद अस्पताल खोले हैं तथा और ज्यादा खोलने का विचार भी कर रही है ?

(2) जालोर जिले में इस समय कुल कितने आयुर्वेद अस्पताल हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कितने आयुर्वेद अस्पताल इस समय हैं ?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष राज्य सरकार ने कितने आयुर्वेद अस्पताल खोले हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम करवाड़ा के आस-पास नजदीक में कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस वर्ष ग्राम करवाड़ा धानोल, साखावास, पुनासा धोबाऊ, काडेका, में भी आयुर्वेद अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1978-79 में केवल 6 नवीन औषधालय खोले गये हैं तथा वर्ष 1979-80 में 66 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है।

(2) जालोर जिले में एक चिकित्सालय तथा 38 औषधालय हैं। सूची संलग्न प्रस्तुत है।

(3) रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 6 औषधालय हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 1978-79 में एक भी औषधालय नहीं खोला गया है।

(5) जी हां, लगभग 10-11 किलोमीटर की परिधि में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं हैं।

नवीन औषधालय खोलते समय ग्रामवासियों एवं विधायकों से निर्धारित मापदण्ड के अधीन नियमित प्रस्ताव आने पर विचार किया जा सकता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर

386. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 44

(५५)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

(1) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल में 24 घंटे मेडिकल ज्यूरिस्ट के ड्यूटी पर रहने के आदेश हैं ? यदि हां तो इस कार्य के लिए कितने मेडिकल ज्यूरिस्ट नियुक्त किये हुए हैं ?

(2) सवाई मानसिंह अस्पताल तथा जनाना होस्पिटल में कितनी मशीनें और उपकरण कब कब से बेकार पड़े हैं ?

(3) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को गर्म भोजन सप्लाई करने के लिए कोई ट्रोली, कटोरी, स्टील की थालियां आदि खरीदी गई थीं ? यदि हां, तो क्या भोजन देते समय इनका उपयोग किया जाता है ?

(4) क्या इस अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि हर वार्ड में एक इमरजेन्सी ट्रोली रखी जायेगी जिससे मरीज का तत्काल आवश्यक इलाज किया जा सके ? यदि हां, तो क्या यह सुविधा इस समय उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस अस्पताल में मरीजों को ठंडे पानी की व्यवस्था हेतु कोई मशीन लगी हुई है ? यदि हां, तो क्या इस समय वह चालू हालत में है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(6) क्या अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले अटेन्डेन्ट के ठहरने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार क्या कर रही है ?

(7) क्या इस अस्पताल के आई थियेटर में पंखों की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(8) क्या इस अस्पताल के मुर्दाखाने में मुर्दे को कुछ समय तक उसी स्थिति में रखने हेतु कोई मशीन रखी हुई है ? यदि हां, तो क्या यह मशीन चालू हालत में है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार अब इस मशीन को कब तक चालू करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां, बुलाने पर इस कार्यालय के लिए एक रीडर, एक लेक्चरार व छः सी. ए. एस. ट्यूटर्स के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक रीडर व एक सी. ए. एस. ट्यूटर्स का पद भरा हुआ शेष कार्य अन्य जगह से डाक्टर प्रतिनियुक्त कर चलाया जा रहा है।

(2) बेकार मशीन व उपकरणों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां, ट्रोली का मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहा है। इस लिए उपयोग में नही लाई जा सकी है। जहां तक थालियों का प्रश्न है वह कुछ मात्रा में खरीदी गई थीं जो वार्डों में सप्लाई की जा चुकी हैं।

(4) इस चिकित्सालय के हर वार्डों में इमरजेन्सी ट्रोली रखी जाती है जिसको आपातकाल में उपयोग में लाया जाता है।

(5) जी हां। मशीन लगी हुई थी जो खराब होने के कारण बन्द कर दी गई है और उसकी मरम्मत के प्रयास चालू हैं।

(चिकित्सा मन्त्री)

(6) जी नहीं।

(7) चिकित्सालय के आई थियेटर में वातानुकूलित यन्त्र स्थापित था। उसके खराब होने पर वहां पेडेस्टल फैन लगाये गये हैं। वातानुकूलित यन्त्र की मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है।

(8) मुर्दे को उसी स्थिति में रखने की मशीन वर्तमान में खराब हालत में है। इसको चालू करने हेतु मेडिकल कालेज स्तर से प्रयास चालू हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

अजमेर नगर परिषद सीमा में खोली गई डिस्पेन्सरीज

387. श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अजमेर नगर परिषद सीमा में सन् 1978-79 में कितनी नई डिस्पेन्सरियां स्वीकृत हुई ? इनमें से वर्तमान में कितनी चालू हैं ? क्या स्वीकृत सभी डिस्पेन्सरियां चालू हैं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

(2) क्या उपरोक्त सभी डिस्पेन्सरियों का स्टाफ वर्तमान में इन डिस्पेन्सरियों में कार्य कर रहा है ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद सीमा में सन् 1978-79 में तीन नई डिस्पेन्सरी स्वीकृत हुई। वर्तमान में सभी/डिस्पेन्सरियां चालू हैं।

(2) जी हां।

ग्राम गांग की ऐड पोस्ट पर स्टाफ की व्यवस्था

388. श्री रतना राम चौधरी (रानीवाडा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गांग में ऐड पोस्ट है परन्तु अभी तक पूरा स्टाफ नहीं है जिससे मरीजों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम करड़ा में सब सेन्टर है परन्तु काफी समय से वहां ए. एम. डब्ल्यू. नहीं है ? अगर हां, तो कब तक लगा दिया जावेगा ?

(3) ग्राम दईपुर, मेड़ा में सब सेन्टर खोले जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है, परन्तु अभी तक कोई स्टाफ वहां पर नहीं है ? यदि हां, तो कब तक वहां पर स्टाफ भेज दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी। हां ऐड पोस्ट पुराने उप-केन्द्र के साथ साथ चल रही है और पेट्रन के अनुसार ए. एच. डब्ल्यू. व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। केवल प्रशिक्षित प्रसाविका उपलब्ध न होने के कारण एक पद प्रसाविका का रिक्त है। प्रशिक्षित प्रसाविका

(चिकित्सा मन्त्री)

उपलब्ध होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी जायेगी। कार्यरत स्टाफ द्वारा मरीजों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा सुलभ कराई जा रही है।

(2) प्रशिक्षित ए. एच. डब्ल्यू. के उपलब्ध न होने के कारण यह पद रिक्त था जिसे अब दिनांक 26-2-79 से पद स्थापन किया जा चुका है जो कार्यरत है।

(3) जी हां।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर ने जिलाधीश जालोर से इन ग्रामों पर उपकेन्द्र खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है। परन्तु प्रशिक्षित प्रसाविका के अभाव में इन उपकेन्द्रों को चालू नहीं किया गया है। जैसे ही प्रशिक्षित प्रसाविका उपलब्ध होगी इन उपकेन्द्रों में स्टाफ (प्रसाविका) लगा दिया जावेगा।

तहसील मावली क्षेत्र में हुए कत्ल

389. श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

मावली तहसील में डेढ़ वर्ष में कितने मर्डर हुए हैं और इन मामलों की क्या प्रगति है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

थाना मावली में जुलाई 1977 से दिसम्बर, 1978 तक चार केस कतल के दर्ज हुए जिनको सूची मय प्रगति संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जयपुर शहर की पुलिस व्यवस्था

390. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार): क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या जयपुर नगर में पुलिस थानों की संख्या कम है तथा इनको बढ़ाये जाने हेतु राज्य सरकार की कोई योजना है? वर्तमान में किन-किन थानों पर जीप और वायरलैस व अन्य आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं।

(2) जयपुर नगर में गत तीन वर्षों में विभिन्न प्रकार के कितने अपराध दर्ज हुए? गुण्डा एक्ट के तहत कितने केस दर्ज हुए? थाने अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(3) क्या जयपुर नगर में पुलिस कमीशन अपनी रिपोर्ट देने आया था? यदि हां, तो उसने पुलिस के बारे में क्या रिपोर्ट दी थी? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या पुलिस कमीशन की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने हेतु किसी कमेटी का गठन किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या थानों पर कार्यरत सभी पुलिस जवानों को ऊंट भत्ते की तरह साई-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

किल भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सम्पूर्ण जयपुर जिले के लिए दुर्घटनाओं के चित्र लेने के लिए एक ही फोटोग्राफर है ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था उपयुक्त है ?

(7) क्या पुलिस विभाग को लाश का पोस्टमार्टम कराने में कोई दिक्कत आती है ? यदि हां, तो क्या ?

(8) क्या राज्य सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी कार्यवाही शीघ्र करने के लिए एम्बुलेन्स गाड़ी, फ्लाइंग स्क्वायड के साथ ही दुर्घटना स्थल पर जाय और गाड़ी में ही फर्स्ट ऐड बोक्स तथा फोटोग्राफर आवश्यक साधन साथ में ले जाय ?

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर शहर में थानों की संख्या बढ़ाये जाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा रहा है । इस समय जयपुर नगर के 5 थानों पर जीप व वायरलेस तथा सभी थानों पर टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(5) जी नहीं । आवश्यकतानुसार साईकिल या ऊंट भत्ते स्वीकृत किये जाते हैं ।

(6) जी नहीं । इस समय फोटोग्राफी के कार्य में प्रशिक्षित 4 आदमी नियुक्त हैं जो पर्याप्त हैं ।

(7) सम्बन्धित मेडीकल अधिकारी की अनुपस्थिति में तत्काल शव परीक्षण में कठिनाई आती है जिसका निराकरण करने का प्रयत्न संबंधित जिला अधिकारी से संपर्क कर लिया जाता है ।

(8) फ्लाईंग स्क्वायड के साथ ही फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था है फोटोग्राफी की भी आवश्यक व्यवस्था कर दी जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

तहसील कोटपूतली में हुई चोरियां

391. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटपूतली में जून 1977 से आज तक कुल कितनी चोरी हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उनमें से कितनी बरामद हुई ?

(3) किस किस समय पर कौन कौन थाना प्रभारी और डी.एस.पी. रहे ?

उत्तर

(1) माह जून 1977 से माह फरवरी 1979 तक तहसील कोटपूतली क्षेत्र के दोनों थानों में 163 चोरी के अपराध पंजीबद्ध

(गृह मन्त्री)

हुए हैं। वर्षवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

जून, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक — 30 अपराध

वर्ष 1978 में — 117 अपराध

जनवरी व फरवरी 1979 में — 16 अपराध

(2) इनमें से कुल 35 चोरियां बरामद हुई हैं।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

पाकिस्तानी शरणार्थियों को आवंटित भूमि

392. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977 में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई है ? अगर हां, तो उनको बसाने हेतु राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? कितने कितने परिवार किन-किन जिलों में बसाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। शरणार्थियों को दी जाने वाली सुविधा का पूर्ण ब्यौरा भी दें ?

(2) क्या यह सही है कि इन शरणार्थियों को जहां जमीन अलाट की उन गांव वालों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपीलें की हैं ? अगर हां, तो इस विषय में राज्य सरकार का आखिरी क्या निर्णय है, अवगत करावें।

उत्तर

(1) शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की कार्यवाही चल रही है। इनको मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर व जालौर जिलों में बसाया जावेगा, क्योंकि इन्हें बसाने के लिए खेती की जमीन की उपलब्धि का सर्वेक्षण किया जा रहा है, इसलिए वांछित जिलेवार सूची देना अभी सम्भव नहीं। इनको बसाने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। कुछ ग्राम ऐसे हैं, जहां के सरपंच अथवा गांव वालों ने उनके गांव में कृषि भूमि विस्थापितों को आवंटन करने के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट पेश कर रखी है। विवादग्रस्त भूमि का मामला सबज्यूडिस है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ता देने की योजना

394. श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं ?

(2) राज्य में जनता सरकार आने के बाद इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

(3) राज्य सरकार की बेरोजगारों को रोजगार या रोजगार भत्ता देने की क्या योजना है ?

(श्रम मन्त्री)

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालय की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-12-78 को 3.22.285 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत थे।

(2) राज्य में जनता सरकार बनने के पश्चात राज्य के नियोजन कार्यालय में 64.695 आशार्थियों का अधिक पंजीयन नियोजन कार्यालय में रोजगार प्राप्त करने के लिए हुआ।

(3) राज्य सरकार का प्रयत्न अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में विकासशील कार्यों को परिचालित करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। राज्य सरकार आर्थिक नीतियों को भी इस प्रकार से बना रही है कि वित्तीय विनियोजन क्रम इस प्रकार हो ताकि रोजगार के अवसर अधिक से अधिक बढ़ें। बेरोजगारों को अभी बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है।

सोजत तहसील के ग्रामों की वन विकास की योजना

396. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत तहसील में ग्राम रुंदीया व जटवाड़ा व खारीयानी में वन विकास योजना के अन्तर्गत वन विभाग को भूमि हस्तान्तरण की है? यदि हां, तो प्रत्येक गांव से कितनी-कितनी भूमि व कौन-कौन से खसरे राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को कब हस्तांतर किये गये? यदि नहीं, तो कब तक कर दिए जायेंगे?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम अटवाड़ा सूंदिया में और भी कई हजार बीघा भूमि बंजर दबी पड़ी है जो इस योजना के अन्तर्गत ली जा सकती? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस भूमि को वन विभाग अपने कब्जे में लेगा?

(3) उपरोक्त योजना को देखते हुए क्या राज्य सरकार विभाग रेंजर का आफिस सोजत में खोलने तथा एक नर्सिंग नर्सरी बनाने का प्रस्ताव रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूमि हस्तान्तरण हेतु जिलाधीश पाली को निवेदन किया गया है। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से सहमति प्राप्त होने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी हां। ग्राम अटवाड़ा व संदिया की पंचायतों से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ऐसे क्षेत्रों को वन विकास के लिये लिया जा सके।

(3) सोजत के आस पास जब भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण हो जावेगी तो रेन्ज आफिस तथा नर्सरी बनाने पर विचार किया जावेगा।

राज्य की काश्त काबिल वन विभाग से राजस्व विभाग को दी गई भूमि

398. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री एच. एन. शर्मा)

(1) क्या राज्य सरकार ने इस वर्ष कोई काश्त काबिल जमीन वन विभाग से निकाल कर राजस्व (रेवेन्यू) विभाग को दी है ? अगर हां, तो किस-किस जिले में कितनी जमीन किस-किस गांव में दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या तहसील बेगूं में भी इस वर्ष वन विभाग के द्वारा रेवेन्यू विभाग को जमीन दी गई है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितना रकबा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

व्यवस्था का प्रश्न
अशोभनीय शब्दों का प्रयोग

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न काल में एक माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य को कहा, ये X X खड़े हैं, मैं समझता हूं ये शब्द डेरोगेटरी हैं। सदन की प्रतिष्ठा को कम करता है और कोई माननीय सदस्य दूसरे सदस्य को क्या इस तरह से सदन में खड़ा होकर कह सकता है ? उसको X X शब्द से सम्बोधित करता है तो यह शब्द कार्यवाही से हटाना चाहिए और X X शब्द एक्सपंज होना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आधे घण्टे तक व्यवस्था कायम नहीं हो और सत्ता पक्ष के सदस्य इस प्रकार से व्यवहार करें, सदस्यों को XX कहें, आपाधापी में सदस्यों को XX कहे जायें तो हम ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे ......

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह रिकार्ड में आ गया है। यह बिल्कुल गलत है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है ...

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर पहले तो मेरा था। व्यवस्था का प्रश्न सबसे पहले तो मैंने उठाया था........

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल महामना (वैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले जिस प्रकार से सदन में X X जैसा प्रदर्शन किया गया और X X जैसी उच्छृंखलता की गई माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगल में तो XX होते हैं लेकिन यहां पर सदन में X X का सा आचरण करके बाकी के अन्य सदस्य इस पवित्र सदन की गरिमा बनाए रखने में क्या इस तरह का व्यवहार करना उचित समझते हैं और इसमें आपकी क्या व्यवस्था है ?

X X X शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री श्योपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : There are number of point of orders, पहले एक पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, फिर दूसरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्रापको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यदि इस तरह से दस-दस पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठायेंगे तो मैं मौन धारण करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस तरह का सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य वर्ताव कर रहे हैं....

श्रीमती सुमित्रा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यदि ग्राप मौन धारण कर लेंगे तो काम नहीं चलने वाला है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम ग्रापका समर्थन चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : व्यवस्था के लिए कड़ाई करिये। ग्रापके बगल में सार्जेंट है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कभी-कभी, माननीय सदस्या, साइलेंस है वह गोल्डन है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम ग्रापका प्रोटेक्शन चाहते हैं। ग्राप कहते हैं कि मैं तो चुप हूं तो हमारा प्रोटेक्शन कौन करेगा, हमारे विचारों का प्रोटेक्शन कौन करेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं करूंगा ग्रापका प्रोटेक्शन।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिस प्रकार का व्यवहार सत्तापक्ष के माननीय सदस्य सदन में कर रहे हैं, या तो इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दीजिए ताकि कम से कम इनको मालूम हो कि कब बोलना चाहिए ग्रौर कब नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। यह काम तो विरोधी पक्ष का है लेकिन विरोधी पक्ष जिस शालीनता से पेश ग्रा रहा है, जिस तरह की गरिमा के साथ पेश ग्रा रहा है ग्रौर ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस तरह से सत्तारूढ दल के सदस्य व्यवधान डाल रहे हैं, जान बूझ कर व्यवधान डाल रहे हैं उसमें किस तरह से सदन की कार्यवाही चल सकती है अध्यक्ष महोदय, कृपया बतावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। रहा सवाल यह कि शब्द XX का प्रयोग उचित है या ग्रनुचित है। मैं तो कहता हूं कि ग्रनुचित भी नहीं है तो उचित भी नहीं है। माननीय सदस्यों को, मैं ग्राशा करता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में परहेज करना चाहिए।

X X X शब्द अध्यक्ष महोदय के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किए गए।

Page No. 52

(52)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रणमलसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम कटराथल जिला सीकर में स्वर्गीय हरिजन श्री छोटू क परिवार की खातेदारी की जमीन पर सवर्णों द्वारा कब्जा करने की कोशिश के विषय में।

(2) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान शिक्षक संघ एवं संयुक्त शिक्षक संघ द्वारा अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर किये जाने वाले प्रदर्शन व आन्दोलन के विषय में।

(3) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में परमाणु बिजली घर तथा बदरपुर बिजली घर में बिजली का उत्पादन बन्द हो जाने से 35 लाख यूनिट बिजली की कमी पड़ जाने के विषय में।

(4) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर के शिक्षकों द्वारा पिछली 27 जनवरी से की जा रही हड़ताल के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(5) श्री मदनसिंह दांता, सदस्य विधान सभा की ओर से पुलिस, बार्डर सिक्युरिटी फोर्स व आर.ए.सी. के सेवा निवृत कर्मचारियों को भूतपूर्व सैनिकों के समान सुविधायें देने की मांग के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह दांता : तो आन्दोलन होंगे, पुलिस कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं। वैसे आपकी मर्जी है।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन में पान खाना

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जैन।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दस दिन से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय रतनलालजी वर्मा मुंह में इतना पान खाकर आते हैं कि मेरा धुला धुलाया कुर्त्ता रोज खराब हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो मेरी सीट बदल दी जाय या इनको निर्देश दें कि ये पान कम खाकर आया करें और जोर से बोलना कम करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अगर इनका कुर्त्ता मेरे पान खाने से खराब होता हो तो मैं उसकी पूरी कीमत देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय रतनलालजी

(श्री अध्यक्ष)
वर्मा से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि पान बाहर जाकर खा लिया करें।

श्री रतनलाल वर्मा : खाकर तो मैं बाहर से ही आता हूं लेकिन पीक इन पर थोड़े ही थूकता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। कई माननीय सदस्य पान खाकर सदन में कागज की पुड़ियां में पीक भर कर दराज के अन्दर रख देते हैं जिससे हमारे सब कपड़े खराब हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, पान खाकर हाउस में आना ही रोक देना चाहिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द, कटारिया व्यवस्था का प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था दिलायें कि 26 तारीख को एक इतना आवश्यक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, पिछले 56 दिनों से यह संस्था बन्द है, बच्चों की पढ़ाई बन्द हो रही है और 26 तारीख को....

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की बात है। इस समय तो स्थगन प्रस्ताव चल रहे हैं। इस समय किस तरह से बोल रहे हैं, हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा शुक्रवार या वृहस्पतिवार तक शायद आ जाएगा ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसको तो बाद में ले लीजिए....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : It is no point of order. He can not raise point of order at this stage.

श्री अध्यक्ष : No point of Order, but Hon' ble young member is agitating.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट आप सब्र करिये। सरकार का उत्तर आने दीजिए। मैं किस नियम के अन्तर्गत आपको बोलने की इजाजत दे सकता हूं। मैं मानता हूं कि आपका महत्वपूर्ण विषय है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने की इजाजत के लिए नहीं कह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : फिर आप क्या कर रहे हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इतना आवश्यक प्रश्न होते हुए भी सरकार की ओर से जवाब क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि....

श्री अध्यक्ष : यह तो आपकी सरकार है, आप राज कर रहे हैं। पहले इनको बोलने दीजिए। आप शांति रखिये। अनुशासन मुख्य चीज है।

श्री रणमलसिंह (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। अजमेर नगर की पानी की समस्या विकट रूप धारण कर रही है....

सरकार को जानकारी देने हेतु भेजे गये स्थगन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा था.........

श्री कल्याणसिंह सांखला : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सरकार को यह सूचित कर रहा हूं कि यदि अमुक समय तक सरकार की ओर से इन स्थगन प्रस्तावों या ध्यान आकर्षण प्रस्तावों का उत्तर नहीं आया, याने सरकार से जो उत्तर मांगा गया है और वह उत्तर सरकार नियत समय में देने में असमर्थ रही तो इस पर चर्चा उठाने की मैं माननीय सदस्यों को अनुमति दूंगा।

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, शराब बन्दी के बारे में 31 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, उसका जवाब कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य काफी चर्चा हो चुकी है। अब और क्या नशाबन्दी पर चर्चा होगी। सरकार का क्या निर्णय है यह आप सरकार से पूछिये।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 7-3-79 को दिया था ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझ से मिले हैं। यदि शुक्रवार, बृहस्पतिवार तक उत्तर न आया, इस समय तक आप ठहरें। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसका उत्तर दें और उत्तर नहीं आता है तो आपको मैं इजाजत दूंगा। आपके अधिकार का मैं हनन नहीं करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रणमल सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त बनने से पूर्व यह 22 रियासतें थी और जयपुर स्टेट के अन्दर सीकर एक बड़ा ठिकाना था। संवत 1998 में सैटलमेन्ट हुआ था और 2012 सं. 2011 की गिरदावरी के आधार पर जो पर्चा खतौनी की गई थी, उसके आधार पर श्री छोटूराम पुत्र श्री मंगलाराम हरिजन गांव कटराथल, जिला सीकर की जमीन दर्ज हुई थी।

(श्री रत्नमल सिंह)

संवत 2012 में जागीर रिज्यूम हुई थी। उस गरीब हरिजन को जमीन जो खसरा नम्बर 367/1, 12 बीघा 16 बिस्वा थी, वह जमीन दूसरे के नाम सं. 2014 की अपनी गिरदावरी में आधी दर्ज कर दी और उस हरिजन को मालूम ही नहीं। उस गरीब हरिजन को यह पता नहीं चला। संवत 2022 में यह चौसाला चेन्ज किया गया और खसरा नम्बर 367/1, 12 बीघा 16 बिस्वा जमीन एक दम से उड़ गयी। यह जमीन पेमाराम पुत्र हणुताराम जाट के नाम दर्ज कर दी गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न तो उस हरिजन ने उस जमीन को किसी को बेचा है और न उसने किसी को जमीन पर कब्जा दिया न कभी काश्त करने दिया था। पटवारी की गलती से उस गरीब हरिजन की यह जमीन उड़ गई। उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वह गरीब आदमी है और वह मुकदमा नहीं लड़ सकता है। केवल एक पटवारी की वजह से यह काम हुआ है। उसकी जमीन पर सन् 1972 में उस आदमी ने कब्जा कर लिया है और अब उसके पास आज की तारीख में 3 बीघा 16 बिस्वा जमीन रह गई है। उस पर भी वह जाट कब्जा करना चाहता है। मैंने इस सम्बन्ध में कलेक्टर महोदय से बात की थी। उन्होंने कहा कि यह रिकार्ड में दर्ज हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने एस. डी. एम. को लिख दिया। इस तरह से उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एस. डी. एम. और कलेक्टर के द्वारा। इसलिए मैंने उस की यह दास्तान इस पवित्र सदन के द्वारा आपके माध्यम से राज्य सरकार को पहुंचाने की कोशिश की है। हमारी सरकार गरीब की भलाई के लिए ढिंढोरा पीटती है। तो मेरा निवेदन है कि इस गरीब को राहत दिलाई जावे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सख्ती से कदम उठावे और उस गरीब के पास जो 3 बीघा 16 बिस्वा जमीन रह गई है, वह कम से कम उसके पास काश्त के लिए रह जावे वरना बरसात होते ही उससे वह जमीन छीन ली जाएगी। वह ताकतवर आदमी है और हरिजन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह उससे लड़ सके। उस गांव में हरिजनों के बीस, पच्चीस घर है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जाट का सामना कर सकें। गांव में इतने अधिक जाट हैं कि उनका मुकाबला करने की हरिजन में हिम्मत नहीं है। जिलाधीश से तो मुझे उम्मीद नहीं है। मैं राज्य सरकार से उम्मीद करता हूं और खास कर के हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय बहुत दयालु हैं गरीबों के प्रति, वे गरीबों की सुनते हैं, कम से कम वे इतना तो इन्तजाम कर दें कि उस हरिजन से, 3 बीघा 16 बस्वा जमीन जो रह गई वह छीनी नहीं जा सके और उस पर वह काश्त कर सके। इसकी सिक्यूरिटी वे दिला दें कि यह जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी। पटवारी ने रिकार्ड में चेन्ज कर दिया है। राज्य सरकार का यह नियम है कि हरिजनों की जमीन सवर्णों के नाम नहीं लिखी जा सकती है, बदली जा सकती है। पटवारी ने बिना किसी कायदे कानून के यह कार्यवाही कर दी है। यह गलती दुरुस्त करवाई जाएगी, यह आश्वासन दिया जाए और उस गरीब के पास जो जमीन है, वह बरसात के टाइम के पहले उससे नहीं छीनी जाए, इतनी सुरक्षा करें, यह मैं आशा करता हूं।

(56)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस हरिजन भाई की जमीन का मामला उठाया है उस की तत्काल जांच करवाकर कर जो राहत उसको दिलवाई जा सकती है, उसको सरकार की तरफ से दिलवाने का प्रयत्न किया जाएगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के जो फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उस सम्बन्ध में शिक्षक संघ द्वारा राज्य सरकार को एक 22 सूत्री ज्ञापन पेश किया गया है। राजस्थान के जिला हैड क्वार्टर्स पर कुछ अर्से पहले भी मांग पत्र पेश किये गये थे और जिला कार्यालयों पर धरणा और सत्याग्रह किया गया था और उनको आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन के आधार पर जिला स्तर पर वह आंदोलन खतम किया गया था। उस समय के शिक्षा मन्त्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने एक सक्यूंलर निकाला था और यह कहा था कि सरकार के पास आने की जरुरत नहीं है। उस सक्यूंलर में शिक्षकों की 12/18 मांगें मान ली गई थीं। उस सक्यूंलर में यह भी कहा गया था कि स्थानीय संघ के जो पदाधिकारी हैं, कोई शिक्षक होगा तो उस पदाधिकारी का स्थानान्तरण किसी हालत में नहीं किया जाएगा। मोटे तौर पर वह डिमांड सरकार ने लिखित में आश्वासन देकर मन्जूर की थी परन्तु उस सब के ऊपर पानी फिर गया है। सांचोर में रुगनाथराम शिक्षा प्रसार अधिकारी की शिक्षक संघ का अध्यक्ष होते हुए भी पलटी की गई। उनका ट्रान्सफर कलेक्टर जालोर द्वारा गलत क्यों किया गया? आज दिन तक की सुनवाई नहीं की गई है। उनकी वाजिब मांगें थीं। उनके पोस्टिंग, ट्रांसफर के बारे में सरकार की जो नीति थी, वह उस सक्यूंलर में प्रसारित की गई थी, उनकी परिपालना न करने के बारे में वे सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि इसकी परिपालना हो। इसके अलावा मैंने एक सूचना और भी दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय चतुर्वेदी जी को भी लिखा था और माननीय भंवर लाल जी को भी लिखा। उन्होंने कहा कि मैं कार्यवाही करूंगा। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है लैटर लिखने के बाद भी, सरकार के नोटिस में होने के बाद भी सरकार शान्त है, इसका कारण क्या है? सैकण्डरी स्कूलों में हैड मास्टरों के प्रमोशन किये गये एडहाक बेसिस पर, जब कि कोई रिजर्विस्ट लिस्ट डी. पी. सी. की थी ही नहीं, डी. पी. सी. के अनुसार प्रमोशन विभागीय तौर पर किये गये हैं। यह सूचना दी गई है सरकार की ओर से एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में भी। जो प्रमोशन किये सरकार ने वे रिजर्व लिस्ट से किए उसकी यह सूची पेश की गई है। तो अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन को यह गलत सूचना देकर सदन के साथ धोखा किया। सारी गलत सूचना क्यों दी, हालांकि प्रिवीलेज मोशन मैंने दिया था परन्तु उसमें यह नहीं आता, हालांकि सरकार ने सदन को गलत सूचना देकर सदन को धोखा दिया है। इसके बारे में माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि अध्यापकों की वाजिब मांगों पर जो हैड मास्टरों के एडहाक प्रमोशन किये गये जब कि इस प्रकार के प्रमोशन ज्यादा से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

ज्यादा 6 महीने तक ही की अवधि के लिये होते हैं डी. पी. सी. की रिजर्व लिस्ट के अनुसार फिर आटोमेटिकली वह लिस्ट खारिज हो जाती है। लोक सेवा आयोग का भी यही नियम है, सरकार का भी यही नियम है। रिजर्व लिस्ट में नाम थे ही नहीं, तो आप मेहरबानी करके जो सीनियर टीचर्स, जो कि बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, वे रोते फिरते हैं और दूसरों को गलत प्रमोशन दे दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसी कारण शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के आज आन्दोलन हो रहे हैं। जब वे आपको सक्यूंलर बताते हैं, नियम बताते हैं तो आप मानते नहीं। इसी कारण राजस्थान युनिवर्सिटी ठप्प हुई, फिर जोधपुर युनिवर्सिटी ठप्प हुई। लड़के आन्दोलन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी पढ़ाई खराब होती है। अगर यही हाल रहा तो सारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई खराब हो जायेगी, एग्जामिनेशंस नहीं हो सकेंगे। जब शिक्षकों के हकों को ही मारा जा रहा है तो जैसी लोकतन्त्र की व्यवस्था कायम हुई है, जब दूसरे सब अपने हकों के लिए लड़ते हैं, सत्याग्रह करते हैं तो यही शिक्षण संस्थाओं में होगा प्रमोशन्स में वरिष्ठता का कोई ध्यान नहीं रखा गया और शिक्षकों के साथ अन्याय किया। पहले तो आप बात मान कर, लिखकर, धोखा देकर आन्दोलन समाप्त कराते हैं, और मांगें मन्जूर न होने पर फिर आन्दोलन होता है। इसलिये शिक्षा मन्त्री जी, मैं आपकी मार्फत यहां पर सदन में जो सूचना गलत बताई है उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कम से कम आप और कुछ नहीं करें तो अध्यक्ष महोदय, जब पहले आप हां कर देते हैं, बाद में मजबूरी जाहिर कर देते हैं इतनी कमजोर सरकार है। जब शिक्षकों की वाजिब डिमाण्ड हैं। वे आपका वाजिब सक्यूंलर दिखा रहे हैं जिसके अनुसार वे अपनी मांग कर रहे हैं तो उसकी पूर्ति तो करनी चाहिये। फिर भी आप कुछ नहीं सुनेंगे तो सारी शिक्षण संस्थाएं ठप्प हो जायेंगी। एक यह आपका प्रौढ़ शिक्षा का ढांचा है, कोई पता नहीं कहां खर्चा करेंगे आप, किसको क्या मिलेगा इस बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर पूरी तरह से, विस्तार से ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : शिक्षण संस्थाएं बन्द हो रही हैं, शिक्षकों की मांग कोई आपने मानी नहीं है। क्या-क्या मांगें पूरी करेंगे आप ? शिक्षकों ने जो आपको नोटिस दिया है, आप कब तक उनकी वाजिब डिमाण्ड मन्जूर करेंगे, स्ट्राइक अवाइड कर सकेंगे या नहीं, यह आश्वासन दीजिये आप तो।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको यह चिन्ता हो रही है....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने तो सुझाव दिया है....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : हम तो आपको बता रहे हैं ताकि आपकी शिक्षण संस्थाएं बन्द न हों, सुचारू रूप से चलती रहें। इसीलिये तो हम कह रहे हैं। हमें क्या सुझाव दे रहे हैं आप ? हम तो चाहते हैं बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिये। आप कन्वींसिंग रिप्लाई दीजिये। ऐसा न हो कि सारी शिक्षण संस्थाएं बन्द हो जाए। इस बारे में आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

शर्मा साहब, आपके पास कुछ कहने को है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले डागा साहब बोल रहे हैं तो....

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : पहले आप सब बोल लें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : आप तो चौधरी साहब तनख्वाह लो....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मामला है ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब दूसरे मन्त्री खड़े होकर जवाब देते हैं तो आप इतने सुस्त क्यों हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने सरकार का इस प्रश्न पर ध्यान आकर्षित कराया है, इसके बारे में समुचित उत्तर जब डिमाण्ड आयेगी उस समय आ जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : डिमान्ड का इससे क्या लेना देना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य बोलेंगे, फिर डागा जी बोलेंगे, तब कहीं मेरा नम्बर आयेगा। कल शिक्षा के बारे में डिमाण्ड्स हैं। इसके बारे में जो भी सरकार का पक्ष है, उसमें निवेदन करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विद्युत मन्त्री अपनी बलन्द आवाज से बार-बार कहते हैं कि राजस्थान में बिजली का विकास विद्युत गति से किया जाएगा। लेकिन कल ही यह अखबार से मालूम हुआ कि 35 लाख यूनिट बिजली की राज्य में कमी पड़ गई है और विद्युत उत्पादन न होने के कारण उद्योगों को बिजली पूरी नहीं मिल पाती। राजस्थान परमाणु बिजली घर और बदरपुर बिजली घर में उत्पादन अचानक रुक जाने से राज्य

(श्री मूलचन्द डागा)

में 2-3 दिनों के लिए बिजली का संकट पैदा हो गया है।

बिजली का जीवन से कितना सम्बन्ध है, यह तो आप खुद बताते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सारी इन्स्टाल्ड केपेसिटी आज बिजली की 1330 मेगावाट है और 1330 मेगावाट आपकी बिजली की इन्स्टाल्ड केपेसिटी है उसके अन्दर पीक पीरियड के अन्दर 937 मेगावाट बिजली आपको मिलती है हमको जो बिजली मिलती है उसके हिसाब से गिनती लगाकर देख लें कि उसमें 463 मेगावाट बिजली की कमी है। 463 मेगावाट बिजली की आज कमी है और राजस्थान में 50000 कर्मचारी विद्युत विभाग में काम करते हैं। 20 करोड़ की तनख्वाह उनको देते हैं। 20 करोड़ का प्रति वर्ष का बजट बनता है उनकी तनख्वाह का। बिजली हमारी आ रही है भाखरा से, चम्बल से और सारे राजस्थान में केवल एक कोटा का थर्मल स्टेशन बनने वाला है। मैं राजस्थान के विद्युत मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो हमारी बिजली की आज 463 मेगावाट की कमी है तो इतने मेगावाट बिजली की कमी को कैसे आप पूरा कर रहे हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं कि कल जो 35 लाख यूनिट की कमी हुई तो उस कमी का क्या कारण था? क्या यह सही है कि वह लाइन टूटी। बदरपुर की लाइन ठीक काम नहीं करती है। उसका मेंटीनेन्स कौन करता है। कल भी यह घटना हुई कि टी. वी. का जो कनेक्शन था तो लाइट आते-आते वह टूट गया और एक घण्टे तक सारे राजस्थान में टी. वी. का आनन्द लेना चाहते थे वह उससे महरूम रह गये। यह आपने बिजलीघर के अन्दर 60 हजार कर्मचारी लगा रखे हैं और 27 करोड़ की तनख्वाह आप उनको देते हैं 5 अरब का इन्वेस्टमेंट है और उस बिजलीघर की यह हालत है। और गांवों के अन्दर जब बिजली का वोल्टेज बढ़ जाता है तो कई लोगों की मोटरें खराब हो जाती हैं और किसान अपने भाग्य को रोता है। इस प्रकार आज यह बातें करते हैं, योजना बनाते हैं और जो योजना विभाग है सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास है उन्होंने आपको मना कर दिया। जो धन-राशि की आपने मांग की थी वह भी उन्होंने स्वीकृत नहीं की। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा थर्मल स्टेशन बनाने की जरूरत है? कोटा का थर्मल स्टेशन और बीकानेर का थर्मल स्टेशन यह कब तक शुरू हो जायेंगे। तो 5 साल के लिए राजस्थान को आने वाला खतरा है। यह एक छोटा सा प्रश्न नहीं है। आप कृपया बतायें कि लाइन खराब कैसे हो गई? लाइन का मेंटीनेन्स कौन करता था? बदरपुर बिजली घर को पानीपत से नरोरा जाने वाली लाइन खराब कैसे हो गई? क्या आपका वहां पर मेन्टीनेन्स है जो इस बात को देखता है कि लाइन ठीक प्रकार से काम करे? क्या आपके स्टाफ ने जो लाइन टूटी उसको देखा है? कल भी नुकसान हो गया। इस प्रकार का घाटा और इतनी धन राशि लगाई गई तो यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यह बतायें मन्त्री महोदय, कि हमारे यहां पर 463 मेगावाट की कमी है वह कैसे पूरी होगी? इस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे, इस बारे में आप संजीदगी से सोचकर उत्तर दें।

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा चाहूंगा कि माननीय सदस्यों

(श्री मदनसिंह दाता)
को और मन्त्री जी को पसीना आ रहा है। आपका हुकूम हो तो पंखे शुरू करा दें।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** (विद्युत मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय विधायक डांगाजी ने जो सवाल किया है, यह बात सच है कि आर. ए. पी. पी और बदरपुर से बिजली बंद हो गई थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बदरपुर से बिजली आना वापस चालू हो गई है। जहां तक आर. ए पी.पी. का सवाल है ..

श्री **सूर्य नारायण चौधरी** : वह बन्द होता है तो वह आपने ही बनवाकर दिया था।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : जहां तक आर.ए.पी.पी का सवाल है, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर ए. पी.पी. की कन्डीशन के विषय में माननीय विधायक परिचित हैं। उसमें जिस प्रकार की गड़बड़ियां आ जाती हैं तो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत वह आता है। उसको पूरा ठीक करने का लगातार वह प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि यह बात सच है कि जैसा उन्होंने कहा बिजली की कमी है और वह इस नाते से पैदा हो जाती है, किन्तु बिजली का उत्पादन कोई एक दिन का विषय नहीं है। कोई एक साल का विषय नहीं है, कोई पौने दो साल का विषय नहीं है जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई है। पता नहीं किस तरह से कैसी योजना बनी थी कि जनरेशन और इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार से गैप का निर्माण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जब से हम आये हैं लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि कई वर्षों से जो स्टेगरिंग कर रहा था गैप प्राइमरी योजना से उसके लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो जाय, और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 110 मेगावाट का एक यूनिट मार्च, 1980 में प्रारम्भ हो जायेगा। 110 मेगावाट के एक यूनिट वर्ष 1981, में चालू हो जायेगी। दो यूनिट की स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से ले चुके हैं। 220 की और स्वीकृति के लिए हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है। वह स्टेगरिंग था तो मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार रही तो कैसे उसको स्टेगरिंग करती रही। जब से हम आये हैं हम कोशिश कर रहे हैं। प्रत्येक महीने में स्वयं जाकर देखता हूं कि काम विधिवत् चल रहा है कि नहीं। इतनी बात और भी कहना चाहता हूं कि जो कोयला खान पलाना में है उसके लिए हमने यह प्रयत्न किया है कि और सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी को एक एप्लीकेशन भेजी है कि पलाना का जो प्रोजेक्ट है उसका जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन किया जाय। जनता पार्टी की सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, लेकिन पिछला जो गैप रहा है कि कभी बदरपुर बन्द हो जाता है, कभी यह बन्द हो जाता है। आपने बिजली की लाइन टूटने वाली बात कही और बड़े ढंग से उसमें टी.वी. की बात को जोड़ दिया। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि टी.वी. और बिजली विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। आप जानकारी कर लें तो इस प्रकार की बात उठायेंगे नहीं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हूं कि इस प्रकार से आकस्मिक जो बातें पैदा होती हैं तो हम चाहते हैं, आखिर बिजली जितनी है उतनी ही है। इस संबंध में हम प्रयत्न अवश्य कर रहे हैं और उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। उपयोग चाहे सफर करें किन्तु किसान को सफर नहीं कराना चाहते हैं। हम बिजली उद्योग को न दें लेकिन किसान को पूरी बिजली मुहैया करायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि राजस्थान में कोटा का थर्मल स्टेशन आयेगा उससे तो आपने बताया कि 220 मेगावाट बिजली पैदा होगी, लेकिन मैंने आपको यह निवेदन किया था कि हमारी जो वर्तमान डिमाण्ड है उससे 637 मेगावाट की कमी है तो उसको मीट आप और कैसे करेंगे ? मैंने छोटी सी बात कही है। बीकानेर का स्टेशन जो नया थर्मल स्टेशन है उसकी कोई योजना इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी ने स्वीकार नहीं की है। आपने मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। 600 मेगावाट की बिजली की कमी होगी वह 220 मेगावाट से कैसे पूरी होगी ? बीकानेर का थर्मल स्टेशन, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथोरिटी ने अभी तक आपकी राय नहीं ली है, और न उन्होंने उसको मंजूर किया है, और न आपकी योजना बनी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने कहा कि जिस गैप का निर्माण किया गया है उसको इतनी बार कहने पर भी आप नहीं समझें तो इसमें मेरा दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त सूचना और मिली है। आपकी जानकारी के लिये और कह दूं कि इस प्रकार की स्थिति का तो आकस्मिक निर्माण होता है जो हमने एन. आर. ई. आर. को निवेदन किया है जिसके फलस्वरूप 50 मेगावाट अतिरिक्त बिजली हमको दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग और 50 मेगावाट भाखरा, ब्यास, बदरपुर सिस्टम से मिलने की व्यवस्था हो गई है। इस प्रकार से अप्रत्याशित घटना के लिए जिसके ऊपर आर. एस. ई. बी. का कोई नियन्त्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार की सहायता आवश्यकता पड़ने पर उत्तर प्रदेश और मथुरा से अतिरिक्त बिजली हम निश्चित रूप से ले लेंगे और उसकी कमी को मिटाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री मूल चन्द डागा : 35 लाख यूनिट जो कम हो गई तो जो लाइन शुरुआत से ही खराब है तो मेन्टीनेन्स लाइन कौन करता है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा स्थगन प्रस्ताव उदयपुर विद्या भवन के बारे में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो 1980 कहा था, वह 1982 है।

श्री मूलचन्द डागा : हां, 1982 है। तब तो डिमाण्ड और बढ़ जाएगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह चुनाव क्या पहले करायेंगे या बाद में करायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : राजस्थान एटामिक पावर प्रोजेक्ट से हमको बिजली नहीं मिलती है। जनता पार्टी जिस वक्त से आई है, उस प्रोजेक्ट से हमको बिजली नहीं मिलती हैं। मैंने कहा कि आपकी बिजली की मांग 600 मेगावाट होगी। 1982 में आप उत्पादन करेंगे। यह 400 मेगावाट कहां से मिलेगी?

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर रूरल इन्स्टीट्यूट के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच विवाद चल रहा है। सूचना मिली है कि कल रात को नरेन्द्रपालसिंह जी की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ है। उनकी सूचना के आधार पर इन्स्टीट्यूट खुल गई हैं। माननीय सदस्य सूचना लाने गये हैं। वह जो सूचना लेकर आयेंगे, उनकी जानकारी के आधार पर मैं सदन को सूचना दे दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नरेन्द्रपालसिंह जी........

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। वहां से अध्यापक आये हुए हैं। हमको हर बार यह कहा गया कि कल समझौता हो रहा है, परसों या परले दिन समझौता हो रहा है। हमेशा यह कहा है। 64 दिन के बाद आज मजबूर हो कर यह प्रश्न उठाया है। विद्यार्थियों की पढ़ाई की हानि हो रही है। विद्यालय की परीक्षाएं होने जा रही हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेन्द्रपालसिंह जी आ गये हैं। उनसे विद्या भवन के बारे में पूछ लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आॅन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मन्त्री महोदय को कोई अथेण्टिक बात कहनी चाहिए।

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्य की जानकारी पर आधारित शासकीय वक्तव्य

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय श्योपतसिंह मकासर ने सूचना दी। वह बोलना चाहते थे। उससे पहले माननीय मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया या सूचना दी। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नरेन्द्रपालसिंह जी के साथ में समझौता हुआ है। और वे माननीय सदस्य सूचना लाने गये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सदन की परम्परा यह रही है, मंत्री जो भी कहेगा, वह अपनी जानकारी के आधार पर कहेगा। कभी इस प्रकार वक्तव्य नहीं दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने सूचना दी है। वक्तव्य नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : On a point of information उन्होंने सूचना दी है। वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था चाहता हूं कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्या सरकार की तरफ से बोलने वाला मन्त्री, किन्हीं माननीय सदस्य का रेफरेंस देकर यह कहे, व दूसरे माननीय सदस्य का हवाला देकर कोई बात कहे, क्या यह सदन की परंपरा है ? क्या मन्त्री को दूसरे की सूचना के आधार पर बोलना होगा ? मन्त्री को कहना होगा कि मैं अपनी बात कह रहा हूं। सरकार को अपनी बात कहनी होगी।

(व्यवधान)

इस सदन के अन्दर माननीय मन्त्री को अपनी बात कहने का हक है। किसी दूसरे की बात वह नहीं कह सकते हैं। अगर वह बात सही है तो माननीय सदस्य कह सकते हैं। सरकार की ओर से जानकारी की गई और क्या फैक्ट्स की जानकारी की गई। फैक्ट्स की जानकारी करना मुश्किल नहीं है। यह जो उत्तर दिया गया है, यह बोगस है। यह शर्म की बात है। सदन को गुमराह करते हैं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय मंत्री इस प्रकार का स्टेटमेण्ट दे सकता है ? क्या यह कह सकता है कि मुझे माननीय सदस्य से जानकारी मिली है। इस आधार पर कह रहे हैं कि स्ट्राइक टूट गई है।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : बस उनका स्वार्थ पूरा हो जाये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आप कृपया इस पर अपनी व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्वाइण्ट आफ आर्डर उठाया है, इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था नहीं होने से यह फायल हो जाएगा। हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसकी क्या परम्परा है। अब तक क्या व्यवस्था रही है। माननीय सदस्य नरेन्द्रपाल सिंह जी इसकी इत्तला के सोर्स हैं या शिक्षा मंत्री जी का अपना खुद का सोर्स है। कृपया बतावें ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से इतनी जानकारी चाहता हूं कि आपकी उदयपुर के किन अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने नरेन्द्रपालसिंह जी को हड़ताल टूटने की जानकारी कब दी है। क्या उन्होंने कलेक्टर से कोई जानकारी की है। या उनको यह सूचना प्रबन्ध समिति के लोगों ने दी है कि इन्स्टीट्यूशन खुल गया है। क्या उनके आधार पर वह अपना दिमाग बना रहे हैं। समझौता हुआ तो किन शर्तों के आधार पर

Page No. 64

(64)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किन बातों के आधार पर और किन शर्तों के आधार पर यह हड़ताल तोड़ी गई है ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इसी प्रकार माननीय सूर्यनारायण चौधरी बोल रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दी जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग देखकर, विचार कर, व्यवस्था दूंगा। कोई आपत्तिजनक परिस्थिति हो ऐसा नहीं लगता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसे महत्वपूर्ण इश्यू को साइडट्रेक किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइन्ट इम्पोर्टेन्ट है तो मैं ड्यू इम्पार्टेन्स दूंगा, प्रॉसीडिंग देखकर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि मेरे पास खबर आई है। नरेन्द्रपालसिंह जी से सूचना आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं रात को 10 बजे बस से चला हूं। प्रबन्ध समिति के सदस्य आये हैं। रात के 10 बजे तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इस इन्स्टीट्यूशन की लाखों करोड़ों रुपयों की जायदाद है। सेण्ट परसेण्ट सब्सिडी सरकार देती है। 27 जनवरी से आज 56 रोज हो गये हैं, हड़ताल हो गई है। सारे के सारे अध्यापक हड़ताल पर हैं। शिक्षा मन्त्री महोदय की क्या मजबूरियां हैं यह मैं समझता हूं। प्रबन्ध समिति के जो लोग हैं, वह बहुत शक्तिशाली है। दिल्ली तक उनका असर है।

श्री रघुनन्दन व्यास : नाम बताइये, उनका।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नाम जानना चाहते हैं ? नाम है, जगत मेहता। मेहता परिवार का वह इन्स्टीट्यूशन है। यह सारी मेहता परिवार की हो गई है जबकि करोड़ों रुपये सरकार के लगे हैं। दो हजार बीघा जमीन उदयपुर में है, करोड़ों रुपयों के भवन बने हुए हैं। ग्रामीण किसानों के लड़कों के लिए, उनके नाम से इन्स्टीट्यूशन है, और इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मजे कोई कर रहा है और बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह माननीय शिक्षा मन्त्री जी को देखना चाहिए। अगर आप यह चाहते हैं कि इन अनियमितताओं की जांच नहीं हो, अगर आप यह चाहते हैं कि इसके लिए कोई आवाज नहीं उठे, और मेहता परिवार का ही वहां पर अलग से शासन कायम हो जाय तो मैं बता देना चाहता हूं, शिक्षा मन्त्री जी को, कि उनका असर दिल्ली में हो सकता है, मगर राजस्थान की जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जरा इस बात को सोचिये, मेहता परिवार के असर से अगर आप यह मानते हैं तो सारा का सारा इन्स्टीट्यूट बरबाद हो जायगा। यह उनकी कोई जागीर नहीं है, आपमें अगर होसला है तो उस इन्स्टीट्यूशन को ले लीजिये। सारी एड सरकार दे रही है, उनकी तरफ से एक पैसा भी नहीं लगा। आपने क्यों नहीं फैसला किया ? हम नहीं जानते कि नरेन्द्र-

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पालसिंह जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। आप खुद मालूम कीजिये, आपके पास आज सूचना नहीं है तो कल दीजिए। आपको इण्टरवीन करना चाहिए, आप प्रबन्ध समिति को आदेश दीजिए। मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, केवल समझौते के लिए ही नहीं रखा है। मैंने आपको यह भी कहा है कि इस प्रबन्ध समिति ने लाखों रुपयों के घोटाले और अनियमिततायें की हैं, गलत लोगों को नौकरियां दी हैं जैसे एक ही परिवार की इन्स्टीट्यूशन हो। सरकार का इसमें करोड़ों रुपया लगा है, आप इसकी जांच करवाइये। राजस्थान में कई इन्स्टीट्यूशन में आपने इण्टरवीन किया है। वनस्थली में हड़ताल हुई आपने इण्टरवीन किया, गोवा की एक लड़की थी, एक लड़की ने वहां पर सूसाइड किया। कोई भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन हो, आखिर राज्य सरकार का उसमें पैसा लगता है, कोई बात हो तो क्यों नहीं आप पता लगाते? गड़बड़ हो तो आपका काम है, जांच करवाना। चाहे वनस्थली हो, चाहे विद्या भवन हो, राजस्थान सरकार का पैसा लगता है, उसमें गड़बड़ी हो तो उसकी जांच होनी चाहिये। शिक्षा मन्त्री जी, आप पंच बने थे वनस्थली में, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर, कभी राष्ट्रपति को कभी किसी को, और कोई अनियमितता करे तो आप उसकी जांच नहीं करेंगे तो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन के अध्यापक आन्दोलन करेंगे। जहां पर भी सरकार का पैसा हो वहां पर सरकार को दखल देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और शिक्षकों की मांगों को मानना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव........

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर: खीर में आप मूसलचन्द क्यों बनते हो?

श्री कौशकिशोर जैन: बीच मे चीं चीं मत किया करिये।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्याभवन रूरल इन्स्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ बातें माननीय सदस्य ने बता दी हैं। वहां से दो अध्यापकों को आपातकाल में निकाला गया, उनकी अपील राज्य सरकार के पास थी। 16-1-78 को सरकार ने एक आदेश निकाला कि उन दोनों अध्यापकों को ले लिया जाय। उसके बाद 24-1-78 को वहां की मैनेजमेन्ट की मीटिंग हुई उन्होंने यह बिल्कुल तय करके लिख दिया गया कि वे सरकार के किसी आदेश की पालना नहीं करेंगे और उसके पश्चात् सरकार ने उनकी एड को रोके रखा, लेकिन पिछली 26 फरवरी के दिन मैनेजमेन्ट के कुछ लोग आये और उन्होंने लिख–कर दे दिया कि उन दो लोगों को ले लिया गया है। उस पर मिनिस्टर साहब का आदेश हुआ कि उनको नौकरी पर लेने के पश्चात एड को रिलीज कर दिया जाय।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि एड उससे पहले ही रिलीज कर दी और व्यक्तियों को नौकरी पर नहीं लिया गया। इसी तरह से मैनेजमेन्ट की तरफ से सूचना मिली कि इन्स्टीट्यूशन खोल दी गई है, वहां के लोगों से क्या बात हुई, उन्होंने एकतरफा कार्यवाही की और आपने एड रिलीज कर दी। एक ओर आप कहते हैं जो मजदूर फैक्ट्री में काम करता है उसकी सर्विस को सिक्यूरिटी पहले होगी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों की क्या सिक्योरिटी है? आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है और आप एड रिलीज कर रहे हैं। 52 दिन हो गये आन्दोलन को, उनको बुलाकर अभी तक नहीं सुना गया, उनसे कोई बात नहीं की गई, यह जो आपने व्यवहार किया यह उचित व्यवहार नहीं लगता है। बड़े लोगों के होने से यह तो नहीं होना चाहिये कि इस तरह का व्यवहार शिक्षकों के साथ हो। कोई भी गलती करे तो चाहे उसको आप फांसी पर लटका दो। लेकिन बड़े आदमियों के दवाब के कारण, आप दब जायं यह कोई न्याय नहीं होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जो कुछ भी समझौता करें, उनको साथ बुलाकर, उनके साथ बैठकर करें। 56 दिन से संस्था बन्द है। यूनिवर्सिटी की परीक्षायें 24 अप्रैल से होने वाली हैं, पीरियड बहुत कम है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन दो अध्यापकों की सर्विस की सिक्यूरिटी होनी चाहिये। आपने उनको विश्वास भी दिलाया। आप यही बतलावें कि क्या वास्तव में समझौता हो चुका है, क्या विद्यालय खुल गया है? मैनेजमेन्ट का एक आदमी सरकार से बात करके आया और कहा कि इन्स्टीट्यूशन खुल गया है, आपकी सूचना के सोर्सेज क्या खतम हो गये, क्या आपका वायरलैस सिस्टम खतम हो गया, क्या आपको जानकारी करने का कोई अवसर नहीं मिला? अध्यापकों ने इतना लम्बा आन्दोलन किया, विद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी आन्दोलन किया कि इसको विश्वविद्यालय में मिला दिया जाय। ऐसी कौन सी बात है जो ग्रामीण क्षेत्र का नाम लगाकर लूटने वाले लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है? आपने लिखा था कि आपके पाठ्यक्रम में ग्रामीण पाठ्यक्रम नहीं होने के कारण एड बन्द कर रहे हैं। क्यों बाद में केन्द्रीय सरकार से लागू कर दी गई, उन्होंने बन्द कर दी उसके बाद राज्य सरकार ने दे दी कि पाठ्यक्रम के हिसाब से दी जा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं आपका क्या वह पाठ्यक्रम बन गया? इस तरह यह जो परम्परा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

है और यह जो अन्याय है उसको रोका जावे, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न केवल रूरल इन्स्टीट्यूट का ही नहीं है, राजस्थान के अन्दर जितनी भी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें हैं उन सबके अन्दर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सब का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के बाहर रुक्टा के अध्यापकों और प्राध्यापकों ने प्रदर्शन

(श्री कौशल किशोर जैन)

किया, इसी बात को लेकर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट का ही सवाल नहीं है। यही प्रश्न लाल बहादुर शास्त्री कालेज का है। राजस्थान में....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या आप मेरे स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर पहले व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

पाइंट आफ आर्डर।

श्री रघुनन्दन व्यास : भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। करोड़ों रुपयों का घपला है। पहले स्थगन प्रस्ताव का उत्तर दिलाया जाय। मोहनसिंह मेहता वाले इन्स्टीट्यूट में काफी गड़बड़ है, कितनी ही भ्रष्टाचार है उसका मंत्री जी उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : प्रश्न केवल उदयपुर इन्सटीट्यूट का नहीं है। राजस्थान में जितनी प्राइवेट संस्थायें हैं .. ....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री मदनसिंह दांता : You must to point of order.

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय जब कहेंगे तब सुनूंगा, आपके कहने से नहीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पाइंट आफ आर्डर। मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा, उस पर विचार हो रहा है, बीच में माननीय सदस्य अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। अगर कोई माननीय सदस्य मेरे स्थगन प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्री महोदय जवाब देने की स्थिति में हैं, जवाब देंगे, इससे पहले दूसरा सवाल आ जाए यह सही नहीं है। इस सवाल को पहले लिया जाए।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह पर्टीक्यूलर संस्था की गड़बड़ियों और हड़ताल के बारे में है। इसको जनरल पाइंट से नहीं जोड़ा जा सकता। विद्या पीठ रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर में जो गड़बड़ घोटाले है, स्टाफ हड़ताल पर हैं, श्री श्योपतसिंह ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और माननीय कटारिया ने जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है उस पर हम मन्त्री महोदय से उत्तर चाहते हैं, जनरल इश्यू से इसको नहीं जोड़े।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचंद्र (पिडावा) : क्या यह सही है कि विज्ञान मोदी........

श्री कौशल किशोर जैन : मैं आपकी स्वीकृति से खड़ा हुआ था, अध्यक्ष महोदय।

श्री ईश्वरचंद्र : श्राप दूसरी संस्थाश्रों के बारे में बोल रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे एक मिनट माननीय श्योपतसिंह के स्थगन प्रस्ताव पर बोलना है।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचंद्र : मंत्री महोदय यह बतायें कि विज्ञान मोदी जब शिक्षा राज्य मंत्री थे उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर उन दो श्रध्यापकों को वापस नौकरी पर रखने का श्रादेश दिया था जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने एन्डार्स किया था। उसके बाद हाई कोर्ट जजमेंट श्राया उसके बाद भी उन दो श्रध्यापकों को नौकरी में नहीं रखा जा रहा है। मैं रूरल इन्स्टीट्यूट उदयपुर की बात कर रहा हूं। शिक्षा मन्त्री प्रकाश डालें कि क्या मोहनसिंह मेहता बड़े हैं, क्या वे सर्वोच्च हैं? देश के प्रधान मंत्री से भी बड़े हैं कि वे जो श्रार्डर चाहें करा लेते हैं, जब चाहे एड रिलीज करा लेते हैं, जब चाहे स्कूल खुलवा देते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो श्रतिक्रमण हो रहा है, जब तक बड़े बड़े मठाधीश नहीं हटेंगे तब तक यह श्रतिक्रमण बंद नहीं होगा। 56 दिन से यह रूरल इन्सटीट्यूट बंद पड़ा है, लाखों रुपए की एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट की लेबोरेटरी खराब पड़ी है, फर्नीचर मेकिंग सेंटर के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला है। श्री मोहनसिंह मेहता के पुत्र जगत मेहता विदेश सचिव हैं जिन्होंने चीन के मामले में हिन्दुस्तान को नीचे दिखाया, वह श्रादमी श्री मोरारजी से तिकड़म भिड़ाकर शिक्षा मंत्री को बाई पास करते हैं:.....

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : कैसे चीन के मामले में नीचे दिखाया?

श्री ईश्वरचन्द्र : वह सारी विदेश नीति में भी गड़बड़ कर रहे हैं। मोहनसिंह मेहता ने राज्य सरकार के पास श्री मोरारजी से टेलीफोन करवाया है। मन्त्री के श्रार्डर की श्रवहेलना करते हुए रातों-रात दूसरे श्रादेश जाते हैं, हमारी सरकार कठपुतली बनी हुई है। श्री मोहनसिंह मेहता उदयपुर के शिक्षा जगत में सांप की तरह छाया हुश्रा है, जहां पूरा वातावरण दूषित है, लोगों के साथ श्रन्याय हुश्रा है, श्रांदोलन हुश्रा है, उनके साथ खिलवाड़ हुश्रा है, श्राप इस तमाशे को बन्द करें। नन्दकिशोर चतुर्वेदी श्रान्दोलन कर रहे हैं।

श्री नरेंन्द्रपालसिंह चौधरी : जो वहां श्रान्दोलन कर रहे हैं वे वहां के इन्चार्ज बनना चाहते हैं। चतुर्वेदी ने विज्ञान मोदी को गुमराह किया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : श्रापका फर्माना गलत है।

(व्यवधान)

श्राप गैर जिम्मेदारी से बोल रहे हैं।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : श्राप धमकी देते हैं श्रान्दोलन की श्राप गैर जिम्मेदार हैं?

श्री नूरा : चौधरी साहब, श्राप बुजुर्ग श्रादमी है, श्रापको शोभा नहीं देता इस तरह बोलना। श्राप किस भाषा का प्रयोग करते हैं?

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : आप अपनी जिम्मेदारी महसूस करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री): आज जो यह प्रस्ताव है केवल इस सीमा तक है कि उदयपुर के रूरल इन्स्टीट्यूट में जो हड़ताल चल रही है उसकी क्या स्थिति है? चर्चा के दौरान इससे दूर जाकर माननीय सदस्यों ने बहुत सारे प्रश्न उठाये। मैंने जो प्रारम्भ में सूचना दी थी वह यह दी थी कि हमारे माननीय सदस्य, श्री नरेन्द्रपालसिंह जी चौधरी दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने में लगे हुए थे और जब यह प्रश्न आया तो मैंने उनसे जानकारी की कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने बताया कि कल की बातचीत के बाद आपस में उन्होंने तय किया है कि आज से इन्स्टीट्यूट खुल जायेगी। मुझे सूचना है केवल माननीय सदस्य के कहने के आधार पर। वह भी कह रहे थे कि वायरलैस से सूचना आयेगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या उन अध्यापकों को लिया गया?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जो एड राज्य सरकार ने बन्द की थी क्या वह प्रधान मन्त्री के हस्तक्षेप से और मुख्य मन्त्री के कहने से रिलीज की गई और यदि एड दी गई तो फिर इन मंत्रियों को रहने का क्या अधिकार है? मुख्य सवाल यह है कि जो राज्य मन्त्री ने आर्डर दिया था कि उन दोनों लेक्चरर्स को पुनः नियुक्त किया जाये। एड जो बन्द की गई थी वह किन कारणों से एड रिलीज कराई? माननीय भटनागर ने जो आरोप लगाया है वह सही है। प्रधान मन्त्री ने मु.मं. से कहा और मुख्यमन्त्री ने अपने अन्त्योदय के योजना मंत्रियों को आदेश दिया और उन्होंने आदेशों की अवहेलना करके एड रिलीज की, राज्य सरकार पर कालिख पोती गई। यहां पर किसी व्यवस्था का, नियम का, सिद्धान्त का राज न होकर एक व्यक्ति की इच्छा का राज है। तो मन्त्री जी जवाब दें कि आपने एड किन कारणों से रिलीज की? आप पर मुख्य मंत्री का दबाव था और मुख्य मन्त्री पर प्रधान मन्त्री का दबाव था।

(व्यवधान)

राजस्थान यूनीवर्सिटी के भूतपूर्व वाइस चान्सलर और जो पाकिस्तान में भारत के राजदूत भी रहे हुए हैं और जिनका लड़का श्री ज्ञान मेहता सचिव है....

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : माननीय सदस्य की सूचना के आधार पर मन्त्री महोदय ने कहा है तो क्या सूचना सदस्यों की जानकारी के आधार पर भी दी जाती है? क्या सरकार के पास स्वयं की कोई सूचना नहीं है?

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह मुख्य मन्त्री या शिक्षा मंत्री का फैसला नहीं था? पूरी केबिनेट ने निर्णय लिया था और यह निर्णय लिया था कि उन प्राध्यापकों को पुनः रखा जाये और राजस्थान सरकार की पूरी केबिनेट के निर्णय को मान्य नहीं किया जा रहा है केवल मोहनसिंह मेहता के द्वारा, यह क्या रहस्य है? यह बतायें।

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य समझौते के

(श्री टीकमचन्द कांत)

बीच में लगे हुए हैं और वे आकर यदि कोई सूचना दें तो उस समय यह क्यों प्रश्न उठता है कि सदस्य की हैसियत क्या है ? जबकि बारबार सदन में यह प्रश्न उठा है कि आप मन्त्रीगण नौकरशाही की ही बात मान लेते हैं और माननीय सदस्य की बात को नहीं मानते हैं और अब नौकरशाही की बात को वजन दिया जायेगा न कि चुने हुए सदस्य की बात को।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने श्री नरेन्द्रपाल सिंह जी चौधरी को समझौता कराने के लिए उदयपुर भेजा था ? यदि भेजा था, तो वे कितने बजे, किन किन लोगों के बीच में जाकर बैठे और क्या बात तय की और क्या रिटन डाकूमेन्ट पढ़ा ? वह रिटन डाकूमेन्ट लेकर दें। क्या रिपोर्ट दी ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ कि वहां की मैनेजिंग कमेटी का एक व्यक्ति गाड़ी में चल कर आया और उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने तय कर लिया कि स्कूल खुल रहे हैं। उस व्यक्ति के आधार पर यह सूचना दी गयी है। 16 प्राध्यापक आपके नीचे खड़े हैं उनकी बात जाकर पूछें। वह प्राध्यापक उदयपुर से चेतक से आने के बाद मुझे मिले हैं। वहां आन्दोलन कन्टीन्यू है, विद्यालय खुले नहीं हैं। केवल उस व्यक्ति के आधार पर यहां कहा जाये तो यह कहां तक उचित है, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि केबिनेट का निर्णय यह था कि इन दोनों प्राध्यापकों को पुनः नियुक्त किया जाये तभी अनुदान रिलीज किया जायगा......

श्री मदनसिंह दांता : पाइन्ट आफ इनफर्मेशन, सर। अध्यक्ष महोदय, एक बहस यह थी कि आन्दोलन बन्द हुआ या नहीं। इसके ऊपर मन्त्री महोदय ने कहा कि सदस्य गये सो गलत कहा है। वहां हड़ताल चल रही है और स्कूल बन्द हैं। आपने यह कहा कि वायरलैस आयेगा ......

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीस वर्ष के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मंत्री यह कहे कि मुझे फलां सदस्य ने इनफार्मेशन दी है और उसको सदन के पटल पर रखें। यह बहुत बुरी बात है। अगर कोई बात हो गयी थी तो शिक्षा मन्त्री जी को अपनी तरफ से कहना चाहिए कि यह बात हो गयी है। यह सारी एन्टायर रेस्पान्सीबिलिटी सरकार की है और मन्त्री महोदय, सारी बात सरकार की तरफ से आनी चाहिए। यह कोई पंचायत है क्या ? यह विधान सभा है। विधान सभा कोई पंचायत नहीं है, जैसे पंचायत में बात कहते हैं उस तरह से यहां भी कहें कि मेरे पास समाचार आ गया और मैंने सुना दिया। यह सदन की परम्पराओं का, अध्यक्ष महोदय, घोर अपमान है, इसलिए यह मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कोई ग्राम पंचायत नहीं है। आप इस तरह से ग्राम पंचायत को यहां बीच में नहीं घसीटे, ग्राम-पंचायतें फैसला करती हैं और लिखित में करती हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बीच में मूसलचन्द बन जाते हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह मूसल कह रहे हैं तो ऊखल कहां है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक बात कह दूं ....

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह जी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई भी मंत्री इस तरह से बिना सरकार की किसी अधिकृत सूचना के या बिना किसी बात के सिर्फ एक इनफार्मेशन पर सदन के अन्दर कोई बात रख सकता है या नहीं ? यह व्यवस्था का सवाल है और मैं व्यवस्था चाहता हूं।

दूसरे, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, मैं दो अलफाज उसके पढ़ना चाहता हूं। यह सिर्फ हड़ताल से ही ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा है कि विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर तथा उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं में भारी अनियमितता, पक्षपात तथा आतंक फैलाये जाने के खिलाफ वहां के तमाम शिक्षक वर्ग ने पिछली 27 जनवरी से हड़ताल की है जिसकी वजह से हजारों छात्रों को वहां पर बहुत ही नुकसान हुआ है–क्या यह सही है ? साथ ही यह भी कहा है कि शत प्रतिशत अनुदान पाने वाली संस्था जिसमें करोड़ों रुपया राज्य सरकार का लगा है सरकार अपने हाथ में ले या उसकी जांच करे। यह सवाल संबंधित है। सिर्फ हड़ताल से संबंधित नहीं है। श्री नरेन्द्रपाल सिंह जी ने हड़ताल के लिए कह दिया होगा। मेरा निगोसियेशन्स से ताल्लुक नहीं है। अच्छी बात है निगोसियेशन्स हों, हम चाहते हैं लेकिन मेरे स्थगन प्रस्ताव पर अपनी बात कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे पूरा बोलने दिया जाये तो सारी स्थिति एक्सप्लेन कर सकूंगा। मैंने जो सूचना दी है उसके साथ ही साथ यह भी निवेदन किया था कि वहां हड़ताल खुली या नहीं उसके लिए वायरलैस मेसेज का इन्तजार कर रहे हैं और मैंने कहा कि मैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इसको कन्फर्म करके कहूंगा। लेकिन यह बात सुनने से पहले ही माननीय सदस्य उतावले हो जाते हैं और किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं हैं। संस्थायें खुली हैं या नहीं इसकी जानकारी करने के बाद में जो भी स्थिति होगी वह सूचना दूंगा। जहां तक गुप्ताजी का प्रश्न है जो उनकी भाषा है और स्तर है चाहे कोई भी विषय हो वह बीच में बोलते हैं ...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कैसी भाषा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह जो आप कहते रहते हैं....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैंने हाउस की प्रतिष्ठा के खिलाफ कभी कोई बात नहीं कही है। मैंने अन्त्योदय मन्त्री की बात कही है। अन्त्योदय कार्यक्रम जो कि बहुत प्रसिद्ध है तो इसमें क्या बात है। अन्धे को अन्धा कहना कोई अपमान नहीं है। जब पूर्व में एड बन्द करने का फैसला ले लिया ...

श्री मूलचंद डागा : अन्धे को अन्धा न कहकर सूरदास कहना चाहिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मन्त्री मण्डल का पूरा आदर करता हूं लेकिन अन्त्योदय मन्त्री कहूंगा क्योंकि आप अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। आप ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो डूबने वाली है।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य किसी को अन्त्योदय मन्त्री कह सकता है ? इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय से यही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अथान्टिक स्टेटमेंट को ही हाउस में दें और किसी की भी नहीं सुनें और जो आपका कथन है वह कह कर बैठ जायें। सारी दुनियां के पचड़े में क्यों पड़ते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया ...

श्री मदनसिंह दांता : हमारे लिए सारी दुनियां का....

श्री अध्यक्ष : उदयपुर में जो कुछ हो रहा है, जो नाम लिये हैं, दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के नाम आये हैं। ये नाम अब क्यों मन्त्री महोदय से कहलवाते है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह परम्परा ऐसी नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि चर्चा जल्दी समाप्त हो जाये। यही मेरा मूल लक्ष्य है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन्स्टीट्यूट खुला या नहीं खुला, क्या स्थिति है, अविलम्ब सदन को जानकारी दूंगा और अधिकृत जानकारी दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 27.1 से लेकर आज 19 मार्च हो गई....

श्री अध्यक्ष : अभी इनको जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी, तब दे देंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्य सरकार के किस आदेश से एड ली, जब मन्त्रिमण्डल ने निर्णय ले लिया था।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मुद्दा यह है, क्या जांच करवायेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने निवेदन किया है, इसकी सारी जानकारी सदन को दूंगा। जो कानून वर्तमान में है उसके अन्तर्गत क्या किया जा सकता है, वह करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई जांच का मुद्दा होगा, जांच भी करायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने हनुमानगढ़ की एड बन्द कर रखी है, वहां की बन्द क्यों नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार केवल यही उत्तरदायित्व मानती है। स्कूल खुल जाये, काम समाप्त हो जाये। जिस कारण से सारा झगड़ा शुरू हुआ था। क्या वे जो सारी कमियां थीं उनकी पूर्ति आपने कर ली और इस कारण से ऐड रिलीज की या सारी अनियमिततायें जिनके बारे में डेढ़ वर्ष से प्रयत्न किया जा रहा है वे अनियमिततायें दूर हो गई ?

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या मोहनसिंह मेहता से यह अन्डरटेकिंग ली कि दो प्राध्यापकों को रखा जायेगा ? उन्होंने एड भी ले ली। सरकार को बेवकूफ बनाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सम्पूर्ण विषय पर मैं निश्चित रूप से हाउस को जानकारी दूंगा।

एक माननीय सदस्य : कब देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यथा शीघ्र दूंगा। जो आदेश सरकार ने दिये हैं उसकी पालना करवाई जायेगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल दो मिनट दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, भारत के 13 राज्यों की विधान सभाओं में एक्ट बन चुका है प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए। किन्तु राजस्थान के अन्दर 30 वर्षों में कोई एक्ट नहीं बना और इन दो वर्षों के अन्दर भी कोई एक्ट नहीं बना। अध्यक्ष महोदय, इसी कारण प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राजस्थान विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले शिक्षा मन्त्री ने यू. जी. सी. के वेतनमान राजस्थान के अन्दर लागू किये। पिछले सत्र में और इस सत्र में भी मैंने निवेदन किया था कि अभी भी तीन फैकल्टीज ऐसी हैं जहां यह लागू नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर फैकल्टी में लागू नहीं हुआ, बी. एड. में लागू नहीं हुआ है संस्कृत के अन्दर लागू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यू. जी. सी.

(श्री कौशल किशोर जैन)

ने सिफारिश की थी 1.1.73 से लागू किया जाये किन्तु शिक्षा मन्त्री ने 1-9-76 से लागू किया। तीन साल का केन्द्र से भुगतान क्यों नहीं लिया गया? यू. जी. सी. 80% एड देती है। आपको 20% देनी पड़ती है। शिक्षा मन्त्री महोदय, आपने व्यवस्था नहीं की। 3 साल के अन्दर जितना और मिलता वह आपने छोड़ दिया। 80 प्रतिशत अनुदान छोड़ दी। आप 20 प्रतिशत की व्यवस्था नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी काम करते हैं। लालबहादुर शास्त्री कालेज और इसी प्रकार की जितनी संस्थायें हैं उनमें काम करनेवाले कर्मचारियों को सेवा की गारण्टी दी जाये। यू.जी.सी. के वेतनमान दिये जायें। शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, नियंत्रण की व्यवस्था कीजिए। राज्य सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। जो ऐडेड संस्थाओं में काम करते हैं उनको नौकरी की सुविधायें मिलें। दो साल में कितने कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं शीघ्र ही इस विधान सभा के अन्दर सरकार बिल लेकर आये, जिस प्रकार भारत की अन्य 13 विधान सभाओं में बिल आया है ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा विधेयक का सवाल है, इसमें राज्य सरकार ने चिन्तन किया है और इसका प्रारूप तैयार हो गया है और इस समय यह मन्त्रिमण्डल के विचाराधीन है। वहां से क्लीयर होने के बाद विधान सभा में आ जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या इसी सत्र में रख देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उम्मीद है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के कारनामें पेश करना चाहता हूं। केवल एक मिनट में। दो मिनट नहीं लूंगा। उदयपुर विश्व विद्यालय में जो व्याख्याता के पद हैं उनका इण्टरव्यू होने जा रहा है। सारी यूनिवर्सिटी एडहाक है। वाईस चांसलर एडहाक, डाइरेक्टर, डीन एडहाक। डाइरेक्टर पदोन्नति की चयन समिति का सदस्य है उस पर मुन्सिफ कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। वह कमेटी में बैठता है तो जो चयन होगा, अनियमित होगा। अगर नहीं बैठता है तो वह समिति पूरी नहीं होती है। कई तार आ रहे हैं। शिक्षा मन्त्री से मिला। यह उत्तर मिला कि 11 हजार रुपये का नुकसान हो जायेगा। वाईस चांसलर की गार्ड पर 40 हजार रुपया आपने एस. पी. को सुपुर्द किया। वाईस चांसलर की गार्ड के लिए 40 हजार रुपया खर्च कर सकते हैं, जो कल कोर्ट में चैलेन्ज होगा उनको आप क्यों नहीं रोकते हैं ? सारी यूनिवर्सिटी एडहाक। वाईस चांसलर का पैनल में नाम नहीं। वह निश्चित रूप से 5-7 दिनों में जाने वाला है। ऐसा आदमी 200 नियुक्तियां कर रहा है। इसमें हजारों, लाखों रुपया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकर घर भरना चाहता है। इस भ्रष्टाचार को रोकिये !

श्री मूलचन्द डागा : वाइस चांसलर को अधिकार नहीं है। नियम बने हुए हैं। उसमें कमेटी बैठती है जो चयन करती है। अगर वह करता है तो गलत होगा और आप उस पर गौर फर्मायें, उसको रोकें क्योंकि एक कमेटी होती है और वह कमेटी ही नियुक्ति करती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री कटारिया जी ने जो सवाल उठाया है वह बिल्कुल उचित है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक मात्र तो उदयपुर यूनिवर्सिटी है और उसकी सरकार ने क्या दुर्गति की है। वहां के जो वाईस चांसलर लाम्बा साहब थे उनको मारपीट कर आपने भगाया है और उसके स्थान पर आपने एक एडहाक वाईस चांसलर बिठाया है तो क्या आपका इस युनिवर्सिटी को खतम करने का प्लान है तो ऐसा बता दीजिए। कोई लड़के वहां पढ़ नहीं सकते, लड़के मारे फिरते हैं और हमारे पास वो पिछले साल छिप कर एडजार्नमेंट मोशन मूव कराने के लिए भी आये थे। शिक्षा मन्त्री जी क्या जवाब देते हैं, बतायें ?

(व्यवधान)

आपके अन्दर में उदयपुर विश्वविद्यालय आ गई है क्या ? मेरे ख्याल से नहीं है। मामला आपने उठाया है लेकिन मैं समझता हूं सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है।

श्री टीकमचन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, सारे सदन की इच्छा है कि गलत नियुक्तियां नहीं होनी चाहिये तो क्यों नहीं आज ही इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं कि ये नियुक्तियां रोकी जायं।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी को निर्देश दीजिए।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का उत्तर सुन लीजिए, फिर चर्चा समाप्त होगी।

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी में जो चयन हो रहा है, उसके बारे में यहां चर्चा की गई है। जैसा माननीय सदस्य डागा जी ने कहा वाईस चांसलर अकेला कोई नियुक्ति नहीं करता है, उसके लिए सलेक्शन कमेटी होती है और जो सलेक्शन हो रहा है यह उसी के द्वारा हो रहा है। माननीय सदस्य श्री कटारिया जी ने एक मुद्दा उठाया है कि उस कमेटी में एक ऐसे सदस्य हैं जिनको मुन्सिफ कोर्ट

(श्री भंवरलाल शर्मा)

द्वारा स्टे मिला हुआ है, यह मेरी जानकारी में नहीं है। अगर स्टे मिला हुआ है तो निश्चित रूप से वे उस कमेटी में नहीं बैठ सकते हैं और अगर बैठेंगे तो न्यायालय की मान हानि होगी। मैं समझता हूं यह केवल सरकार का विषय नहीं है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा इस सदन के 2 या 3 माननीय सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर दें और वह जो फैसला करेगी, उसको देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त नहीं होगी, माननीय सदस्य अब कोई चर्चा इस विषय में नहीं होगी। अनुदानों की मांगों पर ...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, के. के. महर्षी हैं जिनको मुन्सिफ कोर्ट द्वारा स्टे मिला हुआ है। वे चयन समिति के सदस्य हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा जब यह विषय आ गया है और गहन है तो निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिये। विरोधी दल के नेता माननीय परस राम जी मदेरणा भी यहां विराजमान हैं वे हमारी मदद करें और आज ही कोई निपटारा कर दें। जो कानून और व्यवस्था में होगा, उसे अवश्य करेंगे। इस विषय को निपटाने के लिए विरोधी दल के नेता महोदय भी यहां बैठे हैं, भूतपूर्व दो-दो शिक्षा मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं जो भी कोई निर्णय करें, मुझे बता दें।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, विरोधी दल के नेता और भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री इस विषय में क्या करेंगे। वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी को निर्णय लेना है। आप इसके औचित्य के बारे में सरकार को अवगत करायें। माननीय मन्त्री जी ने जो उद्विग्नता जाहिर की है और जो एम्फेसिस दिया है, जोर डाला है उससे आप कंविन्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, यह तो आपको ही देखना है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सहयोग करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। It is not a political issue.

श्री परसराम मदेरणा : सहयोग करना हमारा औचित्य भी है और कर्तव्य भी, लेकिन उस सहयोग के नाम पर माननीय सदस्यों ने जो कुछ सुझाव दिया है और जो तथ्यपूर्ण बातें रखी हैं उन पर आपने क्या माइन्ड अप्लाई किया है, एक बात। दूसरी बात जो माइन्ड अप्लाई किया है, उससे आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और तीसरी बात उस निष्कर्ष से आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं। निर्णय नहीं लेना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, जो रुख शिक्षा मन्त्री जी ने अख्तियार किया है वह एक होशियारी और चतुराई से जो विकल्प करने का प्रोसीजर अडाप्ट किया है, प्रक्रिया तो निश्चित रूप से अच्छी है, क्योंकि जिस तरह का सम्मान दे रहे हैं सदन को और विरोधी दलों के प्रति जो उदारता दिखाई है। यह नई चीज पैदा हुई है उसके लिए तो मैं शुक्र

(श्री परसराम मदेरणा)

गुजार हूं लेकिन आपके सदस्यों की जो न्याय पूर्ण मांग है और समय के अनुसार है वह तो समय पर ही हो जानी चाहिये, अन्यथा अपाइन्टमेंट हो जाय फिर क्या निर्णय होगा, इसलिए निर्णय आज ही कीजिये।

श्री मदन सिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन....

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय मन्त्री जी आप बहुत उदार है, बस अब बहुत हो गया।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं दूसरी इनफार्मेशन देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय यह नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : X X X

श्री अध्यक्ष : जैसा अभी माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कहा कि जो कुछ तथ्य रखे हैं सदन में वे गंभीर हैं। सरकार आपकी है और सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और उसका निराकरण निकालेगी, अगर स्वयं निराकरण नहीं निकालते तो आपके सबके सहयोग से निकालेगी लेकिन इस तरह के हाइपोथेटिक क्वेश्चन से क्या फायदा है, सदन का बहुमूल्य समय है माननीय सदस्य गण।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

राज्य सरकार की मद्य निषेध नीति

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में हमारी ओर से शराब बन्दी 1 अप्रैल, 1979 से लागू करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा गया है।

(व्यवधान)

109 सदस्यों ने मेमोरेन्डम मुख्य मन्त्री जी को इस बारे में पेश किया है और यदि इस पर कोई व्यवस्था नहीं दी गई तो हम सरकार को सहयोग देना बन्द कर देंगे। ऐसा उन्होंने कहा है इसमें ज्यादातर सदस्य जनता पार्टी के हैं। और राजस्थान में एक तरह का क्राइसस पैदा हो जायगा। इसलिये मैं चाहूंगा गोकुल भाई, माननीय मास्टर जी और मेहता साहब अब अनशन पर बैठने वाले हैं, ऐसी स्थिति में यह सरकार गिर जायगी तो एक अनिश्चितता का वातावरण राजस्थान में बन जायेगा। और जो कुछ नहीं होने वाला है, वह हो जायेगा। स्पष्ट है मास्टर जी ने कहा है दो दिन में शराब बन्दी की घोषणा कर दूंगा, दो दिन हो गये, फिर दो दिन के कहने के बाद केबिनेट की मीटिंग दो दिन चली और अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। जनता पार्टी के बहुत

X X X अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सारे माननीय सदस्य भी इसमें आ गये हैं। अब यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि शीघ्र ही इसकी कोई घोषणा हो जानी चाहिये। अभी जीरो आवर दो बजे तक का है, ये मास्टर जी भी उसमें अनशन करने वाले हैं इसलिए दाल में कुछ काला है सरकार को इस अनिश्चितता को खतम करने के लिए एक वक्तव्य इसके बारे में देना चाहिये। तो इसलिए यह क्या मसला है, राज्य सरकार का क्या मानस है, यह बतायें। मैं चाहूंगा कि आप या तो समय रख कर सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलायें, यह अन-इम्पोरटेंट क्वेश्चन नहीं है। यह गोकुल भाई भट्ट महान नेता हैं, वे बराबर कह रहे हैं कि मैं इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं आमरण अनशन करुंगा और उन्होंने सरकार की सारी बातें ठुकरा दी हैं। मास्टर जी ने कहा है कि मैं भी भूख हड़ताल करूंगा और मनोहरसिंह जी मेहता ने तो कह ही दिया है कि वे आमरण अनशन करेंगे। इसलिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो बहुत चिंताजनक बात है। आप सरकार से पूछें कि आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप सदन को स्थगित करके एक समय निर्धारित कर हमको बहस करने का मौका दें, विरोधी पक्ष को बहस करने के लिए दो तीन घण्टे का समय निर्धारित कर दीजिए ताकि यह सारा अनिश्चितता का वातावरण खतम हो जावे। यह सारी स्थिति रहने से लोगों में कटुता फैल रही है, और ज्यादा कटुता नहीं फैले इसलिए यह बहुत जरुरी है कि सरकार शीघ्र एक वक्तव्य दें।

श्री भंवरलाल ऐरन : क्या आप केबिनेट की मीटिंग में मौजूद थे ? किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : हमारे में ज्ञान है बात को जानने का····

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : 1 अप्रैल से शराबबन्दी हो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसीलिए वित्त मन्त्री जी ने भी यह कहा था कि एक दो दिन में निर्णय हो जावेगा। यह साफ बता दें कि शराबबन्दी 1 अप्रैल से कर रहे हैं या नहीं। इसका स्पष्ट जवाब आ जाना चाहिए। शराबबन्दी 1 अप्रैल से नहीं हुई तो गोकुल भाई और कई माननीय सदस्य आमरण अनशन करेंगे, हम लोग भी साथ देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय वित्त मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था अपने भाषण में कि यह सारी बात एक दो दिन में मालूम हो जावेगी। आज तीसरा दिन है इसलिए जो उन्होंने आश्वासन दिया था, सदन को बतायें कि उनका निर्णय क्या है ? उन्होंने खुद ने आश्वासन दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, और चर्चा न करें। माननीय माथुर साहब, अगर सदन का समय बर्बाद ही हो तो बात दूसरी है वरना कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण करें ! अभी तो 1 अप्रैल दूर है।

श्री अब्दुल अजीज : आल इण्डिया रेडियो से समाचार प्रसारित हुआ है कि 103 सदस्यों ने....

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप इसको भी चलाओ और उसको भी चलाओ जैसी आपकी मर्जी।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अभी 1 तारीख बहुत दूर है। कल को भूख हड़ताल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही सरकार से जानना चाहता हूं, यह सरकार का दायित्व है, उनकी जवाबदारी है कि प्रोहिबिशन करें, नहीं करें, कुछ भी करें। हर रोज अखबारों में हम खबरें पढ़ते हैं। अखबारों में यह खबर आ रही है कि बराबर केबिनेट की मीटिंगें हो रही है इस शराबबन्दी के प्रश्न को लेकर और सरकार शीघ्र ही निर्णय करेगी। हम इस सदन के माननीय सदस्य इस बात को जानने के इच्छुक हैं कि इस वातावरण में राज्य सरकार का क्या फैसला हुआ। माननीय वित्त मन्त्री जी ने दो दिन में फैसला करने के लिए कहा था उसके बाद....

श्री भंवरलाल ऐरन : एक दो दिन के लिए कहा था।

श्री मथुरादास माथुर : आज चार पांच दिन हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, उनका भाषण भी सुना....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको परमिट मिलेगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार तरफ से इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आये। जो कुछ भी करना हो, करें। लेकिन कोई स्टेटमेंट तो आए ताकि समस्या समाप्त हो जावे। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि प्रोहिबिशन हो।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी कहा गया है स्टेटमेंट दिए जाने के सम्बन्ध में....

श्री नवरंगसिंह (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी कुछ कहें उसके पहले एक मिनिट में मैं अर्ज कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज ही दैनिक नवज्योति में एक खबर छपी है और उस खबर में यह कहा गया है कि सत्ता का दुरुपयोग कर विधायकों को लालच देकर प्रति हस्ताक्षर कराने की सरकारी नेताओं की नीति की भर्त्सना की है।

अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि हमारा राजस्थान का मन्त्रिमण्डल जब से मास्टर आदित्येन्द्रजी ने यह घोषणा की है कि एक दो दिन में इस बात की घोषणा कर

(श्री नवरंगसिंह)

देंगे तभी से राजस्थान का तमाम मंत्रिमंडल विधायकों के जबर्दस्ती हस्ताक्षर अभियान में लगा हुआ है और इसलिए....

श्री मदनसिंह दांता : They are not school boys ये स्कूल के लड़के हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह दवाव की राजनीति है, यह भ्रष्टाचार की राजनीति है, यह दबाब की राजनीति है । यह लोकतांत्रिक तरीके में तानाशाही प्रवृत्ति है....

श्री अब्दुल अजीज : जिन लोगों से जबर्दस्ती दस्तखत कराये हैं....

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के 109 माननीय विधायकों ने जिनमें 79 विधायक जनता पार्टी के हैं और 30 विधायक विपक्ष के हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम 10 मार्च, 1979 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दिया था । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन 109 विधायकों को दबाकर मंत्रिमण्डल ने जबर्दस्ती रेडियो द्वारा प्रचार करवाया है कि उन्होंने प्रति हस्ताक्षर किए हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल पर क्योंकि राजस्थान विधान सभा के बहुमत सदस्यों ने, 109 सदस्यों ने यह लिख कर दे दिया है और मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं कि क्या लिखा है :

"1 अप्रैल, 1979 से राजस्थान में पूर्ण शराबबन्दी के लिए सर्वोदयी तपस्वी नेता, श्री गोकुलभाई भट्ट ने आमरण अनशन की घोषणा की है । हमें समाचार पत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि आपने राजस्थान के विकास कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए 1 अप्रैल, 1979 से पूर्ण शराबबन्दी करने में असमर्थता प्रकट की है ।

इस प्रश्न पर हमने गम्भीरता पूर्वक विचार किया है और हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि 1 अप्रैल, 1979 से पूर्ण शराब बन्दी राजस्थान के हित में है । यह भी मान लिया जाए कि शराब बन्दी से आबकारी आय की क्षति होगी परन्तु इस बात को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि अधिकतर गरीब वर्ग की जेब से शराब पर खर्च होने वाली 1 अरब से ऊपर की धन राशि की भी बचत होगी, जिसका उपयोग जनता अपने तथा प्रदेश के विकास कार्यों में करेगी । इसके अतिरिक्त पूर्ण शराब बन्दी से अपराध वृत्ति व दुर्घटनायें कम होने से करोड़ों रुपये की जो बचत होगी उसे भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है । श्रमिक वर्ग शराब मुक्त होने से विशेष उत्पादन कार्य कर सकेगा । हमारी मान्यता है कि शराब बन्दी भी एक प्रकार से उत्कृष्ट अन्त्योदय योजना है । इसके अलावा यह बात भी आपके ध्यान में होगी कि सरकार के अनेक विभागों में होने वाली फिजूलखर्ची को रोक कर काफी धन की बचत की जा सकती है और यातायात, बिजली तथा सिंचाई की

(श्री नवरंग सिंह)

आय में की जाने वाली संगठित चोरी को रोक, आय बढ़ाई जा सकती है। शराबबंदी के लिए केन्द्रीय सरकार से 50 प्रतिशत मदद मिलने ही वाली है। ताजा समाचार से जैसा कि अभी विदित हुआ है, राज्य के आबकारी मन्त्री महोदय ने केन्द्रीय उप प्रधान मन्त्री, श्री चरणसिंह जी से इस विषय में विचार विमर्श किया है और जैसा उनका निर्णय रहा है उससे तो शराबबन्दी करने में और भी आसानी होगी। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार जनता से ऋण भी ले सकती है। हमारी यह दृढ़ मान्यता है कि शराबबन्दी के लिए केवल दृढ़ निश्चय ही आवश्यक है। धनाभाव की उसमें कोई बाधा महत्व नहीं रखती।"

अतः इन सब विधायकों ने यह लिखकर दिया है कि राजस्थान में 1 अप्रेल, 79 से शराबबन्दी कर दी जावे क्योंकि राजस्थान के महामहिम और राजस्थान के वयोवृद्ध नेता गोकुल भाई भट्ट ने यह आमरण अनशन की प्रतिज्ञा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, से और मन्त्रि मण्डल से और राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के और भी विधायकों से मन्त्रियों ने खुद जा जाकर प्रति हस्ताक्षर कराये हैं। और चूंकि मास्टर आदित्येन्द्र जी ने कहा था कि एक दो दिन में इस बारे में निर्णय हो जाएगा और भारत के उप प्रधान मन्त्री और प्रधान मंत्री ने यह कह दिया है कि राजस्थान के अन्दर शराब बन्दी होनी चाहिये। इसलिये सरकार का इसके बारे में स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के रूप में कोई माननीय मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें। यह जो अखबारों में छपा है और जो कुछ आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया है, क्या यह सही है या नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि मुझे आज ही माननीय सदस्य, भवानीसिंह जी, एम. एल. ए. ने मुझे बताया कि मेरे पास पांच-पांच मिनिस्टर कार लेकर आये कि आपको दस्तखत करने हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार दस्तखत कर दिए तो फिर दुबारा दस्तखत नहीं करूंगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वस्तुःस्थिति के बारे में उत्तर दे और गोकुल भाई भट्ट ने जो प्रतिज्ञा की है, उसके बारे में स्टेटमेंट दें।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : एक नेता जो अस्पताल में पड़ा है, जे. पी. अस्पताल में है, उनकी चिन्ताजनक हालत है जिन्होंने यह कहा है कि इस मसले को जल्दी से मत निपटाइये। उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी चिन्ताजनक हालत है....

(व्यवधान)

राजस्थान की तीन करोड़ जनता शराब बन्दी की इच्छुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो चर्चा हो रही है वह नियमों के विपरीत हो रही है। आपकी भावना है तो मैं इससे इन्कार नहीं करता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस सदन में एक अहम सवाल उठाया है। प्रजातन्त्र में मन्त्री मण्डल एक जोइन्ट रेस्पांसिबिलिटी के सिद्धांत पर कार्य करता है और आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मन्त्री मण्डल के सदस्यों द्वारा मन्त्री मण्डल में विचारणीय विषयों को आउट नहीं किया जा सकता है परन्तु इस मन्त्री मण्डल के सदस्यों द्वारा राजकीय कार में गए और राजकीय कार में माननीय सदस्यों को ले जाकर दस्तखत करवाये गये, इस अभियान पर कि वे राज्य में शराबबन्दी नहीं चाहते हैं। मन्त्री मण्डल में इस विषय पर विचार-विमर्श हो रहा है, जो कि सीक्रेट है। इस प्रकार से मन्त्री मण्डल की सीक्रेसी आउट की गई है। आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मंत्री मण्डल में डिसकस हुए किसी विषय की सूचना कोई मन्त्री नहीं दे सकता है। मंत्री मण्डल ने शराबबन्दी पर विचार-विमर्श किया है और मुख्य मन्त्री इसके स्पोक्स मेन हैं तब कोई मन्त्री इस प्रकार के अभियान में भाग नहीं ले सकता परन्तु मन्त्री मण्डल में भी कुछ विशेष मन्त्रियों का एक ग्रुप है, एक घटक है, वह घटक हिन्दू परम्पराओं की बात करता है, वे जनसंघ मन्त्री इस बारे में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने माननीय सदस्यों से इस पर दस्तखत कराये हैं। इस प्रकार उन्होंने मन्त्री मन्डल की गोपनीयता को भंग किया है। मन्त्री मण्डल की जोइन्ट रेसपांसिबिलिटी को नहीं निभाया है उसको भंग किया और एक प्रकार से हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था का उल्लंघन किया है, हनन किया है इसलिए इन सारे मन्त्रियों को त्याग पत्र देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पहले एक बात यह आई थी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण से आदरणीय गोकुल भाई भट्ट को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि वह अपना अनशन त्याग दें। अध्यक्ष महोदय' मैं आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह धोखा है। माननीय लोकनायक से ऐसा पत्र श्री गोकुल भाई भट्ट को धोखे से लिखवाया जाकर भेजा है। माननीय गोकुल भाई ने स्पष्ट रूप से लोकनायक को यह लिख दिया है कि वे अपने निश्चय पर दृढ़ हैं और एक अप्रैल, 1979 से नशाबन्दी नहीं हुई तो वे अनशन पर बैठेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री मण्डल के सदस्यों ने यह जो अभियान चलाया है, हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर का नशाबन्दी के सम्बन्ध में यह अभियान निन्दनीय है और उन्हें इस प्रकार की घृणित कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

श्री मदन सिंह दांता : यह जे. पी. का अपमान है। क्या धोखा दिया गया ? जे. पी. को कौन धोखा दे सकता है ?

श्री रघुनंदन व्यास । क्या श्री सिद्धराज ढढ्ढा जो चिट्ठी लाये हैं, वह धोखा है, जैसा माननीय भंवरलाल जी ने कहा है ?

श्री भंवरलाल : इसलिये तो पत्र का उत्तर स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित रूप से गोकुलभाई एक अप्रैल से अनशन पर बैठेंगे। यह स्पष्ट कर दिया है।

Page No. 83

83

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : सत्याग्रह करेंगे, अनशन पर बैठे जायेंगे तो क्या हो जायेगा। प्रजातंत्र में ऐसा होता रहता है। पहले से ही क्यों यह हल्ला मचाया जा रहा है। भूख हड़ताल करेंगे तो हम भी मदद करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग की डिमाण्ड पर डिस्कशन हुये अभी 24 घण्टे ही नहीं हुए हैं कि अभी इस सदन में नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उस सूचना से सारा सदन स्तब्ध रह गया है। इसलिये स्तब्ध रह गया है... (व्यवधान).... आप धैर्य रखिये। धैर्य से मेरी बात को सुनिए। शेक्सपीयर ने कहा है : वह आदमी कितना निर्लज्ज है जो किसी आदमी की बात सुनने का धैर्य नहीं रखता है।

श्री माणक चन्द सुराणा : अब आपको शेक्सपीयर पढ़ने का अवसर मिल जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ता तो मैं शेक्सपीयर हूं पर क्रियान्वित करता हूं गांधी जी के सिद्धान्तों को।

श्री राम रघुनाथ विश्नोई : आपको सुनने की क्षमता रखनी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने मद्य निषेध लागू करने के लिये दस्तखत किए हैं, उन पर दवाब डाल कर उसके विरोध में हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं। इससे अध्यक्ष महोदय, आपकी और मेरी प्रतिष्ठा भी मटियामेट हुई है। यह जो ब्रूट मेजोरिटी है, यह उनके सोचने की बात है। इसके साथ ही इस सदन में यह तथ्य प्रकट किया गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी का जो मन्त्रिमण्डल है, उसके माननीय सदस्य, सदन के माननीय सदस्यों पर दवाब डालकर दस्तखत करा रहे हैं कि मद्यनिषेध लागू नहीं होना चाहिये। मन्त्री गण यह जो दवाव डाल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय यह प्रजातन्त्र के लिये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिये एक जबर्दस्त खतरा है और यह अधिनायकवाद की पराकाष्ठा है, अध्यक्ष महोदय, आपके शब्दों में। अध्यक्ष महोदय, इस देश में जैसी कि चर्चा चल रही है पोलोराइजेशन होगा, समीकरण होगा और राजनीतिक ताकतों का समीकरण होकर रहेगा परंतु इस वक्त एक घटक जायज, नाजायज तरीकों से पार्लियामेंट्री वेल्यूज को वलाए ताक पर रख कर इस तरह से अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों पर अनुचित दवाब डाल रहा है, यह प्रजातन्त्र के लिए, पार्लियामेंट्री वेल्यूज के लिए जबरदस्त खतरा हो गया है। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है माननीय सदस्यों का। आप उनके उपर दवाब नहीं डाल सकते हैं। आबकारी विभाग की डिमाण्ड पास किए हुए अभी चौबीस घण्टे हुए हैं, उसके बाद दवाब डालने की यह स्थिति पैदा हो गई है। तो यह सदन के सोचने की बात है, यह एक अहम विषय बन गया है। हमने अखबारों में पढ़ा था कि जयप्रकाश नारायण इस मामले में इन्टरवीन कर रहे हैं परन्तु जयप्रकाश जी के अस्वस्थ होने की वजह से एक घटक के लोग, सदस्य इस तरह दवाव डाल रहे हैं, दबाव डालने की उन्होंने जो हिमाकत की है, वह हिमाकत लोकतन्त्रीय मूल्यों, इस्टेब्लिस्ड सिद्धान्त, मानदण्ड के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक डेन्जर है, खतरा है। इसलिए इस खतरे

(श्री परसराम मदेरणा)

की जो घंटी बजी है, इसको अगर दबाया नहीं गया तो हो सकता है कि यह प्रवृत्ति आगे फैले और फैल करके यह विशाल रूप धारण करे। जो अंकुर फूटा है, उसे उसी जगह समाप्त करना चाहिए क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मापदण्ड है, जो हमारी वेल्यूज है, उसके आप रक्षक हैं। इसके साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्य, जो लोकतन्त्रीय वेल्यूज में विश्वास रखते हैं, को भी निडर होकर अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करनी चाहिए। यह घटकवाद अब अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है।

श्री मदनसिंह दांता : सुखाड़िया जी ने हमारे गले घोंटे हैं। गला घोंट कर होटल में ले जाकर हम को दबाया गया है। उस वक्त प्रजातन्त्र नहीं था? थोड़े से आदमियों को समझा दिया तो आज हम को शिक्षा दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : गुंडागिर्दी से आप पांच साल तक क्यों दबे रहे?

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना चाहता हूं ....

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1-2 सदस्यों के लिए........

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : आज अखबारों में छपा है। मेरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : आपकी आज्ञा से ही रखी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से ही एक प्रति सदन की मेज पर रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है। प्रति सदन की मेज पर रखी जा सकती है, लेकिन कह कर रखी जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जनता पार्टी के माननीय सदस्य, का नाम आप कहें तो आपके कक्ष में आकर बतलाऊंगा, उस जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा........

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रति सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : प्रति आ गई, अब आप काहे को बोल रहे हैं।

श्री शंकरलाल : जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने मुझे कहा कि यह कह कर दस्तखत कराये जा रहे हैं कि शराबबन्दी हो, मैंने दो बार दस्तखत कर दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं आपके

(श्री शंकर लाल)

कक्ष में आकर पेश कर दूंगा। ये लोग इस प्रकार जनता पार्टी के अन्दर कभी कुछ और कभी कुछ कराते हैं।

(व्यवधान)

इस प्रकार माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन, विशेषाधिकारों का हनन हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दें।

श्री अब्दुल अजीज : दस्तखत कराते हुए देखा है, दबाते हुए देखा है।

श्री माधोसिंह कछवाह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। यह जो चर्चा चल रही है यह आबकारी से सम्बन्धित है और इस विषय पर आलरेडी डिमाण्ड पर बात हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री लालचन्द (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, आज रेडियो पर खबर सुनी कि राजस्थान में शराबबन्दी न हो इस बात पर राजस्थान के करीब सौ विधायकों ने दस्तखत किये हैं। यह बात सुन कर इतना अचम्भा, इतना दुःख हुआ कि हमारी प्रजातांत्रिक वेल्यूज किस प्रकार से कायम रहेंगी। मेरे पास माननीय सदस्य मनीराम जी बैठे थे उनके पास आकर कहते हैं कि हम आपसे इसलिए दस्तखत करवा रहे हैं कि शराबबन्दी जल्दी हो जब कि वास्तविकता कुछ और ही है। यह बात कौन कर रहे हैं? वे लोग जो कहते हैं कि हमें राष्ट्र का चरित्र निर्माण करना है, हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। वे ही लोग शराबबन्दी न हो इस बात के लिए दस्तखत करावें, ऐसे लोग, अध्यक्ष महोदय, जब अपने उसूलों के खिलाफ काम करें तो एक शक पैदा होता है कि क्या इन लोगों को लालच तो नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। इस पर बड़ी गम्भीरता से, बड़ी समझदारी से विचार करना चाहिए। शराबबन्दी के मामले में ऐसा माहौल बन गया है........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इस सामाजिक बुराई को खतम करना है। राष्ट्रीय स्तर के नेता गोकुल भाई भट्ट बैठे हैं जब अनशन पर, और सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी जब कह दिया है कि आर्थिक नुकसान को हम पूरा कर देंगे उसके बाद भी बुराई को खत्म न करें तो यह बड़ी बुरी बात है।

श्री मदनसिंह दांता : A man has got his right to change his mind.

यह यहां भी आ सकता है। वहां भी आ सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : आप जानने तो हैं नहीं....

श्री मदनसिंह दांता : Who were you ?

(श्री मदनसिंह दांता)

आप कौन थे जो हमें सलाह दे रहे थे।

श्री परसराम मदेरणा : Whye ar you encroaching the others' right ? you have no right to rebuke others.

आप इस प्रकार खड़े होकर कहते हो, फिर तो हर वक्ता खड़ा हो जायगा।

श्री मदनसिंह दांता : I have got right to speak as you have got.

(व्यवधान)

He is the man who can rebuke me, not anybody else. वे हमें कहेंगे तभी ...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। सरकार की मंशा बराबर शराबबन्दी करने की रही है। लेकिन न मालूम एक ओर तो घोषणा नहीं की जा रही, दूसरी ओर यह कहा गया कि केबिनेट इस पक्ष में नहीं है तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि हम शराबबन्दी कर देंगे। अगर कुछ परेशानी है तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि शराबबन्दी नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

गोकुल भाई बैठे हुये हैं। हम लोग उत्सुक हैं कि निर्णय लिया जायेगा क्योंकि यह जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों में हैं। हम लोगों की इच्छा है कि सरकार इसको लागू करे। जब सरकार लागू करना नहीं चाहती है तो फिर ऐसी सरकार बनाने की क्या जरूरत थी। हम यह चाहते हैं कि जो कुछ जनता को कहा गया है उसको करो। फिर मैं समझती हूं, विधायकों का मानसिक स्तर इस प्रकार से गिराने का जिन्होंने कार्य कराया है, यह सरासर निंदनीय है।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, यह शराबबन्दी का प्रश्न इस बजट सत्र के साथ ही इस हाउस में चल रहा है और किसी न किसी रूप में ...

श्री अध्यक्ष : आप इसको समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : दो मिनट, अध्यक्ष महोदय।

किसी न किसी रूप में सदन में यह विषय चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब जब यह प्रश्न खड़ा हुआ तभी चाहे इधर के हों या उधर के माननीय सदस्य, सभी ने कमोबेश रूप से पुरजोर शब्दों में मांग की है कि राजस्थान के भविष्य के निर्माण के लिए और एक अच्छी शुरुआत करने के लिए शराबबन्दी जल्दी से जल्दी प्रदेश में लागू हो। इस सदन में और इस सदन के बाहर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे प्रदेश की जनता यह मांग कर रही है कि यह शुभ शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी भावनाओं के बावजूद चाहे

(श्री गोपालसिंह)

तो मन्त्रिमण्डल इन सारी राजस्थान की जनता की भावनाओं को ठुकराकर कोई दूसरा निर्णय करे, लेकिन कोई निर्णय तो करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता और यह सदन और उसके माननीय सदस्यों का बहुमत इस राय का है कि यह अच्छी शुरुआत जल्दी हो। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य अपने स्वतन्त्र विचार की बातों को लेकर सदन में कहना चाहते हैं और कहने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकें और हमारी सरकार के प्रतिनिधि हमारे माननीय सदस्यों के पास एक-एक नहीं एक-एक माननीय सदस्य के पास 5-5 और 7-7 मन्त्रिमण्डल के सदस्य जायं और कहें कि शराबबन्दी आंदोलन के खिलाफ दस्तखत करो, यह सबके लिये बड़े शर्म की बात है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इनको जो भी निर्णय लेना हो वह निर्णय सरकार जल्दी करे। वह चाहे माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठुकरायें या प्रांत की आम जनता की भावनाओं को ठुकरायें, इस बारे में स्पष्ट नीति रखें। जब तक नहीं रखेंगे कि कौन कौन क्या बातें कर रहे हैं और कहां कहां क्या बातें हो रही हैं वह कही जायेंगी। यह भी कहा जा रहा है कि शराब के ठेकेदारों से बहुत बड़ा धन इकट्ठा किया गया....

(व्यवधान)

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: कहना चाहता हूं कि यह जनता पार्टी की सरकार जो भी उचित समझे, जो भी ठीक समझे वह निर्णय लेकर जल्दी सदन में रखे।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में यह बात कहना चाहता हूं....

श्री माणकचंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जो आरोप सदन में....

श्री मूलचंद डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो इस बात का उत्तर सदन के नेता दे सकते हैं या सदन के नेता ने जिनको नोमीनेट किया है वह उत्तर दे सकते हैं, otherwise no body can answer. यह सदन के नेता का सवाल है, यह सारे सदन का अपमान कर रहे हैं कि नेता महोदय उपस्थित नहीं हैं। यह नेता महोदय का कर्त्तव्य है कि ऐसे मामलों में वह उत्तर दें। वह चुप रहें और कोई दूसरा उत्तर दे। मैंने कई बार देखा है कि सदन के नेता सदन का अपमान करते हैं और सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। सदन के नेता को सदन में उपस्थित रहना चाहिए।

श्री रघुनंदन व्यास : आन एक पाइंट आफ आर्डर। डागा जी किस कानून के अन्तर्गत, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के किस नियम के आधार पर खड़े हुए हैं ? अपनी मर्जी से जब कभी चाहे खड़े होकर राजस्थान, सरकार के मन्त्रियों का इस ढंग से अपमान करने की

(श्री रघुनन्दन व्यास)
जुर्रत करते हैं वह प्रशोभनीय है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनको ताड़ना दी जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह कोई अपमान नहीं है....

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो कहा गया है मंत्रियों ने जा जाकर मद्य निषेध के विरोध में माननीय सदस्यों से दस्तखत कराये हैं, यह झूठ है। मैं खुद गवर्नमेंट होस्टल में रहता हूं मेरे पास कोई मन्त्री नहीं आया है। माननीय सदस्य आये थे मैंने भी साइन किए है।

श्री मूलचन्द डागा : आप नींद में होंगे।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : उसमें यह साफ लिखा हुआ था कि मद्य निषेध 2 अक्टूबर 1980 से किया जाय।

(व्यवधान)

श्री मनीराम (तारानगर) : मंत्रि-मण्डल के माननीय सदस्य आये और हमको यह कहा गया कि हम दस्तखत करें। मैंने जवाब में कहा कि मैंने पहले ही दस्तखत कर दिये शराबबन्दी के लिए, दुबारा कैसे करूं। उन्होंने कहा कि यह बात नहीं है हम भी चाहते हैं कि जल्दी बन्द हो इसलिए दुबारा आप दस्तखत करें। हम शराबबन्दी के लिए दस्तखत करा रहे हैं। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था और मैंने दस्तखत कर दिये। बाद में मुझे मालूम हुआ है कि यह शराब चालू रखने के लिए है। हमें धोखा दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपके पास कौन आया था।

(व्यवधान)

कौन आया था आपके पास दबाव डालने के लिए?

श्री मनीराम : नाम मैं भूल गया हूं। अभी यहां बैठे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल झूठ है।

श्री मनीराम : आप झूठे हैं।

(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : कोई मंत्री नहीं गया है।

श्री लालचन्द : नाम बता दिया जायगा।

एक माननीय सदस्य : नाम बतायें नहीं तो झूठे हैं। सदन को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है।

श्रीमती नारंगी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि हम सदन में स्वतन्त्र रूप से विचार व्यक्त करेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया विचार।

(व्यवधान)

श्री गणेशलाल बैरागी (हिंडोली) : यह सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रिमंडल के 7 सदस्यों के लिए कहा गया था और माननीय मंत्री का नाम नहीं बता रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : दबा दबा कर दस्तखत कराये हैं मंत्रियों ने....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : मैं पहला व्यक्ति हूं जो यह चाहता हूं कि शराबबन्दी हो, लेकिन उसके विरोध में कोई मंत्री दस्तखत कराने नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : शराबबन्दी हो या नहीं लेकिन इसमें यह सड़कें और पुलियाएं रह जायेंगी।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी ने दस्तखत कराये या किसी ने दस्तखत नहीं कराये यह हाउस की प्रापर्टी नहीं है। यह हाउस के बाहर की बात है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कैसे नहीं, है हाउस की बात।

श्री रघुनन्दन व्यास : कोई सम्बन्ध नहीं है हाउस का इससे....

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : यह रेलेवेण्ट है।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक पाइण्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। शराबबन्दी के मामले को एक बार संकल्प के रूप में सदन में रख दें। फैसला हो जाये। क्लीयर हो जाये।

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, यह कौन सी बुरी बात है।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हर आदमी जिम्मेदार है। एक एक लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधि है। इस सदन का सदस्य है।

(व्यवधान)

(90)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, शराबबन्दी के मामले को संकल्प के रूप में रख दें। सारा झगड़ा ही खतम हो जाये।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी है या × × पार्टी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

बहुत हो गया।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका ही नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर —

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

'Where is the leader of the House? Has the Minister been authorised to reply? He can't reply. Only the Leader of the House can reply. You can't. How can you?

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : आपके द्वारा उठाये गये पाइण्ट आफ आर्डर भी क्या पाइण्ट आफ आर्डर हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : यह पाइण्ट आफ आर्डर है या वेस्ट आफ टाइम है।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : यह नहीं हो सकता है, नेता महोदय की बात नहीं सुनते हैं।

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : आप बैठ जायें। आप कृपया....

(व्यवधान)

मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहूंगा। इस बात का मुझे सख्त अफसोस है कि रेडियो पर किस प्रकार से गलत समाचार आया कि शराबबन्दी के विरोध में कोई हस्ताक्षर किन्हीं विधायकों ने किये हैं। मैं

(श्री माणकचंद सुराणा)

निवेदन करता हूं कि यह समाचार भ्रामक है। कोई हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर किसी भी विधायक ने नहीं किये हैं कि शराबबन्दी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोई समाचार अगर आपने रेडियो से सुना हो या अखबारों में पढ़ा हो........

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका कहना गलत है।

(व्यवधान)

श्री लाल चन्द : अध्यक्ष महोदय, यह समाचार....

(व्यवधान)

श्री माणक चन्द सुराणा : सरकार का कोई रेडियो पर कण्ट्रोल नहीं है। हमने कोई समाचार नहीं सुना है। आपने जानकारी दी है कि रेडियो पर यह समाचार आया है। इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई हस्ताक्षर नहीं कराये हैं। राज्य सरकार को किसी भी माननीय सदस्य के शराबबन्दी के विरोध में हस्ताक्षर प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह हम भी जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री माणक चन्द सुराणा : बता रहा हूं।

श्री मथुरा दास माथुर : 1 अप्रेल से शराबबन्दी की जाये या नहीं की जाये। पहले यह हुआ कि शराबबन्दी की जाये। अब यह आया है कि 2 अक्टूबर, 1980 से की जाये। यह चल रहा है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह ठीक है।

श्री माणकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है। यदि माथुर साहब को यह जानकारी है कि 2 अक्टूबर के लिए माननीय विधायक हस्ताक्षर कर रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आपको क्या परेशानी है।

श्री मथुरादास माथुर : यह अखबार में आया है। राजस्थान में 2 अक्टूबर, 80 से सरकार शराबबन्दी करेगी क्योंकि जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों को आशंका है कि विकास कार्यों के लिए धन इकट्ठा होना सम्भव नहीं होगा।

(व्यवधान)

इसलिए तीन जिलों झुंझनूं, सीकर सवाई माधोपुर में ही शराबबन्दी की जा रही है। ये तीन जिले है। नाम अखबारों में छपे हैं। आपका कोई काण्ट्रेडिक्शन नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अखबारों में यह भी छपा है कि शराब के ठेकेदार पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। यह भी अखबारों में खबर है।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं हनुमान गढ़ से आने वाले माननीय विधायक से निवेदन करना चाहूंगा, आपकी सदन में शराबबन्दी के बारे में राय हो गई । राज्य सरकार को माथुर साहब की राय भी मालूम हो गई । माथुर साहब ने यह सिफारिश की है कि यदि आपने शराबबन्दी की तो आपको सप्लीमेन्ट्री बजट लाना पड़ेगा । अभी दो दिन पूर्व पिछले शनिवार को पेश किया था।

श्री मथुरा दास माथुर : हां, मैंने यह कहा था कि डिमाण्ड पास मत करवाइये ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : प्रधान मन्त्री के इस आश्वासन पर भी कि मुख्य मन्त्री जी को पूरा खर्चा देंगे ।

श्री माणकचन्द सुराणा : मकराना से आने वाले माननीय सदस्य, जरा धैर्य रखें, थोड़ा सा सुनने का ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कष्ट करें ।

श्री माणकचन्द सुराणा : कष्ट करें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार की दुहाई दे रहे हैं । प्रधान-मन्त्री की दुहाई दे रहे हैं । भारत सरकार को राज्य सरकार ने यह लिख कर भेजा है, माननीय वित्त मन्त्री जी ने भेजा है कि 5 साल रुपया शराबबन्दी से नुकसान के एवज में देना चाहते है, सप्तम वित्त आयोग ने यह घोषणा की है कि 77-78 से जितनी आय का भुगतान आपको होगा, 77-78 में 27 करोड़ 55 लाख की आय होगी, उसका आधा रुपया भारत सरकार देगी । यह सप्तम आयोग ने कहा है । बावजूद यह लिखने के अभी तक सरकार को कोई उत्तर नहीं मिला है ।

श्री मथुरादास माथुर : वित्त मन्त्री जी ने सदन में यह कहा है । भारत सरकार, प्रधान मन्त्री और उप प्रधान मन्त्री ने भी....

श्री माणकचन्द सुराणा : सुनिये, सुनिये ।

श्री मथुरादास माथुर : आप सुनिये पहले ।

श्री माणकचंद सुराणा : सुनिये तो ।

श्री मथुरादास माथुर : कहा है पांच साल में....

(व्यवधान)

प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री जी का नाम है ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : हम सुनने के लिए कतई तैयार नहीं हैं ...

(व्यवधान)

आप सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री माणकचन्द सुराणा : कोई गुम-राह करने का सवाल नहीं है....

(श्री माणक चन्द सुराणा)

(व्यवधान)

प्रश्न इस बात का है....

(व्यवधान)

मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अभी तक माननीय वित्त मन्त्री जी के प्रतिवेदन पर भारत सरकार की कोई विधिवत स्वीकृति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुन लीजिए फिर प्रश्न पूछ लेंगे....

श्री माणक चन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमारे माननीय–

श्री खेतसिंह राठौड : 1 अप्रेल से....

श्री माणकचन्द सुराणा : आप सुनिये तो सही। आपको बड़ी जल्दी है।

श्री खेतसिंह राठौड : हमको इस बात की जल्दी है कि फैसला जल्दी हो, जो भी हो।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि-

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : इस सदन को और प्रदेश को सस्पेन्स से नहीं रखें और तुरन्त अपनी नीति स्पष्ट करें।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय ऐरन साहब, कोई सस्पेंस में नहीं रखा जा रहा है। किसी माननीय सदस्य का कोई प्रतिवेदन नहीं आया है कि शराबबन्दी नहीं की जाय। ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं आया है।

श्री भंवरलाल ऐरन : यह बात असत्य है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मन्त्री महोदय, सारा अपोजीशन आपकी बात सुनना चाहता है।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं यह उम्मीद करता हूं कि तीस सालों से असेम्बली में जो लोग बैठे हैं, माननीय मदेरणा साहब, इस मैटर को राजनैतिक विवाद का मुद्दा बनाने का प्रयत्न नहीं किया जाय, यह मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है। किसी भी माननीय सदस्य ने कोई प्रतिवेदन ही नहीं दिया है कि शराबबन्दी की जाय तो उस स्थिति में कैसे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह नहीं ...

Page No. 94

(94)

श्री माणकचन्द सुराणा : आप जरा सुनिये, इसका कोई आधार नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा 79 जनता पार्टी के विधायक 1 अप्रेल, 79 से शराबबन्दी करने के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन सबने ही नहीं, 30 विधायक कांग्रेस के....

श्री मथुरादास माथुर : कांग्रेस के नहीं अपोजीशन के।

श्री माणकचन्द सुराणा : हां अपोजीशन के भी हस्ताक्षर कर चुके हैं। मुख्य तौर पर कांग्रेस के हैं। सी.पी एम. और सी.पी. आई. के नहीं, अधिकतर कांग्रेस पार्टी के हैं, एक दो निर्दलीय भी हैं....

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : मैं भी हूं।

श्री माणकचन्द सुराणा : हां, मुझसे भूल हो गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपकी पार्टी ने जो हस्ताक्षर किये हैं, उन हस्ताक्षरों को कृपया आपके कर्नाटक के मुख्य मन्त्री देवराज अर्स के पास भी भिजवाने की कृपा करें...

श्री मूलचन्द डागा : क्या मतलब है ? This is no relevant reply. Where is the relevancy ? यह उत्तर मन्त्री का है ?

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : आपकी पार्टी की यह एक्सेप्टेड पालिसी नहीं है कि शराब, बन्दी की जाय इसलिये इस बात को सदन में कहने के अधिकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह राजनैतिक जवाब दे रहे हैं आप।

श्री माणकचन्द सुराणा : आपको, डागाजी, तकलीफ क्या है इस राजनैतिक जवाब से। मैं जवाब सही दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : तीस कांग्रेसी शराबबन्दी मांगते हैं तो कर्नाटक के मुख्य मन्त्री के पास क्यों भेजना चाहते हैं ?

श्री माणकचंद सुराणा : माननीय गुप्ताजी, आपकी भावना को तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन इनके क्या विचार हैं यह समझने की कोशिश करें....

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : We don't want to hear this.

श्री अब्दुल अजीज : 79 ने हस्ताक्षर किए हैं।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : आप सुन लें, आप बैठिये तो सही।

श्री टीकमचंद कांत : आपको समझा तो रहे हैं।

श्री अब्दुल अजीज : आपकी आवाज शराब बेचने वालों की भारी रकम के नीचे दब गई।

(व्यवधान)

श्री माणकचंद सुराणा : जनता पार्टी की सरकार जो भी निर्णय करेगी, जनता पार्टी के विधायकों की राय के अनुसार निर्णय किया जाएगा। बहुत अधिक बहुमत के आधार पर शराबबन्दी की घोषणा की जायेगी। मन्त्रिमण्डल ने माननीय मुख्य मन्त्री जी पर छोड़ दिया है, इसमें आपको क्या परेशानी है--

(व्यवधान)

जैसा कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा एक दो दिन में घोषणा हो जायेगी। वे भरतपुर चले गए हैं इसलिए निर्णय की एक दो दिन में ही मुख्य मन्त्री जी घोषणा करेंगे। वह निर्णय आपकी इच्छा के अनुकूल होगा या नहीं लेकिन जनता पार्टी विधायकों के बहुमत के आधार पर होगा।

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं-

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में शराबबन्दी है लेकिन सड़कें नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मनोहर सिंह जी, अगर इस पर चर्चा होगी तो मैं अनुमति नहीं दूंगा और 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी होगी।

आय-व्ययक अनुमान 1979-80। अनुदान की मांगों पर विचार। श्री जय नारायण पूनिया।

व्यवस्था का प्रश्न

विभाग का प्रतिवेदन

श्री मूलचन्द डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

हमें जो प्रगति विवरण मिला है उससे यह मालूम नहीं होता कि 1978-79 में कौन कौन से काम पूरे हो गये। यह प्रतिवेदन केवल धर्मशाला या गौशाला का है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : यह कोई पांइट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पांइट आफ आर्डर है या नहीं, वह तो आसन के द्वारा निर्णय होगा। 10-10 सदस्य खड़े हो जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : वार्षिक प्रतिवेदन 1978-79 में लिखा गया है कि यह प्रगति हुई, इतनी सड़कें बनीं, इतने पुल बने, इतना रुपया खर्च हुआ, इतना बकाया रहा।

(व्यवधान)

(श्री मूलचन्द डागा)

1978-79 के लिए जो पैसा हमने दिया था उसके आधार पर सड़कें बनी और काम हुए या नहीं, कितनी धनराशि बजट में रखी गई, कितना खर्चा कर दिया गया, कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने, इसके अन्दर एक पैरा है कि वर्ष 1978-79 के लिए 345 लाख रुपयों का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य एवं मांग संख्या 21-सड़कें व पुल की प्रस्तुति

श्री जयनारायण पूनिया (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19–लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,06,70,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 21

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21 सड़कें व पुलों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,41,87,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

1. नागौर जिले के अधिशासी अभियन्ता द्वारा जानबूझ कर लाडनूं क्षेत्र के लोक निर्माण कार्यों की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुरसिंह (-ोहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री डूंगरराम पंवार (टी.वी.)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना)

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा)

2. लोक निर्माण विभाग की शिथिलता, इसमें फैले भ्रष्टाचार को दूर कर इसे क्रियाशील बनाने पर चर्चा के लिए।

3 लोक निर्माण कार्यों का तेजी से विस्तार करने के उपायों पर चर्चा के लिए।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा)

4. एलोपैथी चिकित्सा भवनों एवं परिवार कल्याण केन्द्र के भवनों के निर्माण में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

5. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निर्माण कार्यों में कमीशन प्रणाली को खत्म करने व ठेकेदारी सिस्टम समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

6. सार्वजनिक निर्माण विभाग में उत्पन्न विसंगतियों तथा कर्मचारियों में उत्पन्न नाराजगी पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीशचंद्र शर्मा (रतनगढ़)

7. अधिकारियों की लापरवाही से लोक निर्माण विभाग के कार्यों में होने वाली देरी पर चर्चा के लिए।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर)

8. लोक निर्माण कार्यों में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)

9. विभागीय शिथिलता से लोक निर्माण कार्यों में प्रगति नहीं हो सकी इस पर चर्चा के लिए।

10. चिकित्सालय के भवनों के अभाव पर चर्चा के लिए।

11. सूचना केन्द्रों के भवनों के निर्माण में विभाग पूरी तरह असफल रहा इस पर चर्चा के लिए।

श्री अजीतसिंह (टोंक)

12. पुराने मकानों की मरम्मत कर उन्हें उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

13. नसीराबाद क्षेत्र के बड़े-बड़े ग्रामों को नसीराबाद से सड़कों द्वारा जोड़े जाने पर भिनाय समिति व मराई समिति में सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

14. ठेकेदारी प्रथा को खतम कर विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अजीतसिंह (टोंक)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

15. अकाल राहत में हुए कार्य के सामान का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सदुपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

16. अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारियों को अधिक वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

17. आवश्यक सार्वजनिक भवन के निर्माण करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़)

18. इस मद की राशि सरकार द्वारा बनाये जाने वाले भवनों पर शत प्रतिशत खर्च करने और हल्का काम करने वालों को सख्त सजा दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)

19. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना)

20. खान, सड़क निर्माण के अधूरे कार्य को पूरा कराने की चर्चा के लिये।

21. खनिज क्षेत्रों में उपागमन सड़कें व भवनों के निर्माण में होने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये।

22. मकराना के सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगलों को 25 कमरों तक का बनाया जाय इस पर चर्चा के लिए।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां)

23. लोक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना)

24. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

25. बाड़मेर जिले में स्कूल भवनों के निर्माण में बहुत ही कम राशि का प्रावधान करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर असंतोष व्यक्त करने की चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर)

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)

26. विभाग की अव्यवस्थता एवं इसमें फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

27. प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. लोक निर्माण में मितव्ययता लाने एवं दक्षता में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये।

29. तकनीकी शिक्षा हेतु भवन निर्माण में अव्यवस्थित तथा असंतुलित खर्चा करने

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
(श्री ओंकार लाल चौहान)

पर चर्चा के लिए।

30. विभाग के पुनर्गठन करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर)

31. असंतुलित एवं उपेक्षित क्षेत्रों में चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण)

32. चिकित्सा व परिवार कल्याण के निर्माण कार्यों में जैतारण उपखण्ड की अवहेलना पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर–ग्रामीण)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)
श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज)
श्रीमती गुणवन्ती कुमारी (वैराठ)
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)
श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)
श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)
श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)
श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)
श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)
श्री आलम अली खां (फतेहपुर)
श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

33. लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की उचित देखभाल के अभाव के कारण होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)

34. जिला जालौर में लोक निर्माण कार्यों के बारे में एवं बजट प्रावधान करने में निर्माण कार्य कराने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुरसिंह (नोहर)

35. पंचायत मुख्यालयों तक चिकित्सालय भवन बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री लालूदास (फलासिया)

36. फलासिया क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों के भवनों के अभाव पर चर्चा के लिये।

37. फलासिया क्षेत्र में सड़कों के अभाव से जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

38. नसीराबाद क्षेत्र के छोटे छोटे ग्रामों को पक्की सड़कों द्वारा बड़े ग्रामों से जोड़ने बाबत चर्चा के लिए।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़)

39. नवलगढ़ पंचायत समिति के भवन व क्वार्टरों की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

श्री एच. एम. शर्मा (बेगूं)

40. शिक्षा व परिवार कल्याण हेतु शालाओं एवं केन्द्रों के भवन अपर्याप्त होने पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

41. बून्दी जिले के लोक निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, रिश्वत-खोरी के आधार पर कार्य हो रहे हैं इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

42. लोक निर्माण कार्य में कोटा के साथ पक्षपात के संबध में चर्चा के लिये।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर)

43. विभाग द्वारा स्वीकृति होने पर भी निर्माण कार्य चालू न करने बाबत चर्चा के लिए।

श्री समरथलाल (राजगढ़)

44. राजगढ (अलवर) में सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण का आफिस स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिए।

45. राजगढ़ (अलवर) में रेस्ट हाउस का विस्तार करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ)

46. विश्रामगृहों की व्यवस्था को ठीक किया जावे तथा मोजूदा भोजन खर्चा तथा कमरा किराया बढ़ाया जावे इस पर चर्चा के लिए?

47. ठेकेदारी व्यवस्था को खतम कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बालकृष्ण बानवी (फलोदी)

48. लोक निर्माण कार्यों में परम्परा-गत ढंग से चलने वाली भारी रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा)

श्री विजयसिंह नदेरा (बाँदीकुई)

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा)

49. लोक निर्माण कार्य के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय दौसा में प्रारम्भ किये जाने के बारे में चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

50. सरकारी भवनों के निर्माण हेतु सिकराय क्षेत्र में अब तक कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल (घाटोल)

51. घाटोल तहसील, जिला बांसवाड़ा में चिकित्सालय के भवन निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

52. जैसलमेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के दोनों सब डिवीजन में दो अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता कार्यालय जिला मुख्यालय पर कायम कराने, स्थायी वर्कशाप स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

53. 14-15 डिप्लोमा होल्डर्स उप अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं की सेवा समाप्त कर दिये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

54. लोक निर्माण विभाग मे व्याप्त भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची पर निगरानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. मावली क्षेत्र की लोक निर्माण कार्य में की गई उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

56. सरकारी भवनों के निर्माण एवं सूचना केन्द्रों के भवनों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन)

57. लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

58. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय केशोरायपाटन क्षेत्र में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

59 बाड़मेर जिले में राजकीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं सुधार की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रावतराम (सुजानगढ़)

60. कस्बा सुजानगढ़ के रेस्ट हाउस एवं छापरताल के सैकण्डरी स्कूल के भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर)

61. लोक निर्माण कार्यों में ढिलाई व सही नक्शे नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

62. लोक निर्माण विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्र में कार्य की धीमी गति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़)

63. आदिवासी क्षेत्रों में लोक निर्माण

(श्री जिधिग)
कार्यों के प्रभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा)

64 लोक निर्माण विभाग द्वारा जनहित के प्राथमिक कार्यों की उपेक्षा की गई इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

65. लोक निर्माण कार्यों में भारी घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

66. सिरोही में राज्य कर्मचारियों के आवास हेतु सौ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. सिरोही में सर्किट हाउस का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़)

68. विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार एवं आपाधापी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर)

69. लोक निर्माण कार्यों की भरतपुर जिले में आवश्यकता होने पर भी विभाग द्वारा उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़)

70. भवनों में ठीक मात्रा में मैटीरियल न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. लोक निर्माण विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू)

72. नागौर में, गृह जिले का निवासी, अधिशासी अभियन्ता लगा देने के कारण, स्थानीय राजनैतिक प्रेरणा से गलत कार्य करने पर चर्चा के लिये।

73. सुजला कालेज के भवन को पूरा कराने पर चर्चा के लिये।

74. अधिशासी अभियन्ताओं की नियुक्ति उनके गृह जिले में करने एवं राजनैतिक कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर)

75. सरदार शहर के महाविद्यालय में छात्रावास भवन के अभाव बावत चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

76. डाक बंगला बालोतरा (जिला—बाड़मेर) का विस्तार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू)

77. विभाग द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के भवनों पर खर्च नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)

78. लोक निर्माण विभाग में प्रशासनिक शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

79. राजस्थान में लोक निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसके समाधान की चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा (वनीपार्क, जयपुर)

80. लोक निर्माण में परिकल्पना का अभाव, भ्रष्टाचार की व्यापकता और गतिहीनता पर चर्चा के लिये।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

81. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

82. ज्ञानी राम हरकचन्द सरावगी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सुजानगढ में कमरों की कमी होते हुये भी उपलब्ध धन को चार दीवारी में गलत रूप से खर्च करने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू)

83. लोक निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने में विभागीय ढिलाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

84. लोक निर्माण कार्यालय में व्याप्त अनियमितताएं व फैले हुआ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अयूब खां (तिजारा)

85. ग्राम टपूकड़ा में चिकित्सालय भवन की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचान्द जैन (बड़ी सादड़ी)

86. तहसील भवन डूंगला की खराब हालत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई)

87. सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं तथा प्रशासनिक फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये।

88. सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यक्षमता क्षीण होती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

89. विभाग द्वारा काम के निर्माण में घटिया किस्म का मैटीरियल काम में लेने पर चर्चा के लिये।

90. विभाग में चली आ रही कमीशन प्रथा को समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचंद डागा (पाली)

91. डाक बंगलों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

92. डाक बंगलों की बकाया रकम जो वसूल नहीं की जा रही है उस पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

93. लोक निर्माण में परिकल्पना का अभाव, भ्रष्टाचार की व्यापकता और गतिहीनता तथा विभाग के इन्जीनियरों की चल व अचल सम्पति व बैंक बेलेन्स की जांच कराने तथा शराबी इन्जीनियरों को विभाग से निकालने पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह नदेरा (बांदीकुई)

94. निर्माण विभाग में 'मस्टर रोल' सिस्टम बन्द करने की चर्चा के लिये।

95. विभाग द्वारा अन्य विभागों के निर्मित भवनों का हस्तान्तरण न करने पर चर्चा के लिये।

96. पी. डब्ल्यू. डी. के उपअभियन्ताओं की वेतन वृद्धि रुक जाने के कारण फैली निराशा की चर्चा के लिये।

97. सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपअभियन्ताओं के 20 वर्ष से तरक्की न होने के कारण असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

98. भीनमाल डाक बंगले में कमरों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री अयूब खां (तिजारा)

99. कोट कासिम में पशु चिकित्सालय भवन बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

100. ग्राम गवालदा में चिकित्सालय भवन बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)।

श्री गुलमोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर)

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

2. जयपुर नगर स्थित समस्त सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए और अधिक धन राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली)

3. पाली में बांडी नदी पर पुल की आवश्यकता व उसके निर्माण न होने के कारण लाखों का नुकसान होने पर चर्चा के लिये।

4. पाली में दिवादी से लेकर मांडावास होती हुई जदारियां तक पक्की सड़क का निर्माण कराने की चर्चा के लिए।

5. पाली से पीपाड़ तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मूलचंद डागा (पाली)

6. पाली से सोजत और पाली से खारची जो सड़कें जाती हैं, उनकी दुर्दशा और अनेक दुर्घटनायें होने पर भी उसकी मरम्मत न होने के कारणों पर चर्चा के लिए।

7. पाली से खरवा जो सड़क जाती है रास्ते में आकेलो गांव के पास पुल नहीं बनने के कारण सड़क का उपयोग बहुत कम होने व वर्षा में रास्ता बन्द होने पर चर्चा के लिए।

8. पाली में सेल्स टैक्स व आबकारी दफ्तर के पास रेल लाइन पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

9. जिले की अधूरी सोजत रोड व देसूरी सड़क को पूरा कराने बाबत चर्चा के लिए।

10. सोजत रोड, देसूरी सड़क कार्य मुख्य जिला सड़कों से लेकर पक्की बनाने की चर्चा के लिए।

11. तहसील सोजत में मंडला के पास सोजत बिड़ाला मार्ग पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

12. विभाग द्वारा लाडनूं क्षेत्र की सड़कों की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ)

13. नोहर से साहवा, नोहर से सरदारशहर, सूरतगढ़ से पल्लू, पल्लू से साहता सड़कें बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

14. आवागमन की दुरूहता व्यापार के विस्तार को ध्यान में रख कर सड़क विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री बालचंद आर्य (डग)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना)

Page No. 106

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री डूंगरराम पंवार (टी.बी.)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा)

15. सड़कों के अभाव वाले क्षेत्रों में सड़कें बनाने तथा बनी सड़कों की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिए।

16. सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर अधिक लागत आने की समस्या के हल निकालने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

17. भरुड़ी पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराने बाबत चर्चा के लिये।

18. भीनमाल, भुंभाणी दामण बाघोड़ा, रंगाला तक सड़क निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये।

19. जालोर जिले में सड़कों के अभाव के विषय में चर्चा के लिये।

20. भीनमाल से नरसाणा एवं झाब तक डामर की सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

21. भीनमाल से पाथेली एवं पोषाणा तक डामर की सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

22. भीनमाल, घनवाड़ा, बणदर करड़ा अरणाय, सांचोर सड़क को डामर की सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये।

23. भरुड़ी-तवाव, मोदरा-बाणसा, पोषेड़ी सड़क पर डामर बिछवाने हेतु चर्चा के लिये।

24. भीनमाल-नरसाणा-झावहेमा-गुडा-सिवाड़ा डामर सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री नूरा (मसूदा)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा)

25. पिछड़े व रेतीले इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिये।

26. फेमिन में बनी सड़कों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

27. रेण साजू सड़क जिला नागौर को खरवा ग्राम से होकर ले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

(श्री नूरा)

28. तकनीकी तरीके से सड़कों का निर्माण करने से सड़कों पर पानी रुकने व सड़कों के टूटने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

29. तहसील डेगाना की निम्नलिखित सड़कों- (1) भेरूदा डेगाना वाया निम्बडी (2) लाम्पोलाई से साजू (3) डेगाना से खाटू (4) डेगाना से हरसोर परवतसर को अविलम्ब डामर सड़कें बनाने की चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (डिग्गी)

30. टोंक तहसील में ग्राम पीपलू से राणोली सड़क के बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थाना गाजी)

31. गुढ़ा से किशोरी (थानागाजी क्षेत्र) वाली सड़क को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिए।

32 राष्ट्रीय कृत मार्ग की सड़कों को शीघ्र पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हनवंत सिंह राणावत (बाली)

33. पाली जिले में सड़कों का कार्य शिथिलता से निर्मित होने व अत्यावश्यक पुलों का निर्माण नहीं कराने पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

34. मार्च, 1977 में स्वीकृत योजना में शामिल सड़कों का काम बन्द कर राजनैतिक आधार पर सड़कों की नयी स्वीकृतियां जारी कर दिए जाने पर चर्चा के लिए।

35. प्रदेश में सभी सड़कों तथा पुलों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चंद्र शर्मा (रतनगढ़)

36. आवश्यकतानुसार सड़कों और पुलियाओं के निर्माण नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर)

37 राज्य में सड़कों की जर्जर हालत एवं उनके सुधार हेतु चर्चा के लिए।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा)

38. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में बरती जा रही उपेक्षा की नीति पर चर्चा के लिए।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

39 पीलिया खाल की पुलिया व चेवला नदी पर पुल व भिलवाड़ी नदी पर पुल न बनाने की चर्चा के लिए।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

(श्री शोपत सिंह मकासर)

40. कोटपूतली तहसील में डाबला राजनौता रोड पर पुल बनाने की चर्चा के लिये।

41. 1500 से ऊपर की आबादी वाले ग्राम तक सड़क पहुंचाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

42. 1500 तक आबादी वाले ग्राम को तत्काल सड़कों से जोड़ा जावे इस पर चर्चा के लिए।

43. कोटपूतली से अलवर-बानसर रोड पर शाबी नदी का पुल बनवाने पर चर्चा के लिए।

44. कोटपूतली के खनिज क्षेत्र में सड़कें नहीं बनाई जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

45. सड़कों के अभाव वाले क्षेत्रों में सड़कें बनाने तथा बनी सड़कों की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिए।

46. सड़कों एवं पुलों पर अधिक लागत की समस्या के हल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबगा)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

श्री आलम अली खां (फतेहपुर)

47. ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दी जावे, जिससे कृषकों की उपज आसानी से मंडियों तक पहुंच सके इस पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराज सिंह (बस्सी)

48. तहसील बस्सी व चाकसू क्षेत्र की सड़कों व पुलों को अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

49. अलवर रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज के निर्माण कराने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़)

50. अनूपगढ़ क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिए।

51. सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत व रामसिंह पुर कुपली रोड के पुल के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

52. राज्य राज पथ पर पुलों की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

53. पाली जिले के सोजत रोड देसूरी मार्ग को प्राथमिकता पर लेने की चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टौंक)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

54. टौंक-झिराना-टोडारायसिंह सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़)

55. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी अधूरी सड़कों को पक्का करने में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिए।

56. राजमार्ग नं. 8 पर किशनगढ़ के समीप बनाये जा रहे बाई-पास के निर्माण कार्य में शिथिलता बाबत चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

57. उदयपुर सम्भाग में सड़कों की दुर्दशा से यातायात की भारी परेशानी एवं विभाग की लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

58 उदयपुर आदिवासी क्षेत्र में सड़कों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माणक लाल ठाकौर (नेनवा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

59. राजस्थान में पुल निगम की घोषणा की क्रियान्विति तथा राजस्थान के प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

60. जयपुर भोपाल मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत)

61. सड़कों को वर्षा के जल प्रवाह से होने वाले नुकसान को रोकने की योजना के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना)

62. इस वर्ष निर्माण की जाने वाली सड़कों के निर्माण कराने तथा बोरावड़ से छोटी खाई तक की सडक को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

63. मकराना क्षेत्र में गांवों में आवागमन की सुगमता के लिए दस मील सड़क चारों ओर आस पास बनाई जाने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर चंद्र (पिड़ावा)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

64. झालावाड़ जिले में सड़कों की मरम्मत न कराने व इंजीनियर्स की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां)

65. जोधपुर जिले में सड़क व पुलों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

66. सिरोही क्षेत्र में जावाल-हरजी सड़क को पूरा कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री रघुनन्दनदास व्यास)

67. जावाल हरली सड़क पर सारी पुलियां बनाने हेतु चर्चा के लिये।

68. कालन्द्री-जसवन्तपुरा सड़क पर सारी पुलियां निर्माण की जाने तथा डामर करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

69. शिवगंज-दोसालिया-जावाल सड़क पर डामर करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना)

70. ग्रामों में सड़क विकास न होने, तथा पुलों व सड़कों के बनाने में मैटीरियल की चोरी एवं व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

71. बाड़मेर जिले में निम्नलिखित सड़कों :—(1) बाड़मेर से हरसोणी वाया बैसाली (2) चवा से फलसूंड वाया वायतू (3) रायसर से चौहटन (4) रायसर से राणासर (5) सीयोणी से वालेवा (6) बाटाडू से ऊंडू (7) भाडखा से भीयड़ा (8) बाटाडू से कानोड़, को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर)

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू)

72. ग्रामीण सड़कों के निर्माण में असंतुलन तथा प्राथमिकता के सिद्धान्त के अभाव एवं निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

73. सड़क व पुल निगम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल (जैतारण)

74. जैतारण उपखण्ड की टूटी व अधूरी सड़कों और पुलों की मरम्मत व निर्माण में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए।

75. पाली जिले में सड़कों व पुलों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा के लिए।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

76. खण्डेला मोड़ से चला तक चौकड़ी होकर सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. सीकर जिले के ग्राभावास, दादिया तपीपत्या, कोटड़ी (पायलान) गांवों को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

78. खण्डेला—पलसाना सड़क का काम धीमी गति से चलने से और सड़क अभी अधूरी रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. सीकर जिले में श्रीमाधोपुर से पलसाना वाया जाजोद सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)

80. सड़कें और पुल प्राथमिकता के आधार पर बनाये जायें और देहातों को सड़क से जोड़ने की तुरन्त कार्रवाई हो इस पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ाव)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री आलम अली खां (फतेहपुर)

81 राज्य सरकार से बार बार निवेदन करने पर भी जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा सुधारने में बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर)

82. जिला जालौर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले अकाल वर्षों की अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने में उदासीनता की चर्चा के लिए।

83. सड़क निर्माण कार्यों में विशेषकर ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों में ज्यादा बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. जिला जालौर की मौजूदा सड़कों की दयनीय हालत तथा सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत करने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिए।

85. सड़कें एवं पुल निर्माण कार्यों के लिए बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिए।

86 जिला जालौर में विशेष कर तहसील सांचौर की ग्रामीण अधूरी सड़क निर्माण कराने में सरकार की घोर उदासीनता की चर्चा के लिए।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर)

87. बाकरा रोड तक भागली होते हुए सड़क का निर्माण तथा केशवणा रेवतड़ा, बाकरा रोड, मरन सांयू (लूप) तक सड़क निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए।

88. रायपुरिया नाला (जि. जालौर) पर रपट बनाने हेतु चर्चा के लिये।

89. ग्राम वालवाड़ा को बिशनगढ़ से जोड़ने हेतु सड़क का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

90. जालौर तीखी मार्ग के मध्य जवाई नदी पर छोटे पुलिये एवं रपट निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

91. भीलवाड़ा-बड़ा महुआ-शाहपुरा मार्ग पक्का न बनने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

92. भीलवाड़ा-आरसिया मार्ग तथा काजवे की खराब सड़क के कारण दो लोगों की आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

93. भीलवाड़ा का ओवर ब्रिज पूर्ण न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

94. भीलवाड़ा, हालैंड, आन्थल, वेगूं सड़क मार्ग न बनाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

95. भीलवाड़ा तहसीलों में अप्रोच सड़कें न बनने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

96. भीलवाड़ा मंगरोप, हमीरगढ़ मार्ग डामर का नहीं बनने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

97. भीलवाड़ा के अन्दर गांधी नगर में रेलवे लाइन के ऊपर पुल न बनने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

98. पांसल से मेजा सड़क को विभाग के अन्तर्गत लेकर पुनः निर्माण एवं उसके रख रखाव पर चर्चा के लिये।

99. जिला भीलवाड़ा में पुर, राजोला, देवली, बिल्या मार्ग बनवाने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी)

100. दारापुर एवं बहरेवगढ़ (थानागाजी क्षेत्र) की सम्पर्क सड़क पूरी कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)

101. खटवाड़ा तथा बीगोद के बीच बनास का पुल, आकोला बड़ल्यास के बीच बनास का पुल तथा जोजुवा, भाड़का खेड़ा के बीच केनाल का पुल निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

102. सींगोली से मांडलगढ़ वाया सराना पलासिया, बड़ल्यास से त्रिवेणी वाया सींगोली, जोजवा त्रिवेणी से जहाजपुर वाया मानपुरा काछोला तथा मानपुरा से जलीन्द्री तक की सड़क पूरी नहीं होने से उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

103. ढीपरी (चम्बल), टींपरी (कालीसिंह) तथा खातोली (पार्वती) पर पुलियायें निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. नोनेरा यानी निमोला, रनोदिया, बागली, बलवन, पुसोद, जोरावरपुरा, कवंल्दा, लक्ष्मीपुरा आदि गांवों को अप्रोच रोड से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

105. कोटा ग्वालियर वाया खातोली, श्योपुर कलां मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. मांगरोल-बालूंदा वाया बमोर-कलां इन्टर स्टेट सड़क के शोघ निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. सीसवाली-मांगरोल सड़क के शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. इटावा-इन्द्रगढ़ डींपरी (चम्बल) जो कि राज्य मार्ग का हिस्सा है सड़क के शीघ्र निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

109. अकाल में बनी अयाना-लुहावद-पीपल्दा कलां-खातौली सड़क को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

110. लूनी नदी पर घधाड़ा से जालोर पाली को मिलाने हेतु पुल बनाने पर चर्चा के लिये।

111. बाणगंगा तिलाड़ा पर जो जयपुर-जोधपुर सड़क के मुख्य मार्ग पर स्थित है बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. जोधपुर-सोजत मार्ग पर लूनी नदी पर काकेलाव से आगे बीरढ़ावास के पास बड़ा पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

113. प्रत्येक पंचायत केन्द्र को सड़क से जोड़ने तथा गांवों की सड़कों पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालू दास (फलासिया)

114. फलासिया क्षेत्र में कच्ची सड़कों को पक्का डामर रोड बनवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

115. ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र के जालीया प्रथम से जवाजा रोड ठीक कराने, भीम से टाटगढ़ रोड की मरम्मत कराने तथा बडा-खेडा से बन्जारी भीम सडक को ठीक कराने की चर्चा के लिये।

116. ब्यावर से सुमेरपुर वाया पाली राजकीय मार्ग की सड़कों की खराब हालत पर चर्चा के लिये।

117. सोजत रोड सरुपा सडक जो मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ती है, अधूरी पडी है उस पर चर्चा के लिये।

118. जैतारण चंडावत की सडक वर्षों से अधूरी पड़ी है उसका निर्माण कराने की चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

119. बाड़मेर जिले की महत्वपूर्ण सड़क जोधपुर से बाड़मेर सड़क पर बालोतरा एवं सिलछी पर पुलों के निर्माण की स्वीकृति में विभाग द्वारा उदासीनता की नीति

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

अपनाने के कारण स्थिति पर चर्चा के लिये ।

120. बाड़मेर जिले में कई सड़कें अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई गई थीं, परन्तु उन सड़कों की सार्वजनिक निर्माण विभाग मरम्मत एवं सुधार नहीं करता है जिसके कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

121. सड़क निर्माण हेतु नवलगढ़ व मुकन्दगढ़ नगरपालिकाओं में सार्वजनिक निर्माण के लिए विभाग की देय राशि में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये ।

श्री एच.एन. शर्मा (बेगूं)

122. ग्रामीण क्षेत्रों में बहने वाली नदियों पर पुल अथवा पुलियायें बना कर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये ।

123. अकाल राहत कार्य के तहत बनाई गई सड़कों को अविलम्ब पूरा कराने की चर्चा के लिये ।

124. चारभुजा, दीपपुरा घाटे की सड़क जिसे कि 1962-63 में डामर किया गया था उक्त घाटे को अविलम्ब पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर)

125. तीर्थ स्थलों तथा दर्शनीय स्थानों पर जाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सड़कों तथा पुलियाओं का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)

126. प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत सड़क निवाई बोली को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

127. केयून से लालसोट वाया दणवास सड़क की मरम्मत कर उस पर डामर बिछाने हेतु चर्चा के लिये ।

128. निवाई निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु नई सड़कों के निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर)

129. भरतपुर जिले में सड़कों एवं पुलों की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

130. बून्दी जिले में पुल जो सड़कों पर बांधे जा रहे हैं उनमें पत्थर गिट्टी डामर कम लगा कर कार्य किये जा रहे हैं जिससे एक वर्षा में ही साफ हो जाते हैं, इस भ्रष्टाचार की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

131. बून्दी जिले में सड़कों की दुर्दशा एवं इनके निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

डा. गंगा सहाय (कठूमर)

132. कठूमर-खोवराणा-मण्डावर तक बनने वाली सड़क 15 साल से अधूरी पड़ी

(डा. गंगासहाय)
इसे प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा के लिये।

133. खेड़ली से सोंखर-सोखरी-नाटीज-घोलागढ (बहतू) होते हुए खुदियाल को जोड़ने वाली वर्षों से अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन)

134. चोहटन क्षेत्र से धणाऊ-धोरीमणा, बुरहान कातला-सेड़वा, सिहाणी पनोरिया व साता-धोरीमणा सड़कों के निर्माण कराने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर)

135. कुम्हेर क्षेत्र में बड़े ग्राम तथा ग्राम समूह जिनकी आबादी रास्ते के ग्रामों को मिला कर 6000 के करीब हैं उन्हें सड़क से जोड़ने तथा पुलों के न होने के कारण जहां कई-कई माह तक वर्षा में आवागमन बन्द रहता है, उनके बनाने हेतु चर्चा के लिये।

वैध गोविन्द सहाय (गंगापुर)

136. विभाग द्वारा सड़क व पुलों के निर्माण कराने के बारे में शिथिलता बरतने बाबत चर्चा के लिये।

श्री भेरूंलाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल)

137. कोटडी से नन्दराम सड़क जिला भीलवाडा को डामर से पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. शाहपुर जिला भीलवाड़ा से आसीन्द मार्ग के रख रखाव तथा इस पर डामर कराने पर चर्चा के लिये।

139. शाहपुरा से विजयनगर मार्ग को डामर का बनाने पर चर्चा के लिये।

140. शाहपुरा केकड़ी मार्ग सडक निर्माण सामग्री के पड़े होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

141. काली सिंध एवं पार्वती नदी के पुल एवं रामगढ़ व अन्ता सांगोद रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर, पूर्व)

142. अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 की खराब सड़क के कारण प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन)

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा)

143. सवाई माधोपुर जिले की सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कें बनाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

144. जिला सवाई माधोपुर में सड़कें एवं पुल बनाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

(श्री श्रवणलाल)

145. करौली से महुवा सड़कों की दुदर्शा के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)

146. सोजत रोड से जोजावर देसूरी सड़क को प्राथमिकता से बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

147. देसूरी से रवीवाड़ा व काली घाटी से जोजावर व मामावास से नाडोल सड़कों व पुलों के निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री समरथलाल (राजगढ़)

148. माचाड़ी से चिमरावली वाया पाटन सड़क का निर्माण कराने के क्रम में चर्चा के लिये ।

149. राजगढ़ (अलवर) एरिया की पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कों को शीघ्र ही बनाने के क्रम में चर्चा के लिए ।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा)

150. ग्राम मंडावर से कोटलिक रोड का निर्माण कराये जाने में पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिए ।

151. हिण्डौन महुआ रोड को चौड़ी किये जाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

152. बाणगंगा पर ग्राम बापी के पास पुल बनाने पर चर्चा के लिए ।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़)

153. बाय से खाटु श्यामजी की रोड बनाने, रानोली से दांता रोड बनाने, पलसाना से भलोदा की रोड बनाने एवं ग्राम दांता में ग्राम की रोड की मरम्मत करवाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)

154. गांवों तथा शहरों को जोड़ने वाली सड़कों को सीधा बिना मोड़ के बनवाने तथा पुलों का निर्माण शीघ्र कर दूरियों को कम किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

155. ब्यावर-बीलाड़ा-जोधपुर बालेसर-पोकरण-जैसलमेर सड़क को भारत सरकार के प्रतिरक्षा विभाग को सुपुर्द कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

156. फलौदी तहसील में सड़कों व पुलों की दुर्व्यवस्था की चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई)

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा)

157. दौसा उप जिले में विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण व मरम्मत ठीक प्रकार से न करने के बारे में चर्चा के लिये ।

158. दौसा के पास बाण गंगा नदी पर बापी व सिकन्दरा तथा काली पहाड़ी ग्रामों के पास पुल बनाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

159. सिकन्दरा से गीजगढ़ सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

160. सिकराया क्षेत्र में गत दो वर्षों में एक इंच सड़क की भी स्वीकृति न दिए जाने पर व्याप्त जन असंतोष व विभाग की भेदभाव पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये।

161. सिकन्दरा से बहरावण्डा सडक को विभाग द्वारा अपने हाथ में न लिए जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

162. भाण्डारेज से लांका बहरावण्डा तक की सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

163. सिकन्दरा के पास बाण गंगा नदी पर पुल बनाए जाने बाबत चर्चा के लिये।

164. सिकराय से मानपुर सड़क को दो बार टेण्डर होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)

165. निवाई निर्वाचन क्षेत्र की जमात बोडोली सूरज का खेड़ा राहोली की प्रस्तावित सड़क का काम चालू न करने पर चर्चा के लिये।

166. निवाई निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम जयात से चोरपुरा, झुझार पुरा खणदेवत डागरथल प्रस्तावित सड़क का कार्य चालू नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री कुंजीलाल (बामनवास)

167. बामनवास से बंद मोरासागर तक सड़क को डामर किए जाने व पूर्ण कराए जाने पर चर्चा के लिये।

168. मित्रपुरा से बोंली सड़क को पूर्ण कराए जाने पर चर्चा के लिये।

169. दौसा-लालसोट रोड से बंध माधोसागर तक की तीन किलोमीटर सड़क जो अधूरी पड़ी है, अविलम्ब पूरी कराए जाने पर चर्चा के लिए।

श्री अचलाराम (देसूरी)

170. योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर विशेषतया गिरासियों का ओड़ा से धाणेराव अप्रोच रोड निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

171. खोड़ जवाली, नाडोल, आना सादड़ी व सोमेसर नाडोल सड़क निर्माण कराने के बारे में चर्चा के लिए।

172 रानी नदी (जिला पाली) पर पुल निर्माण कराने के प्रयोजन के बारे में चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

173. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र स्थित रामगढ़ रोड की दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

174. जयपुर स्थित कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा में सड़कों के सर्वथा अभाव पर चर्चा के लिए।

175. राजस्थान के नेशनल हाई वे 11 व 8 की दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूलाल (घाटोल)

176. घाटोल तहसील (बांसवाड़ा) में कई सड़कों के पुल नहीं बने हैं, कहीं अधूरी सड़कें पड़ी हुई हैं, उन्हें पूर्ण करने व नई सड़कों का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर)

177. पुलों के निर्माण में देरी एवं सड़क निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

178. सड़कों की चिन्ताजनक हालत को सुधारने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिए।

श्री भेरूंलाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा)

179. विजय नगर रोड से धनोप माताजी (त. शाहपुरा) रोड का पुर्ननिर्माण एवं नव निर्माण कराने पर चर्चा के लिए।

180. बिगोद से नन्दराय (जिला भीलवाड़ा) मार्ग को पक्का डामरयुक्त कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली)

181. तहसील फागी जिला जयपुर में चितोड़ा गांव है जहां रोड का निर्माण हो रहा है वहां गांव के पास न होकर यह किसी उच्चअधिकारी के फार्म के पास बनाई जा रही है पर चर्चा के लिये।

182. मावली क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य की उपेक्षा जनता की मांग होने पर भी विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने तथा पक्षपात बरतने की नीति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

183. रामगंज मण्डी और पंचायत समिति लाड़पुरा की टूटी फूटी गिट्टी डली सड़कों को विभाग द्वारा ठीक नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर)

184. श्रीमाधोपुर से कोटड़ी व गढ़-भोमजी की दो हजार से अधिक की आबादी होते हुए भी सड़क का सर्वे व कार्य चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. ग्राम हाथीदेह से अजीतगढ़ (सीकर) तक सड़क पक्की का सर्वे व कार्य नहीं शुरू होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. ग्राम झाडली से आगे हाथी देह तक रास्ता खराब होने से सड़क पक्की नहीं बनने से यातायात में भारी असुविधा पर चर्चा के लिये।

187. ग्राम कांवट (सीकर) के पास पुल का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. अप्रोच रोड झाड़ली (सीकर) पर डामर नहीं डालने से यातायात में होने

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

वाली असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरा-पाटन)

189. राजस्थान में सड़कों व पुलों की दुर्दशा सुधारने हेतु काम के बदले अनाज योजना प्रारम्भ कर विभाग से रोड रोलर मुफ्त दिलाये जाने बावत चर्चा के लिये।

श्री हरीकृष्ण (नदबई)

190. डहरा पाड़े से झीलत्रावाड़ा, नदबई से हलेना तथा बांसी से मई एवं वाई घास बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

191. प्रमुख सड़कों से गांव को जोड़ने के लिए सहायक सड़कें निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

192. माखोदा क्षेत्र केशवराय पाटन में चम्बल नदी पर पुल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. केशवरायपाटन क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. कापरेन से रोटेदा, गेण्डोली से झालीझी का बरोना, अरनेढ़ा वाया जैथल होकर झालीझी का बराना, पापड़ी से बड़ा खेडा व बांसवाड़ा, लवान स्टेशन से भालोदा सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर)

195. ब्यावर से आबू रोड़ वाया पाली व सुमेरपुर तथा ब्यावर से फलौदी वाया जोधपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. अकाल राहत तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत निर्मित अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सैयद मंजूर अली (सवाई माधोपुर)

197. ग्राम चौकरी के करीब गम्भीर नदी पर पुल बनाने की चर्चा के लिये।

198. ग्राम सरवाली से शेरपर तक सीधी सड़क बनवाने की चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डौली)

199. हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र की सड़कों व पुलियाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर)

200. ग्राम उचियारड़ा तहसील जोधपुर में नदी पर पुल की आवश्यकता बाबत व सड़कें बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रावतराम (सुजानगढ़)

201. रतनगढ़-सालासर सड़क जिला चूरू, सुजानगढ़-लालगढ़ सड़क, छापर राजलदेसर सड़क चूरू-सरदारशहर सड़क पर कार्य चालू न होने पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर)

202. आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार एवं पुल निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

203. सड़कों व पुलों के अधूरे कार्य व नये कार्य के निर्माण कार्यों की धीमी गति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़)

204. आदिवासी क्षेत्रों में सड़क व लों के निर्माण में ढिलाई बरती जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा)

205. मसूदा क्षेत्र की सड़कों की खराब हालत पर चर्चा के लिये।

206. पहाड़ी व रेगिस्तानी इलाकों के हर गांव को सड़कों से जोड़ने बाबत चर्चा के लिये।

207. मसूदा से सखरवा जाने वाले रोड पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. राजस्थान में सड़कों की हालत बहुत खराब होने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री माणकलाल ठाकौर (नैनवा)

209. सरकार ग्रामीण अंचलों को शहरों से अभी तक नहीं जोड़ सकी तथा रामगंजमण्डी और लाडपुरा तहसील पूरी तरह उपेक्षित है इस पर चर्चा के लिए।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर)

210. प्रान्त के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

211. मेढा कृष्णगंज से कालन्द्री तक सड़क बनायी जाय इस पर चर्चा के लिये।

212. लास नदी, मांडानी, नदी जवाई नदी (पचानवा के नजदीक) तथा मणादर नाला पर पुलिया बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

213. जावाल-लास मणादर-हरजी-सड़क, कालन्द्री जसवन्तपुरा सड़क, जावाल-गोल-पोसालिया शिवगंज सड़क, जालोर-हरजी-रोवाड़ा-जोयला-शिवगंज सड़क, शिवगंज नेडा सड़क, हरजी-उम्मेदपुर सड़क निर्माण कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)

214. पिछड़े इलाकों विशेषकर रेगिस्तानी इलाकों में सड़कें न बनाई जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूराम (बागीदोरा)

215. बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्द जहूर (कामां)

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

216. कामां क्षेत्र में नई सड़कें बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

217. कामां से पहाड़ी जाने वाली सड़क की मरम्मत व उस पर पुलियां बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

218. टोडाभीम एवं नादौती क्षेत्र की वर्तमान सड़कों की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

219. बाड़मेर जिले के ग्राम समदड़ी से करमावास के दरम्यान जहां लूणी नदी बहती है वहां वर्षा के दिनों में रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, अतः पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार)

220. खण्डार तहसील में बनास नदी पर पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)

221. सींगोली मांडलगढ बडल्यास से सींगोली, धाकड़ खेड़ी, जोजवा होती हुई सड़क तथा त्रिवेणी से जहाजपुर वाया मानपुरा तथा त्रिवेणी से जलीन्द्री सड़क जल्द पूर्ण करने की चर्चा के लिये।

222. मांडलगढ़ क्षेत्र की हर पंचायत हैड क्वार्टर को सड़क से जोड़ने तथा नदियों पर पक्का पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुशलगढ़)

223 राजस्थान की सड़क व पुलों की भारी दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

224. पुलों के अभाव में जनता को होने वाली जान-माल की क्षति पर चर्चा के लिये।

225 अलवर जिले में नयी सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

226 निम्बी जोधा से दाठड़ी सड़क को पक्का कराने हेतु चर्चा के लिये।

227 लाडनूं से नागौर वाया निम्बी जोधा सड़क को पक्का कराने पर चर्चा के लिये।

228. जसवन्तगढ से मिठड़ी सड़क को पक्का करने पर चर्चा के लिये।

229. विभाग द्वारा लाडनूं क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत नहीं कर सकने पर चर्चा के लिये।

230. लाडनूं क्षेत्र की सड़कों पर कोई खर्चा नहीं करने तथा क्षेत्र मेड़ता में ही सारा खर्चा कर देने पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर)

231. चूरू जिले की अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने बाबत चर्चा के लिये।

232. अकाल राहत में बनी सड़कों को प्लान में देकर लाखों रुपयों के मैटीरियल का सदुपयोग करने बाबत चर्चा के लिये।

233 चूरू जिले की सड़कों की मरम्मत कराने बाबत चर्चा के लिये।

234. सड़क निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

235. लूणी नदी पर बाड़मेर जिले में बालोतरा के पास पुल नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

236. पचपदरा से कानोट (जिला बाड़मेर) की सड़क पर मरम्मत नहीं करने से उसकी अत्यन्त दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

237. आगोलाई से माडपुरा (जिला जोधपुर एवं बाड़मेर) जैसी अत्यन्त पुरानी एवं महत्वपूर्ण सड़क को डामर का नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

238. 1500 की जन संख्या के समस्त ग्रामों को सड़क से नहीं जोड़ने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

239. सीकर से झुंझुनूं तक के राज्य मार्ग की अत्यन्त खराब हालत पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

240 चौमूं क्षेत्र से सड़कों की दुर्दशा एवं उसमें सुधार के लिये किये जा रहे प्रयत्नों की चर्चा के लिये।

241. अकाल में बनी सड़कों की दुर्दशा एवं उनके पूर्ण व मरम्मत न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

242. राजस्थान की प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर)

243. सड़कें व पुल निर्माण में परिकल्पना का अभाव, भ्रष्टाचार की व्याप्ति व दिशाहीनता पर चर्चा के लिये ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

244. सड़कें व पुल बनाने में विभाग द्वारा वर्ती जा रही लापरवाही के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अयूब खां (तिजारा)

245. टपूकड़ा से नूह, कोट कासिम से धारूहेड़ा, पलासली से नगीना, झिवाने से तावड़ अन्तर्राज्य मार्ग को पूरा कराए जाने हेतु चर्चा के लिये ।

246 तिजारा से घासोली वाया खानपुर मेवान सड़क पूरी कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

247. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने हेतु तथा नई सड़कों के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

248. राज्य के सीमावर्ती जिलों की सड़कों को जहां बड़े 2 टैंकों और गाड़ियों से बड़ा नुकसान होता है, वहां मरम्मत के लिये चर्चा के लिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)

249. बड़ल्यास से त्रिवेणी नदी तक मानपुरा से जलन्द्री तक व त्रिवेणी से जहाजपुर तक जहां जहां भी वर्षा काल में आना जाना असम्भव हो जून तक सड़कें एवं पुल के निर्माण के काम सबसे पहले हाथ में लेने की चर्चा के लिये ।

250. खटवाड़ा-बीगोद के बीच बनास पर पुलिया, जोजवा त्रिवेणी के मध्य मेनाली का पुल, बड़ल्यास, आकोला के मध्य बनास पर पुल व सोलंकियों का खेड़ा और गेंदलया के बीच बनास नदी का पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)

251. आसीन्द बाई पास बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी)

252. जिला झुन्झुनू में सड़कों एवं भवनों के लिये बजट प्रावधान करने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये ।

253 जिला झुन्झुनू में सड़क निर्माण कार्यों एवं पुल निर्माण कार्यों के करने के लिये बजट प्रावधान करने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज पंवार (चूरू)

254. सड़क निर्माण में बरती जाने वाली अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये ।

255. इस वर्ष में हुई भारी वर्षा से टूटी सड़कों व पुलियाओं की शीघ्र मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(श्री मेघराज पंवार)

256. सड़क निर्माण के सबन्ध में कोई निश्चित नीति न होने की वजह से होने वाली फिजूल खर्ची में मितव्ययता लाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई)

257. गांवों में सड़कों के बिना ग्रामोत्थान केवल सपना है, इस पर चर्चा के लिये।

258. पुल निगम के गठन में हो रही देरी की चर्चा के लिये।

259 सडक व पुल निगम बनाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)

260. रामसर–चौहटण ग्रेवल रोड जो कि अकाल सहायता के अन्तर्गत निर्मित की गई थी के निर्माण में लाखों रुपयों का घोटाला करने के उपरान्त भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कदम न उठाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

261. बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में अकाल राहत कार्यों से बनी सड़कों की मरम्मत एवं सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी)

262. बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के मार्ग नीकूम से बडी सादड़ी को नहीं बनाए जाने एवं मंगलवाड से निम्बाहेडा के बीच नीकूम के पास पुलियाओं के अभाव के कारण जनता की परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनीराम (तारानगर)

263 तारानगर चूरू सड़क एवं तारानगर–भादरा सड़क जो वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है को पूरा कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर)

264. परबतसर तहसील में 20 साल पुरानी कच्ची सड़कों को पक्का बनाने के के लिये चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

265. करेडा से डमरी सड़क पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. अजमेरा चौराहा से मांडल गांव तक सडक की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. भीलवाड़ा से देवगढ़ रोड की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. मांडल से झरवानपुरा वाया भीमड़िया से सड़क पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये।

269. कटेड़ा से रामपुर रोड पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. नौगावा गाढ़ा माला सड़क को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

271. करेड़ा से भीम रोड को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. भगवानपुरा-बेमाली रोड को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

273. सुरास अमरगढ़ सड़क के निर्माण पर चर्चा के लिये।

274. खारी नदी विजयनगर के पास पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. खारी नदी पंचायत समिति मांडल पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामदेव सिंह (धोद)

श्री रिणमलसिंह (सीकर)

276. सीकर, लोसल सडक वाया धोद, फासमी को बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

277. कूदन, खूडी (जिला सीकर) के बीच में सिर्फ तीन किलो मीटर सडक जो अपूर्ण पडी है को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गम्भीरी लाल (सराड़ा)

278 सराडा तहसील की अधूरी सड़कों को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा)

279. नयी सड़कें केशरीयाजी से झाडोल व गोहावाड़ा से पाटा खेरवाड़ा तहसील में चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

280. खेरवाड़ा तहसील में सड़कों एवं भवनों के नये कार्य खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

281. खेरवाड़ा तहसील में छाणी से पांचरी खेरवाड़ा से सोम खेरवाड़ा से कल्याणपुर खेरवाड़ा से ऋषदेव वाया भुदर जवास की सड़कों के कार्यों को चलाने की चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़)

282 अकाल में बनी सड़कों की दुर्दशा एवं इनके पूर्ण व मरम्मत न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

283. आमेर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा एवं उसमें सुधार के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की चर्चा के लिए।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़)

284. विधान सभा क्षेत्र जमवा रामगढ़ के अन्दर अधूरी सड़कों को पूरी करने तथा मनोहरपुर से मेंड एवं मेंड से प्रतापगढ़ के रोड बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नारायण मीणा (लसाडिया)

285. धरियावद तहसील की अधूरी सड़कों को पूरी करने, लसाडिया से धरियावद

(श्री नारायण मीणा)
सड़क को पूरी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भूरा लाल (गोगुन्दा)

286. गोगुन्दा से भाडौल सडक का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

287. गोगुन्दा से ओगणा सडक से जाडापिपल का निर्माण कार्य तथा सायरा से भानपुरा सड़क के निर्माण हेतु चर्चा के लिए।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना)

288. सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सड़कों को एवं पुल के कार्य के व्यवसायिकरण (कॉमर्शियलाइजेशन) के प्रश्न पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा)

289. बिलाड़ा क्षेत्र में निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा बरतने की चर्चा के लिए।

290. बिलाडा क्षेत्र में ग्रेवल सड़कों पर फेमिन का पड़ा मैटीरियल में क्षति होने एवं लोगों द्वारा चुराया जाने व ठेकेदारों द्वारा काम में लेने पर चर्चा के लिए।

291. बिलाड़ा के पास बाण गंगा नदी पर पुलिया बनाने में की जा रही ढील पर चर्चा के लिए।

श्री अयूब खां (तिजारा)

292. कोट कासिम से नन्दरामपुर हरियाणा अन्तर राज्य मार्ग की सड़क को पूरा किये जाने हेतु चर्चा के लिए

293. तिजारा से घासोली वाया खानपुर मेवान सड़क को पूरा किया जाने हेतु चर्चा के लिये।

294. टपूकड़नूंह रोड को पुलियाओं सहित पूरा किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

295. भिवाना-टपूकड़ा सड़क की मरम्मत तथा इस पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

296. नाहरी का नाका क्षेत्र, जयपुर में सड़कों की जर्जरित स्थिति तथा इन सड़कों की मरम्मत कराने व मिट्टी हटाने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

297. राजस्थान में सडकों की खराब हालत की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने पर चर्चा के लिये।

298. धौलपुर उपखण्ड में जातौली कुथियाना सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

मांग से सम्बन्धित विभाग का प्रगति विवरण

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रगति विवरण सरकार द्वारा दिया गया है, यह एक महत्वपूर्ण

(श्री परसराम मदेरणा)

डिमांड है। उस दिन भी उद्योग विभाग वाली बात पर पाइंट आफ आर्डर रेज किया गया था। मैं उद्योग मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि 3-4 दिन का समय है, आप रिपोर्ट प्रिंट करवा दें, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): मैं आज ही आदेश जारी करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा: जो भी प्रगति विवरण मंत्री महोदय के पास आ रहा है, कम से कम सरकारी अधिकारी उस विवरण में लिखें कि उसके अन्दर जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कितने आपने प्राप्त कर लिये हैं। पेज 5 पर लिखा है वर्ष 1977-78 में 94.95 लाख रुपये व्यय किये गये तथा 17 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 1977-78 में 220 लाख रुपये का प्रावधान है तथा 25 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। यह 1978 है या 1979 है? या किसी दूसरे विभाग की राजस्थान कैनाल की रिपोर्ट है? एक ही साल का मामला है? आलोच्य वर्ष का जिक्र ही नहीं है, तो हम अन्धकार में रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो विवरण मिले उसमें पूरी जानकारी मिले।

श्री मूलचन्द डागा: वर्ष 1978-79 के लिए जो कोई धनराशि हमने पास की, मैं जानना चाहता था कि बजट के आधार पर कितनी सड़कें बनाई गई कितना रुपया खर्च हो गया, कितना बकाया रह गया। इस रिपोर्ट से मालूम नहीं होता। यह रिपोर्ट बिल्कुल इसके लिए शांत है। मैं जानता हूं कि बहुमत के आधार पर मेरा पाइंट आफ आर्डर नहीं माना जाएगा लेकिन प्रतिवेदन का मतलब है कि कितना रुपया खर्च किया गया, क्या फिजीकल परफार्मेंस रहा, यह इस रिपोर्ट से मालूम नहीं होता।

कटौती प्रस्तावों पर वक्ताओं का क्रम

श्री रघुनन्दन व्यास: कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिए परसों व्यवस्था आसन की ओर से दी गई, हम लोगों को कटौती प्रस्तावों के आधार पर सूचना मिलती है लेकिन प्रायः हम लोग सस्पेंस में रहते हैं कि किसको बोलना है, किसको नहीं। इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और जिस भावना को लेकर हम सदन में आते हैं उसके आधार पर मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपकी व्यवस्था बदली है तो वह भी अगर हम शिरोधार्य करेंगे लेकिन कम से कम सदस्यों को सूचना तो मिले कि किसको बोलना है, कब बोलना है। कटौती प्रस्तावों की परम्परा 30 साल पहले कैसी भी रही हो लेकिन दो साल से जो रही है उसको मानते हुए चल रहे हैं। परसों से उस व्यवस्था के बारे में बिल्कुल असमंजस की स्थिति है। हमारे साथ न्याय करिए, हम अपनी बात कह सकें, इस सदन को एक प्रजातांत्रिक फोरम बनाए रखा जा सके, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ न कुछ आदेश प्रदान करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): माननीय डागा जी ने जो पाइंट आफ आर्डर

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

उठाया है प्रगति विवरण के बारे में, वास्तव में 1979 में रोड्स के बारे में विभिन्न जिलों में कोई भी प्रगति नहीं बताई। 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए कह सकते हैं कि कितनी सड़कें बनाई गई, क्या प्रगति इस सरकार ने की, कोई जानकारी नहीं है कि कितना व्यय हुआ। पूरी रिपोर्ट न होने से हमें रिपोर्ट को डिसकस करने में दिक्कत आती है और हमको भी आलोचना सुननी पड़ती है। इसलिये अध्यक्ष जी आप मन्त्री जी को आदेश दें कि इसके बाद जो प्रगति विवरण आयें उनमें 1978-79 का पूरा विवरण हो।

श्री मथुरादास माथुर : (डीडवाना) यह अहम् मसला है। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा हमारे यहां पर संसद की एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिश पर, राजस्थान की पहले की एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिश पर फिजीकल परफार्मेंस बजट पेश होना शुरू हुआ और तीन साल तक होता रहा और जनता सरकार का पहले एक साल में फिजीकल परफार्मेंस बजट पेश हुआ उसके बाद दो साल में यह बन्द किया। अब न तो फिजीकल परफर्मेंस बजट पेश होता है, न रिपोर्ट आती है। एक हैड आफ डिपार्टमेंट का डिप्टी और उसका असिस्टेंट आंकड़े इकट्ठे करके इधर उधर से लेकर रख दिया और उस पर यह बढ़िया पन्ना लगा गया और अन्दर कुछ पढ़ने का मिलता नहीं। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, सदन के साथ राज्य सरकार द्वारा मखौल किया जा रहा है, फिजीकल परफार्मेंस बजट पेश नहीं होता, संसद में हर 4 महीने होता है, आप साल में एक बार भी नहीं करते। फिजीकल अचीवमेंट्स आने चाहियें। एक सड़क का बजट प्रावधान एक करोड़ था, 20 मील बनाने थे, उसके अगेन्स्ट 15 मील बने तो 20 मील वाला पैसा मन्त्री ने दूसरी जगह तो खर्च नहीं किया।

यह सब बातें डिस्ट्रिक्टवाइज और हैडवाइज आनी चाहियें तब ही उसको हम प्रगति रिपोर्ट समझेंगे। इसमें फिजीकल परफार्मेन्स नहीं आती और फिर हमसे आशा की जाती है कि हम यहां बैठकर रचनात्मक तरीके से सरकार को सहयोग दें। जो कुछ परम्परा आज लोकसभा में है और दूसरे राज्यों में है, मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम नौ-दस राज्यों में फिजीकल परफार्मेन्स का बजट पेश करना शुरु किया है और राजस्थान में भी ऐसा हुआ। यहां भी तीन साल तक फिजीकल परफार्मेन्स का बजट पेश हुआ और अब दो साल से आप बिल्कुल चुप हैं और जवाब नहीं देते। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट के ऊपर हम जस्टीफिकेशन दे सकें और माननीय सदस्य बोल सकें और हम सुझाव दे सकें ताकि उनका सरकार फायदा उठा सके और राजस्थान का एक-एक पैसा सही तरीके से खर्च कर सके, इससे राजस्थान का विकास हो। इस भावना के साथ मैंने प्रश्न उठाया है।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह फिजीकल परफार्मेन्स के बारे में जहां तक माननीय माथुर साहब ने अभी आपके सामने निवेदन किया है, यह जान-

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बूझ कर नहीं देते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा था और मैंने जानना चाहा था कि जोधपुर जिले में इस साल कुल कितना खर्चा हुआ और कोटा और डूंगरपुर में कितना खर्चा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके डूंगरपुर जिले में केवल 7 लाख, जोधपुर में 18 लाख और कोटा में 335 लाख रुपया इस साल खर्च हुआ है। तो अब आप देखिये कि कितना डिस्क्रिमिनेशन पिछली साल में सड़कों के ऊपर रहा है। यह जान-बूझकर नहीं देते हैं, क्योंकि जब इनको मालूम है कि कोटा के अन्दर एक ही जिले में 335 लाख रुपया खर्च कर दिया जबकि जोधपुर उसके बराबर का जिला है, उससे बड़ा जिला है और किसी हालत में कम नहीं है और डिवीजन का हैडक्वार्टर है और हाईकोर्ट की सीट होते हुए वहां 18 लाख रुपया खर्च किया है और आपके जिले में 9 लाख खर्च किया है, तो यह जान-बूझकर फिजीकल टार्गेट नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के माननीय नेता महोदय और अन्य विपक्ष के सदस्य महोदयों ने जो आपत्तियां उठाई हैं वह एक हद तक वाजिब हैं। अगर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट के अन्दर कोई मुद्दे ही नहीं हैं कि जिनके ऊपर बहस या चर्चा की जा सके तो वह चर्चा सार्थक नहीं हो सकती। मैंने परसों भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार का पुरजोर शब्दों में ध्यान आकर्षित किया था। मैं अब भी ध्यान आकर्षित करता हूं और सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और प्रोग्रेसिव रिपोर्ट फुल फैक्ट्स के साथ जब तक नहीं आती है तब तक इस सदन के अन्दर दोनों पक्षों में कोई बहस सार्थक रूप से हो ऐसा मैं अनुभव नहीं कर सकता। अतएव सरकार से मैं फिर पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं और यह चेतावनी के रूप में निवेदन करता हूं कि आइन्दा ऐसी शिकायत का मौका नहीं आना चाहिये।

माननीय सदस्य श्री रघुनन्दन जी व्यास ने जो आपत्ति उठाई उसके साथ भी मेरी सहानुभूति है लेकिन बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में यह निर्णय हो चुका है आपके वरिष्ठ नेताओं और प्रतिनिधियों के द्वारा कि जो माननीय सदस्य, शासन पक्ष के कटौती प्रस्ताव दें वह मुख्य सचेतक महोदय को दें और मुख्य सचेतक महोदय जी मुझे तालिका देंगे और जिस क्रम में देंगे उसी क्रम के अनुसार मैं माननीय सदस्यों का नाम पुकारूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। अगर कोई मुख्य सचेतक या पार्टी का वरिष्ठ नेता किसी सदस्य से नाराज हो जाये और आप फिर उसको संरक्षण नहीं दें तो वह कहां जावे और कैसे अपने विचार रखें ?

श्री अध्यक्ष : यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : (बाड़मेर) बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं हुई और न उसको मन्जूर किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : न रिपोर्ट आई और न हमारी स्वीकृति ली गयी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माथुर साहब इनको जरा समझाइये कि उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : इनको तो मैं समझा लूंगा लेकिन आप भी तो समझें।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था Tentative conclusion arrived at जो निर्णय लिया गया उसे अभी प्रकाशित नहीं किया जाये और सदन की अनुमति भी नहीं ली जाये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में शुक्रवार को आपकी व्यवस्था हो चुकी थी। आपकी व्यवस्था के अनुरूप ही बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में डिसीजन लिया गया इसलिए रिपोर्ट का प्रश्न कहां आता है ? नहीं आता है। आप व्यवस्था दे चुके थे हाउस में और आपने कहा था कि मैं बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग बुला रहा हूं और मीटिंग हुई भी और उसमें आपकी व्यवस्था के बारे में सहमति जाहिर की गयी। इसलिए आपकी व्यवस्था तो दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने स्पष्टीकरण किया आप सभी उस व्यवस्था से अवगत हैं।

श्री बहादुर सिंह।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह अलग बात है। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में यह डिसीजन हो जाये कि अमुक-अमुक पार्टी के चीफ व्हिप सूची देंगे और उसके अनुसार पुकारेंगे, ऐसा बिजनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में रिकार्ड नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो आसन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। यह तो आपका इन्टरनल अरेन्जमेण्ट है लेकिन इस आसन को सुशोभित करते हुए ऐसी व्यवस्था चला देंगे कि उनकी लिस्ट आयेगी और उसके अनुसार ही नाम कॉल करते जायेंगे तो, मान्यवर, न तो ऐसा कभी इस सदन में हुआ है, न लोकसभा में हुआ है और मैं समझता हूं कि होगा भी नहीं। यह तो आपका प्रोरेगेटिव है, यह तो इनफार्मल एडजस्टमेन्ट है। वह आपको असिस्ट करते हैं और उनका असिस्टेन्स आप ले रहे हैं और आप अपने विवेक से सदन का संचालन कर रहे हैं तो, मान्यवर, इस पद की गरिमा को स्थायित्व देते हुए कृपा करके बिजनेस एडवाईजरी कमेटी और चीफ व्हिप का उल्लेख नहीं करें। यह इस सदन की परम्परा के अनुरूप नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं कि रामनारायण जी ने कहा वह सही है। जिसकी पार्टी नहीं है उनको रिप्रेजेन्ट कौन करेगा। न तो आपकी पार्टी है और न मेरी है इसलिए उसके ऊपर भी तो विचार करें।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव मांग संख्या 19 और 21 पर हैं और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह तो सर्वविदित है

श्री बहादुर सिंह (नोहर)

कि सड़कों का देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योग के विकास में, व्यापार के विकास में, क्षेत्र के आवागमन के विकास में सड़कों का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश का जो क्षेत्रवार सड़कों का विवरण दिया गया है उसके आधार पर लगता है कि सड़कों का हमारे प्रदेश में बहुत अभाव है। इस अभाव का हमारे विकास पर विपरीत असर पड़ता है, मंडियों के विकास में भी विपरीत असर पड़ता है और हमारे क्षेत्र के उद्योगों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सरकार सड़कों की ओर विशेष ध्यान दे। सरकार ने जो प्रतिवेदन पेश किया है, उस प्रतिवेदन से यह जाहिर होता है कि सडकों के निर्माण में हमारे विभागों का समन्वय नहीं है। सड़कों का जो निर्माण किया गया है वह अलग हैडिंग के तहत किया गया है जिससे हमारे क्षेत्र की उपयोगिता का ख्याल नहीं रह सका हैं और कहीं कहीं तो सड़कें ज्यादा बन गई हैं और जहां ज्यादा जरूरत है वहां नहीं बनी हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विभागों का समन्वय करके क्षेत्रीय विकास की ओर, व्यापारिक विकास की ओर, औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार को कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी ओर मैं विशेषकर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वे सड़कें जो बनती हैं उनकी क्वालिटी और मापदण्ड जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार नहीं बनती हैं–सड़कें जल्दी टूट जाती हैं और फिर टूटी हुई सड़कों की मरम्मत समय पर नहीं की जाती है। इसलिये जो महत्वपूर्ण सड़कें होती है वे भी परिवहन के लायक नहीं रहती हैं जिससे सरकार का पैसा बर्बाद जाता है और क्षेत्र का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है।

तीसरी बात, सडकों के निर्माण में जो बुरी बात है वह यह है कि सड़कों के किनारे विभाग सामान डाल देता हैं, रोड़ी डाल देता है, डामर के ढोल डाल देते हैं और वह सामान खराब हो जाता है, चोरी चला जाता है जिससे भी सरकार को काफी नुकसान होता है और उस नुकसान के कारण हमारी सड़कों का जो विकास होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जब सड़कों के बनाने की पूरी तैयारी हो तब ही सामान डाला जाय, वरना सामान खराब हो जाता है, चोरी चला जाता है। इससे वहां के अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार में प्रोत्साहन मिलता है और साथ में आम नागरिक को भी। कभी-कभी सड़क निर्माण के लिये सड़क के किनारे ईंटें डाल दी जाती है और फिर डालने के बाद विभाग कोई देखभाल नहीं करता है तो वे ईंटें काफी मात्रा में चोरी चली जाती हैं। इसलिये विभागों के नहीं संभालने के कारण विभाग का काफी सामान फिजूल जाता है।

(3-12 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

(श्री बहादुर सिंह)

चौथी बात जिसे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पी. डब्ल्यू. डी. में प्रशासनिक खर्चा और भवनों के निर्माण का खर्चा बहुत ज्यादा कर रखा है, इसलिये प्रशासनिक खर्चों में कटौती की जाय और पी. डब्ल्यू. डी. के जो सर्किट हाऊस और रेस्ट हाउस बने हुये हैं उनमें भी खर्चा कम किया जाय। बड़े बड़े गद्दे, पलंग, कीमती क्राकरी, बड़ी महंगी दरियां, महंगा फर्नीचर, बड़े महंगे करटेन आदि लगा रखे हैं उनमें सम्पूर्ण रूप से सादगी लाई जाय। जो आफिसर उन रेस्ट हाउसेज में या सर्किट हाउसेज में ठहरते हैं और जो रात-दिन अपने घरों में रहते हैं उससे बहुत अधिक सुख-सुविधायें उनको वहां उपलब्ध हो जाती हैं। उनको अपने घरों में वे चीजें नहीं मिलती हैं तो हमारे देश की पूंजी को फिर इस तरह क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. के जितने रेस्ट हाउस और सर्किट हाउसेज हैं उनमें साधारण तरीके का फर्नीचर, साधारण तरीके के पर्दे, साधारण तरीके के पलंग-गद्दे ही होने चाहिये। इन पर जो अनावश्यक खर्चा किया जाता है, वह न किया जाय।

पांचवी बात, मैं सरकार के ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि जो क्षेत्रीय समस्यायें हैं, उनको देखकर ही सड़कों का निर्माण किया जावे। 30 साल तक जो हमारे देश में विकास नहीं हो सका और जिन पर हम एलीगेशन लगाते रहे हैं कि देश की आवश्यकता और उपयोगिता को देखकर सड़कों का निर्माण नहीं किया बल्कि राजनैतिक कारणों से सड़कों का निर्माण हुआ है और जिससे हमारे देश की पैदावार पर विपरीत असर पड़ा है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज भी इस सरकार में वही प्रक्रिया चालू है। सड़कें वहां बनाई जा रही हैं जहां उपयोगिता और आवश्यकता नहीं है और जहां उपयोगिता और आवश्यकता है उस क्षेत्र को आज भी नेगलेक्ट किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नोहर, सरसों को छोड़कर सारे उत्तरी भारत में चने की दूसरे नम्बर की बड़ी मण्डी है लेकिन इस क्षेत्र में सड़कों का अभाव है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके दोनों ओर हरियाणा लगता है और हरियाणा ने राजस्थान के गांवों के पास तक सड़कें बना रखी हैं इसलिये मेरे क्षेत्र का सारा अनाज सड़कों की कमी के कारण हरियाणा को चला जाता है जिससे नोहर नगरपालिका को और नोहर कृषि उपज मण्डी को भी काफी नुकसान होता है, जो उत्तरी भारत के चने की दूसरे नम्बर की मण्डी है। अगर आस-पास में सड़कें बना दी जाय तो जितना पैसा आप सड़क निर्माण में लगायेंगे उससे ज्यादा आपको उस क्षेत्र से मिल जायगा। नोहर की मण्डी की बहुत बड़ी आय है लेकिन आपने पी. डब्ल्यू. डी. को इसका भार दे रखा है। पी. डब्ल्यू. डी. को इतनी बड़ी धनराशि देने के बाद भी सड़कों पर ध्यान नहीं दिया है और जो सड़कें बनी हुई हैं, उनकी वर्षों से मरम्मत नहीं हो रही है।

मेरे क्षेत्र में गंगानगर और दिल्ली की मुख्य सड़क है। वह सड़क भी डिफेन्स में

(श्री बहादुर सिंह)

आ गई है और बहुत थोड़ी सड़क पी.डब्ल्यू.डी. में बची है लेकिन उस पर पी.डब्ल्यू.डी. ध्यान नहीं दे रहा है। आज उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि डिफेंस में आ जाने के बाद न तो पी. डब्ल्यू डी. मरम्मत करा रही और न ही डिफेन्स उस पर पूरा ध्यान दे रहा है। आवागमन का जो एकमात्र रास्ता है, वह टूटा हुआ है। इसी तरह दूसरी सड़कें जो हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में नोहर से सावा, नोहर से सादड़ी उनकी हालत भी यह है कि बसेज नहीं चल सकती हैं, ट्रक नहीं चल सकते हैं और सारा आवागमन का मार्ग अवरुद्ध है, कच्चे रास्ते में होकर जाना पड़ता है। इसलिये मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, सरकार क्षेत्रीय आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखकर सड़कें बनाये तो इससे सरकार को भी लाभ होगा और उस क्षेत्र के व्यापार को, उद्योग को और कृषि को भी लाभ होगा।

मैं मेरे क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, नोहर से साल की ओर। साल चूरू जिले की मण्डी है, बीच में रेगिस्तानी इलाका है, आवागमन बड़ा कठिन है और बड़े-बड़े गांव बीच में पड़ते हैं। ट्रैफिक इतना चलता है कि बसों में बैठने की जगह नहीं मिलती है और लोगों को इधर से उधर जाने में बड़ी कठिनाई होती है। सड़कें न होने से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसलिये ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, कृषि उपज मण्डी का ध्यान रखते हुए नोहर-साला और नोहर-पल्लू जो रेगिस्तानी इलाके का बहुत लम्बा चौड़ा क्षेत्र है उसमें कहीं सड़क नहीं है अतः वहां भी सडक बनाई जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन पेश किया है उसमें यह डिक्लेरेशन किया हुआ है कि पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा किन्तु मेरे क्षेत्र में ललाना क्षेत्र है जिसकी आबादी दस हजार है लेकिन वह किसी भी तरफ से सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको भी सड़क से जोड़ा जाय।

मैं सरकार से, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों के मामले में इस विभाग के द्वारा जो भ्रष्टाचार होता है, जो अनियमिततायें हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको अगर समाप्त कर दिया जावे तो बहुत सा प्रोवीजन सड़कों के बनाने के लिए मिल जाएगा और सड़कें बनाने में सहायता मिलेगी इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगर सड़कें बनाते हैं तो मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर वे ध्यान रखें और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी तरफ ध्यान रखें और आवागमन की आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखकर सड़कें बनायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव सड़कों और पुलों के सम्बन्ध में दिया है, उनमें मुख्यतः राष्ट्रीयकृत मार्गों की

(श्री शिवनारायण)

अवस्था और न्यूनमत आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई जाने वाली सड़कों के बारे में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश के विकास का पैमाना नापने का अगर कोई आधार है तो यह है कि उस देश में सड़कों की बहुतायत कैसी है। यह एक बहुत बड़ा मापदण्ड है। सड़कों की आवश्यकता मात्र आवागमन के लिए नहीं बल्कि उस क्षेत्र के विकास उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास, उस अन्त्योदयी परिवार की न्यूनमत आवश्यकता की प्राप्ति के साधन बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसलिए जो हमारे राज्य में सड़कों की स्थिति है वह उस अनुपात से नहीं बढ़ी कि जिस अनुपात से अपेक्षित थी। सन् 1951 में हमारे राज्य में करीब सवा सत्तरह हजार किलोमीटर सड़कें थीं और 77 तक वह बढ़ कर केवल 39 हजार किलोमीटर हो पाई हैं। जब कि हमारी अन्य आवश्यकताओं की, अन्य सामाजिक जीवन की आवश्यकतायें कई गुनी बढ़ चुकी है। यह माना कि हमारा क्षेत्र देश में दूसरे स्थान पर है और जो क्षेत्रफल है, हमारा राज्य का क्षेत्रफल है वह बहुत वृहद् है परन्तु सड़कों की जो स्थिति है वह हमारे राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बड़ी शोचनीय है। उसमें हमारा स्थान केवल 19 वां है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि हमारी विगत सरकार ने इस ओर जो उपेक्षा की वह वांछनीय नहीं थी। अब जनता सरकार ने जो इस वर्ष सड़कों का बजट 47 करोड़ समर्थिग से बढा कर जो 67 करोड़ समर्पित किया है वह इस बात का परिचायक है कि वास्तव में हम गांवों में, राज्य में, सड़कों की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। सन् 77-78 में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उन सभी गांवों को जोड़ने की स्वीकृति दी कि जिनकी आबादी पांच हजार से अधिक की थी परन्तु दो वर्षों के बाद भी यह 78-79 समाप्त होने जा रहा है, 18 गांव भी अभी तक नहीं जोड़ पाये हैं। और अब छठी पंचवर्षीय योजना में इस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पन्द्रह सौ की आबादी के सभी गांवों को इस योजना के अन्तर्गत जोड़ दिया जावेगा और एक हजार से पन्द्रह सौ की आबादी में आने वाले गांवों में से पचास प्रतिशत को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, यह संदेहास्पद बात है। क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं। हमें घोषणा या हमें लक्ष्य वही रखने चाहियें जो हमारे वित्तीय साधनों के अनुकूल हों और हम कारगर रूप से जिसको निभा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों में यह चैतन्यता है, मैं राज्य सरकार को आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किसी गांव को सड़क से जोड़ना है, उसका प्रबन्ध करना है तो जिस तरह से पहले जलप्रदाय योजना के अन्दर एक पर्सेंट, दो पर्सेंट, पांच पर्सेंट तक गांव वालों से जो रकम जमा कराते थे, उसी तरह से यहां पर रकम जमा करा ली जाय और उस गांव को सड़क दे दी जावे। वे चाहते हैं अपना विकास करना। वे चाहते हैं कि उनकी उत्पादित वस्तु मण्डी में पहुंचे। वे पंचायत समिति स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, उनको तहसील स्तर पर पहुंचना है,

(श्री शिवनारायण)

उनको न्यायालय में पहुंचना बहुत आवश्यक है और मैं यह जो सारी बातें निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान, वह वास्तव में ग्रामीण काश्तकारों को, गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को जो असुविधा होती है, उसके कारण ही निवेदन कर रहा हूं।

हमारे क्षेत्र में थानागाजी क्षेत्र में करीब-करीब सारा मार्ग राष्ट्रीयकृत है और उन मार्गों की अवस्था श्रीमान बडी अजीब है। उन सडकों के अभाव के कारण हमारी जनता सरकार की जो बदनामी होती है उससे हमें बड़ा दुख होता है क्योंकि रोडवेज वाले सड़क का बहाना बना कर अक्सर बरसात में ब्रेक डाउन कर देते हैं और गंतव्य स्थान पर न पहुंच कर दस किलोमीटर, बीस किलोमीटर उरली तरफ ही बस को रोक कर मुसाफिरों को भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। इससे बडी असुविधा होती है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसा लक्ष्य बनाया जावे कि जिसमें जिस किसी क्षेत्र का सम्बन्ध हो, जो भी राष्ट्रीयकृत मार्ग हो, उन सड़कों की दशा किस प्रकार की है उसका सर्वेक्षण कराया जावे ताकि परिवहन की अव्यवस्था न हो, जनता को असुविधा न हो और गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कण्डक्टर और ड्राइवर अपनी अक्षमता का परिचय न दे सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सड़क थानागाजी से गुढा बाया किशोरी अजयगढ सड़क है जिसकी बहुत खराब हालत है। दस वर्ष पहले उसमें कॅश के अन्तर्गत पत्थर जमा दिए गए लेकिन वह जो मार्ग था, चालू मार्ग भी उस पत्थर गड़ाने से अवरुद्ध हो गया और ऐसी बड़ी दिक्कत पैदा होती है कि चार पांच महीने तक बरसात में कोई भी बस या कोई भी ऊंट या कोई भी बैलगाड़ी उसमें से नहीं निकल सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपेक्षा करता हूं और मैं निवेदन करता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि ऐसी सड़कों का सर्वेक्षण कराया जाकर शीघ्र ही उनको लाभान्वित करेंगे ताकि गांवों में रहने वाले लोग जनता सरकार के प्रति पूरी आस्था से रह सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना सड़कों की समुचित व्यवस्था के गांवों में रहने वालों का उत्थान नहीं हो सकता। जिस गांव में सड़क पहुंच गई है, जिस शहर में सड़क पहुंच गई है उस गांव का, उस शहर का, उस कस्बे का बिना किसी प्रयास के उत्थान हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि अब काश्तकार को फसल का पूरा पैसा मिले, उसको सस्ता खाद बीज मिले, उपभोक्ता को उचित समय पर उचित कीमत पर चीज मिले, गांवों की दौड़ शहर की तरफ नहीं हो, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, गांवों में उद्योग धन्धे कायम हों, तो उसके लिए आवश्यक है

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

कि सड़कों का जाल बिछे। बिना सड़कों की समुचित व्यवस्था के न तो गांवों का उत्थान हो सकता है और न शहर ही उत्थान कर सकते हैं। किसी देश की आजादी के लिए तीस साल का समय कम नहीं होता है और तीस साल की अवधि के अन्दर गांवों में झोंपड़ो में रहने वाले काश्तकार, मजदूर, गांवों में बसने वाला देश भारत उपेक्षित रहा है और उस भोली भाली जनता को भुलावे में रख कर कांग्रेस ने तीस साल तक राज किया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्यों कोस रहे हो ? जो हमने सड़कें बनाई है उनकी मरम्मत ही करवा लो तो आपका जनता आभार मानेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुनों तो सही। हमने क्या किया है और आपने क्या किया हैं। हम नई सड़कें बनाने की बात....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जो सड़कें कांग्रेस सरकार ने बनाई हैं उनकी अगर मरम्मत भी कर लो तो आपका बहुत काम हो जावेगा, जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर अगर जुल्म और ज्यादतियां नहीं होतीं, सत्ता का परिवर्तन नहीं होता तो पता नहीं कब तक जनता को भुलावे में डाल कर सरकार चलाते रहते और जनता को, गांवों को उपेक्षित रखते। देश का सौभाग्य रहा कि तीस साल के बाद सत्ता में परिवर्तन आया और हमारी जनता सरकार ने जनता की भावनाओं का आदर करके गांवों के अन्दर निर्माण के कार्य आरम्भ किये हैं। इसका जीता जागता उदाहरण 'काम के बदले अनाज' योजना है। इस योजना के तहत सात हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार ने जिस ने तीस साल तक राज्य किया, उसने कभी गांव की तरफ ध्यान दिया था ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के तहत गांवों के रास्ते ठीक हुए हैं। जहां जीप नहीं जा सकती थी, बैलगाडी नहीं जा सकती थी, पैदल नहीं जा सकते थे, उन रास्तों को 'काम के बदले अनाज योजना' के तहत ठीक किया गया है। और अब वहां पर गाडी, जीप, साइकिल जाने लगी हैं। इसका लाभ किस को मिलेगा, बेशक गरीब काश्तकारों को मिलेगा और इस प्रकार वे अपनी फसलों का सही पैसा ले सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी को समाप्त करना है तो गांवों के अन्दर उद्योग धन्धे खोलने होंगे। शहरों के अन्दर अनुशासनहीनता बढ़ रही है, गांवों से जनता शहर की ओर बढ़ रही है। इसके लिए आवश्यक है कि सड़कों का निर्माण हो। यह नहीं हुआ तो हम कितनी ही योजनाएं बना लें, सत्ता बदल जाये उत्थान नहीं हो सकता। हमारा देश गांवों में बसता है और इसीलिए हमारी जनता सरकार बजट का दो तिहाई गांवों पर खर्च कर रही है। इसका लाभ गांव की जनता को मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति को उठाना है, तो जिस प्रकार से पानी की भूमिका महत्व-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पूर्ण है, बिजली की भूमिका महत्व पूर्ण है, उससे कहीं अधिक उत्थान के लिए सड़कों की भूमिका है। हमारे पी. डब्ल्यू. डी मिनिस्टर अच्छे और सुयोग्य हैं और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके कार्यकाल के अन्दर जब से अकाल राहत, बाढ़ सहायता कार्य हुए हैं, उनके अन्दर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गूंज हमको नहीं सुनाई दी है। यह कहते हुए मैं नहीं हिचकिचाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं भीलवाड़ा जिले से भूतपूर्व मन्त्री श्री रामप्रसाद लड्ढा थे, उनके कार्यकाल में जो अकाल राहत कार्य हुए थे उनका तो एक इतिहास है जहां उनके कार्यकाल में डेढ़ लाख रुपये के काम हुए थे उसमें 15 हजार रुपये भी सड़क निर्माण पर खर्च नहीं किये गये थे। परन्तु इस दो साल की अवधि में जो राहत या बाढ़ सहायता या काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य किये गये हैं, उनमें पहले की अपेक्षा ज्यादा काम हुआ है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस द साल की अवधि में अच्छी उपलब्धि रही है। इसमें कोई शंका नहीं है। यह सराहनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र और जिले की जो मुख्य सड़कें हैं और जो अधूरी पड़ी हुई हैं, चाहे वे वोट के लिए बनाई गई हों, उनको पूरा कराने के लिए मन्त्री महोदय का ध्यान, आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं। कई सड़कें अधूरी हैं। सरकार कम से कम लागत लगा कर बड़ी से बड़ी सड़कों को बना सकती है। करोड़ों लाखों रुपया इन पर लग चुका है और अब कम पैसा लगा कर इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे क्षेत्र में मिनिस्टर साहब ने आकर देखा है और वह 28 किलोमीटर की सड़क ठीक हो गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि जब भी मैं बोलता हूं आप घन्टी बजा देते हैं। रायपुर से करेड़ा रोड और रायपुर, गगापुर एक महत्वपूर्ण सड़क है। इन पर कम लागत लगा कर इसको ठीक किया जा सकता है। इसके साथ उपाध्यक्ष महोदय, देवगढ़ से भीलवाड़ा सड़क है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। इसकी रिपेयरिंग अविलम्ब कराई जाए। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष, महोदय, बेमाली से भाखानपुरा सड़क जिसका काम गत वर्ष हुआ था, वह अधूरी है। इसको भी पूरा किया जाए। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में खनिज की दृष्टि से एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है मगर सड़क के अभाव के कारण से उसका विकास नहीं हो पाया है। सुरास से टूका सड़क को बनाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में जो सड़क निर्माण कार्य हुए हैं और जो अधूरे रह गये हैं, उनको शीघ्र ही पूरा कराया जाए। अकाल राहत या बाढ़ सहायता के अन्तर्गत पहले जैसे गबन घोटाले तो इस बार नहीं हुए हैं किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में कमीशन प्रथा अभी भी चालू है। यह कमीशन प्रथा अभी तक बन्द नहीं हुई है। पहले चलती थी परन्तु अब तो यह बन्द हो जानी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेटेरियल सीमेंट, चूना, काम में लिया जा

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

रहा है उस पर अंकुश रखा जाये ताकि जो गलत पैसा खर्च होता है वह नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो कमीशन प्रथा है वह समाप्त हो

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ताकि सड़क निर्माण कम से कम लागत में पूरा हो जाए व रख रखाव में पैसे खर्च न हो।

अन्त में मैं आपके माध्यम से यह और निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत की बहुत सी सड़कें बनी हुई हैं जो अधूरी हैं। तीस साल में वे पूरी नहीं हो पाई हैं। जनता शासन को इन्हें पूरा करना चाहिए और अविलम्ब इनको पूरा कराया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपा-महोदय, मैंने अपना कट मोशन खान सड़क के अधूरे काम को पूरा करने के लिए और खनिज विभाग से जो रकम सड़क निर्माण के लिए दी गई है इस कार्य को पूरा करने के लिए, मकराना के डाक बंगले में 25 कमरे बनाने के लिए, दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारे देश के निर्माण में, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने में एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार भी इस ओर सतर्क रहती है लेकिन यहां से राशि मन्जूर होने के बाद निर्माण कार्य में हमारे इन्जीनियर्स, ओवरसीयर किस प्रकार से अनियमितता बरतते हैं, राजनैतिक दबाव से वे उसमें किस तरह से शिथिलता लाते हैं, यह तमाम बातें हमारे मन्त्री महोदय के देखने की हैं। मैं इस बात से चिन्तित रहता हूं कि बड़ी मुश्किल से किसी सड़क निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाती है और उस पर काम किसी न किसी कारण से धीमा करके अगले वर्ष ले जाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मकराना-जहां संगमरमर की बहुत अधिक खानें हैं, इसका एक मात्र केन्द्र है, वहां खानों से इन्डस्ट्री तक आने में जो सड़क का निर्माण हो रहा है वह बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। पहले भी मैंने मन्त्री महोदय से अनुरोध किया था, उनका ध्यान आकर्षित किया था और मैं यह यकीन करता हूं कि वे इस पर तत्काल कदम उठाएंगे। करीब सात लाख रुपये की राशि 78-79 के लिए दी और अब 79-80 का बजट पास करने जा रहे हैं। कई निर्माण कार्य सड़कों के अधूरे हैं उन पर ध्यान दें। अधीक्षण अभियन्ता मकराना पधारे थे, कुछ विवादग्रस्त सड़कों को देखने के लिए। निर्माण एक सड़क का हो गया और दूसरी का अभी तक अधूरा पड़ा है। डाक बंगला अभी जो है वह छोटा पड़ता है। मेरा निवेदन है कि मकराना डाक बंगले में कम से कम 25 कमरे और हो जायें क्योंकि मकराना बिजनेस सेन्टर है और सरकारी अफसरों के आने जाने की सुविधा और पब्लिक यूज के लिए मैं आशा करूंगा यह निर्माण करवायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, एक सड़क जो कि मकराना से कुचामन-डीडवाना जाती है उसके शार्टकट कम से कम 30 मील का अन्तर डालने वाली सड़क का जो कि राज्य सरकार ने 60 लाख की राशि उस पर आवंटित की है, मैं अनुरोध करता हूं कि उस कार्य को भी हाथ में लें।

(श्री अब्दुल अज़ीज)

वीरावड से खाट स्टेट-हाई-वे बनाई जाय तो वहां से जो पट्टी वगैरह लेकर जोधपुर से आते हैं, वहां पर अगर सडक बन जाएगी तो पेट्रोल बचेगा, फ्यूएल बचेगा और उनको आवागमन की सुविधा हो जाएगी। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं इन सडकों का भी निर्माण फरमायेंगे। हजारों लोग इस एरिया में गांवों में रहते हैं। मकराना तक साइकिल से खनन कार्य के लिए आने वालों को सुविधा हो जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमाण्ड की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काम हो रहा है इसका तो मुझे यकीन है लेकिन काम की रफ्तार धीमी है इसलिये गति तेज करने के लिये भी निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जालौर पिछड़ा हुआ है इसका सबसे बडा कारण अगर कोई है सडकों की कमी है। अभी जो प्रगति विवरण तो दिया गया है, मैंने इसमें जालौर का स्थान देखा, वह है 26 जिलों में 23 वां स्थान। कुछ समय पहले यह जानकारी मिली थी कि भारत सरकार ने जो थोड़े समय पूर्व कुछ आंकड़े प्रकाशित किये थे उन आंकड़ों के अनुसार हिन्दुस्तान में सड़कों के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए जो जिले थे उनमें जालौर भी था। उपाध्यक्ष महोदय, 10640 वर्ग कि. मी जालौर जिले का क्षेत्रफल है और जो डामर की सड़क हमारे क्षेत्र में आती है वह है 438 किलोमीटर। इस प्रकार पूरे राजस्थान में सड़कों के मामले में जालौर का नाम 23 वें नम्बर पर है।

इसका दोष 30 वर्ष के कांग्रेस शासन को दें या किसे दें समझ में नहीं आता, लेकिन जालौर वास्तव में पिछड़ा हुआ रहा है। अब जालौर बार-बार मांग कर रहा है, जालौर के किसान मांग कर रहे हैं, गरीब मांग कर रहे हैं कि इतने वर्षों तक तो हम पिछड़े हुए रहे लेकिन अब जो जिले आगे बढ़ गये हैं उनमें कटौती करके जालौर को कुछ सड़कें प्रदान की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, बाकरा रोड ऐसा स्थान है मेरे क्षेत्र में जहां एक वर्ष में करोड़ों की फसल किसानों की वहां आकर बिकती है और ऐसा स्थान जो 40 से 50 गांवों से जुड़ता है उस स्थान को आज तक सड़क से नहीं जोड़ा गया। बड़ा दुर्भाग्य है, उपाध्यक्ष महोदय। अगर बाकरा रोड को तीन ओर से, सडक से जोड़ दिया जाता है तो मैं समझता हूं उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों को, ग्रामों को, व्यापारियों को, बराबर लाभ मिलेगा। विकास का इससे सीधा सम्बन्ध है और विकास की गति का सीधा सम्बन्ध सड़क से है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बाकरा रोड को शीघ्रातिशीघ्र सड़क से जोड़ा जाय।

दूसरे, सायला पंचायत समिति को जोड़ने वाले मार्ग में जवांई नदी पर पुलिया की बड़े अर्से से आवश्यकता है। अगर कुछ ही अधिक बरसात हो जाये तो न इधर के आदमी उधर जा सकते हैं और न उधर के आदमी इधर आ सकते हैं और जिला मुख्यालय से सम्बन्ध टूट जाता है। इसलिये मैं

(श्री टीकमचन्द कान्त)

चाहूंगा, बहुत ज्यादा खर्चे का भी काम नहीं है, बहुत थोड़े खर्चे में ही इस नदी का कार्य हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कृपा करके इस ओर विशेष ध्यान दें।

इसके अलावा सायला से आगे सिन्दरी की ओर जाकर बाड़मेर से वर्षों पहले सड़क मिलनी थी, इसके कारण बाड़मेर और जालौर एक दूसरे के निकट आने थे। दोनों में व्यापार की वृद्धि होनी थी और दोनों में आवागमन बढ़ना था। इसका सीधा संबंध जिले की उन्नति से है लेकिन वर्षो से सड़क के दोनों ओर मेटेरियल पड़ा हुआ है। कोई उपयोग नहीं हुआ इस मामले में किन कारणों से पैसा नहीं मिला? शायद जिला ज्यादा पिछड़ा हुआ होने के कारण ही। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस सड़क की ओर ध्यान दिया जाय।

एक भरूड़ी से तवाव तक जो सड़क है उसके आगे जो सड़क नहीं है वह बननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि माडेरा-सेरणा धाणसा थलवाड़ पांथेड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़क से बिलकुल कटे हुए हैं। इस क्षेत्र को जोड़ना अति आवश्यक है। लेकिन किसी भी योजना में इन्हें नहीं लिया गया है। किसी भी हैड से इस क्षेत्र को पैसा मिलना चाहिये, सड़क बननी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रगति विवरण मिला है इसमें किसी भी हैड से जालौर को पैसा नहीं मिल रहा है। न कोई सड़क की योजना, न कोई पुलिया।

उपाध्यक्ष महोदय, दुग्ध विकास योजना में भी सड़कके निर्माण में जालौर का नाम नहीं है। जालौर तो पिछड़े ही गया। अगर कोई योजना बनती है तो वह सिवाय भरतपुर, अलवर, जयपुर के अलावा आगे बढ़ती ही नहीं। दूसरे जिलों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। पश्चिमी राजस्थान के सातों जिलों के आंकड़े देख लीजिये, आपको मालूम होगा सातों जिलों में सड़क निर्माण सबसे कम है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां से जयपुर से चला जाय तो बर एवं ब्यावर तक तो बड़ी लम्बी चौड़ी सड़क मिलती है, राष्ट्रीय मार्ग है। इसके बाद सड़क और तग राज्य मार्ग आता है। बर से आगे पाली तक और पाली के आगे आप चल नहीं सकते। रात को भय लगता है सड़कों पर खड्डे देखकर, साइडों में खड्डे बने हुए हैं, आमने-सामने दो गाड़ीयें जायं तो कहां से? ऐसी हालत में यह राज्य मार्ग है। दो वर्ष तो जनता पार्टी को हो गये। 30 वर्ष वालों ने तो ध्यान नहीं दिया इतने इम्पार्टेन्ट मार्गो पर क्या आप भी ध्यान नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि जालौर का सम्बन्ध गुजरात से भी है। उसके विकास का सम्बन्ध गुजरात से है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गुजरात का सम्बन्ध अगर अब सड़क से जुड़ जाय जो नजदीक है 7 किलोमीटर दूर दहीपुरा है उससे अगर जोड़ दिया जाय रानीवाड़ा कोगुजरात और जालौर बिलकुल बोर्डर पर आये हुए हैं उसको जोड़ दिया जाय सात किलोमीटर अन्तर्राज्य सड़क होती है, जालौर के लिए बहुत बड़े हित की बात होगी।

(श्री टीकम चंद कान्त)

उपाध्यक्ष महोदय, जसवन्तपुरा पुराना तहसील स्थान है। उस क्षेत्र के आसपास आये हुए करीब 50,60 और 70 गांव हैं, जिनका सम्बन्ध भीनमाल से है उसी सड़क पर सूंधा माता का स्थान है जहां पर बाहर के यात्री भी जाते हैं और जगह-जगह से लोग वहां पहुंचते हैं। वह बहुत पुरानी कच्ची सड़क है। मेरा ख्याल है कि और मार्गों पर पहले गाड़ियां चलती भी थीं या नहीं मुझे मालूम नहीं और किसी जगह बसें चलती भी थीं या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जसवन्तपुरा से भीनमाल के बीच गाडियां बहुत पुराने समय से चलती रही हैं, उस सड़क निर्माण का आज तक कुछ नहीं हुआ, उस सड़क को आज तक पक्की बनाने का सरकार ने कोई भी विचार नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि अगर जालौर के पिछड़े हुए होने के कलक को मिटाना है, अगर उसको कुछ देना है, अगर पुराने पापों को धोना है, इनके (विपक्ष) पापों को अगर धोना है तो पुण्य करिये आप। मैं कहता हूं कि जालौर दूसरे उन जिलों से बहुत पीछे है जिनके पास सडकें हैं। 100 वर्ग किलोमीटर पर, कहीं 17 किलोमीटर, कहीं 18 किलोमीटर और जालौर के पास साढ़े पांच, पौन छः किलोमीटर उस ओर ध्यान दें। वहां से धन लाकर जालौर में लगायें और जालौर के विकास के लिए कुछ विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पुनः एक बार और निवेदन करूंगा कि जालौर की सड़कों का विशेष तौर से ख्याल रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना रह गई ... ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया अपने विचार समाप्त करिये।

श्री टीकमचन्द कांत : सियाना के बाहर और सिरोही की ओर जो रास्ता जाता है उसके बीच रायपुरिया नाला आता है। वहां पुलिया 2-3 लाख रुपयों में पूरी बन सकती है। पिछले वर्ष तो मैंने इसकी कोशिश की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस पुलिया को तुरन्त बना दिया जाय। सिर्फ 2-3 लाख की बात है। उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये। विचार हो चुका। काफी समय आपने ले लिया है।

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, सडकों से जोड़ने हेतु 5 हजार तक के गांव लिए गये हैं, लेकिन जालौर को कोई लाभ नहीं वहां पर बालवाड़ा एक बड़ा गांव है वह दो-तीन किलोमीटर ही एक रेलवे स्टेशन से दूर है वह सडक से नहीं जुड़ पाया यह कितने दुर्भाग्य की बात है ? 5 हजार में कोई गांव नहीं आये तो थोड़ा कम करके भी इसको कर देते। मैं चाहूंगा कि इस बार उस गांव को सड़क से अवश्य जोड़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगर राम।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय मैंने कट मोशन दिया है ...

श्री डूंगरराम पंवार (टी बी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मेरे क्षेत्र में ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं अवसर दे दूंगा आपको।

श्री डूंगरराम पंवार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में टी. बी. तहसील हैडक्वार्टर है और क्योंकि मेरे यहां गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की हर तहसील जिला मुख्यालय से जुड़ी हुई है, लेकिन टी.बी. तहसील ही एक ऐसी है जिसका तहसील हैड क्वार्टर जुड़ा हुआ नहीं है सड़क से। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और टी.बी. क्षेत्र से हनुमानगढ़ की सड़क आज तक नहीं बनी है। यह, उपाध्यक्ष महोदय, इनटर स्टेट रोड है जो आगे जाकर हरियाणा से जुड़ जाती है और टी बी. से जाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। यह टी.बी. क्षेत्र नाली का क्षेत्र है। वहां पर थोड़ी सी बारिश आने पर सड़क के नीचे कोई वाहन नहीं चल सकते हैं। वहां पर चिकनी मिट्टी है इसलिये वहां पर काश्तकार को हनुमानगढ़ मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए इस खराब रास्ते से जाना पड़ता है और उसको माल ऊंटों पर ले जाना पड़ता है, क्योंकि ऊंटगाडी, ट्रैक्टर, ट्रक कोई उस रास्ते पर नहीं जा सकता है। इसलिए आज तक वह सड़क से कटा हुआ है टी. बी. तहसील।

दूसरी सडक टी. बी. से सेन्वया 5-6 साल से अधूरी पड़ी हुई है। वह ठेकेदार वहां के अधिकारियों और सरकार का लाडला है। उसके टेण्डर मन्जूर हुए हैं। वह सड़क को लिये बैठा है। मेटेरियल वहां पर पड़ा हुआ है। कहीं पर सोलिंग है और कहीं पर मिटी पड़ी हुई है। इस प्रकार से टी बी. में यह सड़क अधूरी पड़ी हुई है।

तीसरी, रावतसर से कांजड होती हुई सड़क जो सूरतगढ़ से जुड़ी हुई है वह सडक करीब-करीब सारी बन्द है। कहीं पर डामर पड़ा हुआ है, कहीं पर सोलिंग हो रही है, लेकिन राजस्थान कैनाल पर पुल और टी. एन. सी. पर पुल अभी नहीं बने हुए हैं। वह इतना बड़ा ब्रिज है कि अगर सड़क भी तैयार हो गई तो भी उस रास्ते पर नहीं जा सकते। वह आज तक अधूरी पड़ी हुई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को निवेदन है कि हनुमानगढ़ से टी.बी. को तुरन्त जोड़ा जाय। आज तक वह जुड़ा हुआ नहीं है।

चौथी संगरिया से टी.बी. सडक है वह भी अधूरी पड़ी हुई है।

पांचवीं सड़क तलवाड़ा और टी बी. की है। उसका भाग्य भी अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इन पांचों सड़कों का निर्माण जल्दी हो कराया जाय, और दोनों जो ब्रिज है जागरिया सड़क पर राजस्थान कैनाल का पुल और दूसरा टी. एन. सी का वह बनाये जायें।

तो मेरे क्षेत्र में जो सड़के बनी हैं, जितनी हैं वह जीर्ण-शीर्ण हाल में हैं। उनकी मरम्मत कराई जाय। इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन ।

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क और पुलियाओं की दृष्टि से हमारे राजस्थान की स्थिति अत्यधिक शोचनीय है। पिछले शासन के उपेक्षा करने से राजस्थान का सड़कों में नम्बर बीसवां है। यद्यपि हम जानते हैं कि पिछले दो साल में हम कुछ प्रगति के पथ पर हैं, लेकिन अगर मैं यह कहूं कि जिस तरह शरीर से रक्त संचालन के लिए नाड़ियों और कोशिकाओं का होना आवश्यक है उसी प्रकार राज्य के विकास के लिए सड़कों का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि सारा विकास सड़कों के इर्द गिर्द घूमता है उससे सम्बन्धित है। सड़कें अच्छी होंगी तो यातायात उपलब्ध हो सकेगा और यातायात उपलब्ध होगा तो शिक्षा, चिकित्सा व अन्य विकास की बातें हम कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के द्वारा जो सड़कों का और पुलियाओं का निर्माण किया जा रहा है उनकी दशा ऐसी है कि एक ही वर्षा का वह सामना नहीं कर पातीं। एक वर्षा आने पर हमारे यहां की सड़कें और पुल धराशायी हो जाते हैं। केवल कहने के लिए ही सड़कें और पुलियां बनाने का हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए, लेकिन वह परमानेन्ट व ड्यूरेबल हैं या नहीं यह देखना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निर्माण मंत्री जी से पुरजोर सिफारिश करती हूं कि वह अपने विभाग का मुआयना करें और देखें कि कितनी नई सड़कें और पुलियाएं बनी हैं और कितने समय में वे धराशायी हो गईं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निर्माण मंत्री महोदय की नजर में कुछ ऐसी सड़कें लाना चाहूंगी जो पिछली सरकार के समय में चालू तो हो गई थीं लेकिन आज भी वे अपनी हालत पर रो रही हैं और वहां से मनुष्य गुजरे तो उसके पांव में खून आ जाता है और यदि बैलगाड़ी, ऊंट का लड्ड़ा चला जाता है तो उनके पहियों के पंचर की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। वे सड़कें हैं — झोटवाड़ा से खोरावीसल वाया वेनाड़, झाटवाड़ा से निवारू, नींदड़ से जयरामपुरा और टोडी से दौलतपुरा।

उपाध्यक्ष महोदय, सामान सड़कों के इर्द-गिर्द पड़ा हुआ है। लाखों रुपये खर्च हो गये हैं। इसके लिए मैंने कई बार विभाग से और माननीय मन्त्री महोदय से कहा, लेकिन आज तक उन सड़कों को पूरा करने के उद्देश्य से कोई कदम नहीं उठाया गया है। जब सरकार जनता के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में लेती है और उससे सड़क व निर्माण कार्य करती है तो उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि नई सड़कें बनाने से पूर्व जो सड़कें अधूरी बनी हुई हैं उनको प्राथमिकता दी जाय और उन्हें पूरा करें। कई सड़कें अकाल राहत कार्यक्रम में ले ली गईं और अधूरी ही छोड़ दी गईं। जब उनके लिए पुकार की जाती है तो कहा जाता है कि यह कार्य अकाल राहत में किया गया है। अकाल राहत के कार्य अब जब दुबारा शुरू होंगे तभी वह पूरे होंगे। आखिर ये समस्त कार्य सरकार के अन्तर्गत हैं। चाहे यह किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये हों, उन्हें पी. डब्ल्यू. डी. को दे देना चाहिए ताकि जो लाखों और करोड़ों रुपया लगा है

(सु.श्री पुष्पा जैन)

उन पर, उसका सदुपयोग हो। मैं इस ओर निर्माण मन्त्री महोदय, का ध्यान दिलाना चाहती हूं। जयपुर में कालवाड़ पुल को पिछले साल बनाया गया था किन्तु उसी वर्ष पूरा होने से पहले पूरा पुल गिर गया। आज सदन में इस पर चर्चा हो रही है तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि साल में आठ महीने तो यह महकमा सोता रहता है। जब बरसात शुरू होती है तो निर्माण कार्य शुरू किये जाते हैं। क्या यह महसूस नहीं करते हैं कि आपकी अपनी जेब भरने के लिए अपने ही भाई-बहिनों की गाढ़ी कमाई को बरबाद कर दिया गया है। जब कि इन्हीं निर्माण कार्यों के अभाव में किन्हीं भाई-बहिनों को जान से भी हाथ धोने होते हैं।

[समय-समाप्ति-सूचक घंटी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगी कि साल के 11 महीने महकमा सोता है। मार्च में बजट लैप्स होने के डर से फर्जी भुगतान किये जाते हैं। आखिर क्यों? क्या मन्त्री महोदय ने कभी ख्याल किया कि मार्च के महीने में यह बजट क्यों उठाया जाता है? पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर से मैं नम्र निवेदन करूंगी कि जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, उनको पूरा करायें। जो सड़कें उपेक्षित हैं, उनको लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री रणजीतसिंह राठौड़

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ... ...

श्री उपाध्यक्ष : इनका नाम बाद में बढ़ा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा महत्व ज्यादा है।

(व्यवधान)

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसा राजस्थान में टैक्स के जरिये से हर गरीब की जेब से राज्य के खजाने में आता है। राज्य के खजाने से अलग अलग विभागों में खर्च किया जाता है। यह लोक निर्माण विभाग बहुत पुराना विभाग है। इसके काम करने का तरीका बहुत पुराना है। इस तरीके को न तो कोई बदल सका है और न बदल सकेगा। इस आधार पर जितना पैसा खर्च होना चाहिए, वह बजट के आखिर में खर्च होता है। उसी का परिणाम है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो इस महकमे में है। इस महकमे के भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बहुत भ्रष्टाचार है।

श्री रणजीत सिंह : ठेकेदारों के द्वारा काम होता है। यह प्रणाली ऐसी ही चली आ रही है। इसमें राज्य के लोगों का पर्सेंटेज बन्धा हुआ है। वह कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह से दूसरे और काम

(श्री रणजीतसिंह)

हुए हैं। ये जो काम किए गए हैं, उनकी क्वालिटी हल्की है। बरसात के थोड़ा शुरू होने से पहले इनका काम शुरू होता है ताकि कोई काम में खामी नहीं निकाल सके और बजट रफा दफा हो जाये।

हमारा इलाका रेगिस्तानी इलाका है। वहां पर अगर आवागमन के कोई साधन नहीं है तो आदमी क्या करेगा। पहले के साधन दूसरे थे। उस समय आवागमन के साधन नहीं थे। ऊंटों से काम चलता था। आज भार लाने का तरीका है, वह ट्रक पर है। जब तक ट्रकों के आने जाने की व्यवस्था नहीं होगी तो काश्तकार का काम नहीं चल सकता है। पिछली सरकार ने भी बड़े बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ने की कोशिश की है। यह सरकार भी कोशिश कर रही है। मेरा निवेदन है कि पश्चिमी इलाके में बड़े-बड़े गांव नहीं मिलेंगे। वहां पर छोटी छोटी ढाणियां हैं। आपने जो तीन हजार, पांच हजार, और डेढ़ हजार की आबादी के गांवों के लिए जो योजना बनाई है तो इतनी आबादी के गांव पश्चिमी इलाके में नहीं मिल सकेंगे। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले इलाके को देखते हुए आपको विशेष प्रावधान रखना होगा। हमारे यहां लगातार अकाल पड़ते आए हैं। अकाल के कारण दूसरे काम हो नहीं सके। वहां की सड़कों के काम हुए। जैसे ही अकाल खतम होता है वह काम खतम हो जाते हैं। वहां के काम भी खतम हो गए। वहां पर बहुत जगह रा-मेटीरियल पडा हुआ है। सरकार के पास इतना धन नहीं था। वह काम आगे नहीं बढे। पुराने कामो में जो लाखों रुपया लगा हुआ है अगर थोड़े से पैसों में वह काम पूरे हो जायें तो उन कामों के लिए व्यवस्था की जा सकती है। इससे पश्चिमी इलाके को कुछ फायदा हो सकता है। अभी जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे थे। सभी जगह एक ही तरीका है। काम कहां हुआ? काम वहां पर ही हुआ जहां का मन्त्रिमण्डल में ज्यादा बल था। आज कोटा में ज्यादा काम हो रहा है। यह होना स्वाभाविक है, यह जो पुस्तक छपी है, इसमें जिलेवार तालिका नहीं दी है। अगर जिलेवार भरा जाता तो वहा के आदमियों के हक में रहता। भूतपूर्व सरकार के समय में उदयपुर डिवीजन में ज्यादा काम हुआ है। आज वही स्थिति चल रही है। आज कोटा जिले में काम चल रहा है। दूसरे इलाकों में जायेंगे तो यह महसूस करेंगे। हमारे यहां का आदमी हम से पूछेगा कि हमारे यहां काम कितना हुआ है?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि काम हो और आवश्यकता के आधार पर हो। और इसके बाद मैं निवेदन करूं कि जोधपुर और जैसलमेर दो जिले ऐसे हैं जहां पर हमेशा मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, वे लोग जैसलमेर जाते हैं तो शेरगढ़ तहसील में आते हैं और उनकी मोटरें और ट्रक इतने होते हैं कि चाहे कितनी सडकें ठीक बनी हुई हों एक साल में ही तहस-नहस हो जाती हैं। जिस तरह से जैसलमेर का ऐतिहासिक महत्व है उसी प्रकार से ओसियां भी एक हिस्टोरिकल स्थान है। यहां पर टूरिस्ट भी आते हैं लेकिन जोधपुर से दस-पन्द्रह मील चलने के बाद ही अपनी गाडियों को मोड लेते हैं। इसलिए

(श्री रणजीतसिंह)

मेरा निवेदन है कि टूरिस्ट विभाग की तरफ से और लोक निर्माण विभाग की तरफ से यह मांग होनी चाहिये कि डिफेन्स विभाग से एड लेकर उनसे बातचीत की जाय कि उनके द्वारा जो सडकें खराब की जायं उनकी एवज में हम पैसा देंगे इसलिए फलोदी, जैसलमेर, ओसियां और जोधपुर जिनका सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्व है, जहां की सड़कें सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं इनकी मरम्मत कराई जाय

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मथानिया में मिर्च बहुत अधिक होती है, 8-10 करोड़ की मिर्ची होती हैं लेकिन उसको जोधपुर लाने में दुविधा है, हालांकि सड़क है लेकिन कच्ची है, ग्रेवल रोड है अधूरी है, मथानिया से माणकलाव होकर, जोधपुर में पत्थर की खाने हैं, उनको जोड़ दिया जाय तो डेजर्ट से लोग आते हैं उनकी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि खाली कोटा की तरफ ही ध्यान नहीं रखें आप समस्त राजस्थान के हैं, आपको चहुंमुखी राजस्थान की तरफ ध्यान देना चाहिए और जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता दी जाय जिससे हमारा प्रान्त आगे बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय विभाग से सम्बन्धित हैं और मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं उनको राय दूंगा कि कितनी ही सड़कें बना दें, अगर वहां पर जो नदियां हैं उन पर आप पुल नहीं बनाओगे तो वही हालत होगी जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। आज भी समस्त राजस्थान की तो नहीं, लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर तीन मन्दिर हैं जो हिन्दुस्तान के मशहूर हैं। जैसे खाटू की श्याम का मन्दिर जहां पर सम्पूर्ण देश के लोग, बंगाल, बिहार, कलकत्ता, बम्बई के लोग आते हैं लेकिन सड़क की जो हालत देखते हैं, चौमूं से आगे बढ़कर जो रैनवाल की नदी आती है, जिससे आगे मुख्य मन्त्री जी का गांव भी है खचरियावास, तीन-चार दिन बरसात हो जाय या बरसात के अलावा भी वहां पर रेत और मिट्टी इतनी आ जाती है, वहां पर जो नदी है जहां के विधायक सत्तारूढ़ दल के हरिसिंहजी भी हैं, जिनकी कान्स्टीट्युएन्सी है। रैनवाल की पुल के आगे दांता रामगढ़ के आगे रुण्ड नदी पडती है। आगे हालत यह है कि रुण्ड के यात्री दांतारामगढ़ नहीं जा सकते और दांतारामगढ़ के यात्री रुण्ड नहीं जा सकते। वहां पर डाक भी नहीं जा सकती, वायरलेस से या किसी अफसर की जीप से डाक भेजते है। थाना भी उधर होने से, कोई घटना हो तो सूचना भी नहीं मिलती। इसके लिए बार बार निवेदन भी किया है, इसलिए रोड़ तो आपने काफी बना दी और आज भी डिपार्टमेन्ट सक्रिय है। इस सरकार ने दो वर्ष में ज्यादा रोड्स बनाई हैं और जोड़ी भी हैं, सीधी भी बनी

(श्री मदनसिंहदांता)

है, पहले रोड में मोड आते थे, आज सीधी भी बनी हैं परन्तु आपने ब्रिजेज पर जोर नहीं दिया है। जैसे पलसाने से आते हैं तो दांतारामगढ़ और जीन की माता या खाटू श्यामजी जाते हैं तो वहां पर रोड़ टूटी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, नालों का प्रश्न था, अनाज क बदले काम की योजना से यह अच्छा हुआ कि नाले और खुर्रे बनाने की व्यवस्था हो गई है। मगर पहाड़ के जो यात्री हैं, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि कालवाड़ से दांतारामगढ़ जाते है तो वहां की पुलियां टूटी हुई है और आज तक उसको तैयार नहीं करवाया गया है, इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं माननीय निर्माण मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरफ भी आप दौरा करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि चारों रूट आप रोड़वेज को देने वाले हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आगे आपका दूर हो जाएगा तो मैं आपको उन रास्तों पर ले जाऊंगा और आपको महसूस हो जाएगा कि सड़कें कितनी बनाओ, अगर अच्छे पुल नहीं बनते हैं तो मैं समझता हूं कि हालत वही होगी जो पुराने जमाने में होती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्रजातन्त्र में जनता पार्टी कह रही है कि हम गांव गांव में निर्माण करना चाहते हैं, आप कैसे निर्माण करेंगे? जगह जगह नदियां आती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मैंने कई बार लिखित रूप में भी दिया है जहां-जहां पर सड़कों का काम हो गया है वहां पर खाटू की श्याम से दांतारामगढ़ की सड़क, आगे बाय तक आ गई है। वहां की जनता ने पचास हजार रुपये, जब जोशी जी चीफ मिनिस्टर थे, दिये हैं, वहां पर कंकर पटक कर छोड़ दिए हैं, मैं इस बात का तो धन्यवाद दूंगा कि आपने दांतारामगढ़ से बाय तक काम शुरू करवा दिया लेकिन सड़कें कितनी ही बनाओ, पुल नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि वहां पर तांगों में जाना पड़ा है, एक बार मैं भी बैठ गया, रात को 12 बजे तांगे में जाना पड़ता है। रेनवाल तक, और तांगे वाले डेढ़ दो मील के टुकड़े के बीस तीस रुपये लेते हैं। वहां पर जो घटना हुई, मैं खुद जोश में आकर, लोगों से कहा राजपूत होकर डर गए, तांगे में बैठ गया, कुंए में गिर गए, वो तो तैरना आता है इसलिए निकल गया, घोड़ा समेत तांगा डूब गया, 25-26 आदमियों ने मिलकर उसको खींचा। इस तरह की घटनाएं होती है। दांतारामगढ़ से कालवाड़ की पुल पर काम हो जाय तो अच्छा है। आप वहां का दौरा करें तो आपको महसूस हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सड़कों और पुलों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे उन्हीं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सड़क व पुलियाओं का किसी राज्य के विकास के लिए बहुत महत्व होता है। जहां दूसरे राज्यों में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है, वहां राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

सरकार ने 5000 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए एक योजना बनाई थी और उसमें राज्य सरकार की योजना के आधार पर काम हुआ। लेकिन इस बारे में मेरा सुझाव है कि 5 हजार की जनसंख्या के आधार पर तय किया, उसमें थोड़ा अमेंडमेंट करें कि जिस गांव की आबादी अगर 5 हजार से कुछ कम है लेकिन वह पिछड़ा हुआ है, उपेक्षित रहा है तो सरकार को उन बड़े कस्बों को भी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निर्माण मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा झालावाड़ का जिला राजस्थान में पिछले 30 सालों में सबसे उपेक्षित रहा है, सबसे अधिक उस क्षेत्र की उपेक्षा की गई। कुछ समय पहले हमारे जिले के सारे विधायकों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया और निर्माण मंत्री ने झालावाड़ जिले को पैसा भी दिया लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह रही कि वहां के निकम्मे, निष्क्रिय एक्जीयूटिव इंजीनियर के कारण उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाया। हमारा डेपूटेशन बार बार मन्त्री से मिला कि आपने पैसा रखा है लेकिन आपका एक्स. ईएन. काम नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा मैं देखूंगा। पता नहीं मन्त्री के सामने क्या मजबूरी थी कि जितना पैसा उन्होंने दिया, आज भी वह पैसा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, एक चौथाई या आधा ज्यादा से ज्यादा खर्चा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? यदि पैसा खर्च नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? पिछले दिनों आपके सेक्रेटरी श्री शेरसिंह झालावाड़ जिले के दौरे पर गए थे, उनसे भी मैंने निवेदन किया था आपका एक्स. ईएन. इस पैसे को अपनी जेब में ऐसे रखे हुए है जैसे पैसा उनके घर से जा रहा है। जहां दूसरी जगह टेन्डर्स 15-20 पर्सेंट पर आए, वहां हमारे जिले में 7 या 10 पर्सेंट पर आए। तो जो पैसा खर्च नहीं हुआ है कहीं ऐसा न हो कि पैसा लैप्स हो जाए। अगर लैप्स हो जाए तो अगले साल रिन्यू करना चाहिए।

पिछले दिनों सरकार ने एक प्रगति पुस्तिका प्रस्तुत की, उसमें इस बात की घोषणा की थी कि राजस्थान में पुल निगम का निर्माण किया जाएगा। मध्यप्रदेश के अन्दर कई जगह पर यह व्यवस्था है हालांकि वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी नदियों पर से गुजरने वाली सवारियों ट्रकों से, बसों व ट्रेक्टरों से एक शुल्क बांधा हुआ है। वहां की सरकार जीवन बीमा निगम व विश्व बैंक से पैसा लेती है और पुल बनाती है। हमारे मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि राजस्थान में पुल निगम बनेगा लेकिन उस निगम ने आज तक काम शुरू नहीं किया है। एक साल का समय बीत चुका है, सरकार को जागरूक होकर निर्णय लेना चाहिए और उसकी शीघ्र क्रियान्वित करे।

काम के बदले अनाज योजना में गांव-गांव में ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ा काम हुआ है। पंचायतों ने काम किया है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आप पंचायतों को

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

पैसा दे रहे हैं लेकिन अगर निर्माण विभाग में पैसे की कमी हो तो उस पैसे का एक अंश निर्माण विभाग को दें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण होगा। मैं जिस क्षेत्र मनोहर थाने से आता हूं वह राजस्थान की अंतिम सीमा पर है। वह एक बड़ा व्यापारिक कस्बा है। मध्यप्रदेश सीमा पर बसा हुआ वह आदिवासी क्षेत्र भी है। मनोहर थाने के लोगों को जाने के लिए मध्यप्रदेश में 14 मील पर एक रेलवे स्टेशन है मीनागंज। वह बरसात में चारो और नदियों मे घिर जाता है, न कोई जा सकता है न आ सकता है मनोहरथाने में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वह भी राजस्थान की सीमा है। मध्यप्रदेश सरकार ने 5 मील की सड़क अपने आप यह पुल बनाकर पूरी कर दी है। राजस्थान सरकार ने उस ग्रामीण सड़क की 1967 में योजना बनाई थी आज 1978-79 में भी 7 मील की सड़क को पिछले 12 साल में नहीं बना पाए हैं। पुलियाओं के लिए आपने 4 लाख रूपए मंजूर किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 लाख में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। इस बारे में आप तवज्जोह देकर अपने अधिकारियों को जागरूक करें।

एक और सड़क के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, मनोहर थाने से छीपा बड़ौद और छबड़ा रास्ता है, वह मुख्य मन्त्री का निर्वाचन क्षेत्र है। मैं चाहता हूं कि हरनावद्दा से मनोहर थाने की सड़क को जोड़ें तो उस क्षेत्र की जनता के साथ कृपा होगी, छीपाबड़ौद से हरनावद्दा पहले ही सड़क बना दी है। उस क्षेत्र की सड़क की बुरी हालत है, कोई मन्त्री जाने को तैयार नहीं होता सड़क की खराबी के कारण, मुख्य मन्त्री गए हैं लेकिन दूसरा एक भी मन्त्री पिछले दो साल में नहीं जा पाया है। इसलिए निर्माण मन्त्री आप पधारें और सड़क की स्थिति को देखें। मुख्य मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र से लगा हुआ इलाका है।

श्री उपाध्यक्ष . श्री उमरावसिंह।

(अनुपस्थित)।

श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है और मैं उस क्षेत्र से आया हूं जो 25 साल से शियूल्ड कास्टस का सुरक्षित क्षेत्र रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी एक पैसे का काम वहां नहीं हुआ। जो सड़कें बनी हुई थीं उनकी मरम्मत उनके राज्य में नहीं हुई और इन दो सालों में भी नहीं हुई।

(व्यवधान)

हम जानते हैं आपके कारनामे। आप जब बोलती हैं मैं बीच में नहीं बोलता हूं। नहीं तो आप जब बोलेंगी तो मैं ऐसा बोलूंगा जो सदन छोड़कर भागोगे। एक तरफ तो हम गांव के लोग सड़कों के लिए तरसते हैं और दूसरी तरफ मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं विभाग की उपेक्षा का। महला के पास सड़क बनी हुई है, उसमें बांध बना हुआ है उसके पेटे में सड़क

(श्री रतनलाल वर्मा)

बन रही है। जब बांध बना तो उसके अन्दर सर्वे किस ने किया? उस सड़क से ऊंचा बांध क्यों बांधा? उस सड़क पर कई दुर्घटनायें हो गईं, ट्रक उलट गए, आज वह सड़क ऊंची उठ गई है।

वह बांध ऊंचा बांध दिया और सड़कों पर पानी भर जाता है और वह पुलियायें जो कि छोटी-छोटी हैं वह लाखों रुपया खा रही हैं और आज भी अस्त-व्यस्त हैं। आज भी घंटे भर रुकना पड़ा। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस तरह के काम गलत हो रहे हैं। उनका सर्वे किस ने किया? यह गलत सर्वे क्यों हुआ? गलत सर्वे करने वाले और गलत काम करने वालों को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक यह काम ठीक नहीं होंगे और लोग भी नहीं सुधरेंगे। कहते हैं तो जवाब आता है कि गलती हो गयी। कांग्रेस के राज्य में 3 पैसे का गबन का केस मेरे ऊपर बना और मैं प्रधान के पद से दो वर्ष सस्पेण्ड रहा। तो उपाध्यक्ष महोदय, अधिक न कह कर इतना ही मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो आपका अभी का प्लान है सड़कों का और निर्माण कार्यों का यह भी शहर के अन्दर अधिक खर्च हो रहा है और मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि गांवों के अन्दर इस निर्माण बजट का 30 प्रतिशत भी खर्च नहीं हो रहा है। जितना पैसा निर्माण का खर्च हो रहा है वह तमाम का तमाम सरकारी बिल्डिगों पर, डाक बंगलों पर, वहां की सुविधाओं, पलंग, ड्रेसिंग टेबुल और फूल बगीचों में खर्च हो रहा है। फ्लश की लेट्रीन बनाने पर और नये तरीके की बनाने पर सारा पैसा खर्च हो रहा है। बन्द कीजिए इन कामों को। पहले आप मेहरबानी करके हमारे गांवों को सड़कों से जोड़िये। जो मक्का, बाजरा, ग्वार, मोठ आदि शहर में आता है उनको शहर तक लाने का साधन तो कीजिए। आपको रुपये, दो रुपये मन का फर्क पड़ेगा सड़कें होने से। आज किसानों को उनकी चीजों का पूरा मूल्य नहीं मिलता वह अपनी चीजों को शहर में टाइम पर नहीं ला सकते। बरसात का मौसम है और पानी बरस रहा है और मक्की दूधिया हो रही है। उसको यूरिया खाद देनी है लेकिन बैलगाड़ी से वह खाद बरसात में नहीं ला सकता। सड़कें नहीं हैं, रास्ते नहीं हैं और बीच में नाले आ रहे हैं। वह यूरिया का कट्टा माथे पर रखकर लाता है और दो तीन दिन बाद फसल में खाद देता है। वह फसल गल जाती है। तो वह टाइम पर फसल को खाद भी नहीं दे सकता सड़कें और रास्तों के नहीं होने के कारण से। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप मेहरबानी करके बिना किसी पक्षपात के ऐसा प्लान बनाइये कि हर पंचायत हैड-क्वार्टर को सड़क से आप कब तक जोड़ देंगे? सब गांवों को मत जोड़िये लेकिन पंचायत हैड क्वार्टर तो सड़कों से जोड़ दीजिए।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरा गांव देवलियाकलां है और मेरे क्षेत्र में देवलिया-कलां से इंटड़िया गांव के बीच एक खारी नदी है और इस नदी पर पुल नहीं होने की वजह से शाहपुरा बस नहीं जा सकती।

(श्री रतनलाल वर्मा)

तीस साल में इन पापियों ने सड़कें नहीं बनाई लेकिन क्या बताऊं कि जनता राज्य में भी नहीं बन रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खारी नदी पर पुल बनाया जाये और एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने का काम कीजिए। इसी तरह से टांवा से कुम्हानिया डाई नदी पर भी पुल बनाया जाना चाहिए। बरसात में बीस बीस गांव बिलकुल टापू हो जाते हैं। और इधर में निवेदन करूं कि मोहनलाल जी के क्षेत्र में जो सरवाड़ सड़क जाती है और बीच में नदी आती है उस नदी के ऊपर आज तक पुल नहीं बना। श्री हरिभाऊ जी वहां से खड़े हुए थे और चकमा देकर मजदूर लगाकर काम शुरू कराकर उस क्षेत्र के लोगों से वोट लेकर आ गए लेकिन वहां आज तक पुलिया नहीं बनी। तो इस तरह से यह गांधी जी के चेले कांग्रेसी सफेद पोश धोखा देते थे कम से कम आप तो मत दो

श्री मूलचन्द डागा : आपने गांधी जी की शपथ नहीं ली ?

श्री रतनलाल वर्मा : गांधी जी के हत्यारे हो आपने उनके सिद्धान्तों का खून किया। आपने बेईमानी, अनाचार फैलाया और आज आप गांधी जी के नाम की दुहाई देते हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा समय यों ही जा रहा है उपाध्यक्ष महोदय। तो मैं निवेदन करूंगा कि बांदनवाड़ा से सरामां रोड है उसके बनने के बाद उसकी कभी मरम्मत नहीं हुई और इस सड़क पर चार-चार और पांच-पांच इंच के गड्ढे हैं। नागौला से विजयनगर, और बादनवाड़ा से भिनाय रोड ऐसी है कि गर्भवती औरत के बच्चा हो जाये। और ऐसी घटनायें हुई हैं और मैं नाम तक बता सकता हूं। सब बातें बता सकता हूं कि किस किस के साथ क्या क्या घटना हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

नसीराबाद से बोराड़ा रोड़ पर भी काफी गड्ढे हैं और उस पर डामर होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो 4 मिनट ही हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। जल्दी समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : आप इनको रोकें बीच में बोलने से। विजयनगर से गोवला रोड वाया भिनाय टांटोटी बसें चलती हैं यह सड़क बिलकुल खराब है। देवलियाकलां से कादेड़ा रोड़ है और कम से कम 20 मील का मेटोरियल पत्थर, बड़ी गिट्टी छोटी गिट्टी पढ़ी है और बरसों से पहाड़ में पड़ी हुई हैं और वह कम होती जा रही है। साइट पर पड़ी है उसका काम नहीं हुआ। भिनाय से विजयनगर मन्डी को जोड़ती है यह सड़क भी बेकार है और विजयनगर नगर पालिका ने एक किलो मीटर सड़क एक लाख 20 हजार रूपया खर्च करके बनाई

(श्री रतनलाल वर्मा)

है। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि जो सड़क 1 लाख 20 हजार में बनाई है हम इसी पैसे में ड्योढ़ी सड़क और इससे अच्छी बना सकते हैं।

इसी तरह से विजयनगर से राताकोट, सराना के 12 मील से डबकेला रोड़ और कनेई से करोट रोड़ की हालत बहुत ही खराब है और बरसात में इतना बुरा हाल हो जाता है कि साइकिल तक नहीं चल सकती। इसी तरह से नागोला से सरवाड़ रोड़ है। आपने कहा कि 68 करोड़ रुपया खर्च होगा तो कम से कम 200 विधायकों के क्षेत्रों के अन्दर इस पैसे को बांटा जाये तो 40 लाख रुपया तो हमारे भी हिस्से में आना चाहिए। जो हमारे हिस्से में आता उतना तो दें और पालिसी के हिसाब से दीजिए।....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री रतनलाल वर्मा : सिर्फ एक मिनट और।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का अपने क्षेत्र की सड़कों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा जिन पर काम होना जरुरी है। भिनाय से सरवाड़ 12 मील का टुकड़ा है, देवलिया से भिनाय शाहपुरा रोड़ को यह जोड़ेगी और इंटड़िया से शाहपुरा सड़क बनी हुई है पहले ही 12 मील की। इसी तरह से भिनाय से सिंगावल 6 मील जगह है जो कि मसूदा को जोड़ेगी। इसी तरह से बोराड़ा से मनोहरपुरा....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जायें। आप लिस्ट मंत्री महोदय को दे दें।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर तो जो सड़कें बनी हुई हैं उसकी पटरियों को भी डामर की बना रहे हैं। दोनों तरफ पैदल जाने की जो जगह है वहां डामर की जा रही है और वह भी पी. डब्ल्यू. डी. बना रही है कोई यहां की म्यूनिसिपैलिटी नहीं बना रही है, विकास का काम पी डब्ल्यू. डी कर रहा है और गांवों की सड़क बनाने में जोर आ रहा है इसलिये जो बजट बनाया है, वह गांवों का घातक बजट है तमाम का तमाम पैसा शहरों में लगाया है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके आप इसमें संशोधन करिये। अगर दुनियां में कोई दातार है तो वह किसान है बाकी सब मंगते है। स्पष्ट रूप से कह सकता हूं सब मंगते हैं और उसमें मैं भी हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री समरथ लाल।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आपका रूटीन पाइन्ट आफ आर्डर है या कोई नया है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा साहब ने

(श्री राम कृष्ण दास गुप्ता)

यह कहा कि किसान की कमाई सब खाते है....

श्री रतनलाल वर्मा : हां, हां कहता हूं आपने कब बीज बोया, सब फालतू जाते हैं।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति बहुत गंभीर है अगर इन्होंने यह आरोप लगाया है और मैं चुप बैठा रहूंगा तो यह मौन स्वीकृति होगी। वर्मा साहब अपने लिये कहें या जनता पार्टी के मेम्बरों के लिये कह सकते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : आप तो खुद जनता पार्टी से जीतकर आये हो....

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : कांग्रेस सरकार ने इन पर गबन का केस लगाया था....

(व्यवधान)

आरोप लगाया है....

श्री रतन लाल वर्मा : आपने तो बहुत बड़ी गद्दारी की है, उधर बैठकर जनता पार्टी के साथ गद्दारी की है। जनता पार्टी से ही तो जीतकर आये हो।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : जो गबन का आरोप लगाया है वह सही है और रोज जनता पार्टी की गाली काढ़ते हो।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : कोई गबन नहीं है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : तुम तो जोकर हो।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं तो जोकर हूं तुम तो बांदरी हो। मैं गले में जंजीर डालकर नचवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों को ही बैठाया जाय, हमारे सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अब कोई अवसर नहीं दूंगा। आपने जो सूची दी उसमें नाम है....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आपको तकलीफ क्या है, मैं नहीं बोलता। मैं आसन का व्यवहार अपने प्रति जानता हूं, इसलिए नहीं बोलता। ये चाहते ही नहीं हैं।

श्री समरथ लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो समय है वह श्री प्रद्युम्नसिंह जी को दे दिया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा था मेरे खड़े होने से आपको तकलीफ हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान खास तौर से धौलपुर जिले की सड़कों और पुलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। धौलपुर में चम्बल का पुल आज से 4-5 वर्ष पहले टूटा था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन हैं? मन्त्री महोदय, बता दें। उस पर काफी बड़ी रकम खर्च हो चुकी है लेकिन अभी भी दो-तीन साल बनने के आसार नजर नहीं आते हैं, इससे जनता को काफी तकलीफ हो रही है। तो एक तो यह बता दें कि इस जिले के लिए जिम्मेदार कौन हैं। जो कान्ट्रैक्टर है, उसकी तरफ से ढिले नहीं है। या तो आपके विभाग की देरी है या भारत सरकार की—कौन जिम्मेदार है, बता दें?

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रगति विवरण दिया है मन्त्री महोदय, ने उसमें दर्शाया है पार्वती व गम्भीर नदी पर भरतपुर और धौलपुर के बीच पुल निर्माणाधीन है। वह कब से है? पिछले 4-5 वर्षों से काम बन्द है। उस पुल पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है यह भी बताने की कृपा करें? फिर, श्रीमान्, जो क्रेस प्रोग्राम के तहत कार्य हैं आप कहेंगे कि कांग्रेस ने क्रेस प्रोग्राम पर रुपया लगाया है। अब आप ही उसका श्रेय ले लीजिए। जो क्रेस प्रोग्राम में सड़कें बनी थीं वे अधूरी हैं अगर आप पूरा करवा दें तो जो पैसा बर्बाद हो रहा है वह बच जायगा और लगा हुआ पैसा काम में भी आ जायगा।

चौथे, श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूं फूड फार वर्क में जो सड़कें बनी हैं उसका क्या होगा। बरसात का मौसम आ रहा है, अगर समय रहते हुए निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो बरसात में उन सब सड़कों की मिट्टी बह जायगी, क्यों कि आपको भारत सरकार से ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है। 40 करोड मन्त्री महोदय ने फुड फार वर्क में रखा है तो ढाई करोड़ से अधिक आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये काम किस तरह पूरा करने जा रहे हैं। इस पर प्रकाश डाल सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

एक बात और निवेदन करने जा रहा था, आपके जो गैंग्स की व्यवस्था है और आप अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा गैंग्स पर खर्च करते हैं लेकिन इनसे क्या काम लेते हैं। बहुत से माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि गैंग्स की उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। काम कुछ करते नहीं हैं ठाली बैठे रहते हैं और श्रीमान् मैं कोई इनके विरोध में नहीं हूं कि इनको निकाल दिया जाय और बेरोजगार कर दिया जाय लेकिन जो काम नहीं आ रहे हैं, घर पर बैठे रहते हैं और आफिसरों को नौकरी देते हैं तो श्रीमान् अब इनका रखना कोई उचित नहीं है। मेरा निवेदन है गैंग्स के बारे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

में आपको पालिसी बनानी पड़ेगी कि जो रिटायर होते जा रहे हैं उनकी जगह अब नये नहीं लगायेंगे तो वह पैसा आपका बच सकता है और सड़क निर्माण में काम आ सकता है ।

हमारे मुख्य मन्त्री जी बहुत हिमायती हैं कि राजस्थान से भ्रष्टाचार खतम किया जायगा । क्या आपके विभाग से, मन्त्री महोदय, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया । आपके यहां अब भी जो ठेकेदारों से कमीशन लेने की प्रथा है वह समाप्त नहीं हुई है । मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन कमीशन अभी भी लेते हैं और क्या आप कह सकते हैं कि नहीं लेते हैं ?

श्री जयनारायण पूनिया : आदमी का नाम बता दें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसको लोग मानकर चलते हैं और पी डब्ल्यू.डी. का एक अंग है यह भ्रष्टाचार आपके विभाग के अन्दर अभी मौजूद है । इसको समाप्त करना चाहिए । अगर विभाग के अन्दर नहीं है तो खड़े होकर कहिये कि नहीं है । आप खुद जानते हैं....

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्य, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार है लेकिन आप नाम गिना दें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जितने ठेके चल रहे हैं उनमें 99.99 पर्सेन्ट में आपके इंजीनियर को 15 पर्सेन्ट तक कमीशन देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : 12 पर्सेन्ट बन्धा हुआ है ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : नाम बताने से भी होता क्या है । मैंने फोटो स्टेट कापीज दी थी । पी.डब्ल्यू.डी. एक्स.ईएन. के बारे में, कुछ हुआ है क्या ? बता दीजिए । इसी सदन में फोटो स्टेट कापीज प्रस्तुत की थी एक्स. ईएन. मिस्टर भण्डारी के बारे में जिसने डेढ़ लाख का गबन घोटाला जब नागौर में एक्स. ईएन. थे, किया था ।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय रात्रि को 8 बजे तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय रात्रि को 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की कार्यवाही का समय रात्रि को 8 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को नाराज होने की बात नहीं है ?

श्री जयनारायण पूनिया : मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। दरग्रसल इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप नाम बता दें तो पकड़ने के लिए व्यवस्था करें। हम तो इसमें आपकी मदद चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपको सूची भी दे दूंगा। अगर आप इतने इच्छुक हैं तो मैं आपको सूची भी दे दूंगा।

श्री जयनारायण पूनिया : Thank yon very much.

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप बड़े भले आदमी हैं लेकिन मैं जाहता हूं कि आप कार्यवाही कर नहीं पायेंगे, मैं जानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में एक बात अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि एक सड़क जातेली से कुधियाना के बारे में निवेदन कर रहा हूं। इस पर पुलियां बनाते हुए 15-20 लाख रुपये खर्च कर दिए, इसके बारे में मैं पिछले कई सालों से निवेदन कर रहा हूं, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को भी लिख कर दिया था कि बरसात के अन्दर आवागमन सड़क का रुक जाता है। आपने कुछ रुपया पुलियाओं केलिए दे दिया लेकिन इससे क्या होता है। इस पुलिया का निर्माण पूरा कराया जावे ताकि सड़क का आवागमन बारहों महीने बना रहे।

ये ही चन्द बातें थीं जिनको मैंने आपके सामने रख दिया है। मेरे दल का बाकी समय माननीय समरथलाल जी को दे दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : न नौ मण तेल होगा और न राधा नाचेगी। मैं समझता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बन सकती। आपने जो योजना बनाई है उस योजना के आधार पर ....

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं माननीय डागा जी से एक बात पूछना चाहता हूं। एक सड़क का नाम बता दें जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है। ये पाली में रहते हैं और इनके सारे गांवों में किसान रहते हैं जिसके डागाजी विरोधी हैं इसलिए ये सड़क बनाना ही नहीं चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे सारे निर्वाचन क्षेत्र में करीब चार सौ, पांच सौ, छः सौ से ज्यादा की आबादी नहीं है। पांच हजार की आबादी हो तब सड़क बनेगी इसलिए मेरे गांवों में कोई सड़क बनेगी नहीं। यह अपनी योजना को ग्रामोन्मुखी कहते हैं उसका मुझे विरोध है। यह क्या आपकी नीति है....

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : आपने पनपने ही नहीं दिया गांवों को।

श्री मूलचन्द डागा : पाली से लेकर पीपाड़ तक सड़क की सिफारिश की थी। आप पाली से चले जाइये, पाली से निमोली, जूथडा, कालासांव, सांवलदा कलां और आगे जाकर सरदारपुरा। ये सारे गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि पहले भी सड़कें नहीं बनी और आज भी नहीं बन रही हैं और आपको यह बताऊं कि दीवादी से लेकर भांडावास होते हुए जदारियां और फिर सीधे पाली तक सड़क बन जाय। मैं चाहता हूं कि छोटी-छोटी सड़कों से कोई नया जनजीवन पैदा हो। गांवों में इससे दूध ज्यादा मिल सकता है, उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जा सकता है, नई जिन्दगी दी जा सकती है और ग्रामोन्मुखी का नारा देते हैं। इसकी औसत मत काढ़िये, इन नारों को असली रूप दीजिए। मैं यह कहता हूं कि न तो मेरे यहां के गांवों में पांच हजार की आबादी हो, न तो इतनी पापुलेशन हो और न मेरे यहां कोई सड़क बने। पांच हजार की यह क्या नीति है? नीति का मतलब यह होना चाहिए कि आप इम्बैलेंस मिटाइये तभी ज्यादा गांवों को फायदा मिलेगा। मैं समझता हूं कि एक सड़क बीस माइल तक जायेगी और कम से कम 70 हजार की पापुलेशन फायदा उठायेगी। यह नीति मेरी समझ में नहीं आती।

मैंने एक बात कही थी कि नीति किस प्रकार से बनती है। कई दफा आपने लिखा है कि इन सड़कों के निर्माण से आप सफेद क्रांति लाना चाहते हैं। मेरे यहां सारा रेगिस्तानी एरिया है जहां पर ज्यादातर पशुधन है। वे पशुधन पर जिन्दा रहना चाहते हैं, वह एटलस साइकिल पर दौड़ता हुआ जायेगा और अपना दूध बेच आयेगा। लेकिन आप यह चाहते ही नहीं हैं। आप तो चाहते हैं कि बड़ी-बड़ी सड़कों को जोड़ देंगे, बड़े-बड़े गांवों को जोड़ देंगे। नहीं जोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। नाथद्वारा को जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, वहां तो साधु सन्त रहते हैं पड़े बड़े। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक अन्त्योदयी योजना चला रहे हैं, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए को आगे लाना चाहते हैं, उसका उत्थान करना चाहते हैं, समाज के पिछड़े वर्ग को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो यह रीजनल इम्बैलेंसेज को मिटाने के लिए यह जो आपकी नीति है वह ठीक नहीं है। एक तरफ गांवों में इन्टीरियर में जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जयपुर की सड़कें बनायेंगे। जितने बड़-बड़े शहर हैं उनकी आवाज है, शहर वाले बोलना जानते हैं, उनसे कहो कि खुद बनायें। सवाल यह है कि जितने शहर हैं, उनकी नगर परिषदें और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं वह खुद सड़कें बनायें। लेकिन वहां तो चुप रहते हैं क्योंकि बड़े-बड़े लोग आते हैं, स्वागत कराते हैं। कहेंगे कि जयपुर तो टूरिस्ट सेन्टर है इसलिए यहां पर सड़कें बनानी पड़ेंगी। शहर के अन्दर पानी का लाभ उठायेंगे, शहर के अन्दर बिजली का लाभ उठायेंगे, यहां पर बड़ी-बड़ी ट्यूब लाइटें लगायेंगे, सड़कें बनेंगी और फिर कहते हैं कि ग्रामोन्मुखी करना चाहते हैं, ग्रामों का उत्थान करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई शहर में सड़क नहीं बने और मैं चाहता हूं कि एक-एक गांव में सड़क बने। वहां ज्यादा पापु-

(श्री मूलचन्द डागा)

लेशन नहीं है, एक माइल डेढ़ माइल के फासले पर गांव हैं, अगर मैं सुबह निकलता हूं घर से तो एक कोने से दूसरे कोने तक शाम को पहुंच जाता हूं। नजदीक-नजदीक में, पास-पास में गांव हैं और सारे गांवों के लोग आते है। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सड़क नहीं है और आगे भी यकीन नहीं है कि कोई सड़क बनने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप अपने निर्णय को बदलिये और जस्टिस कीजिये, विचार कीजिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अपने यहां पाली से खैरवा सड़क है, वह सड़क मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, वह विज्ञान मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में है। श्रीमान, उस खैरवा सड़क पर आकेली में एक पुल नहीं बनाया। छः साल से सड़क बन गई लेकिन पुल नहीं है। आप सड़कें कैसे बनाते हैं मेरी समझ में ही नहीं आता। मैं सुनता हूं कि आज जो चीफ इन्जीनियर है, राजस्थान में थोड़े दिनों पहले ही आये हैं, कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने सुना है, अगर मैं और कुछ कहूंगा तो कहेंगे तारीफ कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि वह सड़कें बनीं कैसे? कभी-कभी मन्त्रीजी उनकी जांच करते हैं, उन सड़कों को देखते हैं कि सड़कें बनती कैसे हैं। कभी आपने एक बार भी देखा कि भ्रष्टाचार क्या है? मुख्य मुद्दा यह है कि मधुमक्खी और गुलाब के फूल का सम्बन्ध है। ये इन्जीनियर तो हैं मधुमक्खी और ठेकेदार हैं गुलाब के फूल। उस सम्बन्ध को आप मिटा नहीं सकते। जब तक मधुमक्खियां हैं उसके लिए फूल खिलेंगे। यह कोई मिटा नहीं सकता। यह तो जैसे शिष्टाचार हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, मन्त्री महोदय आप में ताकत है, विचार कर लिया कि भ्रष्टाचार मिटाना है और यह दृढ़ निश्चय कर लिया है तो सारे इंजीनियर्स की जांच करवा लें, उनकी प्रापर्टी की घोषणा करवालें कि कि कितनी प्रापर्टी है, इसकी कितनी दौलत है और इतने वर्ष नौकरी करने पर इतनी दौलत कैसे बढ़ गई....

श्री रतनलाल वर्मा : साथ में मिनिस्टरों की भी कि पहले क्या थे और अब क्या हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और एम. एल. एज. की भी।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के विधायकों ने तो घोषणा कर दी? आप जांच करवा लीजिए।

अब मैं डाक बंगलों के बारे में कहना चाहता हूं जहां पर विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं लेकिन उनकी रिकवरी कितनी बाकी रहती है। बीसों बरसों से बकाया चल रही है। मैंने देखा है कि एक एक के अन्दर तीन तीन हजार रुपए बाकी हैं। ये डाक बंगले कैसे बने हुए हैं किसी ने देखा जाकर, किसी ने उनको खोलकर देखा? मैं समझता हूं कि इतने डाक बंगले हैं, हम राजस्थान में टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहते हैं, यह क्या है डाक बंगलों की हालत? कोई आदमी जाकर देखता है? मैं बताना चाहता हूं, आप उसका बाथरूम देखिए, उसकी

(श्री मूलचन्द डागा)

लेट्रीन देखिए। ये क्या डाक बंगलोज हैं। डाक बंगलों के अन्दर आपकी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी समझ से यदि इन डाक बंगलों की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती तो....

श्री रतनलाल वर्मा : और सर्किट हाउसेज ?

श्री मूलचंद डागा : सर्किट हाउसेज बन गए तो डाक बंगलों को भी इम्प्रूव करना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : डाक बंगलों में एम. एल. एज. का पैसा बकाया है। मैं भी जब बाहर जाता हूं तो उनमें ठहरता हूं और उसका एक रुपया रोज लेते हैं फिर तीन तीन हजार रुपए कैसे बकाया रह गये। यह डागाजी क्लीयर कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो कहा कि कई मिनिस्टरों में बकाया है।

श्री निर्मलकुमार : कांग्रेसी मिनिस्टरों की बकाया होगी ?

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस का सवाल नहीं है....

श्री निर्मल कुमार : आपके साथियों की बाकी है।

श्री रतनलाल वर्मा : दस दस वर्षों से बकाया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या कहते हैं, इसमें कांग्रेस वालों का कहां सवाल है। आपके साथी ईमानदार हैं और धरती पर वे ही पवित्र हैं बाकी तो सब को बेईमान ही समझते हो, और सब लोग तारीफ करते हैं।

(व्यवधान)

जनता पार्टी धुंधली हो गई है। निर्वाचित होकर आने के बाद उन्होंने जो अपनी तस्वीर बनाई है, वह जनता को मालूम हो गई है। यह हमें मालूम है आप के कदम पाक हैं और आप अपना दामन साफ रखते हो। यह मालूम है। इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता।

सवाल यह था, मैं डाक बंगलों के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, कह रहा था। आज जहां पर सर्किट हाउस बन गया है वहां पर डाक बंगलों की इम्पोर्टेन्स कम हो गई है। जितने भी डाक बंगले हैं उनमें से कुछ तो आफिसरों के ठहरने के लिए रिजर्व्ड हैं, कुछ इन्जीनियर्स, कुछ ओवरसीयर और कुछ में उनके लड़कों के लिए जो पढ़ते हैं, रिजर्व्ड है। डाक बंगलों का जो चौकीदार होता है, वह भी बहुत होशियार हो गया है। वह जानता है किस को ठहरने देना है। वह पहले ही कह देता है मिनिस्टर साहब के लिए रिजर्व्ड है। हमारे विधायक अगर दिल्ली

(श्री मूलचन्द डागा)

जाते हैं तो जोधपुर हाउस, जयपुर हाउस में उनके ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है। यह कानून के खिलाफ है। मन्त्री और विधायक में यह अन्तर, फर्क क्यों रखा गया है। मन्त्रियों के लिए जयपुर हाउस, जोधपुर हाउस, आबू के काटेजेज हमेशा खुले रहते हैं। विधायक जायेंगे तो ये खाली नहीं रहेंगे। यह क्या व्यवस्था है? इस सारे प्रश्न की ओर मन्त्री महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बंद कर रहा हूं। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। पाली से, जो स्टेशन की तरफ से आते है, यानि जोधपुर से सुमेरपुर, इस सड़क को आज सात साल हो गये हैं। जोधपुर के पास चुंगी चौकी और सुमेरपुर चुंगी चौकी के पास एक सड़क बनाई, इस सड़क को पांच साल हो गये, इस सड़क का क्या हुआ? जो मजदूरों के बच्चे हैं, वहां पर रोज दुर्घटना होती है और हर तीसरे चौथे दिन के बाद एक दुर्घटना हो जाती है। यह एक मानवीय प्रश्न है। पार्टी के आधार पर नहीं सोचा जाना चाहिए। पाली का जो बाय पास है, तो इसके लिए आप 1971 के सेन्सस को आधार मत लीजिए। 1971 से 1979, 8 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है पाली की कि जहां 1971 में पाली की पापुलेशन 35 हजार थी वह आज पापुलेशन पाली की 80 हजार है....

श्री रतनलाल वर्मा : इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ाई?

श्री मूलचन्द डागा : आप जैसे कई शरणार्थी मिनाय से आ गये? वहां पर सारे इससे पाली की इम्पोर्टेन्स बढ़ गई। उद्योग लग गये। इससे पापुलेशन बढ़ गई। इसलिए वहां सड़क निर्माण के लिए 71 के सेन्सस को आधार मत मानिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विकास, सभ्यता और संस्कृति की पहुंच के लिए सड़क महत्वपूर्ण कड़ी है। इस दृष्टिकोण से देखें तो जो नये कार्यक्रम हैं जनता पार्टी के और नये जमाने के हिसाब से, दुरस्थ क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, असन्तुलित क्षेत्र, इनको दूसरे क्षेत्रों के बराबर लाने की दृष्टि से राजस्थान में अभी तक इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है जिसकी कि हम अत्यधिक प्रशंसा कर सकें। हां, कुछ कदम उठाये गये हैं। इस दृष्टिकोण से स्थिति को देखें तो राजस्थान में सड़कें बहुत कम है। 47 प्रतिशत से 67 प्रतिशत, तुलनात्मक रूप से यह आंकड़ा तो आज है, लेकिन फिर भी राजस्थान में सड़कों के लिए बजट बहुत ही कम हैं। राजस्थान के इन्टोरियर को, राजस्थान के बार्डर को, राजस्थान के बैकवर्ड गांवों को राजस्थान की पंचायत के मुख्यालय को अगर दूसरी सभ्यता से जोड़ना है, विकास के आधार से जोड़ना है, और उनकी प्रगति करनी है तो सड़कों के बारे में जिस तरह से कृषि, पशुपालन,

(श्री किशनसिंह भाटी)

मरुस्थलीय विकास, नहरें, सिंचाई, विद्युत, दूसरे क्षेत्रों में ये महती कार्य हुए हैं, इनके तुलनात्मक आंकड़े देखें तो इनका बजट प्रावधानों के मुकाबले सड़कों का बजट प्रावधान बहुत ही कम है। इसको मैं एप्रीशिएट नहीं कर सकता। यह दूसरी बात है कि केन्द्र ने पैसा कम दिया है या और कोई कारण हो जिसकी वजह से यह बजट कम हो। जहां तक विकास का सवाल है, इसमें आदिवासी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। आज भी वही पुरानी परिपाटी चल रही है आंकड़ों की। जब सन् 1977 में हम लोग चुन कर आये, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोग प्रतिनिधि चुन कर आए, आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुन कर आए, तो सबसे पहले सन् 1977 में हमने अपनी मेडन स्पीच में यह मांग की थी कि क्षेत्रीय असन्तुलन की विचारधारा को मिटा कर सामाजिक न्याय दिया जाए। यह विकास का आधार जनसंख्या के आधार को छोडना होगा और विकास को क्षेत्र के आधार पर आपको लेना होगा। यह जो प्रगति विवरण आपने दिया है उसमें भी जनसंख्या का आधार है। केन्द्रीय सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वे सारी की सारी दोषपूर्ण है और राजस्थान सरकार स्वयं अब भटक कर के इस रास्ते पर आई है। सातवें फाइनेन्स कमीशन ने आबादी का जो आधार बनाया है, उसका राजस्थान सरकार विरोध कर रही है और यह कह रही है कि आबादी का आधार न हो कर क्षेत्र को आधार माना जाए और इसी प्रकार से हमारी सरकार आज गाडगिल फार्मूले का भी विरोध कर रही है। यह राजस्थान सरकार को पहले से सोचना चाहिए था। राजस्थान सरकार की कथनी और करनी के अन्तर को देख कर ही शायद सातवें फाइनेन्स कमीशन ने पैसा कम दिया क्योंकि वह यह जानता था कि राजस्थान सरकार ने बाड़मेर, जैसलमेर, शेरगढ़ फलोदी ओसियां आदि और अन्य आदिवासी क्षेत्रों के नाम से जो पैसा लिया है या पैसा ले जा रही है, वहां यह पैसा खर्च नहीं करेगी। इसलिए पैसा कम मिला। आइन्दा के लिए कमीटमेन्ट कर दें केन्द्रीय सरकार से और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं रहेगा। मैं जयपुर, कोटा का विरोध नहीं कर रहा हूं और क्षेत्रीयता में मेरा विश्वास नहीं है। परन्तु मैं यह देखता हूं कि जयपुर की सड़कों पर 10/15 करोड़ रुपया लगाकर विकास का काम किया जा रहा है। अच्छा काम हो रहा है। जहां गड्ढे वगैरह हो उनको ढकने के लिए तो डामर की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु जयपुर की सड़कों पर जिस प्रकार से डामर लगाया जा रहा है वह एक प्रकार से शीयर क्रिमीनल वेस्टेज है। इतना डामर खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। आज स्थिति यह है. उपाध्यक्ष महोदय कि जयपुर की सड़क पटरियों से ऊपर चली गई है। जयपुर की सड़कों पर जितना पैसा खर्च किया गया है, वह पैसा राजस्थान के चार, पांच अविकसित पिछड़े हुए क्षेत्रों में खर्च करके उनका विकास किया जा सकता था। क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए हमारे राज्य के पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब को खास तौर से ध्यान देना होगा। इस दृष्टि से देखें

Page No. 162

(162)

(श्री किशनसिंह भाटी)

तो जो इस विभाग के नये चीफ इंजीनियर हैं, राजस्थान सरकार के वह ग्रानेस्ट आदमी हैं लेकिन उनका सारा महकमा ऐसा नहीं है। इस महकमे में आज करप्शन पर्यायवाची है। यह हमारे ब्लड में केन्सर की तरह है। इसको मिटाने की आप घोषणा करें। आज राजस्थान केनाल और दूसरे कई महकमे, पी.डब्ल्यू.डी. महकमे से आगे हो गये हैं। परन्तु इसमें और दूसरे महकमों में फर्क इतना ही है कि इस महकमे में मोस्ट लीगलाइज्ड वे में करप्शन होता है, और इस कारण से यह करप्शन आम जनता के पकड़ में नहीं है। इसको आप कैसे चैक करेंगे। इस मामले में आपको घोषणा करनी चाहिए। लीगलाइज वे में जो करप्शन होता है उसको कम करने की डिवाइसेज का कुछ काम किया है। वर्तमान चीफ इसको कम करने के लिए लेब्स सिस्टम को अपनायें। मैं भी इसका समर्थक हूं। लेब्स सिस्टम को अपनाने से राजस्थान सरकार, पब्लिक एक्सचेकर के धन का जिस तरह से आफिसर और ठेकेदार मिल कर शीयर क्रिमिनल वेस्ट करते हैं, वह रुक जायेगा। किसी सड़क की लीड बनाई जाती हैं। 10, 12, 15 मील रेगिस्तानी क्षेत्र में दूरी की लीड बताई जाती है, आदिवासी क्षेत्र को दूरी की लाड बनाकर मेटीरियल नजदीकी क्वेरिज से लिया जाता है और इस प्रकार इस नाम से लाखों रुपयों की गड़बड़ होती है और सरकार को घाटा होता है। इस मटीरियल की चैकिंग के लिए लेब्स सिस्टम को स्ट्रैंग्थन किया जाए इसके अलावा, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक एन्टी-करप्शन सैल पी.डब्ल्यू.डी. में कायम किया जाए। एक्स. ईएन. इन्जीनियर्स के लिये गांव में, मौके पर जाना अनिवार्य कर दिया जाए। महीने में 20 दिन वे मौके पर रहें। एक एक्स. ई.एन. जो अपने इलाके में डेढ़ साल से है, वह जयपुर में चक्कर लगाता रहता है, वे एक्स ई एन, इन्जीनियर उनके क्षेत्र के गांवों की सड़कों की दूरी नहीं बता सकते हैं। जो दो साल से अपने क्षेत्र में नहीं आ रहा था इसलिए दौरा कपलसरी किया जाय और इस क्षेत्र में सड़कों को देख आवें यह मेरा सुझाव है।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि जो सड़कें हैं-बाड़मेर की, जैसलमेर की, जोधपुर की, फलौदी की जहां एशिया के बिगेस्ट फायरिंग रेंज है 750 वर्ग मील की, जो जैसलमेर में बनी हुई है उसमें शेरगढ़, फलौदी, बाड़मेर मार्गों पर मिलिट्री की 20-20, 20-30 टायरों वाली भारी गाड़ियां, मशीनरी जाती हैं। इसलिए इन सड़कों को आप मिलिट्री को दे दीजिये। मिलिट्री इसको मेन्टेन करे क्योंकि हर साल मिलिट्री इन सड़कों को तोड़ती है तो पैसे की तो उनके पास कमी है नहीं, न अकाउन्टेबल फन्ड्स है। तो इन मार्गों पर हर साल जैसलमेर, जोधपुर, के इलाकों में कम से कम मिलिट्री 12-13 लाख की सड़कों का हर साल नुकशान करती है और आप उनसे केवल 2-3 लाख मंजूर करा लेते हैं। इसलिए डिफेंस से पैसा लेकर इन सड़कों की मरम्मत की जावे। सिर्फ जयनारायण जी व्यास के वक्त 12 फुट चौड़ी सड़कें जोधपुर-जैसलमेर में वहां बनीं। आज उन पर मिलिट्री की गाड़ियां रोडवेज की गाड़ियां इतनी गुजरती हैं,

(श्री किशनसिंह भाटी)

इतना ट्रैफिक गुजरता है वह राष्ट्रीय मार्ग है, उसे बड़ा कीजिये। इसमें सब का इंट्रेस्ट है। इसके अलावा हमारे जिले की क्षेत्रीय आवश्यकता को भी देखें। 30401 वर्ग किलोमीटर, दुनियां का बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। उसमें कम से कम दो एक्स. ई एन होने चाहिये, एक एस. ई का आफिस होना चाहिये। इसके लिये एक रचनात्मक सुझाव देना चाहूंगा। पी. डब्ल्यू डी के जितने पैसे मार्च के अन्त तक खर्च नहीं होते उसका एक कारण है प्रक्रिया की कमी। हालांकि पूनिया साहब सुधार करना चाहते हैं, अगर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को हम अपनाना चाहते हैं तो जयपुर में जो सचिवालय स्तर पर आपने जितने पावर केन्द्रीकृत कर रखे हैं उनको डिसेन्ट्रलाइज किया जाये। आप 1 लाख तक के एक्स. ई एन. को वित्तीय स्वीकृति के पावर देते हैं। 20 प्रतिशत भी ज्यादा हो जाये तो एस. ई. के पास जाना होगा। उससे अबव की मंजूरी भी हो जाती है तो भी कार्य की शुरुआत होने में 8 महीने लग जाते हैं। इसलिए मेरा सुधारात्मक सुझाव है कि पी. डब्ल्यू. डी. के एक्स ई एन. को मैं कहता हूं, पांच लाख रुपये, पांच किलोमीटर तक की सड़क बनाने के फाइनेंशियल पावर दिये जायं। आपका एक लाख का शिड्यूल बहुत पुराना है।

दूसरा सुझाव यह है कि जिलों में कार्य के लिए जिस तरह से आप राजस्व अभियान चलाते हैं इसी प्रकार जयपुर से अधिकारी चले जायें जिला हैड क्वार्टर पर। वहां तुरन्त इसी प्रकार मंजूरी दी जावे ताकि वर्क जल्दी शुरू हो जाये तो सड़कों का काम अधूरा नहीं रहे। एक सुधार के दृष्टिकोण से कहूंगा कि अफसरों की योग्यता और अयोग्यता को जज करने के लिये, जितना बजट देते हैं वह अगर समय पर खर्च नहीं किया जाता है तो उस क्षेत्र के अधिकारी को अयोग्यता का रिमार्क दिया जावे, उसकी पदोन्नति कीजिये, इससे अपने आप बजट खर्च हो जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आगे मैं इतना ही कहूंगा कि क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रेगिस्तानी इलाकों में छोटी कार्य शालाएं स्थापित कीजिए। मैं जिले के लिये नहीं कह रहा हूं जैसलमेर की तरफ देखते हुए नहीं, इसके लिये जनरल चौधरी, चव्हाण नाराज हुए, प्राइम मिनिस्टर नाराज हुए और रिजल्ट यह हुआ कि बाड़मेर-जैसलमेर की 1200 वर्गमील जमीन गई और नेशनल प्रापर्टी का लॉस हुआ। सुरक्षा खतरे में पड़ी। सिविल सड़कें जयनारायण जी व्यास की मृत्यु के बाद जैसलमेर को बहुत कम मिली हैं। इसलिए जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलादी को ज्यादा से ज्यादा सड़कें दी जायें। आपका वहां के लिए पर्सेन्टेज जीरो है मेरे जिले का 26 वां नम्बर है। फिर भले ही जनरल जिया उल हक आराम से चले जायें, जयपुर जोधपुर की बारी तो बाद में आयेगी। मैं बोर्डर पर रहने वाला हूं। 1971 में पाकिस्तानी फोर्सेज 22 किलोमीटर दूर थीं हमारे यहां से। तो इसमें जनसंख्या को न देखा जाय। बाड़मेर जैसलमेर को स्पेशल केयर दी जाय डिफेंस के नाम से। डिफेंस आपको पैसा देगा। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। कम से कम सारे पंचायत क्षेत्रों को जहां 500 से

(श्री किशनसिंह भाटी)

एक हजार की पापुलेशन हो सड़कों से जोड़ा जाय। इसके अलावा जैसलमेर में जो भी सड़कें हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं हैं। तीन क्षेत्र ऐसे हैं जैसलमेर के दक्षिण में सोठाण क्षेत्र पांच हजार वर्ग किलमीटर का एरिया 25-30 गांव, आज की तारीख में एक इन्च भी सड़क नहीं है वहां। और आपके फारिनर्स के लिए मरु विकास का बगीचा भी वहां बनेगा। फिर अगर कोई यू. एस. ए. और यू- एस. एस. आर का कोई अम्बेसेडर वहां आ गया तो उसकी कार बीच में ही रह जायेगी। वहां बाड़मेर का क्षेत्र और जैसलमेर के कुछ गांव लगते हैं। 36 गांव जैसलमेर के है, जिला हैड क्वार्टर है, जहां रेवेन्यू सर्किल है, बड़ी बड़ी आबादी के गांव हैं 5-5, हजार की आबादी के गांव भी है जिनको तहसील से जोड़ने के लिये आधे इन्च भी डामर की सड़क नहीं हैं। इसके अलावा जैसलमेर से जोधपुर को पोकरण और देवीकोट से जोड़ते हुये सड़क निकाल दी जाय तो 21 किलोमीटर आते और 21 किलोमीटर जाते, कुल 42 किलोमीटर का फायदा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

करीब 150-200 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, 50 किलोमीटर और कर दें तो यह राष्ट्रीय उपयोगिता का मार्ग है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर, श्रमिक कल्याण के लिये ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साइकिल इत्यादि की उन्होंने मांग की है, 10-10 साल से उनको स्थाई नहीं किया जा रहा है। छोटे कर्मचारी ही सड़कों को सम्भालते हैं इसलिये उनकी अवस्था सुधारने के लिए उन्होंने जो मांगें की हैं, उनकी ओर ध्यान दिया जाय। कम से कम एग्जिस्टिंग शर्तें तो मन्जूर की जावें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री किशन सिंह भाटी : हमको तो बिराजना ही है, उपाध्यक्ष महोदय बहुत बड़ा फाइनेन्शियल बर्डन आपको नहीं पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्रोधित होते हुए भी मुझे बोलने दिया इसका मैं आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल शर्मा।

श्री मोहन लाल शर्मा (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं। चूरू जिले के बारे में निवेदन करूंगा जहां के हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी हैं। चूरू जिले में सड़कों का हाल जो आज से 10 साल पहले कांग्रेस के जमाने में था, 10 साल पहले जो सड़कें बनी हुई है, इस दो साल के अर्से में सिर्फ, राजगढ़, जहां के सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी है, में 5-6 सड़कें बन रही हैं। यह उपेक्षापूर्ण रवैया है। चूरू जिले में न कोई सड़क की मरम्मत हो रही है और न कोई निर्माण हो रहा है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हमारा चूरू जिला सारे का सारा उपेक्षित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस प्रकार से

(श्री मोहन लाल शर्मा)

पक्षपातपूर्ण रवैये को छोड़ कर और दूसरी बहुत कीमती जगह है उनके बारे में भी ध्यान दें। सिवाय राजगढ़ के कहीं और काम होता है तो केवल कागजों में तो भले ही हो लेकिन सारे जिले में किसी प्रकार का वास्तव में काम नहीं हो रहा है। न डवलपमेंट का हो रहा है और न सड़कों के निर्माण का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति का अवलोकन करें और सार्वजनिक निर्माण मन्त्री इस ओर ध्यान दें। यह आपका जिला है इसमें निर्माण कार्य करायें।

अब मेरा जो मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार का उस पर आता हूं। भ्रष्टाचार के बारे में आपको ध्यान है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। चूरू जिले के बारे में आपने कहा था, चूरू जिले की सड़कों के बारे में आपको जानकारी होगी कि यह भूल नहीं है। भूल हो गई यह सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि वहां पर 49 लाख का खर्चा भी नहीं हुआ। कहां 1 करोड़ 69 लाख और कहां 49 लाख। मौके पर काम नहीं 38 लाख का भी। कुछ हिसाब बताकर 11 लाख और जोड़ कर........

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह काम कब का है ?

श्री मोहन लाल शर्मा : 78 का। 1 करोड़ 21 लाख की अगर माननीय मन्त्री जी जांच करवायें। यह रुपये खा गये। इस प्रकार से गबन हो रहा है तो मालूम होता है कि सबसे ज्यादा 1 करोड़ 10 लाख का अमाउन्ट राजगढ़ तहसील में खर्च हुआ है। तो वह कौन लोग थे ? इस बात को छिपाये नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से यह एक बड़ी भारी विडम्बना है कि एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, और सार्वजनिक निर्माण मंत्री कहते हैं कि किसी प्रकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। तो 1 करोड़ 31 लाख का घोटाला पकड़ा गया, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई। अगर इसकी जांच होती, राजगढ़ तहसील की जांच होती जिन आदमियों के जमाने में सीमेंट की बोरियां चली गई थीं, तो मालूम होता कि कौन लोग थे। यह वही लोग थे। सार्वजनिक निर्माण मंत्री के रिश्तेदार थे, और जो आज आज भी उनके पीछे लगे हुए हैं। उन्हीं को आज भी ठेकेदारी का काम मिला हुआ है। उनके सार्वजनिक निर्माण मंत्री बनने के बाद में उन लोगों ने ठेकेदारी प्रारम्भ की है। यदि उनको ठेके पर बुलाते हैं और यदि वे नहीं आते हैं या टेण्डर नहीं देते हैं तो किसी प्रकार भी ठेका दूसरों को नहीं दिया जाता है। अगर मैं गलत बात कहता हूं तो जांच करा लें। किसी आदमी को भेजें तो मालूम हो जायेगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मंत्री महोदय, सुन लें।

श्री जयनारायण पूनिया : अभी जवाब दे सकता हूं एक मिनट में। मेरा कोई रिश्तेदार ठेकेदार नहीं है।

श्री मोहनलाल शर्मा : मेरे राजगढ़ क्षेत्र में आपके भतिजे प्रतापसिंह पूनिया ने

(श्री मोहनलाल शर्मा)

ब्लास्ट लगाने का ठेका लिया। यह स्थिति यहां तक पहुंची कि ब्लास्ट एक बार डाल कर वह उठाया नहीं जाता है, और दूसरी सड़क पर दिखाकर पैसा वसूल कर लिया जाता है। इसकी शिकायत एन्टी करपशन और माननीय मन्त्री महोदय को पेश की जा चुकी है। इसकी जांच भी हो चुकी है, लेकिन जिस दिन जांच करने के लिए राम वल्लभ शर्मा, एन्टी करपशन के डी. वाई. एस. पी. पहुंचते हैं तो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी श्री पूनिया जी भी उनके पीछे पीछे आ गये और उनको धमका कर वापस कर दिया और कागज नहीं देने दिये। अगर यह बात सही नहीं हो तो पूनिया साहब जवाब दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह जनता पार्टी के मन्त्रिमण्डल पर पहला आरोप लग रहा है।

श्री मोहनलाम शर्मा : इसी प्रकार वहां पर सूद सिंह एस. ई. हैं। वहां पर एक ठेका टेन्डर कमेटी द्वारा स्वीकृत दर पर स्वीकृत किया तो वह एक्स. ई एन. के पास पहुंच गया। हनुमानगढ़ में एक ठेका खेतसिंह अल्लाह बक्ष के नाम से मन्जूर हुआ था, लेकिन उनका वर्क आर्डर जारी होने के पहले ही एक्स. ई एन. से कागज वापस मंगा लिये गए और पूनियाजी के चहेते ठेकेदार लूकाराम मूथा को वह ठेका दिया गया। न किसी प्रकार का टेन्डर दिया गया और न किसी प्रकार का नेगोसियेशन किया गया, मगर कमेटी की आज्ञा की अवहेलना करके गलत तरीके से एस. ई. ने नाजायज तौर से स्वीकृति देकर किया है।

इतना ही नहीं जो. पी. डब्लू डी. के पीस वर्क्स का ठेका होता था वह राजस्थान भर में एक सर्क्यूलर जारी करके बन्द कर रखा है, लेकिन राजगढ़ के लिए वह खुला है। इसी प्रकार यह पीस वर्क 3-4 काम पी. डब्लू. डी. के तहत करवाये गये केवल कागजों पर और किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है।

यही नहीं चूरू राजगढ़ सड़क की मरम्मत का बजट 7 हजार से बढ़ कर डेढ़ लाख का बन गया है। अस्थाई मजदूर ता. 3-2-79 में ही बढ़ाये गये थे। वह और बढ़ाये जा रहे हैं टेन्डर लिये जाकर और पूनियाजी के आदमी ले आते हैं वह पूनियाजी को देते हैं या नहीं देते हैं, मैं नहीं कह सकता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आप आरोप लगा भी रहे है और नहीं भी लगा रहे हैं। पूनिया साहब ईमानदार भी हैं और इसके साथ बेईमान भी हैं।

श्री मोहनलाल शर्मा : मैं यह भी बता दूंगा कि वह एक्स. ई एन. ....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह जरूरी नहीं है कि सभी पूनिया इनके रिश्तेदार हों। पूनिया कोई दूसरा आदमी नहीं है क्या ?

श्री मोहनलाल शर्मा : सन् 69 में जो ओवरसियर राजगढ़ में फेमिन के टाइम में

(श्री मोहनलाल)

था उसी ओवरसियर को सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने प्रमोशन देकर वापस राजगढ़ में लगा लिया। एक ए. ई एन, जिसके खिलाफ यह चार्जेज थें, और एन्टी-करप्शन में जांच चल रही थीं डिपार्टमेंटल, में को राजगढ़ लगा दिया ताकि इस प्रकार की गड़बड़ और घोटाले उनके भाई भतीजे करते रहें।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो एम. बी. है, मेजरमेंट बुक है वह ओवरसियर के आदमी को दी नहीं जाती है और इनके चहेते ठेकेदार जिस प्रकार डेली वेजेज पर पी. डब्लू. डी. ने रखे हैं उनसे भरवाई जाती है। यह आप नियमों और शर्तों को मगा कर देख लें।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी प्रकार से ट्रांसफर्स की हालत है। पी. डब्लू. डी. में ओवरसियर के लिए, ए. ई एन. के लिये, एक्स. ई एन. और एस. ई. के रेट बंधे हुए हैं। ओवरसियर के लिए 3 हजार, ए. ई एन. के लिए 5 हजार, एक्स. ई एन. के लिए 7 से 10 हजार और एस. ई. के लिये 30 हजार।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कौन लेता है ?

श्री मोहनलाल शर्मा : मिनिस्टर साहब के आदेश जाते हैं। मैं तो पास में नहीं रहता हूं, लेकिन मेरा यह आरोप है।

इसी प्रकार से प्रमोशन में गड़बड़ियां होती हैं। पिछली बार जो प्रमोशन्स हुए हैं उनमें काफी गड़बड़ियां हुई हैं। एक उदाहरण मात्र देता हूं। राम बाबू एक्स. ई एन. है उनको अब सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर बनाया गया है। वह कम से कम 25 आदमियों के नीचे थे, लेकिन उनको प्रमोशन दिया गया है। डी. पी.सी. के सामने उनको पेश नहीं किया गया है। अगर पेश किया जाता तो पोल खुल जाती। उनके लिए एस. ई. का नया पद निर्माण कराया जा रहा है।

श्री रणमल सिंह : यह राम बाबू भी पूनिया है क्या ?

श्री मोहनलाल शर्मा : इस प्रकार से पद निर्मित करके लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं, और दूसरी तरफ यह जो आन्दोलन चल रहा है कर्मचारियों का, श्रमिक कर्मचारियों का जिस प्रकार से कि माननीय भाटीजी ने फर्माया कि उनके लिये साइकिल एलाउन्स की मेडिकल रिलीफ की इस प्रकार की 7-8 मांगें हैं उनकी व्यवस्था नहीं की जाती है।

(समय-समाप्तिसूचक घंटी)

तो आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इन बातों की जांच कराई जाय। क्या सत्य है क्या गलत है यह जांच से मालूम हो जायेगा। मैं बात गलत कहता हूं या सही कहता हूं, यह भी मालूम हो जायेगा।

इस प्रकार आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

श्री जगदीश शर्मा (रतनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये 5 हजार, 7 हजार लेने के जो आरोप लगाये हैं, ये गंभीर आरोप है । इनकी जांच होनी चाहिये । आखिर यह कौन लेता है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : करा दो ।

श्री उपाध्यक्ष : चार्ज बड़े गम्भीर लगाये हैं । इस बारे में माननीय सदस्य के पास जो जानकारी हो वह मन्त्री महोदय के कार्यालय में जाकर दे दें । इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के आधार पर प्रमोशन्स हुए हैं वह भी आरोप है ।

श्री मोहनलाल शर्मा : मैं उनको बीच में कह चुका हूं लेकिन उनके दिमाग में यह नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने सदन में चार्जेज लगाये हैं । आपके पास जो जानकारी है, वह सदन के पटल पर रख दें ।

श्री जगदीश शर्मा : ऐसे कौन कौन हैं, पी.डब्ल्यू.डी. में जो इस तरह से पैसा खा रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरोप सदन में लगाये हैं अब पीछे हटने वाली बात है तो अपने आरोपों को वापस लें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जांच कराने वाले हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जांच के लिए व्यवस्था करवाऊंगा ।

श्री मोहनलाल शर्मा : मेरे पास जो कागज हैं, वह मैं सदन पटल पर रखता हूं ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्य ने सदन में आरोप लगाये हैं । यदि इन्होंने पहले से सूचित नहीं किया है तो यह नहीं बोल सकते हैं ।

श्री मोहनलाल शर्मा : मेरे पास जो एप्लीकेशन्स आई हैं, वह कागज मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, उत्तर देते समय भी उत्तर दे सकते हैं । चाहें तो इसी समय उत्तर दे दें ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा प्रश्न यह है कि यदि एम.एल.एज. के द्वारा इसी प्रकार से दरख्वास्त लेकर सदन में आरोप लगाये गए और सदन पटल पर रखने लग जायेंगे तो क्या कार्यवाही की जाएगी ? पहले इसकी व्यवस्था करें कि इस प्रकार से सदन पटल पर रख सकते हैं या नहीं ? आसन क्या व्यवस्था देगा, क्या प्रक्रिया बनाई जाएगी । पहले यह व्यवस्था हो जाने दें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत गम्भीर आरोप हैं । इनकी बाकायदा जांच होनी चाहिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : इस काम के लिए सतर्कता आयोग बना हुआ है। एफिडेविट देकर वहां शिकायत हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इन आरोपों में मन्त्री महोदय पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। मोहनलाल जी द्वारा जो भी आरोप लगाये गये हैं, उनमें यही कहा गया है कि मन्त्री महोदय के आसपास रहने वाले लोग हैं, उन पर ये आरोप हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, विराजें। जो भी आरोप लगाये गये हैं, वह स्पष्ट हैं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

• श्री जयनारायण पूनिया का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये गए हैं, जो जानकारी मुझे है, मैं उनका उत्तर दे देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो भी आरोप लगाये हैं, इन्होंने जो भी कहा है, सब मेरे खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की है और कुछ नहीं है। तीन हजार, चार हजार, पांच हजार, यह तय करने वाले हैं, यह इनकी इस प्रकार की लैंग्वेज है। इस प्रकार की एक दो बातें मैं बतला देना चाहता हूं। पहले तो यह कहा है कि चूरू जिले में राजगढ़ में सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ है। यह सही है। क्योंकि 5 हजार की आबादी से ज्यादा का वहां कोई गांव नहीं है। इसलिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में वहां कार्य नहीं हो सकता था। राजगढ़ तहसील बार्डर पर पड़ती है। यह इण्टर स्टेट रोड है। शायद माननीय सदस्य को पता नहीं है। एक सड़क है, भादरा-भट्ठू। जो गंगानगर जिला है। यह सड़कें फूड फार वर्क योजना में, तथा एक करोड़ की नई स्वीकृत योजना में भादरा राजगढ़ नाम से मंजूर की थी। सरदार शहर चूरू जिले की सड़क को लिया है। इस तरह से जितनी आवश्यकता पड़ती थी, फ्लड में रिपेयर वर्क लिये गये। इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है। यह हिसाब अच्छी तरह से मंगाकर देखा जा सकता है। पक्षपात का कोई सवाल नहीं है। अब इन्होंने एक बात और कही है। एक रोड है, जिसके लिये फेमिन में 1 करोड़ 69 लाख का खर्चा होना और 49 लाख वास्तव में लगना बताया है। पता नहीं माननीय सदस्य को ये आंकड़े किससे प्राप्त हुए या कैसे मालूम हुआ। लेकिन यह रोड हमेशा से फेमिन में चलती आई है। वहां पर रोड नहीं बनी है। यह सारा हिसाब जोड़ा जाये तो हिसाब बैठ सकता है।

श्री मोहनलाल शर्मा : 1 करोड़ 31 लाख का घोटाला है।

श्री जयनारायण पूनिया : ठीक है, ठीक है।

(व्यवधान)

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक एक्स. ई-एन के बारे में कहा है, जो सस्पेंडेड था उसको बहाल कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उस एक्स.ई-एन पर किसी भी प्रकार का लाछन साबित नहीं

(श्री जयनारायण पूनिया)

हुआ। इसी आधार पर वह बहाल हुआ है। उस पर कोई लांछन साबित नहीं हुआ। उस पर कोई लांछन था नहीं। बेगुनाह आदमी पर कार्यवाही करना सम्भव नहीं था। वह फाइल अभी भी देखी जा सकती है।

तीसरी बात, एक नाम बताया गया है, प्रताप सिंह पूनिया का। मेरा गांव है, लाखलाण और प्रतापसिंह का गांव है सुलखनियां। दोनों में ही 40 किलोमीटर से ज्यादा का फासला होगा। न वह मेरा कोई रिश्तेदार है।

(व्यवधान)

प्रतापसिंह पूनिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह पूनिया क्यों है।

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्य ने ठेकेदार होने का आरोप लगाया है। उसका शायद लकड़ी का ठेका है। मैं अपने रिश्तेदार को क्या लकड़ी के ठेके में इन्वाल्व करूंगा। लकड़ी का ठेका क्या मैं अपने रिश्तेदार को देता। कोई रेट ऊंची है या नीची है, ऊंची रेट पर किया है या नीची रेट पर दिया है इस बारे में पूर्ण जानकारी यही है कि किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई है। फिर भी माननीय सदस्य को विश्वास हो जाये उनकी लकड़ियों के क्या भाव थे, माननीय सदस्य बता सकते हैं। पूरे फैक्ट्स इन्होंने बताये नहीं है। इसी तरह से बताया है कि रोड़ियां उठवा लीं। इसके बारे में एक आदमी ने मुझे बताया कि प्रताप सिंह नाम का आदमी रोड़ियां कम डाल रहा है। जब जांच कराई तो 9 ट्रक फालतू उसने डाल रखे थे, ट्रक उसने फालतू ही डाले हुए थे। डाला हुआ मैटीरियल फालतू निकला। जैसी कि माननीय सदस्य ने एक बात कही, उसकी जांच करवाई गई है। वहां जांच करने के लिए एक आफिसर भी गया। उसने उनको डराया धमकाया, यह गलत बात है। कोई भी आदमी यह साबित कर दे कि मैं उस आदमी को जानता हूं जो जांच करने के वक्त गया है, मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि मैं आज इस्तीफा दे सकता हूं। यह बात निराधार है जो जांच करके आये हैं उन्होंने इसको झूठा पाया है। माननीय सदस्य को जो इन्फार्मेशन देने वाले हैं वह बिल्कुल झूठे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जांच करवाई गई और यह गलत पाया गया, चाहे तो दुबारा जांच भी करवाई जा सकती है। दूसरा मामला यह था कि आत्माराम को ठेका नहीं देकर मंगतूराम को दिया गया। कृषि उपज मण्डी में हरबिन्दर सिंह एस. ई. हैं। ठेका जिन टर्म्स पर छोड़ा गया वह सबसे कम रेट पर है। माननीय सदस्य किसी ठेकेदार के बारे में कहना चाहें तो मैं तो यही कहूंगा कि यह उनकी भूल है और वे अपनी भूल को सुधार लें।

एक ए. ई एन. के खिलाफ इन्होंने चार्जेज लगाए। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी के भी खिलाफ चार्ज लगाना हो तो साबित होने पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसको वहां से हटा दूंगा। यह मेरे ध्यान में नहीं है किसको राजगढ़ या चूरू लगा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार

(श्री जयनारायण पूनिया)

की बात बिल्कुल वाहियात और बेबुनियाद है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह रंजिश की वजह से कह रहे हैं, जिसका विवरण मैं नहीं देना चाहता। ये जरूर पीड़ित हैं, मुझे भी चिन्ता है, इन्होंने कुछ काम के लिए मुझे कहा था लेकिन मैं उनके पक्ष में नहीं था।

श्री मोहनलाल शर्मा: मैंने एक भी काम के लिए नहीं कहा।

श्री जयनारायण पूनिया: रामबाबू गुप्ता को जो एक्स. ईएन था उसको प्रमोशन देने की बात भी कही गई। मैं इनको रिवर्ट नहीं कर सकता। डी. पी. सी. की मीटिंग होने वाली है। जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाय, इनका प्रमोशन चलता रहेगा। मैं इस बारे में भी जांच करवाने के लिए तैयार हूं और हरदम, हर वक्त जांच करवा सकता हूं, किसी भी अफसर से करवा सकता हूं। एक बात और कही गई, माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने कई बार कहा, माननीय सदस्य ने एक बार मुझसे कहा कि ए. ईएन. का ट्रांसफर कर दो। मैंने पहले ही दिन इनकी बात काट दी। माननीय सदस्य मुझे धमकी देकर चले गए कि मैं तुमको देख लूंगा।

श्री मोहनलाल शर्मा: यह गलत है बिल्कुल।

व्यवस्था का प्रश्न

आरोपों की अध्यक्ष को पूर्व सूचना

श्री रघुनाथ विश्नोई: पाइन्ट ऑफ आर्डर। मैं रूल 272 और रूल 273 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रूल 272 में यह है कि कोई भी माननीय सदस्य बहस के दौरान किसी सदस्य के खिलाफ एलिगेशन लगाता है तो उसको प्रिमिअस नोटिस देना चाहिए और फिर आपकी इजाजत से वह बोल सकता है। रूल 273 में यह है, डिफेम करने के लिए आफिसर के जो नाम लिये गये हैं, उनके लिए वह आफिसर तो अपना एक्प्लेनेशन नहीं दे सकता, उसके बारे में कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उसकी काफी पहले आसन को सूचना देनी चाहिए और उसके बाद फुल फैक्ट्स कहने के आपको अधिकार हैं। यहां पर इन दोनों ही रूल को आब्जर्व नहीं किया गया है। इसके लिए भविष्य में क्या परम्परा रहेगी। एकदम सरसरी तौर पर कह कर इस तरह से आप बैठ जायं, इसके पहले फैक्ट्स का नोटिस माननीय सदस्य को देना चाहिए। कान्क्रीट फैक्ट्स देने पर गवर्नमेंट इसकी जांच करेगी और उसके बाद इस पर बहस की जा सकती है। ब्रीच आफ प्रिविलेज हमारा सुरक्षित है लेकिन रूल की पालना होनी चाहिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है। मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने कृषि उपज मण्डी का ठेका दिया और कहा कि नेगोशिएशन से दिया। पी. डब्ल्यू. डी. के ठेकेदार से नेगोशिएशन किये जाते हैं परन्तु जिस व्यक्ति को दिया गया, मगतूराम का

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

टेण्डर हाइयेस्ट था और उस ठेकेदार को दिलाने की नीयत से नेगोसिएशन किया गया टेलिफोन से। यह एक ऐसा विषय है कि जिससे मालूम पड़ता है कि विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है। जहां तक एलिगेशन का सवाल है डिमाण्ड के अवसर पर मन्त्री महोदय का ध्यान नहीं दिलायेंगे तो वे आराम से बैठे रहेंगे। इसलिए उनको तैयारी करके आना चाहिए। आज तैयार नहीं है तो बाद में इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मुझे भी अखबार में पढ़ने को मिला था इस सड़क के बारे में। उस ठेकेदार को ठेका दिलाना चाहते थे और उसको दिलवाया—

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्य, यह कृषि उपज मण्डी की बिल्डिंग का ठेका है, रोड का नहीं है। यह मेरे से सम्बन्धित भी नहीं है। मैंने कोई इण्टरफीयर नहीं किया। मेरे गांव का ठेकेदार है इसलिए मुझे मालूम है।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : कृषि उपज मण्डी का ठेका सरकार ने दिया और सरकार के माध्यम से दिया जाता है।

श्री जयनारायण पूनिया : माननीय सदस्य पी.डब्ल्यू.डी. का ठेका सड़क के लिए है, बिल्डिंग के लिए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को आरोप लगाने से पहले पूर्व सूचना देनी चाहिये, आपका सारा भाषण ही आरोप लगाने से सम्बन्धित रहा है। मैं अपेक्षा करता था कि आप पहले आसन को सूचित करते।

श्री मोहनलाल शर्मा : मैं अब दुबारा आपके माध्यम से, पूर्व सूचना देकर, आरोप लगाऊंगा।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम 32 साल के कांग्रेस के शासन को और दो साल के जनता पार्टी के शासन को देखें तो कोई भी गांव का आदमी, राजधानी में आए तो उसको बिल्कुल साफ नजर आएगा कि वह नरक में रहता है और यह स्वर्ग है। डामर की बनी हुई सड़क, कोठियों के इर्द गिर्द, बड़ी लम्बी–चौड़ी सड़कें और कहीं नजर नहीं आएंगी। अब गिरधारीलाल जी ने ट्यूब लाइट्स हटाकर मरकरी लाइट लगाना शुरू कर दिया। तो देश में अब तक एक ही लाईन है। जो पूंजीवादी व्यवस्था इधर से शुरू हुई थी जनता पार्टी भी उसी लाइन पर चल रही है। खैर, यह तो उनके सोचने की बात है, गवर्नमेंट जितना भी पैसा ले उस नरक की हालत को कैसे ठीक कर सकती है, यह वह देखे।

अभी सवाल आया पर्सेन्टेज का। पर्सेण्टेज बंधा हुआ है, वही कानून है, वही हाकिम है, वही ठेकेदार है। जनता पार्टी आई है, कुछ चेहरे जो इधर थे वे उधर आ

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

गए। तो चेहरे हाकिमों के बदले हैं या पार्टी बदल गई, उससे पुराने ट्रेडीशन्स, पुराना मुनाफा, पुराना कमीशन खतम नहीं हो गया। लेकिन अब भय की बात नहीं है, मोल तोल की बात नहीं है। बेफिक्री के साथ खाओ। पुराने मन्त्री थे, माहिर हो गए थे, उनका स्टेंडर्ड था, वे कुछ हिस्सा ज्यादा मांगते थे। सारे का सारा हिस्सा अब अफसरों के पास जाता है। खैर, मैंने पिछले साल भी सुझाव दिया था कि अगर आप चाहते हैं भ्रष्टाचार मिटे तो ठेकेदारी सिस्टम खतम करो। ठेकेदारी सिस्टम भ्रष्टाचार की मां है, जब तक मां को नहीं मारोगे उसकी औलाद बन्द नहीं होगी। जब तक ठेकेदारी व्यवस्था रहेगी, यह पर्सेण्टज का हिसाब किताब रहेगा। कौन शिकायत करेगा? एक लाख का काम होता है तो कम से कम 15 हजार वह बचाना चाहता है तो अफसर चाहता है 10 हजार मुझे मिलें। तो 25 हजार रुपये बिल्कुल साफ। अगर ईमानदारी से काम कराना चाहते है तो ठेकेदारी व्यवस्था को खतम करना चाहिए। मैंने पिछले साल भी सुझाव दिया था। मिलिट्री में काम होते हैं, वह मैटीरियल मोल लेती है, टेण्डर्स काल करती है, बाकी काम अपने बिग्रेड से करवाती है। इससे लोगों को स्थाई जोब मिलेगा, इन्जीनियर्स और बाबुओं को जोब मिलेगा यह तय करें कि बिग्रेड का एक कमाण्डर होगा उसके नीचे कर दें, उसको वहीं रहना पड़ेगा जैसे मिलिट्री में होता है। मैंने देखा है मिलिट्री का काम। बड़ा अच्छा काम होता है, सड़कें बहुत बढ़िया बनती हैं। तो मैंने सुझाव दिया था आपको भी एक्सपेरीमेंट के तौर पर करना चाहिए। बंगाल में भी हो रहा है, वे एक्सपेरीमेंट के तौर पर कर रहे हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : बंगाल खुदा हो गया क्या?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कांग्रेस(आई) और जनता पार्टी दोनों के लिए कुछ भी हो लेकिन हमारे लिए तो वह खुदा है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : आपकी बंगाल सरकार ने केवल 1.50 लाख रुपये बेरोजगारों को देने के लिए रखा है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दो लाख लोगों को मिल रहा है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : पिछले साल 1.50 लाख रुपया दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मन्त्री से पूछो। वह उनसे मिलते रहते हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : इस बहाने आपको भगवान तो याद आया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं भगवान को नहीं मानता। मेरे भगवान तो लेनिन है, ज्योति बसु हैं। हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं है। हम ड्रामा नहीं करते, ढोंगी नहीं हैं। खैर! उपाध्यक्ष जी, यह जो इन्ट्रप्शन हो रहा है यह जनता पार्टी के समय में जोड़ा जाए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अब त्रिपुरा की मिसाल देता हूं । बंगाल मे तुमको तकलीफ होती है । मैंने कहा था कि हमारे रेस्ट हाउसेज, डाक बंगलोज क्या हैं ? सर्किट हाउसेज, ये तो पिकनिक हाउसेज हैं । पैसा लगे नहीं, एक रुपया या 12 आने । क्या कोई धर्मादा है ? हमें टी. ए, डी. ए. मिलता है, ड्यूटी पर जाते हैं तो ठीक, नहीं जाय कम से कम 5 रुपये तो लगें । पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारी जाते हैं वे टी. ए. डी. ए. लेते हैं । विधायक को मिलता है 51 रुपये देते हैं एक रुपया । आप कम से कम 5 रुपय क्यों नहीं करते हैं ? नान आफिशियल्स का किराया भी बढ़ाइए । खाने के पैसे भी बढ़ाओ, उसके भी कम से कम 5 रुपये होने चाहिए । अब आप दो या ढाई रुपये चार्ज करते हैं । आप बाबा आदम के जमाने की रेट्स को बढ़ाइए । अगर नहीं बढ़ायेंगे तो सारे अधिकारी मौज करते हैं, मन्त्री मौज करते हैं और भोगना पड़ता है आम जनता को । क्यों ? इसलिए इनके रेट्स ज्यादा होने चाहिए । सिंगल बेड व डबल बेड के लिए ऐसा होना चाहिए कि यदि एक आदमी रहे तो 5 डबल के 10 । एक विधायक जाता है तो अपने साथ 10 जनों को ले जाता है, 10 जने साथ सो जाते हैं । जब से संजय अवतार पैदा हो गया सब रेस्ट हाउसेज में डनलपिलो लगाए, एक एक फुट के ऊंचे गद्दे ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक एक फुट के गद्दे तो कहीं नहीं हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बीकानेर के रेस्ट हाउस में देखिए । तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे रेस्ट हाउसेज पिकनिक हाउसेज नहीं हैं । गजेटेड अधिकारियों व विधायकों पर ज्यादा किराया लगाइए । जो बाहर के हैं उनकी हालत ही अलग है । वहां पर तो एक एक आदमी 6-6 महीने से बैठा हुआ है, जोधपुर हाउस पर कब्जा किए हुए बैठे हैं । विधायक को कमरा मिले या नहीं । वह रेस्ट हाउस में जाएगा तो कहेंगे कि एक कमरा तो रिजर्व्ड है । किसके लिए ? आने वाले मन्त्री के लिए ? कभी भी पैदा हो जाए रात को दिन को नरसिंह अवतार हो गया हमारा मन्त्री ।

एक कमरा रिजर्व्ड रहता है हमारे अधिकारी के लिए । अगर पी. डब्ल्यू. डी. का रेस्ट हाउस है तो हमारे एस. ई. के लिए रिजर्व्ड रहेगा, चीफ इंजीनियर के लिए रिजर्व्ड रहेगा । कोई आने का प्रोग्राम नहीं है । मगर वह जन प्रतिनिधि विधायक वहां नहीं ठहर सकता । यह तमाशा क्या है ? अगर आपके कमरे आक्यूपाइड हैं, कोई अधिकारी ठहरे हुए हैं तो नहीं मिलेगा मगर खाली है तो भी नहीं देंगे, आप इन्कार करते रहेंगे कि न मालूम कब नरसिंह अवतार पैदा हो जाए ।

यह ठहरते हैं तब भी एक रूपया देते हैं और नहीं ठहरते हैं तो खाली रखते हैं याने कितनी बड़ी विडम्बना है । उनके नाम पर रिजर्व है, दूसरा रह नहीं सकता तो वह पिकनिक हाउसेस मत बनाओ । ठीक है आप उनको फेसेलिटीज प्रोवाइड कीजिए लेकिन

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

उसका माकूल पैसा भी लीजिए, जितना होटलों में लिया जाता है।

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें 70 करोड़ रुपया मिला है। हमारी हालत क्या है? 8 महीने तक इंजीनियर लोग मेजों पर बैठे रहते हैं। हमारे एक्स. ई एन. हैं, ए. ई एन. हैं, जूनियर इन्जीनियर्स हैं वह दफ्तरों में क्यों बैठते हैं उन्हें तो फील्ड में रहना चाहिए। उनको आठ महीने कोई काम नहीं है। 4 महीने पिछले होते हैं तो वर्क्स सैंक्शन होते हैं। बजट मार्च में पास होगा, 31 मार्च के पहले पहले पास होगा फिर क्यों नहीं बजट सैंक्शन होता। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से काम होने चाहिए और कौन कौन से नहीं होने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महसूस किया है कि 9 महीने, 10 महीने और 12 महीनों में काम होना चाहिए। यह नहीं कि बजट पास होने के बाद में 6 महीने के बाद तो सैंक्शन होगी। अगर सैंक्शन भेजेंगे तो चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और दूसरे नहीं हैं। आखिर आप कब काम करोगे? सब क्या है यह? आपके पास बहुत पैसा है। मेरे यहां 4 लाख रुपये ले गए हमारी मण्डियों के विकास के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मंडी विकास समिति की तरफ से 4 लाख की सैंक्शन मांगी और पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से भेजी कि हमारा काम करवा दें। वह 31 मार्च से पहले नहीं करवायेंगे। हमारा वह रुपया गया और अगली साल मिलेगा नहीं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

कितना देंगे, कितना नहीं देंगे, पता नहीं। दो साल में एक पैसा नहीं लगा। हमने कहा कि चार लाख की सैंक्शन करके भेजें पहले। वह सैंक्शन नहीं हो रहा है। चीफ इंजीनियर के यहां पड़ा है। वह कहते हैं कि इतने समय में हमारे एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब काम नहीं कर सकेंगे, पैसा यूटीलाइज नहीं कर सकेंगे। यह बहाना है। मैं अभी, उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ से आया तो मुझे कहा गया कि आप कोशिश करें कि 4 लाख रुपया सैंक्शन हो जाये। मैंने कहा कि हो जायेगा। वह कहने लगे कि नहीं होने वाला है। आप, मंत्री महोदय, इस मशीन को ठीक कीजिए। जितना रुपया आये उसको यूटीलाइज कीजिए। हमारे इन्जीनियर्स फील्ड में मिलने चाहिये। दफ्तर में बैठे हुए मिलें तो हमारे बहुत सारे काम नहीं होंगे। 70 करोड़ रुपया आप यूटीलाइज करने जा रहे हैं।

फिर इसके साथ ही साथ में बीकानेर सर्किट हाउस की बात करना चाहूंगा। सर्किट हाउस बहुत बढ़िया है मगर वहां पर कुर्सी की कीलें निकली हुई हैं। जो अधिकारी जायेगा तो अपनी पेंट फड़ाकर आयेगा। मेरे जैसा जायेगा तो पजामा फड़ाकर आयेगा। एक तरफ तो आपने 7 लाख रुपया खर्च कर दिया संजय गांधी आये उस पर और इधर एक पैसा भी नहीं लगा सकते?

एक माननीय सदस्य : सर्किट हाउस तो पी. डब्ल्यू. डी. में नहीं आता जी. ए. डी. में आता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : किसी में भी आये लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं।..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया चर्चा उस सम्बन्ध में करें जिसका सम्बन्ध मंत्री महोदय से हो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अच्छा इसके साथ ही साथ यही सुझाव देता हूं कि महरबानी करके गंगानगर पर दया करो। मैंने गड्ढे बहुत देखे हैं। राजस्थान की सारी सड़कें देखी हैं लेकिन जितनी खूबी के साथ गड्ढे गंगानगर की सड़कों में हैं उतने कहीं पर नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर गंगानगर की सड़कों में सबसे ज्यादा गड्ढे गहरे और चौड़े मिलेंगे। हमारी बदनसीबी यह है कि हम रोडवेज के चैयरमैन से मिले और कहा कि हमारे यहां नई बसें भेजिये तो कहते हैं कि आपको नहीं भेजेंगे। क्यों ? इसलिए कि आपकी सड़कों में गड्ढे बहुत ज्यादा है और हमारे टायर बिलकुल जल्दी खतम हो जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो महरबानी करें। हम बिना सड़कों के काम चला सकते थे लेकिन बाकी सारा आवागमन बन्द कर दिया। आपकी सड़कों को आप जाकर देखिये। मैं आपको ईनाम दूंगा अगर कोई भी बड़ा अधिकारी वहां पर जाये अगर वह एक दिन भी गंगानगर की सड़कों पर चलेगा तो निश्चित रूप से शाम को उसकी तबीयत खराब हो जायेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहता हूं कि दस साल पहले, 15 साल पहले हनुमानगढ़ अबोहर रोड पर एक पुल बना था। क्या पता ठेकेदार कौन था, सारे के सार पिलर्स तो खड़े कर गया, स्लेब्स नहीं डाले। बिना छत के ही पड़े हैं। 15 साल से पड़े हैं और उसका कोई वारिस नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। कौन ठेकेदार था और क्यों बीच में छोड गया, क्या पेनल्टी इम्पोज की गई ? आज उसकी वजह से एक किसान को 7 किलोमीटर दूर का सफर करके आना पड़ता है। जो भी हनुमानगढ़ आता है, जो भी जयपुर जायेगा उसको 7 किलोमीटर का सफर ज्यादा करना पड़ता है इस पुल के नहीं होने की वजह से।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिर में एक ही सुझाव दूंगा। जो भी आप रोड बनायें वह बिलकुल सीधी होनी चाहिये। इससे जगह की बचत, मैटीरियल की बचत, पैसे की बचत, इनर्जी की बचत होती है, हमारा नेशनल फायदा होता है कन्जम्पशन का, टाइम की बचत होती है। तो जितनी कोशिश कीजिये वह इस बात की कीजिए कि सड़कें सीधी होनी चाहिए। अब तक जो सड़कें निकली हैं वह पालिटिकल प्रेशर से निकली हैं। एक चौधरी ने कह दिया कि नहीं जाने दूंगा, एक सरदार ने कह दिया कि मेरे खेत में से नहीं जाने दूंगा तो नहीं गई। फिर यह मशीनरी किस बात की है ? एक आदमी के आने से सड़क

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

बदल सकती है, एक आदमी की इच्छा से सड़कों पर कर्व डालते हैं तो कितना बुरा करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेहरबानी करके जो भी रोड़ बनायें वह स्ट्रेट रोड़ होनी चाहिए। यह कुछ सवाल उठाये हैं इनकी तरफ माननीय मन्त्री महोदय ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य.

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने गांवों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और गांवों के लोग बड़े उपेक्षित रहे हैं ...

श्री समरथलाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल के एक ही वक्ता बोले हैं और हमारा नम्बर कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल के एक वक्ता बोल चुके हैं। मैंने कहा था कि आप चाहेंगे तो बोल सकेंगे लेकिन बाद में। मैं सुविधा के मुताबिक आपको समय दे दूंगा।

श्री समरथलाल : सारे दलों का समय निर्धारित है और हमारे दल के अभी 7 मिनट ही बोले हैं।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह को पर्ची भी दी है और आपके ध्यान में रहे कि मैं बोलना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मैं बराबर देख रहा हूं कि कांग्रेस (आई) के मुकाबले कांग्रेस को प्रिफरेन्स दिया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब तक जो वक्ता बोल चुके हैं आप उनकी शायद संख्या भी देखेंगे तो मैंने विरोधी पक्ष के सदस्यों को ज्यादा समय दिया है अनुपात के आधार पर।

श्री वृद्धिचन्द जैन : (बाड़मेर) कांग्रेस और कांग्रेस (आई) के मुकाबले कांग्रेस को ज्यादा दिया। जबकि कांग्रेस (आई) की संख्या ज्यादा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : सचेतक महोदय की व्यवस्था ही ऐसी है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गांवों की ओर ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से गांवों की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई और गांव जहां का जहां रह गया है और आज स्थिति ऐसी है कि गांव का विद्यार्थी स्कूल तक नहीं जा सका, गांव का किसान मण्डी तक नहीं जा सका, न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय तक नहीं जा सका और गांव का मरीज दवा लेने के लिए चिकित्सालय तक नहीं जा सका और गांव की स्थिति बड़ी नाजुक है। अभी भी मुझे आश्चर्य है कि आजादी के बाद इस बात का महसूस नहीं है कि गांवों में कुछ विकास हुआ हो। आजादी के पहले जिस स्थिति में गांव थे,

(श्री हीरालाल आर्य)
आज भी उसी स्थिति में हैं सड़क अपने आप में सर्वांगीण विकास छुपाये हुए है।

एक माननीय सदस्य : क्यों झूठ बोलते हो।

श्री हीरालाल आर्य : जनता पार्टी के आने के बाद गांवों में विकास हो रहा है। तो निवेदन करना चाहता हूं कि यदि गांवों का विकास करना है तो मैं चाहूंगा कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना चाहिये। पांच हजार की आबादी का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया है उससे गांवों का समुचित विकास नहीं होगा। यदि विकास गांवों का करना है तो प्रत्येक गांव को तहसील मुख्यालय से जोड़ा जाना आवश्यक है और आज विभिन्न विभागों पर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, कुछ विभाग तो ऐसे हैं कि उन पर खर्च नहीं किया जाकर यदि सड़कों पर खर्च किया जाय तो ठीक होगा। यदि सड़कों का जाल हो गया तो उद्योग धन्धे विकसित होंगे, व्यापार विकसित होगा, शिक्षा का विकास होगा और सभी तरह का सर्वांगीण विकास सम्भव है। इसलिए जो गांव अभी तक उपेक्षित रहे हैं, वहां पर पूर्ण विकास किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरा क्षेत्र चारों ओर नदियों से घिरा हुआ है और नदियों से घिरा होने से बरसात में मेरा क्षेत्र टापू हो जाता है बरसात में मेरे क्षेत्र के लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और गांव वाले सभी लोग असुविधा में बैठे रहते हैं। बरसात के दिनों में मेरे क्षेत्र में जानवरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो मेरा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है उसमें जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां पुलियाओं का निर्माण किया जाना चाहिये। काली सिन्ध पर ढीपरी के पास पुल होना चाहिए। पार्वती पर खातौली के पास पुलिया होनी चाहिये। इन दोनों स्थानों पर पुलियाओं का निर्माण हो जाय तो कोठा खातौली सड़क जिस पर लाखों रुपया खर्च किया है सरकार ने, वह भी काम में आ सकता है और कोटा से ग्वालियर मार्ग को जोड़ा जा सकता है, जिससे एम. पी. तक जाने का रास्ता बन जाता है। मेरे क्षेत्र में ढीपरी के पास चम्बल नदी है जो क्षेत्र को दो भागों में बांटती है और नायब तहसील इन्द्रगढ़ का हिस्सा अलग पड़ जाता है। नायब तहसील के लोगों को पंचायत समिति तथा तहसील केन्द्र जाने के लिए 150-200 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ढीपरी पर चम्बल नदी पर पुलिया का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि तहसील में प्रत्येक आदमी आ सके और पंचायत समिति तक पहुंच हो सके।

दूसरा, मैं सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सड़कों के बारे में मेरा क्षेत्र पिछड़ा है। सीसवाली जो कोटा से सम्बन्धित है, वह तो बन गई लेकिन सीसवाली मांगरोल सड़क जो महत्वपूर्ण सड़क है और तहसील को जोड़ती है तथा वहां के आसपास के गांवों को भी जोड़ती है, यह मिसिंग रूट है, इसको प्राथमिकता पर बनाया जाना चाहिये। दूसरी महत्वपूर्ण सड़क मांगरोल–बालूदा वाया बगोरी कलां व मोरी

(श्री हीरा लाल आर्य)

पी.एच. सी. सेन्टर है। यहां पर लोगों को पहुंचने में काफी असुविधा रहती है, इसे तुरन्त बनाया। जावे दूसरा इटावा, इन्द्रगढ़ रोड़, यह राज्य राज मार्ग का हिस्सा है और इस सड़क के नहीं होने से मेरे क्षेत्र के लोगों को नायब तहसील और पचायत सीमित तक आने में असुविधा होती है। इसलिये राज्य राज मार्ग का जो हिस्सा है इसको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाय। अयाना-खातोली वाया पीपल्दा कलां सड़क है - पीपल्दा पी.एच.सी. तथा तहसील का सैन्टर है इसलिये महत्वपूर्ण स्थान है उसको जोड़ा जाना चाहिये। इस पीपल्दा की बराबर उपेक्षा की गई है। यहां पर तहसील हैड क्वार्टर है, पी एच.सी. सैन्टर है इसलिये भी इस सड़क का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में बहुत छोटे-छोटे गांव है जहां पर मिडिल स्कूल हैं और जिनकी आबादी एक डेढ़ हजार की है उनको भी अप्रोच रोड़ से जोड़ा जाना चाहिये। नोनेरा, नीमोला, रनोदिया, बांगली, बलवन फूसोद, जोरावरपुरा, कबल्दार, लक्ष्मीपुरा बाड़ोली आदि ऐसे गांव हैं जहां सड़कें बनाना अत्यन्त आवश्यक है। ढीपरी-अचानी-अयाना सड़क ये क्षेत्र ट्राइबल एरिया घोषित हैं। गैता-ढीपरी जो चम्बल के गांव हैं और महत्वपूर्ण स्थान हैं, इनको भी जोड़ा जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त करें।

बहुत लम्बी चौड़ी सूची है आपकी।

श्री हीरा लाल आर्य : कोटा-ग्वालियर वाया खातोली-श्योपुर कलां को राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जाना चाहिये। इस सड़क पर बहुत पैसा खर्च किया है इसलिये इसको महत्व और दें इससे उधर ग्वालियर, झांसी और आगरा से भी सम्बन्ध हो सकते हैं। इसलिये इसको अवश्य ही राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। इसी तरह चर्चा होती रही तो समाप्त नहीं होगा।

श्री हीरालाल आर्य : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य मैं बहुत उदार हूं, कृपया आप विराज जाइये।

श्री उमरावसिंह।

श्री उमरावसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला सवाई माधोपुर क्षेत्र का है और मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जिला सवाई माधोपुर को कांग्रेस ने जो 25-30 साल शासन किया, उस शासन में सवाई माधोपुर जिला विकास की दृष्टि से, सड़कों की दृष्टि से और पुलों की दृष्टि से बराबर उपेक्षित रहा है। उसका कारण है कि आज भी बड़े बड़े कस्बे सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं निवेदन करूं, राजस्थान के अन्दर उत्पादन की दृष्टि से और सरकार की रेवेन्यू की दृष्टि से सवाई माधोपुर जिले का दूसरा नम्बर आता है। हमारे क्षेत्र में अनाज इतना पैदा होता है जितना गंगानगर में होता है। दूसरा स्थान राजस्थान में सवाई माधोपुर का है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले

(श्री उमरावसिंह)

में जो नेरल रिसॉसिज हैं वे बहुत अच्छे है, माइन्स के मामले में भी हमारा कस्बा बहुत ही अच्छा है। माइन्स हमारे सवाईमाधोपुर में बहुत ज्यादा हैं जिससे सरकार को करोड़ों रुपयों की रेवेन्यू होती है लेकिन आज भी जो माइन्स के क्षेत्र हैं, वे सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। उससे बहुत सा राष्ट्रीय नुकसान हो रहा है। हमारे हिन्डौन और गंगापुर में करीब 800 ट्रकें हैं जिनको सड़कों के अभाव में काफी टायर ट्यूबों का नुकसान होता है। यदि सरकार खानों तक पहुंचने के लिए सड़कें बना दे तो इतना नुकसान नहीं हो सकता है। जितना रेवेन्यू सवाई माधोपुर देता है उतना हमारे जिले में कोई काम नहीं हुआ है। इन पर कई वर्षों से कोई काम नहीं हुआ जब से हमारी सरकार बनी है, जनता सरकार आई है तब से कुछ कार्य विकास का हुआ है लेकिन होना चाहिये उस हिसाब से नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा करौली से महुआ तक का रूट जो है उसमें ट्रैफिक इतना रहता है, इतने ट्रक चलते हैं कि आए दिन एक्सीडेण्ट होते रहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि यदि इसे नेशनल हाइ वे रूट बना दिया जावे तो जो एक्सीडेण्ट होते हैं वह नहीं होंगे। यह सड़क इतनी खराब है कि जगह-जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, उससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 11 आदमी मरे, जोधपुर साईड के रहने वाले थे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे सवाई-माधोपुर जिले की ओर सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे तो वहां के लोग अच्छे प्रकार से तरक्की कर सकेंगे और गांवों की तरक्की हो सकेगी।

सबसे पहले मेरा यह निवेदन है कि गांवों के विकास के लिए, किसानों की तरक्की के लिए सड़क की अत्यन्त आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में, मेरे महुआ क्षेत्र में मण्डावर एक ऐसी कृषि उपज मण्डी है कि 'ए' क्लास की मण्डी है। उस मण्डावर की ऐसी स्थिति है कि वह सबसे नीचे है और बरसात के टाइम में सारा पानी डम्प हो जाता है, सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे कि वहां का जनजीवन, किसान वर्ग का जनजीवन बहुत खराब रहता है बरसात के टाइम में। यहां तक कि नीचे बैठने के लिए कोई टट्टी जाता है तो बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता है। इसके लिए कई बार माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन किया। हालांकि मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान दिया है, स्कीम बना दी है, मण्डावर से कोट रोड तक की रोड मंजूर है लेकिन आज तक भी उस रोड की शुरुआत नहीं की जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में यदि माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें, सरकार ध्यान दे तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के किसानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे इस क्षेत्र में महुआ जो कि नेशनल हाई वे पर स्थित है उस पर रेस्ट हाउस बना हुआ है लेकिन यदि उसे सर्किट हाउस में कन्वर्ट कर दिया जाय तो जो वहां पर आए दिन

(श्री उमरावसिंह)
विदेशी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वे उसमें आकर ठहर सकते हैं और इससे सरकार को इन्कम भी ज्यादा होगी और इसकी स्थिति भी अच्छी होगी।

अब मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो दस-पन्द्रह साल पूर्व प्लान में ली जा चुकी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन आज तक उन पर कोई काम नहीं हुआ है। यह हिण्डौन से षमान फौलेटा रोड पर 15 साल पहले काम शुरू हुआ था लेकिन आज तक यह रोड अधूरी पड़ी हुई है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस रोड को प्लान में लिया जाकर पूरा किया जावे। इसी रोड पर गंभीरी नदी पर लपावली गांव के पास पुल बना दिया जाय तो आवागमन का साधन ठीक हो सकता है। उधर पालाघाट खुर्या कस्बा है, उस कस्बे में बरसात के दिनों में इतनी हालत खराब हो जाती है कि आवागमन नहीं रहता। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में मंत्री महोदय बनावड़घाटी है उसके ऊपर पांच साल पूर्व कटिंग चालू की गई थी। वह अलवर से चालू हुई थी लेकिन बाद में बन्द हो गई। यह कटिंग दुबारा चालू करवाई जाय लास्ट तक ताकि आवागमन का साधन ठीक हो जाय। मंडावर मण्डी को भी इससे रुपयों की इनकम होगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया चर्चा जल्दी समाप्त करें।

श्री उमरावसिंह : अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि ग्राम काजीपुरा, तिघारिया एक किलोमीटर का टुकड़ा है जिसको सरकार तीन साल से पूरा नहीं कर सकी। यह नीची जगह है और नीची जगह होने से बरसात में आने जाने की दिक्कत रहती है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री उमरावसिंह : एक सुझाव और देकर समाप्त करता हूं। होता यह है कि पी. डब्ल्यू. डी. का बजट है वह मार्च के महीने में रिलीज होता है और उसका कार्य एक महीने में पूरा नहीं होता और जो पैसा होता है, एक महीने के अन्दर उसका मिसयूज होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर पहले रिलीज कर दिया जाये तो ठीक रहे या इसका समय जून तक बढ़ाया जावे ताकि जो धनराशि स्वीकृत की गई है वह अच्छे काम में आए। धन्यवाद, जो आपने समय दिया उसके लिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वृद्धिचन्दजी, शायद आप अपना समय दूसरे माननीय सदस्य को देना उचित समझेंगे, आप पहले भी बोले हैं

श्री रामनारायण ।

श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : मुझे आपने कल भी समय नहीं दिया था, आज भी समय नहीं दिया ।

श्री रामनारायण : उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो पुलों और सड़कों पर कटमोशन दिए हैं उसके बाबत जैसा कि हमारे भूतपूर्व मंत्री जी, खेतसिंहजी ने कहा था कि जोधपुर, के लिए केवल 18 लाख रुपया दिया था और बहुत कम मात्रा में अधूरे निर्माण कार्यों के लिए रुपया दिया है। मैं निर्माण मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आने वाला बजट है उसमें जोधपुर के लिए कुछ धनराशि ज्यादा रखी जावे । क्योंकि यह ऐसा एरिया है कि इसमें काफी लम्बी चौड़ी सड़कें फेमिन में बनी हुई हैं और उस पर जो 75-76 में और 76-77 के फ्लड में जो डेमेज हुई थीं वह अभी तक बराबर पूर्ण रूप से मरम्मत नहीं हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बिलाड़ा क्षेत्र में जोधपुर-जयपुर मार्ग पर जो बिलाड़ा के पास बाणगंगा नदी पड़ती है उसकी पुलिया के हमेशा एस्टीमेट बनते हैं लेकिन अभी तक निर्माण कार्य नहीं किया गया है । हमेशा वह बरसात के दिनों में मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । मैं निर्माण मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस साल जो एस्टीमेट दिया है, इस बजट वर्ष के अन्दर उसका निर्माण कराया जावे ताकि आवागमन के साधन सुगम बन सकें व वर्षा में जोधपुर-जयपुर का मार्ग अवरुद्ध नहीं हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बिलाड़ा मे पाली वाया हरियाणा ऐसा क्षेत्र है जहां पर काफी आवागमन रहता है । इस रोड को कम्पलीट बना दिया जावे तो बरसात के दिनों में जो दिक्कत होती है, टोटली खारा एरिया है वह करीब 20–25 गांव बिलाड़ा पाली के बीच में आते हैं, उसका एक अच्छा रास्ता हो जायगा और पाली एक व्यापारिक केन्द्र है, बिलाड़ा को इसमे कपड़े वगैरह आते हैं, की काफी सुविधा उपलब्ध हो जावेगी ।

इसी तरह से खारिया मीठापुर से रणसिंह गांव वाया भांक है वह भी बरसात के दिनों में 32 गांव बिलाड़ा से कट जाते हैं । इनके बीच में जमवना सागर पानी का केचमेंट एरिया है । पानी भरा रहता है यहां कच्ची सड़क का एक काज वे बना हुआ है, यदि उस काज वे के ऊपर पुलिया बना दें तो जो बीस-पच्चीस गांव हैं, बरसात के दिनों में बिलाड़ा से कट जाते हैं, जुड़ जायेंगे । बिलाड़ा तहसील है, यहां पर मुन्सिफ कोर्ट है, यहां आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है ।

(श्री रामनारायण)

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो आसोपा से डिगरना वाया बारूंदा रोड है, यहां पर काफी फेमिन मेटीरियल पड़ा हुआ है, यह 110 किलोमीटर की सड़क है, 35 किलोमीटर का टोटल फेमिन का मेटीरियल पड़ा हुआ है यह कभी से बर्बाद हो रहा है। इसमें थोड़ा कुटाई का, डामर का काम हो जायेगा तो सुविधा हो सकती है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर छोटी सी रोड है पीपाड़ से बारूंदा। यहां पर सबसे ज्यादा फसल होती है गेहूं और जीरे की। बोरूंदा में पैदा होता है और मण्डी पड़ती है पीपाड और इनके बीच में पीपाड सिटी से बोरूंदा वाया मादलिया 3 किलोमीटर का टुकड़ा जो गठसूरिया के आगे और बोरून्दा के बीच इनकम्पलीट है, लाखों रुपया उस रोड पर लगा हुआ है, चार, पांच साल से पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, तीन किलोमीटर का यह टुकड़ा अगर बना दिया जाये तो सीधा सेन्टर बोरूंदा 25 किलोमीटर पास पड़ता है। यह कम्पलीट करा दिया जाये तो पीपाड़ सिटी बोरून्दा नया मार्ग हो जायेगा।

इसके अलावा एक बाढ़ग्रस्त रोड है पीपाड़ से आसोर वाया खांगरा, जो ठेकेदार के कारण से तीन, चार साल से पड़ी हुई है। नींवें खुदी पड़ी हैं। वह पूर्ण नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, या तो इसमें डिपार्टमेंट की गलती हो सकती है। तीन साल से कम्पलीट नहीं हो रही है। अधूरी है। इससे काफी असुविधा हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय, आदेश दें और जो अन्डर कन्स्ट्रक्शन रोड पड़ी हुई है वह तो कम से कम हाथ में ली जाकर पूर्ण कर दी जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मणिराम।

श्री मणिराम (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उस क्षेत्र में ना तो कोई यातायात के साधन हैं, और ट्रेन तो वहां जाने का सवाल ही नहीं है। करीब 150 गांवों का क्षेत्र है। 12 पंचायतें हमारी राजगढ़ तहसील से मिली हुई हैं और 100 के करीब गांव तारानगर के हैं। इतने लम्बे क्षेत्र में सिर्फ एक सड़क है, तारानगर से सावा तक, जो भूतपूर्व सरकार के कार्यकाल में बनी थी। इसके अलावा और कोई सड़क नहीं है, इसलिये मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें और 12 पचायतें जो राजगढ़ तहसील को मिली हैं उनमें भी कोई सड़क नहीं है। महज एक राष्ट्रीय मार्ग जो राजगढ़ तहसील से होकर तारानगर के दक्षिण की ओर से निकलता है और वह सरदार शहर, डूंगरगढ़, बीकानेर तक और आगे पाकिस्तान की सीमा तक जाता है। यह मेहरबानी पाकिस्तान की हुई और उन्होंने झगड़ा किया इस वजह से भारत सरकार को बनाना पड़ा। इसके अलावा कोई सड़क नहीं है।

(श्री मणिराम)

इसलिये मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि एक तो तारानगर से चूरू जाने के लिये, तारानगर से करीब 4-5 कोस तक सड़क पक्की बनी हुई है, चूरू की तरफ को जाती है, चलकोई-भरूसन-सनूसर चूरू को मिलाती है, यह शार्ट रास्ता है। तारानगर के लोगों को चूरू जिले में जाने के लिये बहुत आवश्यकता है इस सड़क की। इधर तारानगर से चगोई मील्याला पन्डरेउताल बांय देवगढ़ जीगासरी बड़ी जीगासरी छोटी होती हुई रामसरा डूंगराना पक्की सड़क आ जाती है, इसको मिला दी जाती है तो इधर से गंगानगर जिले में आने जाने के लिये और चूरू जिले में जाने आने के लिए यह रास्ता बहुत ही सुविधाजनक है। इसलिए मन्त्री महोदय से मैं उम्मीद करता हूं कि वे ध्यान देंगे। इधर से हमारे सावा सडक के ऊपर बहुत सा सामान पड़ा हुआ है। मेटीरियल पड़ा हुआ है। इसको गांव वाले अपने काम में लेते हैं। इधर से डूंगराना वाली सड़क का काम चालू कर दें तो यह सारा सामान जो पड़ा हुआ है वह काम में आ सकता है। मैं पुनः निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि वे इस पिछड़े हुये इलाके की ओर ध्यान देकर इसको ऊंचा उठाने में मदद करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि अब की बार अतिवृष्टि के कारण भारी तादाद में इस क्षेत्र में किसानों के मकान गिरे हैं और हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने भी उनको देखा है। इस क्षेत्र की क्या परिस्थिति रही, क्या हाल हुआ, तो मैं यह मांग करूंगा कि वहां के काश्तकारों को बैंक से ऋण दिलाया जाए ताकि वे विध्वंस हुए अपने मकानों को या गांव को दुबारा फिर से बनाने की कोशिश करें, वे पुनर्जीवित हो सकें। मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट। इधर से यह जो 12 पंचायतें हैं इनमें भी कोई सड़क नहीं है। यह सारा का सारा एरिया बिल्कुल सड़क के अभाव में कहीं से, किधर से भी जुड़ा हुआ नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 12 पंचायतें राजगढ़ की हैं, उनमें सिर्फ एक राष्ट्रीय मार्ग निकलता है, तारानगर की 21 पंचायतों में भी एक ही राष्ट्रीय मार्ग है, इसके अलावा कोई सड़क नहीं है।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, फेमिन के वक्त, चूरू की तरफ और इधर भादरा की तरफ, चौगान होते हुए, इन सड़कों पर पांच सात दफा फेमिन का काम चला है लेकिन वे वैसी की वैसी पड़ी है। अभी तक इन पर कोई बस चलाने का रास्ता नहीं बना है। इस ओर आप ध्यान दें ताकि यह रास्ता खुल जाए और हमारा चूरू जाने के लिए, गंगानगर जाने के लिए सीधा सम्बन्ध हो सकें। ये दो रास्ते आप बना दें तो चूरू और गंगानगर के लिए सीधा रास्ता खुल जाएगा। दो जिलों में आवागमन इससे हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निर्मल कुमार।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरा-पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। जिस एरिया का भी यह विकास करना चाहे, उन्नति करना चाहे, बहुत आसानी से उस एरिया की काया पलट यह कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं झालावाड़ जिले से आया हूं और राजस्थान में जो डामर की सड़कें हैं उनमें से केवल 421 किलोमीटर डामर की सड़क है, जो राजस्थान में सब से कम है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि झालावाड़ जिले की तरफ भी विशेष ध्यान देकर किस प्रकार से वहां की सड़कों का सुधार हो सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे तो मेहरबानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। पूरे जिले की 8/10 सड़कें मध्य प्रदेश को जोड़ती हैं। आपको केन्द्रीय सरकार फण्ड देती है इन्टर स्टेट को जोड़ने के लिए। उस मद से रुपया लेकर इनको जोड़ा जाए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सड़कें जुड़ जाएंगी और दूर होकर जो यात्रियों को जाना पड़ता है, उसमें समय और पैसे की बचत होगी।

अनाज के बदले काम योजना के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ है। मिट्टी डाल दी गई है, गिट्टी डाल दी गई है। अब हमारी पंचायतों के पास न तो रोड रोलर हैं और न उनके पास डामर बिछाने के लिए पैसा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुख्य मन्त्री महोदय यहां बिराजे हुए हैं। यदि पचायतों को रोड रोलर दे दिये जाएं, या काम पैसे में दे दिया जाए तो पंचायतें जो सड़क का निर्माण कर रही हैं वह निर्माण पूरा हो जाएगा और वह बिगड़ने से बच जाएगा। यदि डामर की व्यवस्था कर सकें तो और भी अच्छा होगा। इसके लिए केन्द्र से डामर बिछाने के लिए अनाज ला सकें तो देहातों की जो सड़कें हैं उनको हम शीघ्रता से जोड़ सकेंगे। हम देहातों के लिए इतना काम कर कर रहे हैं, परन्तु वहां पर सड़कों के लिए बहुत ही कम बजट रखा गया है। ऐसा करने से इसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर-भोपाल और जयपुर-इन्दौर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिये पिछली बार भी कहा था मन्त्री महोदय ने, परन्तु अभी तक कुछ भी इस बारे में कार्यवाही नहीं हुई है। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो जाय तो कोटा डिवीजन, टोंक और आगे भोपाल, इन्दौर और बम्बई तक यह सड़क मिलाती है, इस पर काम होना चाहिये।

एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग भवनों की देखभाल तो करता है परन्तु तहसील स्तर पर और पंचायत समिति स्तर पर भवनों की ठीक से देखभाल नहीं

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)

होती है। वहां के भवनों की हालत बहुत ही खराब हो रही है, इनकी देखभाल की जावे ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत ही ठीक रहेगा। एक बजट पास होने पर कई महीनों बाद टेण्डर होते हैं, समय लग जाता है और काम अधूरे रह जाते हैं सो इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि मार्च में बजट पास होते ही 1-2 माह में बजट अलॉट हो जाय। एक महीने में टेण्डर होकर काम शुरू हो जाय तो जो विलम्ब होने पर भागमभाग करके बजट खर्च करने की कार्यवाहियां होती हैं, फर्जी हिसाब दिया जाता है लोहे में, सीमेंट में, डामर में, एन टाइम पर भाग दौड़ करते हैं इसकी ठीक व्यवस्था होनी चाहिये। इससे बजट का सदुपयोग होगा वास्तविक रूप से काम हो सकेगा। मैं झालावाड़ जिले के झालरापाटन क्षेत्र से आया हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दो साल में मुश्किल से 2-3 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क बनी हैं जो बहुत कम है। अब जो बाड़ोदिया अप्रोच की मंजूरी दी है परन्तु वहां पर अभी काम आरम्भ नहीं हुआ है। पाटन से सुनेल मार्ग झालावाड़ से बागोर रोड, मोतीपुरा से मंडावर, मकानी से गागरून रोड पर खनिज विभाग को भी ध्यान देना चाहिये। ये रोड्स खनिज विभाग के बहुत काम आ सकती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारा खनिज निकलता है। खनन मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से बातचीत करनी चाहिये। झालावाड़ जिले को खनिज विभाग ने एक भी पैसा नहीं दिया है। सुनेल में जैन समाज का बहुत बड़ा मेला लगता है। सारे हिन्दुस्तान के जैन आते हैं, इसके महत्व को देखते हुए मंत्री महोदय इसको लेने का प्रयास करेंगे तो मैं धन्यवाद दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कहीं दूध के नाम पर कहीं अकाल के नाम पर रोड बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है। झालावाड़ जिला बहुत सारी अफीम और सन्तरे पैदा करता है। यदि इसी बात पर केन्द्र सरकार से पैसा ले सकें तो विकास की गति तेज हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक आहू नदी पर पुलिया बनाने की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक उसे कार्य रूप में परिणित नहीं किया गया है। आहू नदी पर जो पुल बनना है वह जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारे जिले में बरसात के समय में जो जिला दो भागों में बट जाता है, एस. डी. ओ. मुख्यालय का जिला मुख्यालय से 8-8 दिनों तक सम्बन्ध टूट जाता है, वह नहीं रुक सकता यह हमारे लिये विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, डामर के ड्रमों से हमारे जिले में तगारी, खरस, बाल्टियां बनाते हैं। अगर परमिट के आधार पर जो 5-10 ड्रम देते हैं तो उनको अगर टेण्डर से ज्यादा पैसा आता हो तो देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि इससे यहां के गरीब मुसलमानों की रोजी रोटी चलती है। उन्हें 100-50 ड्रम दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका समय लिया इसके लिये आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सड़कों की हालत पड़ोसी राज्य से कहीं ज्यादा खराब है और राजस्थान की आबादी जो गांवों में रहती है और गांवों के इलाके सारी जीवनोपयोगी चीजें पैदा करते हैं कपास, अनाज वगैरह,

(श्री नूरा)

जिनको वे बाजार में लाकर बेचते हैं तो गांवों में कहीं कहीं तो यह हालत है कि बरसात के दिनों में नाले पानी में भर जाते हैं। गांव रुक जाते हैं जिनसे उनकी खेती का कार्य ही रुक जाता है। उनके पास न अपने गांवों में सामान रखने के गोदाम की व्यवस्था है कि जिनमें अनाज वगैरह को सुरक्षित रख सकें और जो वे सामान बाजार में बेचने निकलते हैं तो अपनी हैसियत के माफिक बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी जो बनवाते हैं उसकी चलने की उम्र जहां 10 साल होती है वह खराब सड़कों के कारण 5 साल हो जाती है। और वैसे तो राजस्थान के भाग्य में अकाल लिखा हुआ है और उसकी वजह से सरकार राहत कार्य खुलवाती है और राहत कार्यों में जो सड़कें बनती हैं उन पर जब अकाल पड़ता है तो मिट्टी पड़ती है और अकाल चला जाता है तो उनकी व्यवस्था निर्माण विभाग नहीं करता। वह निजी रोड्स को तो देखता है लेकिन अकाल राहत कार्य की सड़कों के साथ विभाग बिल्कुल शिथिल व्यवहार करता है। उन सड़कों को दुबारा अकाल पड़ने पर अकाल सहायता विभाग ही देखता है। तो इससे पैसा बरबाद होता है। लाखों रुपयों का जो धन उन पर लगता है वह बह कर चला जाता है। इसलिए जो रोड बनाई जाय अकाल राहत कार्यों में, उनकी भी विभाग निजी रोड्स की तरह ही देखभाल करे तो जो फेमिन रोड्स गांवों को जाती हैं उन पर भी धन लगाया जाय तो इन गांवों में आने जाने का साधन आसानी से हल हो सकता है, लेकिन ऐसा तरीका हो गया है जैसे किसी भी विभाग के कर्मचारी जब तक आन्दोलन नहीं करते तब तक सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती, उसी प्रकार किसानों को भी अपने गांवों में पुलिया, सड़क बनवानी हो तो उसके लिए बार बार आवाज उठानी पड़ती है, आन्दोलन होते हैं तब जाकर पुलिया का काम पूरा होता है। बिना आन्दोलन के कहीं कहीं प्रभावशील लोग भले ही कुछ करा लें, नहीं तो यह हाल है कि वहां काम पूरा नहीं होता, बड़ी परेशानी में लोग रहते हैं। जहां सड़कें हैं वहां पुलिया नहीं हैं। जैसे ब्यावर में मिल एरिया की तरफ सड़क पर से रेलवे लाइन निकलती है वहां जब जब रेलवे फाटक बन्द होता है लोगों की भीड़ लग जाती है विलम्ब होने से मिल में जाने वालों की एबसेंट तक लग जाती है। कई बार यूनियन्स द्वारा केन्द्र सरकार को लिखा गया कि रेलवे लाइन केन्द्र सरकार की है तो जवाब मिलता है कि पुलिया बनाने का काम राज्य सरकार ही करेगी, वहां की नगरपालिका ने भी स्टेट को लिखा लेकिन कोई काम नहीं हुआ और न कोई हलचल पैदा हुई। आज भी रेलवे का फाटक बन्द होता है तो लोग कारखानों में जाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिया बननी बहुत जरूरी है।

जहां-जहां पर पुलियों का काम होना बाकी है वहां पर पुलियों का काम तत्काल किया जाना चाहिए।

साथ ही श्योपत भाई ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा खतम करनी चाहिए। वाकई यह बात सही है कि जो कुछ भी एस्टीमेट बनता है उस एस्टीमेट से ठेकेदार कम खर्च करके, उस काम को कमजोर करके उसमें

(श्री नूरा)

मे बचा कर अपना घर बनाता है और उस पैसे को किस किस जगह भेजता है उस पर मेरे कई साथी अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। जिस काम की उम्र 10 साल की होनी चाहिए वह पांच साल में ही खतम हो जाता है। कहीं कहीं तो यह हालत होती है कि काम करते करते आगे बढ़े कि पीछे से काम खतम हो जायेगा। मैं आपको बतलाऊं कि जो रोड सराधना के नीचे से गांव के पश्चिम की ओर गई है वह रोड तो बन गई है डिपार्टमेंट की तरफ से, मगर वह सड़क उड़ गई है। मेरे इलाके में एक कानिया गांव है, उस गांव और भीलवाड़ा जिले के बीच में खारी नदी पड़ती है। उस गांव से लोग जाडियाण जाते हैं और इधर उधर जाते हैं तो काश्तकार लोग नदी के बीच में कचरा जमाकर फिर गाड़ियां पास करते हैं। लेकिन जब नदी में पानी आ जाता है तो गांव वाले लोगों को घन्टों तक नदी उतरने के लिए बैठा रहना पड़ता है। वह नदी उतरती है तब आते जाते हैं। लेकिन पानी आने के बाद रेत जमा हो जाती है। मैंने इसके बारे में पुलिया बनाने के बारे में विभाग को लिखा है लेकिन उसके मामले में कुछ नहीं हुआ। मैंने अजमेर जिले के चीफ इन्जीनियर से भी कहा तो उन्होंने कहा कि इसको गुलाबपुरा से मिलायेंगे। उससे उन लोगों को 10 मील का चक्कर करना पड़ेगा और इधर केवल दो मील का ही चक्कर करना पड़ेगा।

मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया है कि कई सारी समस्यायें हमारी बनी हुई हैं, लेकिन राजस्थान में सड़कों की समस्या अजीब ढंग से बनी हुई है। पड़ोस के राज्यों से लोग राजस्थान में आते हैं तो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि राजस्थान में सोया हुआ आदमी भी जग पड़ता है। उसको जगाने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप जग जायगा। इसलिये थोड़ा ध्यान सरकार उन रोड्स के बारे में दे जो पहले से बनी हुई हैं उनकी कम से कम मरम्मत की जाय। नई रोड्स तो राजस्थान में बनाने के लिए जब तब कोई आन्दोलन न हो, मांग न करेंगे तब तक डिपार्टमेंट के लोग अपने आप उन सड़कों को देखते तक नहीं हैं। बीच बीच में से वह कटी हुई हैं इस कारण से रोड को छोड़ कर गाड़ियां चलाते हैं और मोटर, ट्रक आदि भी गाड़ियों के रास्ते से निकलते हैं।

मैं एक-एक रास्ता गिनाकर हाउस का समय खराब नहीं करना चाहता हूं लेकिन इन सारी रोड्स की हालत इतनी खराब है। अजमेर और मसूदा की सड़क राजमार्ग से जुड़ी हुई है। जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी देखभाल होनी चाहिए। ठेकेदारी प्रथा खतम होकर डिपार्टमेंट की तरफ से काम होना चाहिये ताकि पैसा सरकार का बचेगा और काम भी ठीक होगा। इन समस्याओं को हल किया जाना चाहिए।

इतनी बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने गत बजट में भी यह

(श्री बालकृष्ण थानवी)

सुझाव दिया था कि लोक-निर्माण विभाग के जितने भी कार्य हों, जितनी भी सड़कों के काम हों या भवन-निर्माण के हों, वे ठेके पर न होकर विभाग खुद कराए। चाहे उसके लिए निगम बनाना पड़े या बोर्ड बनाना पड़े तो उसकी भी व्यवस्था की जाए, ताकि जो बीच में भ्रष्टाचार होता है और उसके कारण मुख्य काम कमजोर होता है वह न हो मैं उसी सुझाव को फिर दोहराता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय विचार करेंगे।

मैं 'दूसरी बात' यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भेदभाव आज बरता जाता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में वह नहीं किया जाना चाहिए। जहां बड़े शहरों में सारे सार्वजनिक निर्माण के काम सरकार खुद अपने व्यय से कराती है वहां ग्रामीण क्षेत्रों में उसका आर्थिक भार ग्रामीणों पर डाला जाता है या पचायतों पर बोझ डाला जाता है कि अमुक काम पंचायत क्षेत्र एव ग्रामीण क्षत्र में होगा, ग्रामीण अथवा ग्राम पचायतें करवा देंगी। तो मेरा निवेदन यह है कि इस भेद-भाव को दूर करके सरकारी खर्च से करवाये जाने वाले कार्यों में ग्रामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और ग्रामों में समस्त निर्माण के कार्य सरकार द्वारा किये जाने चाहिये।

जहां तक सड़कों एवं पुलियों का सवाल है रेगिस्तानी क्षेत्र में यह बहुत ही कम है। जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय किशनसिंह जी भाटी ने कहा कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर का जो क्षेत्र है उसमें सड़कें बहुत ही कम हैं, और सड़के जो हैं भी वे भी टूटी-फूटी हैं। उन सड़कों पर भारी फौजी वाहन चलते हैं जिसके कारण से जगह-जगह से सड़कें टूट चुकी हैं। इस-लिए इन सड़कों की मरम्मत की विशेष तौर से जरूरत है। इस वास्ते इन सड़कों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।

हमारी फलौदी तहसील का जो नमक उत्पादन क्षेत्र है और जिसकी सड़कें भारत सरकार के लवण विभाग से आर्थिक सह-योग लेकर बनाई गई हैं वह इतनी कमजोर हैं कि उनमें घसान हो गई है। चूंकि इन सड़कों पर रोजाना सैंकड़ों ट्रक नमक से लदकर गुजरते हैं इसलिये दुर्घटनाएं होने की घटनाये सामने आती रहती हैं। इस वास्ते इन सड़कों की मरम्मत करवाई जाय, और नमक वाले क्षेत्र में जितने प्लाट्स हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया जाय।

जहां तक नई सड़कों का सवाल है, मेरी यह स्पष्ट राय है कि अकाल के समय में जो भी नाम मात्र की सडकें बनाई गयीं सड़कों को पहले डामर-युक्त बनाया जाय। ये तथाकथित सड़कें ग्रामीणों के काम नहीं आतीं। कारण कि वहां सड़क नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। वहां पर न कोई ककरी दिखाई देती है और न डामर ही है। बीच-बीच में लम्बी दूरी तक वैसी ही धूल पड़ी है अगर वही सड़कें हैं। तो उन सड़कों की तुरन्त मरम्मत करवाई जाय। ताकि सही मायने में ये सड़कें बन सकें।

(श्री बालकृष्ण थानवी)

फलौदी से जोधपुर तक की सड़क में मथानिया कस्बे की रपट आती है। कई वर्ष हो गये इस मथानिया की रपट को खराब हुए लेकिन वह ठीक नहीं करवाई जा रही है। जब कि इस पर कुछ सौ रुपये ही खर्च करने की बात है। उसको ठीक करवाने से रोड़वेज की बसों को निजी वाहनों और ट्रैक्टरों को लाभ होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे। फलौदी से जोधपुर वाया ओसियां, फलौदी से जोधपुर वाया देच्छू एवं फलौदी से नागौर की सड़कें जहां तहां से टूटी हुई हैं। इसलिए इन सड़कों का मजबूत कार्य करवाया जाय। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि पहले अकालग्रस्त क्षेत्रों में जो सड़कें बनाई गई थीं उन पर डामर डलवा कर उन्हें पूर्ण करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

श्री नाथूलाल (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह सड़कों का विषय आज है। यह सड़कें हमारे प्रदेश को देश के दूसरे प्रदेशों से और एक जिले को दूसरे जिले से और एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाला विषय है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आज जो सड़कों की मांग है इस पर मैं, थोड़ा जो है, आपके माध्यम से सुझाव भी देना चाहूंगा।

सड़कें चाहे पी. डबल्यू डी. की हों, चाहे फेमिन में बनी हुई हों या काम के बदले अनाज में बनी हुई हों, उन सब सड़कों को सरकार को अपने हाथ में लेकर उन पर डामर का और पक्का काम कराया जाय ताकि जितना पैसा उन सड़कों पर खर्च हुआ है वह पैसा काम में आ सके।

दूसरा, मेरा यह सुझाव है कि जहां पर सड़कें बनें लेकिन बीच-बीच में जो छोटे-बड़े नाले आते हैं तो उनके कारण से आने-जाने के साधन रुक जाते हैं। इसलिए उन नालों के ऊपर पुलियायें बनाकर उन मार्गों को आने-जाने के लिए हमेशा का रास्ता तैयार किया जाय। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन नालों के ऊपर पुलियायें बनाने का काम पहले किया जाय। ताकि जो मार्ग है वह हमेशा के लिए बहते रहें और यातायात के साधन प्राप्त हो सकें।

इसके साथ-साथ माननीय सभी सदस्यों ने सड़कों के बारे में सैंकड़ों विचार रखे और डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार होने के भी आरोप लगाये।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट को कई जगह कई तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों के कारण यह होता है। इसलिए मैं निर्माण मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा क्षेत्र में जो काम हैं, उनके लिए आपकी तरफ से दया होनी चाहिए ताकि आपकी तरफ से काम हो सकता है। साथ ही मैं अपने क्षेत्र घाटोल के बारे में निर्माण मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में सड़कों के अभाव के कारण से एक गांव से दूसरे गांव को जाने

(श्री नाथूलाल)

में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा।

(व्यवस्था-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आपस में चर्चा नहीं करे। रिपोर्टर्स को नोट करने में बाधा पड़ती है।

श्री नाथूलाल : इसी तरह से फेमिन में कार्य हुए हैं। कुछ सड़कें अधूरी पड़ी हैं। वह खराब होने के कारण ठीक नहीं कराई जाती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान् जी, दो मिनट में समाप्त करता हूं।

डूंगला से घाटोल वाया समेरा की सड़कें हैं। मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य कराएं। इससे आने जाने में लोगों को सुविधा हो सकती है। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ अन्त में यही अर्ज करूंगा कि बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी जिला है। उस जिले में अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो गई है। असिंचित होने के कारण फसल नहीं हो पायी है। इसलिए आज वहां लोग भूखों मर रहे हैं। तो मैं निर्माण मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि बांसवाड़ा जिले को प्रभावग्रस्त और अकालग्रस्त घोषित करें ताकि उनको मजदूरी मिल सके। इसी तरह से, मेरा निवेदन है कि सड़कों में घाटोल से वाया खैरवाड़ा, खैरवाड़ा वाया जगपुरा, जगपुरा-कूकड़ा जो सड़कें हैं, उनका भी ध्यान किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने उत्तर में कितना समय लेंगे ताकि उसके अनुसार ही चला जाये।

श्री जयनारायण पूनिया : करीब आधा घण्टा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल बरबड़।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने सड़कों पर बहुत ज्यादा कहा है। सड़कों के होने से एक गांव से दूसरे गांव को आने जाने में सुविधा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान नागौर जिले के परबतसर की ओर दिलाऊंगा। परबतसर से पुष्कर एक सड़क है जो कि आज से 25 साल पहले बनी थी। उसी पर सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं, उसी पर ट्रक चलते हैं। पुष्कर एक धार्मिक स्थान होने के कारण वहां पर निरन्तर लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुष्कर में एक पशु मेला भी भरता है। मेला होने के कारण सैकड़ों और हजारों लोग आते जाते हैं। परवतसर में भी एक सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यह सड़क 25 साल पहले बनी थी। लेकिन यह डामर की नहीं बनी थी। क्योंकि उसके बीच में अजमेर जिला भी पड़ता है। कभी यह हुआ कि नागौर जिला वाले बनायेंगे और कभी यह हुआ कि अजमेर जिला वाले बनायेंगे। इस कारण वह

(श्री जेठमल बरवड)

अब तक वैसी ही पड़ी हुई है। डेगाना में भी बसें चलती हैं। वह रोड भी 8 मील पहुंच गई है। स्टेट हाई वे है। इसलिये मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस रोड को डामर की रोड बनाये। उनियारा का घाटा-डेगाना, एक एक घण्टे में बसें जाती हैं। यह रोड फेमिन में बनी थी। फेमिन में जो रोड बन जाती है, पी.डब्ल्यू.डी. उसे अपने हाथ में लेता नहीं है। इसलिये उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। परबतसर में इण्डस्ट्रियल एरिया बनाया गया है। उसमें भी पक्की सड़क बनाई जाये। मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, मकराना माइन्स रोड़ इतनी खराब हो गई है कि एक्सीडेन्ट्स का खतरा रहता है। इसके अलावा मकराना से किशनगढ़ रोड़ आती है। उसकी हर साल रिपेयर होती है लेकिन खराब हो जाती है। आप जानते हैं कि मकराना से 300-400 मन का वजन लेकर ट्रक चलते हैं। उसका टर्न ओवर पत्थर का इतना बड़ा रहता है। इसलिए उस रोड़ को चौड़ा बनाया जाये ताकि ट्रकों के लिए कोई असुविधा नहीं हो। इसके अलावा परबतसर में ऐसे गांव हैं, एक गांव है बड़ू, उसकी पांच हजार से ज्यादा की आबादी है उसको सडक से जोड़ना चाहिये। इसके अलावा मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में ऐसे गांव हैं जहां मंडी है। पहले सरकार ने भाखरा पट्टी की योजना बनाई थी, मण्डी को जोडने के लिए कि इसको डेगाना के पास एक गांव है, उस पट्टी को वहां से जोड़ दिया जाये तो मंडी में जो लोग आते जाते हैं उन लोगों को उससे सुविधा होगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मकराना में मार्बल का बड़ा उद्योग है। लेकिन वहां पर डाक बंगला नहीं है। ब्रिटिश टाइम में एक डाक बंगला माइनिंग डिपार्टमेंट ने बनाया था। उसमें आधे में डाक बंगला है, आधे में दफ्तर है। दो तीन मकान हैं। बाहर के अनेक लोग वहां पर आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन वहां पर उनको ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं है। मार्बल खानों के देखने के लिए दिल्ली से और विदेशों से भी लोग आते हैं। लेकिन उनके ठहरने के लिए वहां पर कोई अच्छा डाक बंगला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक डाक बंगला बनाया जाये। क्योंकि मार्बल का एक इण्डस्ट्रियल एरिया बनाकर बहुत बड़ा उद्योग लगाया जा रहा है। उद्योग को देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं इसलिए मकराणा में एक डाक बंगले के निर्माण किया जाना चाहिये। इसके अलावा नावां तहसील में एक रपट है, वहां पर मेटीरियल पड़ा हुआ है, जयपुर से आने के लिए वह एक ही सड़क है जिसका सीधा रास्ता है....

समय-समाप्ति-सूचक घण्टी

इसको भी बनावें, फेमिन की रोड्स भी तैयार की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नरपतराम।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष).

माननीय श्री रघुनन्दन व्यास ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस इलाके से मैं आ रहा हूं, उस सड़क पर दो हजार एक्सीडेन्ट इस वर्ष हुये हैं। जब मैं पहले यहां खड़ा हुआ था और आज भी वही बात कहना चाहता हूं, बारां से आबूरोड, जिसमें शिवगंज से लगाकर आबूरोड तक एक हजार एक्सीडेन्ट ट्रकों के, टकियों के, बसों के और जीपों से हुये है। इसका एकमेव कारण यह है कि सड़क बहुत खराब है। इसके लिये मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था और इस साल भी निवेदन कर रहा हूं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया बीकानेर से काण्डला का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया दिल्ली से अहमदाबाद तक जिस पर चार हजार ट्रक चलते हैं, कम से कम उसको व्यावहारिक तो बना दो। आबू रोड से निकलकर एक नदी आती है, वहां पर तीन सौ एक्सीडेन्ट हुये, तीन वहां पर रपटें हैं, उन रपटों को ठीक करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पी.डब्ल्यू.डी. उसका पैसा दे। लोक कर्म विभाग के पास सड़क और पुलियों का दोनों का अलग अलग पैसा है, 36 करोड़ सड़कों का, और 31 करोड़ पुलियों के लिये। उससे लोक कर्म विभाग में कई काम होते हैं, लेकिन सिरोही जिले के लिये भयंकर अन्याय हुआ है, वहां पर कलेक्टरेट के लिये बिल्डिंग नहीं है, आफिस नहीं है, दरबार का बंगला मोल लिया है, वहां पर यह हालत है कि मूत्रालय में भी आफिसर बैठते हैं। इस प्रकार की दुर्गति सिरोही में है, जिसके लिये कभी चिन्तन नहीं किया गया, कलेक्टरेट की यह हालत है। बरसात में बैठते हैं तो पानी पड़ता है। यह इसलिये दुर्गति है कि सिरोही में राजा का राज था। चांदी के बर्तन चले गये, फर्नीचर चला गया वहां पर एवरेज टूरिस्ट की सख्या प्रतिदिन 40-50 है, गुजरात मार्ग से और महाराष्ट्र मार्ग से आते हैं लेकिन वहां पर रहने के लिये जगह नहीं है। इसलिये वहां पर एक सर्किट हाउस बनाया जाय। स्टाफ के लिये मकान नहीं है, एक वर्ष में एक पर्सेन्ट ही मकान बने हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पी. डब्ल्यू. डी. ने 100 क्वार्टर बनाये। आफिसरों के लिये और पब्लिक के लिये वहां पर जगह नहीं है, यह दुर्गति है। आबू पर्वत, टूरिस्ट का नाम और सड़कों की दुर्गति। सिरोही आबू मार्ग दस साल से चल रहा है। इस लाल पुस्तक में लिखा है कि आबू में सर्किट हाउस बनेगा लेकिन उसमें विधायक नहीं ठहर सकते, फिर कौन ठहरेगा, यह कितनी घिनौनी बात है, यह लिखकर अपमानित करना है। मैं निवेदन करूंगा कि इस भाषा में सुधार किया जावे। दिल्ली में भी सर्किट हाउस है वहां अफसरों को जगह मिलती है, विधायकों को नहीं, यह भयंकर स्थिति है। सिरोही एक ऐसा इलाका है जहां डेजर्ट भी हैं, पहाड़ भी हैं और रेगिस्तानी इलाका भी है। वहां पर कल्वर्ट, पुलिया और रपट हर जगह नहीं है। फेमिन में कुछ काम हुआ है लेकिन सड़कों की रिपेयर दो साल के बाद भी नहीं हुई है। इस बार थोड़ा काम हुआ है, पिछली बार तो भण्डारी जी एक्स. ईएन. थे, बिलकुल काम नहीं हुआ। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहां नई व्यवस्था हो गई है कि सचेतक महोदय चाहेंगे तो वही बोलेंगे,

(श्री रघुनन्दन व्यास)

हम अपने जिले की बात यहां नहीं कह सकते। हमारे पेट का दर्द नहीं बता सकते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले की भयंकर स्थिति है। पहले स्टेट थी। वहां पर पब्लिक पार्क होना चाहिये। पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं कि जमीन वहां पर पड़ी है, हम चाहते हैं कि वहां पर एक फलों का उद्यान लगाया जाय, पी. डब्ल्यू. डी. लगावे या म्युनिसिपल कौंसिल लगावे। वहां पर कालेज और हायर सैकण्डरी स्कूल की बिल्डिंग है, लड़कियों का स्कूल ऐसी जगह है जहां पर घोड़े बंधते थे, बग्घीखाने में हायर सैकण्डरी स्कूल चलता है। पैसा देने को कोई तैयार नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सिरोही में प्राइमरी स्कूल तीस सालों से नहीं खोला गया है, यह सड़कों की दृष्टि से हमेशा उपेक्षित रहा है। पांच हजार की आबादी की बात सरकार ने कही है। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, पांच हजार में 113 की जनसंख्या कम है, वहां पर 113 की जनसंख्या नहीं बढ़ी, राज्य सरकार को यह नहीं कहना चाहिए था और अगर कहा तो उसका मखौल नहीं उड़ाना चाहिए था, with a plan, with a motive राज्य सरकार को काम करना चाहिए, लालाडास, हरजी, उम्मेदपुर सड़क पूरी नहीं हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं हैं, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन यह नई व्यवस्था की गई है तो कहने का पूरा अवसर देना चाहिए अन्यथा समय नहीं होगा तो हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। उदयपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जालौर मार्ग, उदयपुर-सिरोही, भीनमाल, बाड़मेर सड़क बनाई जावे वाया भाग। इसको टच भी नहीं किया गया है और भीनमाल की सड़क की हालत तो बहुत ही खराब है। चार मील सड़क काटनी पड़ती है। फेमिन वालों का पैसा, प्लान का पैसा वहां खर्च किया जाना चाहिए। अब छठा पंचवर्षीय योजना चल रही है। मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सिरोही जिला पूरा अकाल से ग्रस्त है, और कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। कम से कम माननीय मन्त्री महोदय एक अप्रेल से वहां काम शुरू करवा दें तो कितने ही मजदूरों को काम मिलेगा और 10 हजार लोगों को वहां पर रोजी मिल सकेगी। जैसलमेर के लिए भी निवेदन करूं, भाटी जी कह रहे है लेकिन मैं तो अपने घर को रो रहा हूं। कम से कम फेमिन में सड़कों का काम किया जाय, आबू राजस्थान की नाक है इसको निग्लेक्ट करके सारे राजस्थान को बदनाम नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवराज सिंह

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जीतमल जैन

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय श्री गुरुशरण छाबड़ा

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया

(अनुपस्थित)

माननीय श्री चिरंजीलाल

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन का अपमान है, नाम पुकारते हैं और लोग यहां मिलते नहीं हैं।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग का जो प्रतिवेदन मिला है, उसमें कुछ नये कामों को करने के लिए और पिछले पुराने कामों को संरक्षण देने की बात कही गई है। कुछ पुरानी सड़कें तो नेस्तनाबूद हो गई है उनको फिर से ठीक करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा इसलिए इनको पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे कि व्यर्थ ही पैसा खर्च नहीं हो। हटूण्डी से राजगढ़, हटूण्डी से तबीजी डामर की सड़क बनी हुई हैं, उनकी हालत जाकर देखें कि वे नष्ट प्रायः हो रही हैं। इसी प्रकार ब्यावर से जालिया, कोटड़ा होती हुई जवाजा तक की सड़क खराब हो रही है। भीम-टाटगढ़ की 4 मील की सड़क बनी है, बाकी की 4 मील सड़क और बनना अनिवार्य है। कच्ची सड़कों को पक्की कराई जाए और कार्य शुरू होने चाहिए। जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं वे हैं, बड़ाखेड़ा से बेडारी भीम।

इसके अलावा अनेक पुलियाएं हमारे क्षेत्र में खराब स्थिति में है। पुष्कर से गोविंदगढ़ के बीच 2 पुलियाएं हैं। रास्ते में सरस्वती नदी है, लगातार 365 दिन पानी बहता है, गाड़ियां फंस जाती है। एक दिन रात के समय मैं वहां से निकल रहा था, एक गाड़ी में महिलायें बैठी थीं वह गाड़ी फंस गई। इस प्रकार मेन रोड्स पर लगातार गाड़ियां फिसलती हैं, दुर्घटनायें होती हैं, हर साल आदमी मरते हैं। डूमाड़ा की स्वीकृत पुलिया बनानी है। केकड़ी से सरवाड़ के बीच एक पुलिया, रामनेर ढाणी के चौराहे से अड़कों, एक पुलिया गगल से रामनेरढाणी तक दो पुलियायें, पीसिगन से पिचोलिया के मार्ग में पीसिगन से निकलते ही पुलिया इन सब पुलियाओं का निर्माण होना है। अगर सरकार इन्सान के जीवन का महत्व नहीं समझती और सरकार चाहती है कि आबादी कम की जाए तो फिर पुलिया बनाई जाय या नहीं, तो हमें एतराज़ नहीं। इस प्रकार सड़कों व पुलियाओं की दुर्दशा होने से माता व बहनों को परेशानी होती है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार ऐसी पुलियाओं को जल्दी हाथ में ले। इसी प्रकार कृषि मंडी के टेन्डर्स स्वीकृत हो चुके लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। बरसात के दिनों में हर साल काम रुक जाता है। समझ में नहीं आता विभाग वाले क्या करते हैं। जब टेंडर मंजूर हो गया तो काम क्यों नहीं हुआ ?

अब मैं पुष्कर के तीर्थ स्थानों व दर्शनीय स्थानों पर आता हूं। वहां निम्न मार्ग बनाये जायें :-

(श्री चिरंजी लाल गर्ग)

पहले फाई सागर से अजयपाल तक, पुष्कर से पंचकुंड तक, पुष्कर वाया देवनगर से बैजनाथ, पुष्कर से बूढ़ा पुष्कर। यहां कई पर्यटक आते हैं उनको वहां जाने की सुविधा प्राप्त हो सके। पुरानी सड़कें जो नष्ट हो रही हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाये, पुलियाओं को भी प्राथमिकता दी जाए तथा तीर्थ स्थलों व दर्शनीय स्थलों पर सड़कें बनवा कर लोगों को सुविधा प्रदान की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरज पाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, विकास की गति को तेज करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता सड़कों के निर्माण की है। जालौर जिला सड़कों के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रगति रिपोर्ट को अच्छी तरह से देखा जाए तो जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन हमारे क्षेत्रफल और जैसलमेर के क्षेत्रफल में फर्क नहीं है ...

श्री विश सिंह भाटी : 20 हजार स्क्वायर किलो मीटर का फर्क है।

श्री सूरज पाल सिंह : जालौर जिले की सड़कें काफी समय से उपेक्षित रही हैं। 5 हजार की आबादी का जो लक्ष्य जनता सरकार ने रखा उसमें जालौर जिले का एक गांव भी प्रभावित नहीं हुआ। राजस्थान में केवल 41 गांव 5 हजार की आबादी के थे। तो जो 5 हजार की आबादी का क्राइटेरिया रखा है उससे लाभ होने वाली बात नहीं है। सिरोही, जालोर के जिलों में एक भी गांव को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। जालौर जिला कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। भीनमाल में 60 लाख की लागत से कृषि उपज मंडी बन रही है लेकिन सड़कों का निर्माण नहीं होता है तो जितना भी वहां का उत्पादन है, वह उत्पादन कृषि उपज मंडी में नहीं आ सकेगा, सारा माल भीनमाल कृषि मंडी का मारा जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, पाली से भीनमाल एक बोरी का किराया 10) लगता है और 28 मील की दूरी है और उझा 150 मील दूर है, 6 रुपए लगते हैं। तो जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तब तक ट्रांसपोर्टेशन का भार भी अधिक पड़ेगा, हर चीज महंगी उपलब्ध होगी। किसान को क्रूड ले जाना है। राजस्थान का 80 प्रतिशत क्रूड का कजम्पशन जालौर जिले में है। तो जो जिला कृषि क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहा है और जहां कृषि उपज मंडियों का निर्माण कार्य भी चल रहा है वहां सड़कों को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपके 58 लाख रुपए ऊंझा मंडी में गए। सड़कों के अभाव में आप अपनी टेट रेवेन्यूज को खो रहे हैं। इसलिए जालौर जिला, जो अब तक उपेक्षित रहा है, उसकी ओर विशेष ध्यान दें और सड़कों के निर्माण का काम तेज गति से करें। जालौर जिला कृषि के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है, सड़कों की सुविधा मिलने से ज्यादा उत्पादन हो सकेगा।

मेरा निवेदन है कि निम्न सड़कों को जल्दी पूरा करायें : भीनमाल-नरता, दांसपा-कोरा, पाथेडी, उनड़ी, पोषणा, मेघलवा-जीवाणा। इनको पूरा किया जाए। भीनमाल में जो कृषि उपज मंडी 60 लाख की

(श्री सूरजपाल सिंह)

लागत मे बन रही है तो जितना सुमेरपुर मंडी में माल जाता है और पोषणा के पास पुल का निर्माण न होने से नदी की रुकावट के कारण सारा माल जालौर होकर जाता है। तो ओलावृष्टि की वजह से जो अकाल की स्थिति है, अकाल में प्रपोजल्स तीन सड़कों की गई है। भरुडी-तवाव, बाड़ा घनजी, भादार, घानसा, थरवाड़ पायेडी। तीन प्रस्ताव हैं जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेजे हैं। इसके अलावा पादरा-बोरटा, भीमपुरा से भादेरा। ये सब 15000 आबादी वाले गांव हैं। इसके अलावा 30 हजार की आबादी के गांव भी हैं, भीनमाल-भुंभाणी, जेरणा, सेवड़ी, नरसाणा, डूंगरवा, मेड़ा, जोगावा, अणखोल, भाव, हेमागुड़ा, तेतरोल सिवाडा (जोधावा वाली एप्रोच)। भीनमाल-भुंभाणी-कावतरा-जेर-दामण, दादाल-बाघोड़ा। भीनमाल--गाडीपुरा--जसवंतपुरा। अगर सिवाड़ा वाली सड़क बनाई जाए तो भीनमाल से बाड़मेर तक 41 मील का कम डिसटेंस हो जाएगा।

जिस प्रकार 5 हजार की आबादी का जो क्राइटेरिया रखा है, मगर भीनमाल से जो 28 मील का फासला है और उसमें 30 हजार की आबादी वाले गांव आते हैं। आप 28 मील का एरिया नहीं जोड़ सकते? भीनमाल-गजीपुरा-जसवंतपुरा वाली बहुत पुरानी सड़क है, 7-8 किलोमीटर का बाकी टुकडा है, वहां माताजी का मन्दिर है। अकाल की स्थिति है। तो इन सब सडकों की तरफ ध्यान दें और जालौर जिला जो सड़कों के लिहाज से आज तक उपेक्षित रहा है, उसकी ओर ध्यान दें।

इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि भीनमाल में जो डाक बंगला है उसमें सिर्फ तीन कमरे हैं। भीनमाल सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर है और एक कमरा हमेशा वी. आई. पी. के लिए बुक रहता है और दो कमरे हैं सारे आफिसर्स आते रहते हैं और भीनमाल की हालत यह है कि वहां पर आप को करोड़पतियों की सैकड़ों कोठियां मिलेंगी लेकिन किसी भी अधिकारी या व्यापारी को किराये पर मकान चार सौ रु. देने पर भी नहीं मिलेगा। न वहां धर्मशाला है और न ठहरने की सुविधा है। इसलिए में निवेदन करूंगा कि भीनमाल डाक बंगला है उसमें सिर्फ दो ही कमरे हैं, वहां कम से कम चार कमरों की व्यवस्था की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय कृपया उत्तर दें।

श्री जयनारायण पूनिया (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लेकर सड़कों के निर्माण व पुरानी सड़कों के सुधार व मरम्मत तथा नये पुल व लोक निर्माण के अन्य कार्यों के बारे में जो सुझाव दिये और जो आवश्यकतायें बतायीं वह काफी महत्वपूर्ण हैं। इन सुझावों से काफी लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मांग इस बात की, की जा रही है कि सड़कों की कमी के कारण और उनकी मरम्मत आदि के मामले में ढिलाई के कारण तथा आज तक सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण विकास के कामों में काफी रुकावट

(श्री जयनारायण पूनिया)

आई हुई है जिनका निर्माण जल्दी हो, मरम्मत जल्दी हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस प्रकार के कुछ सुझाव आये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों का प्रश्न है। अपने राजस्थान के क्षेत्रफल को देखते हुए 3,42,314 वर्ग किलोमीटर उसका फैलाव है और उसके अनुसार जो सड़कें होनी चाहिए वह राजस्थान में नहीं बन पायीं। इसलिए विकास की गति में तथा ट्रैफिक के आवागमन में जो सकट आते हैं वह स्वाभाविक हैं। अन्य राज्यों की तुलना में जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको छोड़कर हमारा सबसे नीचे नम्बर है सड़कों के मामले में। वैसे राष्ट्रीय स्तर सड़कों में जो बना हुआ है वह प्रत्येक 100 कि मी. पर 15 कि. मी. आता है और वहां भी पक्की सड़कों का हमारा है 8.7 कि.मी.। इस प्रकार से बहुत नीचे हम हैं। सड़कों की बहुत आवश्यकता है हमारे राजस्थान में और यहां पर गांवों की संख्या को देखते हुए बहुत कम गांव सड़कों से जुड़ पाये हैं। जैसा कि जनतापार्टी की सरकार के आने के बाद में जो एक नीति आबादी के आधार पर बनायी गयी कि सड़कों को किस प्रकार से जोड़ा जाये और प्राथमिकता दी जाये, इसके ऊपर भी माननीय सदस्यों ने कुछ आक्षेप किये हैं कि यह ठीक नहीं है। जहां आदमी कम हैं और ज्यादा आबादी के गांव नहीं हैं वह सड़कों से महरूम रह जाते हैं। इस प्रकार की बातें भी कही गयीं और कहा गया कि जो नार्म्स हैं उनको बदला जाये।

सबसे पहले सोचने की तो बात यह है कि जहां आबादी गहरी है वहां भी सड़कें नहीं हैं। जहां पांच हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की बात कही गयी थी उसमें 41 गांवों को छांटा गया और पांच हजार से ऊपर की आबादी के भी हैं, सात-सात और आठ-आठ हजार की आबादी के गांव भी हैं सन् 1971 की जनगणना के अनुसार, यह गांव जुड़े हुए नहीं थे। पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स भी जुड़े हुए नहीं थे और तहसील हैडक्वार्टर्स भी जुड़े हुए नहीं थे। तो इस प्रकार से यह सड़कों की इतनी बड़ी कमी है इसको एकदम पूरा करना तो सम्भव नहीं है और न ही हर जगह सड़कें शुरू कर देना भी सम्भव है। लेकिन जहां सघन आबादी है, ज्यादा बड़े गांव हैं, ट्रैफिक ज्यादा है और हर प्रकार से माल वहां ज्यादा ढोया जाता है, सबके लिए यह सोचा गया था कि सबसे पहले बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ा जाये और यह कुछ हद तक सही भी है लेकिन जैसे राजस्थान के अन्दर रेगिस्तानी इलाके हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू आदि, जो कम आबादी वाले गांव जहां हैं उनमें पांच हजार की आबादी के गांव नहीं होने के कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी, कुछ जिलों में यह स्वाभाविक बात है कि नार्म्स में नहीं आने की वजह से कुछ माननीय सदस्यों को एतराज हुआ कि हमारे इलाकों में इस साल कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ।

अब जो सड़कों के बारे में हम प्लान बनाकर काम कर रहे हैं, छठी पंचवर्षीय योजना में हमने इस प्रकार से एक प्लान तैयार किया था कि इस योजना के अन्दर

(श्री जयनारायण पूनिया)

हम 1500 से ऊपर की आबादी वाले जितने गांव हैं वह करीब 1600 गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ देंगे और 1000 और 1500 की आबादी के बीच के 50 प्रतिशत गांवों को भी सड़कों से जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमने अपने प्लान को तैयार करके उस पर काम करना शुरू किया है। अब यह पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह आगे आने वाले समय में अपने साधनों के ऊपर निर्भर करेगा। हम कितने साधन जुटा सकते हैं, कितनी मदद हमें मिल सकती है यह बात आगे के हमारे साधनों पर निर्भर करेगी। अगर साधनों की कमी रहेगी तो यह योजना पूरी नहीं हो सकती और जो सदस्यों ने इसके प्रति शक जाहिर किया है वह सही हो सकता है। लेकिन प्लान बनाया है उसके अनुसार साधन जुटाने की कोशिश करेंगे, जो कि जुटा सकते हैं और उनको जुटाया भी जाना चाहिए। मिनिमम नीड प्रोग्राम रखा गया है जो सारे गांवों को नहीं जोड़कर इतनी आबादी वाले गांवों को तो कम से कम जोड़ना जरूरी है। इसके हिसाब से जो प्लान बनाया गया है उसके अनुसार सरकार कार्य कर रही है और इस प्रकार से सड़कों का प्लान तैयार किया गया है।

इस साल हम चाहते थे कि सड़कों के मद में हमें काफी पैसा मिले लेकिन उसके मुताबिक हमें पैसा कुछ कम मिला है। लेकिन पीछे के सालों में जो सड़कों के मद पर और मरम्मत आदि पर जो रुपया मिल सकता था उससे तो बहुत ज्यादा है लेकिन जितना हम चाहते थे उतना नहीं मिल पाया है। तो उससे भी सोचे हुए कार्य में थोड़ा बहुत अन्तर आयेगा।

मैं थोड़े आंकड़े बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमने इस नीति के अनुसार कोशिश करके धन आदि जुटाने के प्रयत्न किये हैं और आगे के बजट में, जिस पर हम बहस कर रहे हैं उसमें काम आयेंगे। 1975-76 के अन्दर सड़क निर्माण और मरम्मत आदि में जिसमें केन्द्रीय योजना भी शामिल है 18 करोड़ रुपये थे और 1976-77 में 29 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 1977-78 में 34.26 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और 1978-79 में 47.66 करोड रुपया खर्च हमने किया है जिसके अन्दर जो स्टेट प्लान में 12.50 करोड़ का सड़क निर्माण के लिए प्रावधान रखा था रिवाइज्ड बजट हुआ वह भी 18 से ऊपर हुआ। इस साल का मूल बजट 12.50 करोड़ था। वह रिवाइज्ड होकर करीब 18.25 करोड़ के लगभग पहुंचा है। इसके मुकाबले में जो बजट हम पास कर रहे हैं आगामी वर्ष के लिये यह होगा 19.63 करोड़ जिसके अन्दर हमने 400 लाख रुपया रखा है सड़कों का निर्माण करेंगे। यह जो 400 लाख रुपया रखा है, सड़कों के निर्माण के लिये और नये कार्यों के लिए, जो स्वीकृति के लिये रखा है पीछे के तमाम फीगर्स को देखते हुए तो सबसे अधिक है और इस प्रकार कभी भी नये निर्माण कार्यों के लिये, आज तक इतनी राशि नहीं रखी गई है, तो यह हमारी नीति का एक द्योतक है। हमारी बनाई प्लान पर हम पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसके अनुसार हम सड़कों का निर्माण करने जा रहे हैं। इस

(श्री जयनारायण पूनिया)

प्रकार सड़कों की मरम्मत के लिये भी जहां पर पीछे की तालिका को देखें तो 75-76 में मरम्मत पर खर्च था 7.49 करोड़ रुपया, मैं समझता हूं यह शायद गैंग के खर्चे पर भी लग सकता है। इसके बाद 76–77 के आंकड़े देखे उसमें बढ़ोतरी हुई है–फ्लड रिपेयर के खर्चे जो एडवांस प्लान पर मिलता था वह मिलकर बनाया 14.10 करोड़ लेकिन 77–78 की योजना में हमने सड़कों की मरम्मत के लिये 14.82 करोड़ रुपया बजट में रखा और साढ़े सतरह करोड़ सड़कों की मरम्मत पर खर्च कर रहे हैं। मरम्मत पर जो नार्म्स निर्धारित हैं उसके अनुसार पैसा नहीं मिल पा रहा है। अनुसार तो 22 करोड़ का होना चाहिये उसके अनुसार तो 22 करोड़ रुपया चाहिये तब जाकर हम सड़कों की मरम्मत कर पायेंगे लेकिन उसके अनुसार बजट में कटौती होती है और यह बजट जो 22 करोड़ का होना चाहिये था वह कम है और केवल 17 करोड़ का हो रह जाता है। इसलिये सड़क मरम्मत में भी कई रोड्स रह जाती है। जिन माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि मरम्मत नहीं हो पा रही है और जिनकी डामर उड़ गई है–री-डामर की जरूरत है तो मैं कहना चाहता हूं कि पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये जो तकनीक अपनाई गई हैं वे भी आज के माहौल में इतनी नहीं हो सकती। धान्धला से जो बनी हुई सड़क थी, उस पर डामर यदि हम कर देते हैं तो वे वहन करने में सक्षम नहीं होती है और आज इसीलिये कई जगह दरारे पड़ी हुई हैं, उबड़-खाबड़ हो गई है। तो तकनीकी ज्ञान के कारण कई समस्यायें बनी हुई है। यदि हम उन सड़कों के पुन: निर्माण में ध्यान दें तो कई करोड़ रुपया हमको खर्च करना पड़ता है तब जाकर वे चालू हालत में बन सकती है। इसलिये सड़क बनाने में जो सरकार की नीति है वह इस साल के बजट में बहुत ज्यादा है और जो सड़कें बनेगी, उसके अनुसार हम कह सकते है कि चालू बजट में 78-79 में जहां हमने सड़कें बनाई है 536 किलो मीटर और नई बनाई है, 175 के लगभग जो सड़कें बनी है उनको सुधारा गया है। इस प्रकार ये सड़कें चालू बजट में बनाई है। जो बजट हम पेश कर रहे है आने वाले वर्ष के लिये उसमें 820 किलोमीटर नई सड़कें और 275 किलोमीटर सड़कों का सुधार करेंगे। जिस गति से हम कर रहे है, फिर भी मैं मानता हूं जितनी आवश्यकतानुसार चाहिये थी निर्माण करना और मरम्मत करना, उस गति से हम आगे नहीं बढ पा रहे और उसका एक ही कारण है कि जो हमारी आर्थिक सीमायें हैं उससे मजबूर होकर हमारे प्लान में कटौती करनी पड़ रही है।

यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सड़क के महत्व को समझा जाय। मैं समझता हूं सड़कों को प्रायरिटि देनी चाहिये और हर ओर से प्रायरिटि की मांग की जा रही है। साथ ही सड़कों का महत्व भी समझा जा रहा है। आज आम आदमी में चर्चा है कि सड़कें गांवों तक पहुंचाई जाय और इसका बहुत बड़ा भारी दबाव पड़ा हुआ है। इसलिये जो सड़कों के निर्माण का मसला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां

(श्री जयनारायण पूनिया)

पर बहस के दौरान मांग की गई कि कई नई सड़कें बनाई जायं और कई पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाय। ये काफी संख्या में बताई हैं। मैं समझता हूं इन सारी सड़कों को हम नहीं बना पायेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों को बतायें जैसी हमारी आर्थिक सीमायें है और जो हमारे पास बजट है उसके दायरे को देखते हुए व्यक्तिगत रूप से मिल कर हमें समझाने की कोशिश करें ताकि उनके क्षेत्र की जो मूल समस्यायें हैं उनको किसी हद तक निपटाया जा सके· लेकिन जो सारी सड़कों के सुझाव दिये और कई क्षेत्रों के नाम बताये उनको तो लिया जाना सम्भव नहीं होगा। उसके लिये तो बहुत बड़े धन की जरूरत है।

इसी प्रकार भवन आदि पर भी बहुत रकम खर्च की जायगी। पिछले वर्ष का भी काफी बजट था। 78-79 का जो बजट था हमारे पास, वह 60 करोड़ के वर्क्स का था और इस वक्त वह करीब 67-68 करोड़ का है। यह काफी बड़ा बजट है, जिनमें भवन भी हैं और सड़कें भी हैं। काफी बड़ी रकम का काम हम ग्राम लेवल तक करेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह बजट शहरों तक ही सीमित हैं, मैं समझता हूं यह बात नहीं है। जो सड़कों की मरम्मत हो रही है वे सब बाहर के क्षेत्रों में हो रही है। निर्माण कार्य भी और सुधार का काम भी। जो बजट का बहुत बड़ा भाग होगा वह देहाती क्षेत्रों में होगा। शहरों में न तो इतनी जरूरत है और न कोई इतनी लम्बी चौड़ी सड़कें होती है जो बनेंगी। माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें कुछ समस्यायें भी बताई हैं और कुछ सुझाव भी दिये हैं। उन पर मैं कुछ माननीय सदस्यों की राय से सहमत होते हुए कार्य करूंगा जो सड़कें मरम्मत के काबिल है, उन पर भी सम्भव है कुछ काम हो सकेगा और उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

वैसे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान कुछ सुझाव दिये हैं जैसे प्रशासनिक आदि उन पर भी विचार किया जायेगा। इसी प्रकार आबादी का जो नामं रखा गया था वह उसकी उपयोगिता को देख कर रखा गया था, लेकिन जहां पिछड़े क्षेत्र हैं और आवादी कम है सरकार उन पर भी विचार करेगी कि सड़कें बनाई जायं। जो हमारा लक्ष्य है उसमें एक हजार से डेढ़ हजार और डेढ़ हजार से ऊपर तक जनसंख्या के करीब सारे गांव आ जाते हैं उनको भी सड़कों से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। छठी योजना में हम छोटी आबादी वाले गांवों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। कोई हमारे रिजिड रूल्स नहीं हैं, जो पांच हजार, 3500 या 3000 की आबादी के गांव हों, वे ही जरूरी हों, ऐसा नहीं है। इसलिये माननीय सदस्यों को कोई असंतोष की बात को महसूस नहीं करना चाहिये।

एक बात और भी माननीय सदस्यों ने उठाई कि ठेकेदारी प्रथा को बन्द करना चाहिए, पुल निगम बनाना चाहिए। इस प्रकार की बातों को यहां पर प्रगट किया गया है। मैं उसका डिटेल में विवरण दे देना चाहता हूं। पुल निगम जो बनाया है उसके अनुसार सड़कों के काम कराये जाय और पुलों के काम भी कराये जायें। उसके

(श्री जयनारायण पूनिया)

अन्दर ठेकेदारी प्रथा को एक तरह से बन्द करने का सुझाव है वह इसमें समावेश हो जाता है। इस तरह से एक पार्शियल तौर पर इसका स्कोप था पुल और सड़क निर्माण निगम का, जिसके द्वारा हम समस्या के हल करने की ओर कदम उठा रहे हैं। पुल निगम का निर्माण हो चुका है और इस समस्या को सोल्व करने की ओर हमने कदम उठ या है। जहां तक की ठेकेदारी प्रथा को खतम करने का सवाल है, इसके अन्दर कई मसलें सामने आते हैं। अगर हम ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें तो ये सारे के सारे काम डिपार्टमेंट को करने पड़ेगें। यह भी सम्भव नहीं है। कानून ऐसे बने हुए हैं कि अगर डिपार्टमेंट से कोई काम करवाते हैं तो इन नियमों के मुताबिक जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले मजदूर हैं उनको मजदूरी स्थायी तौर पर देनी पड़ेगी। वह मजदूर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी फौज के रूप में सामने आयेगें और वह जो मजदूर होगें, उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जायेगा इस प्रकार से जो मजदूर होंगे स्थायी रूप से भर्ती करके अपने डिपार्टमेंट के अन्दर उनको रखना पड़ेगा तो उनका जो मकसद है रखने का, सड़क बनाने का या और निर्माण के काम कराने का, यह जरूरी नहीं है कि हर साल उनको काम ही मिलता रहे, सड़क निर्माण या मरम्मत का काम हो रहा हो। कभी कोई ऐसा टाईम भी होसकता है जबकि मजदूर को न तो सड़क बनाने की जरूरत पड़ेगी, न मरम्मत करने की जरुरत पड़ेगी। महीने दो महीने ऐसे भी हो सकते है कि जिसमें वे बेकार बैठे रहें और उनकी तनख्वाहें देनी पड़ेगी, सारा खर्चा वहन करना पड़ेगा, फिर और भत्ते वगैरा देने पड़ेगे। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि यह जो गेंग प्रथा है उसको हटाया जाय क्योंकि इसके अन्दर कुछ और बातें आ गई है, जहां मजदूर लोग कम काम करते हैं। इस प्रकार से इतनी बड़ी फौज मजदूरों की अगर हम भर्ती करने लगें तो यह भी बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। माननीय सदस्यों का सुझाव यह भी था कि ये काम नहीं करते हैं, हड़ताल आन्दोलन आदि करके दूसरों का भी काम करने से रोकेंगे। इससे दूसरा दुष्प्रभाव भी पड़ने वाला है और दूसरी तरह के काम होने वाले हैं, जिनको रोकना कठिन होगा। हम यह प्रथा समाप्त करना चाहें तो इस प्रकार से हमारे सामने कठिनाई होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक्सपेरीमेंट किया जावे।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण पूनिया : दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। इस भ्रष्टाचार के मामले को ले करके कई माननीय सदस्यों ने बहस में मुद्दे उठाये हैं। उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार की बात बताई है कि कमीशन देते हैं और कोई बात, कोई बड़ा उदाहरण नहीं बताया गया कि यह सड़क ठीक नहीं बनी या किस में भ्रष्टाचार हो गया लेकिन कमीशन की बात आई। तो इसलिए कमीशन की मार्फत जो भ्रष्टाचार की बात बताई गई है उसके लिये भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के जो मामले होते हैं, उसमें पूर्व की प्रणाली थी वह इस प्रकार से थी कि जहां पर कोई भी निर्माण का कार्य हो उसका ठेका उठाया जाता था। उससे पहले स्वीकृति देने के बाद उसका सर्वे होता था, उसमें एस्टीमेट बनता था और उस एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व ही उस सड़क

(श्री जयनारायण पूनिया)

का टेन्डर काल करके उसका निर्माण करना शुरु कर देते थे। चाहे सड़क हो, चाहे पम्प का हो या और कोई काम हो। इस प्रकार से जहां टेक्निकल स्वीकृति होती नहीं थी लेकिन टेन्डर काल करने के बाद उस सड़क का काम शुरु कर देते थे। इससे आगे जब टेन्डर काल होने के बाद टेक्निकल स्वीकृति के बाद एस्टीमेट बनते हैं तो उसमें बहुत टाईम लगता था और उसके आधार पर उसमें जो खामियां रहती हैं, टेक्निकल ग्राउण्ड पर जो जांच होती थी उसके आधार पर, उस टेन्डर के आधार पर सड़क के काम के अन्दर जो आइटम्स की घट बढ़ हो जाती थी उसकी वजह से यह सड़क हो, चाहे बिल्डिंग हो, उसके अन्दर भ्रष्टाचार का मामला उत्पन्न होता था। उनको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है कि सर्वे करने के बाद एस्टीमेट बने और उसके बाद, एस्टीमेट बनने के बाद उसकी तेकनीकी स्वीकृति हो। अब जांच करने के बाद उसके एस्टीमेट बनाए जाते हैं, जो सर्वे हुआ है वह सही है या नहीं, उसके बाद टेण्डर काल करेंगे और उसके बाद निर्माण का काम शुरु किया जावे। उसमें भ्रष्टाचार की किसी प्रकार की सम्भावना खत्म हो जाती है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से मांगें पारित हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री श्यापतसिंह मकासर: जब तक सड़क नहीं बनती, समय बढ़ा दें।

मांग संख्या 19 व 21 पर विचार

श्री जयनारायण पूनिया: इसी प्रकार से सड़कों के अन्दर जहां काम करने के तौर तरीके होते थे उसमें भी भ्रष्टाचार की बात होने की सम्भावना होती थी। इसके लिए जहां पर काम करने का वर्क लोड हो उसमें एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज उसके आधार पर रहते हैं और स्टाफ रहता है। हमारे राजस्थान के अन्दर एस्टीब्लिशमेंट चार्जेज पी. डब्ल्यू. डिपार्टमेंट के सबसे कम हैं। ईसी आधार पर अगर हम आंकें दूसरे प्रान्तों को तो वह कहीं 13 पर्सेंट, 14 पर्सेंट और 15 परसेन्ट से किसी प्रकार से कम नहीं है। लेकिन तमिलनाडू में और केरल आदि में तो 18 परसेन्ट, 20 परसेन्ट और 22 परसेन्ट तक एस्टीब्लिशमेंट चार्जेज का उस पर खर्चा पड़ता है। वहां पर जो टेक्निशियन की कमी नहीं रहती, वहां पर ओवरशियर, एक्स-ई-एन. ए ईएन, सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर आदि जो आवश्यकतानुसार अफसर चाहिए उसका सर्वे करने में, उसका एस्टीमेट बनाने में, उसकी हर तरह से देख भाल करने में, मरम्मत आदि में, निर्माण हो उस वक्त देख भाल करने के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत होती है। यह सब नोर्मली जीतना होना चाहिए उस हिसाब से राजस्थान पी डब्ल्यू

(श्री जयनारायण पूनिया)

डिपार्टमेंट के अन्दर जो एस्टब्लिशमेंट चार्जेज हैं वह 6 पर्सेन्ट से भी कम थे। लेकिन इस बात को देखते हुए कि यह सारा काम हो, इसमें जो कमियां हैं उसकी वजह से न तो सही टाइम पर काम हो सकता है और न ही सही प्रकार से उसकी सर्वे आदि हो सकती है और न सही प्रकार से उसकी निगरानी रखी जा सकती है, न ही किसी प्रकार से भ्रष्टाचार या बदइन्तजामी के कारण हेरा फेरी हो तो उसकी देखभाल की जा सकती है, न जांच की जा सकती है। इस प्रकार से अब इस एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज को बढ़ाया गया है। अब इस डिपार्टमेंट का री-आर्गनाइजेशन किया गया है और बढ़ाकर 7 पर्सेन्ट किया गया है। इसके आधार पर हमने जो कार्यवाही की है उसके अनुसार एक सर्किल खोला गया है। दूसरा सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन के लिए 4 खण्ड और 16 उपखण्ड कार्यालय खोले गये हैं। सिविल इन्जीनियरिंग और मैकेनिकल इन्जीनियरिंग के 2 वृत्त कार्यालय स्थापित किये हैं, इसी तरह से इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग के 2 खण्ड कार्यालय और 2 उपखण्ड कार्यालय और खोले गये हैं। मुख्यालय पर एक आर्चीटेक्ट विंग की भी स्थापना की गई है। इसके अलावा प्लानिंग एवं मानीटरिंग सैल खोला गया है। स्टेन्डर्ड स्पेसिफिकेशन सैल और बिल्डिंग सैल भी स्थापना की गई है जिनके अन्दर एक-एक अधीक्षण अभियन्ता, सुप. इन्जीनियर, और 2 एक्स. ईएन. की पोस्ट और नीचे का सम्बन्धित स्टाफ जो क्लर्क और ए. ईएन. वगैरह हैं, उनकी भर्ती की गई है। एक क्वालिटी कण्ट्रोल सैल और एस्टेब्लिशमेंट सैल, रेन्ट रिलाईजेशन यूनिट आदि की स्थापना की गई है। यह जो काम होते हैं उनकी क्वालिटी सही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्वालिटी कण्ट्रोल सैल है जिसके ऊपर काम करेंगे। इससे भ्रष्टाचार आदि होने की सम्भावना नहीं रहेगी। उसमें जांच होकर कार्यवाही हो जाती है। तो एक प्रकार से जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसी प्रकार से और भी यूनिट रेंट रिलाईजेशन की कायम की हैं। एक हमने इंक्वायरी सैल भी स्थापित किया है। इस इंक्वायरी सैल के माध्यम से कोई भी शिकायत होगी उसकी जांच कराई जायेगी। मौके पर जाकर जो भ्रष्टाचार के मामले होंगे उनकी जांच आदि करने के लिए डिपार्टमेंट के अन्दर यह एक इंक्वायरी सैल एस्टेब्लिश किया गया है। इस प्रकार से हमने भ्रष्टाचार के अन्दर, उनको चैक अप करने के लिये, उनको रोकने के लिये इस प्रकार से कदम उठाये हैं। उससे मैं समझता हूं कि काफी प्रभाव पड़ेगा और इस वक्त भी बहुत अच्छा असर इस बात का पड़ा है कि आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की पहले कहानियां उठती थीं आज उठ नहीं पाई हैं, वह मौका नहीं मिल पाया है। ये सारी बातें हैं।

श्री स्योपतसिंह मकासर : आज तो आप पर ही बौछारें हुई हैं।

श्री जयनारायण पूनिया : भ्रष्टाचार के मामले में मेरे पर माननीय डागा साहब ने लांछन लगाया था और उसके अन्दर यह बात बताई थी कि चूरू जिले के अन्दर जितने ठेकेदार हैं, उनमें अपने रिश्तेदार भर लिए हैं। मैं बताता हूं कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। उनमें ज्यादातर दूसरे लोग हैं। चूंकि उसमें एक पूनिया नाम मिल

(श्री जयनारायण पूनिया)

गया इसलिए उसे मेरा रिश्तेदार बना दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आपकी मार्फत बताना चाहता हूं कि उसके अन्दर ज्यादातर ब्राह्मण हैं। वहां ठेकेदार तो बहुत हैं, उनमें एक मुसलमान है। उसके अन्दर एक गंगानगर का चौधरी है जो बहुत बड़ा ठेकेदार है, शायद माननीय श्योपतसिंह जी जानते हों।

श्री रघुनन्दन व्यास : इनके भी रिश्तेदार होंगे इसीलिए नहीं बोले।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे तो सारे ही रिश्तेदार हैं।

श्री जयनारायण पूनिया : यह बहुत बड़ा ठेकेदार है। इस प्रकार से जो चूरू जिले का ठेका दिया गया है उस ठेके में एक ब्राह्मण है, एक पुराना ठेकेदार मंल का है, मंल जो हरियाणा में है उस ठेकेदार ने ठेका लिया है। एक मोमडन ने लिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मोहनलाल जी के कहने से क्यों नहीं दिया ठेका ?

श्री जयनारायण पूनियां : एक गुजरात के अन्दर काम करता था। शायद वह ब्राह्मण या वनिया है। इस प्रकार दूर दराज के आदमियों ने ठेका लिया है।

इसके अलावा एक बात और बतायी गयी। यह बताया गया है कि इस विभाग के अन्दर कमीशन लिया जाता है। इस कमीशन के बारे में यह कैसे लिया जाता है, यह मैंने माननीय सदस्यों से बार-बार पूछा है परन्तु कोई यह नहीं बताता है परन्तु सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि कमीशन ले रहे हैं। तो यह समस्या कैसे हल हो। इस कमीशन को कैसे बन्द किया जाए....

श्री सूरजपाल सिंह : कौन नहीं लेता है, यह बताइये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आपको प्रस्तुत कर देंगे क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जयनारायण पूनिया : आप सबूत दें कि इस प्रकार से कमीशन लिया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री मूलचन्द डागा : जितने इंजीनियर्स हैं उनकी दौलत की जांच करवा दीजिये। एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट से कह दीजिये। वह जांच कर देगा। कितने इन्जीनियर्स के पास नौकरी करने के समय कितनी दौलत थी और आज कितनी दौलत है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : कांग्रेस के समय कितनी थी और जनता राज में कितनी थी यह अलग अलग जांच हो जाए ?

(व्यवधान)

श्री जयनारायण पूनिया : उपरोक्त तथ्यों के आधार पर....

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय डागा जी अपने कारनामें जनता राज में उजागर कर रहे हैं।

श्री जयनारायण पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, इन तथ्यों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह जो मांग रखी गई है, उनको पारित किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब आपने इतने सारे सेल स्थापित कर दिए हैं, क्वालिटी कन्ट्रोल सेल, सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन सेल, मानेटरी सेल, स्टेण्डर्ड स्पेसिफिकेशन सेल, मैकेनिकल सर्किल, फील्ड डिविजन इलैक्ट्रिकल सर्किल अलग स्थापित कर दिया, तो इसके बाद, इतनी भारी फौज इकट्ठी कर लेने के बाद डिपार्टमेंटल काम करने में आपको क्या कठिनाई है। इतने इन्जीनियर्स है। फिर आपने कहा है कि हमने पुल निगम बनाया है। तो क्या यह पुल निगम डिपार्टमेंटल काम करवायेगा ? इसका सारा काम डिपार्टमेंटल होगा ? यह स्पष्ट कर दीजिए।

श्री जयनारायण पूनिया : 25 लाख से ऊपर के जो पुल होंगे वह तो पुल निगम करेगा और इससे छोटे काम डिपार्टमेंट करेगा।

श्री मूलचन्द डागा : इस साल से आपका एस्टेबिलिशमेंट खर्च कितना बढ़ जायेगा ?

श्री जयनारायण पूनिया : पूरे राजस्थान के अन्दर जो दूसरे डिपार्टमेंटस हैं उनके मुकाबले इसका एस्टेब्लिशमेंट खर्च कम है। जबकि दूसरे डिपार्टमेंटस के 12% 13% एस्टेब्लिशमेंट खर्च आता है, इसका 7% से कम खर्च आता है और अब इसको बढ़ा कर 7% कर दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कितने करोड़ का खर्च होगा।

श्री जयनारायण पूनिया : यह 69 लाख रुपये का खर्च होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतना अच्छा कार्य मुस्तैदी से कर रहे हैं। इसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिये। तीस साल तक तो कोई काम नहीं कर सके।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। पांच हजार की जनसख्या वाले गांव लिए जाएंगे किन्तु अजमेर जिले में एक भी गांव नहीं लिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहूंगा। अभी जो भ्रष्टाचार के बारे में, उसको रोक थाम के लिए मन्त्री महोदय ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि इसके बारे में मन्त्री महोदय ने ऐसा कोई प्रपोजल, योजना या तरीका सामने नहीं रखा है जिससे कि अगले वर्ष जो 400 करोड़ रुपया खर्च होगा उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। अगर

(श्री माधोसिंह कछवाहा)

दस परसेन्ट कमीशन लिया जाये तो कम से कम से कम यह 40 करोड़ रुपया होता है ...

एक माननीय सदस्य : यह 400 लाख है....

श्री माधोसिंह कछवाह : तो भी यह 40 लाख रुपया होता है जो कमीशन केरूप में चला जाएगा । मेरा यह निवेदन है कि पहले के जो काम किये हुए हैं, इनमें पुराने को मत लीजिए, इसके लिए एक सेल क्रिकेट कीजिए जिसमें राजस्थान के इन्जीनियर्स नहीं हो, बम्बई, मद्रास से इन्जीनियर बुलाकर इसमें लगाये जाए और ये इन्जीनियर्स यह देखें कि जो काम किये गये हैं वे स्पेसिफिकेशन के अनुसार किये गये हैं या नहीं । मिलीटरी में जो काम होते हैं, उनकी चैकिंग एक टीम करती है, काम होने के बाद और यह देखती है कि ये काम स्पेसिफिकेशन के अनुसार हुए हैं या नहीं । अगर स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम की चैकिंग कराई जाएगी तो राजस्थान के 90 प्रतिशत काम खराब मिलेंगे और यह प्रत्यक्ष सबूत होगा भ्रष्टाचार का यह रोड और बिल्डिंग में भी मिल जाएगा । यह व्यवस्था की जाए तो इसके बाद इन्जीनियर्स जो काम करेंगे वह सही करेंगे और उनमें एक दहशत बैठ जाएगी और वे हमेशा स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही काम करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन कन्स्ट्रक्टिव सजेशन मन्त्री मन्त्री महोदय को दिये थे ।

श्री उपाध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने सजेशन दिए हैं और मन्त्री महोदय उन पर विचार कर रहे हैं ।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया । भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछने का अवसर आपने दिया तो मुझे भी यह अवसर मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह से आप अपने कथन को दोहराते रहेंगे तो ...

श्री किशनसिंह भाटी : मैंने पाइन्टेड क्वश्चन किए थे। why are you so angry.

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कोई कम्पीटीशनमें पूछ रहे हैं। आप भी पूछ लीजिए ।

श्री किशनसिंह भाटी : आप इस ढंग से फर्मा रहे हैं जैसे मैंने कोई आफेन्स किया है । I did not get the reply

श्री जयनारायण पूनिया : इनके सुझावों पर विचार किया जाएगा ।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा प्रश्न एक तो यह था कि ठेकेदार लीड देंगे 15 मील

(208)

(श्री किशनसिंह भाटी)

की ओर ववेरी पास में होती है। इससे लाखों रुपयों का सरकार को नुकसान होता है। मैंने कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं उनमें एक सुझाव तो उनका यह था कि हमारी कई सड़कें लिट्री के ट्रक्स के आवागमन के कारण टूट जाती हैं। इसलिए इनके रख-रखाव के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार से बात करनी चाहिये कि वह हमें इन रोड्स के मेन्टीनेन्स के लिए कुछ सहायता दे। मैंने इस प्रश्न को भारत सरकार के समक्ष लिया था एक दो बार चिट्ठी भी लिखी। अभी भी मामला विचाराधीन है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सदन में भी इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की गई हैं, इसे भी हम भारत सरकार को लिखेंगे।

मांग संख्या 19 व 21 का पारण

मांग सं० 19

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग सं.19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,60,67,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग सं० 21

प्रश्न यह है कि मांग सं० 21-सड़कें व पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,41,87,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक कल मंगलवार, दि. 20-3-79 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 8.12 बजे मंगलवार, 20.3.79 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 358 का विवरण

प्रश्न के भाग एक की सूची

नागौर जिले की योजनाओं का नाम जो वर्ष 78—79 में स्वीकृति हेतु चयनित की गई है उनका विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्राम जो लिये गये हैं	कोड नं.	तहसील	अनुमानित लागत (लाखों में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्षे. ज. यो. देशवाल	1. देशवाल	10	मेड़ता	4.564	स्वीकृत कर दी गई है
2.	क्षे. ज. यो. सिलनवाद पेज।	1. रोजा	67	लाडनू		
		2. सिलनवाद	68	,,		
		3. ढिंगसारी	66	,,		
		4. धुड़िला	69	,,		
		5. गेनाना	61	,,		
		6. मलगांव	62	,,		
		7. कोयल	59	,,		
		8. बेर	58	,,		
		9. खीखरो	60	,,	35.92	स्वीकृति हेतु विचाराधीन है
3.	क्षे. ज. प. यो. राजोद घानाठो दुगोली	1. राजोद	48	जायल		
		2. सियाला	47	,,		
		3. दुगोली	41	,,		
		4. घातिपाद	37	,,		
		5. घानानी	30	,,		
		6. छपरा	28	,,		
		7. रोटू	40	,,	21.935	स्वीकृत कर दी गई।

1	2	3	4	5	6	7
4.	क्षे. ज. यो. रामसा-वास-लाडावास	1. रामसावास	42	डीडवाना		
		2. लाडावास	66	,,		
		3. निम्बो खुर्द	68	,,	4.625	स्वीकृत कर दी गई है
5.	विस्तार ज. प्र. यो. गेरलो करना	1. गेरलो करना	74	डेगाना	0.436	स्वीकृत कर दी गई
6.	पम्प एवं टेंक योजना डेगाना	1. डेगाना	100	डेगाना	0.88	,,
7.	पम्प एवं टेंक योजना करनू	1. करनू		नागौर	3.36	,,

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मनोहरथाना कस्बे में महिलाओं की हत्या का मामला

363. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अगस्त, 77 को मनोहरथाना कस्बे में जिन दो महिलाओं की हत्या की गई थी क्या उनके अपराधियों का कोई पता चला है ? यदि हां, तो अब तक किन किन व्यक्तियों को उसमें गिरफ्तार किया गया है और क्या अपराधियों के पास से कुछ जेवरात आदि बरामद किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अपराधियों में एक अपराधी थाना झालरापाटन की निगरानी में था और वह हत्यारा पुलिस को धोखा देकर भाग गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, अब तक तीन अपराधियों (1) राम कैलाश उर्फ रामविलास (2) कंवरीया उर्फ जगन्नाथ (3) जमना पुत्र रामकिशन को गिरफ्तार किया गया है, उनकी निशादेही पर कुछ सोने एवं चांदी के चुराये गये जेवरात भी बरामद किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

अजमेर सिटी बसों को नगर परिषद की 10 कि. मी. की परिधि तक चलाने का मामला

364. श्री चिरन्जीलाल गर्ग (पुष्कर): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 31 अगस्त, 1978 को तत्कालीन यातायात मन्त्री से मिलकर मैंने नियमों के तहत सिटी बसें अजमेर नगर परिषद सीमा से 10 कि. मी. दूर तक चलाने की स्वीकृति के लिये आग्रह किया था ?

(2) क्या यह सही है कि मेरे आग्रह को माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर को आवश्यक कार्यवाही कर क्रियान्विति के निर्देश दिए थे ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक इसकी क्रियान्विति नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय ने निर्देश वापस ले लिये? यदि नहीं, तो मन्त्री जी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद छः महीने तक आदेशों की क्रियान्विति न होना कहां तक उचित है ? अब कब तक इसकी क्रियान्विति की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन परिवहन मंत्री महोदय के आदेशानुसार जिला परिवहन

(यातायात मन्त्री)

अधिकारी अजमेर को अजमेर शहर के मार्गों का सर्वे कर विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। जिला परिवहन अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तथा अब इस मामले में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की दिनांक 9-4-79 को निर्धारित बैठक में विचार किया जाकर निर्णय लिया जावेगा।

(2) जी हां।

(3) जी हां, जैसा कि प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में उल्लेख किया है यह मामला प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की दि. 9-4-79 की निर्धारित बैठक में विचारार्थ रखा हुआ है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिये जाने पर तदनुसार अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

राजस्थान में ग्रेट इम्पीरियल बस्टर्ड

365. श्री करतार सिंह (किशनगढ़): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–:

(1) गोडावण (ग्रेट इम्पीरियल बस्टर्ड) नामक लुप्त प्राय: पक्षी राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की जलवायु के कारण भी यह लुप्त प्राय: पक्षी यहां बहुतायत में मिलता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अजमेर जिले में इस पक्षी की सुरक्षा के वास्ते कोई सुरक्षित क्षेत्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक संभव है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गोडावण राजस्थान के समतल चट्टानी भाग जैसे धौलपुर, टोंक जिले के कुछ हिस्सों, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पाली, जालौर जिले के घास के मैदानों तथा सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान विशेषकर कनासर, देवीकोट, मेजलोर, खूर्दी, गुडारोड के कुछ भाग, रामगढ़, चांदन, पोकरण, फलोदी रामदेवडा, दयात्रा, बीकानेर व गंगानगर जिलों के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।

(2) अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र के समीप माधोपुर और कुम्हारों का खुर्रा क्षेत्र में यह पक्षी देखा गया है। राज्य सरकार इस क्षेत्र को आगामी वर्ष बन्द क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है।

चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और डबोक की सीमेंट फैक्ट्रियां

366. श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़, निम्बाहेड़ा और डबोक की सीमेन्ट फैक्ट्रियां पोर्टलैण्ड सीमेंट के स्थान पर "पोजोलोना सीमेन्ट" (अधिक मिला हुआ सीमेन्ट) बना कर बेच रही हैं?

(2) क्या राज्य सरकार ने इन्हें ऐसा काम करने की स्वीकृति दे रखी है? यदि

(श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी)

हां, तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या पोजोलोना सीमेंट और पोर्टलैण्ड सीमेंट की एक ही रेट है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) पजोलोना सीमेंट और पोर्टलेण्ड सीमेंट में आई. एस. आई. के नियम के अनुसार क्या बोरियों पर कोई मार्का लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) राज्य सरकार अपने काम के लिये क्या पोजोलोना सीमेंट काम ले सकती है ? यदि हां, तो उसकी लिखित स्वीकृति सदन की मेज पर रखें। पोजोलोना कौन कौन से कार्यों के लिए प्रयोग मे ली जा सकती है और किसके लिए नहीं ?

(6) राज्य सरकार ने पिछले 6 माह में कितना सीमेंट खरीदा ? उसमें पोजोलोना सीमेट कितना था ?

उत्तर

(1) तीनों ही सीमेंट फैक्ट्रियां पोर्टलेण्ड सीमेंट एवं पोजोलोना सीमेंट का उत्पादन करती हैं। पोर्टलेण्ड सीमेंट हेतु चूने का पत्थर, लेटेराइट तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है जबकि पोजोलोना सीमेंट हेतु सिलीसियस मेटीरियल अर्थात् बर्न्टशेल (एक प्रकार का पत्थर) तथा बर्न्ट ब्रिक्स (एक प्रकार के ईंटों का चूरा) भी मिलाया जाता है।

(2) सीमेंट निर्माण संबंधित लाइसेंस भारत सरकार द्वारा दिये जाते हैं। भारत सरकार को आदेशों की प्रति भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है। प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(3) पोर्टलैण्ड एवं पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट की विक्रय दर समान है। सीमेंट की विक्रय दर सीमेंट कन्ट्रोल आर्डर 1967 के खण्ड 8 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

(4) भारतीय मानक संस्थान की ओर से उक्त फैक्ट्रियों को X का मार्का मिला हुआ है, और ये फैक्ट्रियां अपना मार्का अंकित करती हैं। पोर्टलैण्ड सीमेंट की बोरी पर काले रंग से वाइन्डिग की जाती है एवं पोर्टलैण्ड पोजोलोना सीमेंट पर लाल रंग से वाइन्डिग की जाती है। प्रत्येक बोरी पर फैक्ट्री का नाम, स्थान, ब्रान्ड एवं नेट वजन अंकित किया जाता है।

(5) राज्य सरकार को पोर्टलैण्ड एवं पोर्टलैंड पोजोलोना दोनों प्रकार की सीमेन्ट भारत सरकार द्वारा आवंटित की जाती हैं। विभिन्न विभागों द्वारा दोनों ही प्रकार की सीमेंट का उपयोग किया जाता है।

पोर्टलैण्ड पोजोलोना सीमेंट सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के काम में ली जा सकती है। वैसे भारतीय मानक संस्थान के मानक सं. 1489/1976 के अनुसार जहां पानी की मार अधिक होती है वहां पोर्टलैण्ड पोजोलोना सीमेंट अधिक लाभदायक मानी गयी है।

(उद्योग मंत्री)

(6) राज्य के 8 बड़े उपभोक्ता। को जुलाई, 1978 से दिसम्बर 1978 तक, 1, 17, 121 मैट्रिक टन सीमेंट आवंटित भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसमें से कितनी सीमेंट पोजोलोना थी व कितनी अन्य प्रकार की यह सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

राज्य में देवस्थान बोर्ड की स्थापना

367. श्री अजीत सिंह (टौंक) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) देवस्थान विभाग के कितने भवन राज्य सरकार के पास किराये पर हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार देवस्थान बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है?

(3) क्या राज्य सरकार बदलती मान्यताओं को ध्यान में रखकर नया देवस्थान एक्ट बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

(4) देवस्थान विभाग की अतुल सम्पत्ति का समाज के हित में किस प्रकार उपयोग हो सकता है? क्या यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित मन्दिरों के 44 भवन राज्य सरकार के पास किराये पर हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। यह मामला विचाराधीन है।

(3) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान सरकार

(देवस्थान विभाग)

देवस्थान विभाग के भवन जो राज्य सरकार के पास किराये पर हैं की सूची

क. सं.	नाम मन्दिर व संस्थान	श्रेणी	नाम विभाग व संस्थान	मासिक किराया	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
			जिला जयपुर		
1	मंदिर श्री मेसताब बिहारी जी व मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी।	डायरेक्ट चार्ज	डाक तार विभाग	352.00	
2	मंदिर श्री आनन्द बिहारी जी व धर्मशाला माजी साब।	"	पुलिस विभाग	997.00	
3	मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी व	"	कृषि विभाग	51.00	
4	मन्दिर श्री आनन्द कृष्ण बिहारी जी	"	भू प्रबन्ध विभाग	150.00	
5	मन्दिर श्री रामचन्द्र जी	"	रसद विभाग	25.50	
6	मन्दिर श्री रसिक बिहारी जी	"	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	9.44	
7	मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी	"	जलदाय विभाग	257.00	

1	2	3	4	5	6
8	मन्दिर श्री रामचन्द्र जी	डायरेक्ट चार्ज	राजस्थान राज्य प्राप्य क्रिया प्रतिष्ठान	65.00	
9	मन्दिर श्री मदन मोहन जी	"	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	2,133-00	
10	मन्दिर श्री कालेश्वर जी	"	कमला नेहरू स्मृति रा0 मा0 विद्यालय	1,228.00	
11	मन्दिर श्री बलदेव जी परशराम द्वारा	,,	राजकीय उद्योग प्रशिक्षणालय	1,448.00	
12	मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी	,,	राज0 प्राथमिक विद्यालय	60.00	
13	मन्दिर श्री रतन बिहारी जी	,,	—,,—	30.00	
14	मन्दिर श्री बुद्धराज बिहारी जी	डायरेक्ट चार्ज	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	150.00	
15	मंदिर श्री रसिक बिहारी जी	(प्रत्यक्ष प्रचार)	राज्य हिंदी प्राथमिक विद्यालय	61.00	
16	मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी	,,	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	76.00	
17	मन्दिर श्री बृजराज बिहारी जी	,,	कन्या राज0 उच्च प्राथमिक विद्यालय	144.00	
18	मंदिर श्री रामचन्द्र जी	,,	महाराजा संस्कृत कालेज	778.00	

1	2	3	4	5	6
19	मंदिर श्री रामचन्द्र जी	डायरेक्ट चार्ज (प्रत्यक्ष प्रचार)	महाराजा संस्कृत छात्रावास	78.00	
			जिला भरतपुर		
20	मन्दिर श्री बिहारी जी जिला	आत्मनिर्भर	जिला आयुर्वेद अधिकारी	157.00	
21	मंदिर श्री बिहारी जी जिला	,,	सिचाई विभाग	792.00	
22	मंदिर श्री बालाचन्द जी	,,	जिला शिक्षा अधिकारी	540.00	
			जिला करोली		
23	मन्दिर श्री राधा गोपाल जी	,,	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	110.00	
24	मन्दिर श्री प्रताप नवल बिहारी जी	,,	—"—	100.00	
			जिला धोलपुर		
25	जसवन्त सराय, जोधपुर	डायरेक्ट चार्ज	नगरपालिका	3.62	
26	मन्दिर श्री रसिक बिहारी जी	,,	भू प्रबन्ध अधिकारी	322.80	
27	मन्दिर श्री रसिक बिहारी जी	,,	उप निदेशक शिक्षा	155.00	
28	मन्दिर श्री रसिक बिहारी जी	,,	उपनिरीक्षक शिक्षा	251.00	

1	2	3	4	5	6
29	मन्दिर श्री रसिक बिहारी जी	डायरेक्ट चार्ज	नगरपालिका	16.00	
30	मन्दिर श्री कुंज बिहारी जी	आत्मनिर्भर	धुलेश्वर प्राथमिक विद्यालय	8 50	
31	मन्दिर श्री गंगाधाम जी	,,	बादन्त पिमोल डिस्पेन्सरी	8.50	
			जिला उदयपुर		
32	मन्दिर श्री चारभुजा जी, गड़मोर	आत्मनिर्भर	आयुर्वेद औषधालय	116.00	
33	मन्दिर श्री चारभुजा जी, गड़मोर	,,	नायब तहसील कार्यालय	60.00	
34	मन्दिर श्री भीम परमेश्वर जी, उदयपुर	,,	संस्कृत कालेज	744.00	
35	मन्दिर श्री जवान परमेश्वर जी	,,	जिलाधीश कार्यालय	21.00	
36	मन्दिर श्री ,, ,,	,,	जिलाधीश कार्यालय	39.00	
37	मन्दिर श्री ऋषभदेव जी	,,	पंचायत समिति, खैरवाड़ा सालुक घाणोराव सराय में प्राथमिक विद्यालय	352.00	
38	मन्दिर श्री ऋषभदेव जी	,,	कन्या पाठशाला	89.00	
39	मन्दिर श्री ऋषभदेव जी	,,	प्रसाद सराय में शिक्षा विभाग	8.00	

1	2	3	4	5	6
40	मन्दिर श्री ऋषभदेव जी	आत्मनिर्भर	तहसील खैरवाड़ा का कमरा किराया	8.00	
			जिला बून्दी		
41	मन्दिर श्री केशोराय जी पाटन	डायरेक्ट चार्ज	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	11.00	
42	मन्दिर श्री हनुमान जी धर्मशाला	आत्मनिर्भर	संस्कृत पाठशाला	5.00	
			जिला झालावाड़		
43	मन्दिर श्री द्वारकानाथ जी	आत्मनिर्भर	आयुर्वेदिक औषधालय	50 00	
44	मन्दिर श्री द्वारकानाथ जी	आत्मनिर्भर	छात्रावास समाज कल्याण विभाग	30.69	

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष में बालकों के लिये विशेष चिकित्सा सुविधा

368. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बालकों के लिए प्रत्येक जिला एवं नगरपालिका स्तर पर राज्य सरकार ने क्या कोई विचार किया है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

जिन जिला अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत नहीं हैं, वहां बाल रोग में पोस्ट ग्रेजुएट सी. ए. एस. डाक्टरों को लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं।

सभी जिला अस्पतालों में बाल रोगियों के लिये कम से कम दस शैयाओं की इकाई की व्यवस्था कर दी गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना काल में सभी नगर पालिकाओं के अस्पतालों में जहां दो डाक्टर नहीं हैं, एक महिला डाक्टर का पद सृजित करने का प्रस्ताव है।

चालू वर्ष में जिन नगरपालिकाओं की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 10,000 से ऊपर है, वहां एक महिला डाक्टर का पद सृजित किया है।

उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालाओं की क्रमोन्नति का आधार

369. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इस वर्ष कन्या उच्च माध्यमिक व माध्यमिक पाठशालाएं क्रमोन्नत करने का क्या आधार निश्चित किया गया था व उसके आधार पर कितनी पाठशालाएं इस वर्ष क्रमोन्नत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि क्रमोन्नत के आधार पर एक भी पाठशाला क्रमोन्नत नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बिलाड़ा कस्बा, जिसकी आबादी लगभग 25 हजार के आस पास है, में उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला में क्रमोन्नत नहीं गई है ? अगर हां, तो क्रमोन्नत नहीं करने का क्या कारण रहा है ?

उत्तर

(1) कन्या पाठशालाएं खोलने का कोई पृथक से आधार निश्चित नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बिलाड़ा में सहशिक्षा वाला एक उच्च माध्यमिक विद्यालय पहले से है। अतः कोई नया माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया।

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड

370. श्री माधोसिंह कछवाह सरदारपुरा: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(1) क्या यह सही है कि रासा एजेन्सी पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. जोधपुर से घी खरीदने वाली विभिन्न दुकानों में से एक है ?

(2) क्या यह सही है कि रासा एजेन्सी जोधपुर से घी का व्यापार जोधपुर डेयरी के साथ श्री गर्ग के जनरल मैनेजर बनने के पश्चात् शुरू किया ?

(3) क्या यह सही है कि रासा एजेन्सी को घी अधिक मात्रा में उस समय दिया गया, जब घी की कीमत उस दिन व उससे एक दिन पहले बढ़ाई गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि सबसे पहले रासा एजेन्सी को घी दिया जाता है क्योंकि श्री गर्ग के मित्र और दूध के टैंकर के भागीदार श्री छबरलाल ओझा रासा एजेन्सी के भागीदार है जिनको गर्ग अपने साथ नौकरी लगवाने के लिए लेकर आये ?

(5) जोधपुर डेयरी द्वारा एजेन्सी को कब कब कितना घी किस दर से बेचा गया ? कृपया दिनांक वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) श्री बी. के. गर्ग के आने के पश्चात् जोधपुर डेयरी में घी के भाव कितनी बार बढ़ाये गये और किस तारीख को कितना घी का भाव बढ़ाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(6) जी, केवल एक बार दिनांक 2-10-78 को 50 पैसे प्रति किलो 21.50 प्रति किलो से 22-00 बढ़ाया गया है। प्रति-किलो पेकिंग व विक्रय कर अलावा।

घी बिक्री का विवरण जो रासा एजेन्सी को बेचा गया
दिनांक 5-10-78 से 28-2-79 तक

दिनांक	पीपे संख्या	विवरण
20-10-78	5	21-50 रुपये प्रति किलो पैंकिंग व सेल्स टैक्स अतिरिक्त।
27.10-78	6	
28.10-78	7	22 रुपए प्रति किलो व पैंकिग व सेल्स टैक्स अतिरिक्त (21-10-78 से दर बढ़ी है)
4-11-78	5	
4-11-78	8	
6-11-78	5	
9-11-78	5	
9-11-78	12	
15-11-78	2	
23-11-78	5	
23-11-78	10	
30-11-78	6	
1-12-78	5	
6-12-78	3	
8-12-78	3	
14-12-78	2	
18-12-78	3	
30-12-78	2	
1- 2-79	1	
2- 2-79	1	
5- 2-79	1	
कुल योग	97	

विधान सभा क्षेत्र बाडी व धौलपुर में खोले गए नए स्कूल

371. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सत्र 77-78 व 78-79 में धौलपुर व बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में कितने सैकण्डरी स्कूल (हाई स्कूल) खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या धौलपुर सिटी में केवल एक ही हायर सैकण्डरी स्कूल है और सैकण्डरी स्कूल एक भी नहीं ? हायर सैकण्डरी स्कूल में दो शिफ्ट चलती हैं, फिर भी बहुत से लड़कों को 9 वीं व 10 वीं में एडमीशन जगह न होने की वजह से नहीं मिल सके ?

(3) क्या यह सही है कि स्कूल खोलने की शहर धौलपुर की मांग काफी पुरानी है? यदि हां, तो स्कूल कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 में इन क्षेत्रों में राजपुर में सैकण्डरी विद्यालय खोला गया। वर्ष 1978-79 में सलेमपुर एवं मोरोलीडांग में भी सैकण्डरी स्कूल खोले गये थे। किन्तु मोरोलीडांग में निर्धारित संख्या में छात्र न होने से वह बन्द कर दिया गया।

(2) धौलपुर सिटी में दो हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं। इनमें से एक कन्या विद्यालय है। कक्षा-नवीं एवं दसवीं में छात्रों को प्रवेश न मिलने की कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(3) जी हां। आगामी सत्र में विचार किया जावेगा।

सरकारी भवनों का तामीर के समय वाटर प्रूफिंग

372. श्री सैयद मन्जूर अली (सवाई माधोपुर): —क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि अधिकतर सरकारी भवन बारिश के मौसम में चूते हैं तथा इन भवनों के चूने के कारण इनमें रहने वाले व्यक्तियों को भारी असुविधा होती है तथा उनकी कार्यकुशलता में भी कमी आती है ?

(2) क्या इस असुविधा से सरकारी दफ्तरों में कार्य कुशलता कम नहीं होती और सरकारी रिकार्ड खराब नहीं होता ?

(3) क्या इन भवनों की तामीर के वक्त व बाद में आवश्यकता पड़ने पर वाटर प्रूफिंग का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या तमाम सरकारी भवनों की तामीर के वक्त वाटर प्रूफिंग कराया जाता है ? अगर हां, तो फिर भी इन भवनों का टपकना क्या डिफेक्टिव वाटर प्रूफिंग नहीं है ?

(5) अगर वाटर प्रूफिंग प्रावधान नहीं है, तो दफ्तरों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए क्या सरकार इन इमारतों में

(श्री सैयद मन्जूर अली)

वाटर प्रूफिंग का प्रावधान जरूरी नहीं समझती ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यदि अधिक वर्षा से कहीं चूते की रिपोर्ट आती है तो तुरन्त मरम्मत कर दी जाती है !

(2) जी नहीं।

(3) जी हाँ। आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत का प्रावधान है।

(4) जी हां। वाटर प्रूफिंग कराया जाता है तथा डिफेक्टिव नहीं होता है। अधिक वर्षा या नालियों के रुक जाने से अगर कहीं टपकता है तो उसे तुरन्त दुरुस्त कर दिया जाता है।

(5) प्रत्यक इमारत में वाटर प्रूफ का प्रावधान होता है।

राज्य पुलिस में हरिजन थानेदार एवं अधीक्षक आरक्षी

373. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य पुलिस सेवा में कितने थानेदार तथा एस. पी. हरिजन हैं तथा कहां कहां नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है राज्य में पुलिस विभाग के व्यवहार में मार पीट तथा गाली गलोच की प्रमुखता है ? क्या राज्य सरकार पुलिस के इस व्यवहार में तब्दीली लाने का इरादा रखती है ?

(3) क्या इसके लिए राज्य सरकार कोई योजना बना रही है ? अगर हां, तो कब तक तथा क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस सेवा में 36 थानेदार एवं 3 एस. पी. अनुसूचित जाति के हैं। तैनाती की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

अनुसूचित जाति के पुलिस अधीक्षकों एवं थानेदारों के नाम मय पदस्थान के सम्बन्ध में सूचना

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	जिला	थाना पदस्थान
1	2	3	4	5
1	श्री रामनारायण	पुलिस अधीक्षक	जयपुर	—
2	श्री रोहितास्व कुमार	,,	जैसलमेर	—
3	श्री पी. एन. राछोया	,,	झालावाड़	—
4	श्री आनन्दी लाल	उप निरीक्षक	भीलवाड़ा	पुलिन लाइन, भीलवाड़ा
5	श्री बोदन राम	,,	अजमेर	सी. आई. ए. अजमेर
6	श्री चिरंजीलाल तंवर	,,	भरतपुर	थाना रूपवास
7	श्री दुलीचन्द	,,	कोटा	थाना खातौली
8	श्री ईश्वर सिंह	,,	कोटा	केजुअल रिजर्व
9	श्री झम्मन लाल	,,	कोटा	थाना मांगरोल
10	श्री नारायण दास	,,	जयपुर	थाना सदर
11	श्री ओमप्रकाश पंवार	,,	जयपुर	थाना कोतवाली
12	श्री सुहाग राम	,,	जयपुर	थाना चन्दबाजी
12	श्री डूंगर चन्द	,,	जयपुर	सी.आई.डी.(आई.बी.)
14	श्री वीरम राम	,,	जयपुर	,,
15	श्री बजरंग लाल वर्मा	,,	आर.पी.ए.	जयपुर में प्रशिक्षण पर
16	श्री अनिलकुमार	,,	,,	
17	श्री बिहारी लाल	,,	,,	
18	श्री गणेशमल	,,	,,	
19	श्री ग्यारसीलाल	,,	,,	
20	श्री गणेशलाल	,,	,,	
21	श्री गणपतलाल	,,	,,	
22	श्री हनुमान प्रसाद	,,	,,	

226

1	2	3	4	5
23	श्री हरपाल सिंह	उप निरीक्षक	आर.पी.ए.	
24	श्री इन्द्रराज	,,	,,	
25	श्री जगमाल वर्मा	,,	,,	
26	श्री जगदीशप्रसाद	,,	,,	
27	श्री ओमप्रकाश	,,	,,	
28	श्री प्रेमप्रकाश	,,	,,	
29	श्री प्यारेलाल	,,	,,	
30	श्री रिसाल सिंह	,,	,,	
31	श्री शिवनाथ कुदिया	,,	,,	(सीआईडी आई बी)
32	श्री तगाराम	,,	,,	,,
33	श्री बुद्धराम	,,	ए. पी. अजमेर	
34	श्री मिश्रीलाल	,,	ए. पी. उदयपुर	
35	श्री दीन दयाल	,,	आर.ए.सी. 6 बटालियन, जोधपुर	
36	श्री ताराचन्द	,,	,,	,,
37	श्री गुरुदयाल	,,	पी. आर. ओ., जयपुर।	
38	श्री परसराम	,,	,,	
39	श्री भजनलाल	,,	,,	

कृषि उपज मण्डियों के चुनाव

374. श्री शंकर लाल (जैतारण): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कराने की घोषणा के पश्चात् चुनाव फिलहाल न कराने का वापस निर्णय ले लिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) अब इन संस्थाओं के चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि सभी मण्डी समितियों में समस्त सदस्यों का एक साथ निर्वाचन कराने है।

(2) इन संस्थाओं के चुनाव शीघ्र ही करवाये जाने का प्रस्ताव है।

गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल, झालावाड़ में इतिहास का विषय

375. **श्री निर्मल कुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झालावाड़ गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल में 11 वीं कक्षा में इतिहास का विषय है ? जब कि 9 वी व 10 वीं कक्षा में इतिहास का विषय नहीं है ? यदि हां, तो 9 वी 10 वी कक्षा में इतिहास का विषय प्रारम्भ करने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर

जी हां। अगले वर्ष विषय प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

गोगुन्दा से झाड़ोल वाया बगडून्दा मजावद, छाली, उन्डीथल, गोराणा, देवास सड़क को पक्की बनाने का मामला

376. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गोगुन्दा से झाड़ोल वाया बगडून्दा, मजावद, छाली, उन्डीथल, गोराणा, देवास जाने वाले मार्ग, जिस पर करीब 42 गांव आते हैं और लम्बे अर्से से यह रोड़ कच्ची पड़ी हैं । को पक्की बनाने के लिए कई बार आवेदन भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो यह रोड कब तक पक्की बन जावेंगी ?

(2) क्या यह सही है कि बरसात में यह मार्ग पूर्ण रूप से बन्द हो जाता है और इन गांवों में कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो इस स्थिति में इस रोड को पक्की बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सड़क 44 किलोमीटर लम्बी है जिसमें $5\frac{1}{2}$ किलोमीटर ग्रेवल है बाकी कच्चा रास्ता है।

(2) जी हां। कच्ची सड़क बरसात में बन्द हो जाती है। इस सड़क को बनाने की अनुमानित लागत 92 लाख रुपये है। धनाभाव के कारण यह सड़क अभी विचाराधीन नहीं है।

राज्य में सीमेंट के बड़े कारखाने लगाने हेतु भारत सरकार से अनुमति

377. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भारत सरकार ने राज्य में चार बड़े सीमेंट कारखाने लगाने की अनुमति कौन से साल में दी है और यह कब तक लगा लिए जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2 क्या राज्य में मिनी सीमेंट कारखाने लगाने की सम्भावनायें हैं यदि हां, तो कहां-कहां और किन किन को भारत सरकार ने लाइसेन्स दे दिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा राज्य में चार बड़े सीमेंट कारखाने लगाने हेतु वर्ष 1978 में आशय पत्र जारी किये गये हैं। आशय पत्र की अवधि एक वर्ष के लिए है। पार्टियों द्वारा उद्योग स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। इसके पश्चात् पार्टियों को भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त करने होंगे। लाइसेन्स प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि में उत्पादन प्रारम्भ करने की शर्त लाइसेन्स में होती है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार इन उद्योगों को शीघ्र लगवाने हेतु प्रयत्नशील है।

(2) जी हां। उन स्थानों के नाम जहां मिनी सीमेंट प्लांट लगाने के लिए खनन पट्टे उपलब्ध कराये जा सकते हैं एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आशय पत्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राज्य में 4 बड़े सीमेंट कारखानों की सूची (सीमेंट के लिए मिले आशय पत्र के सम्बन्ध विवरण)

क. सं.	पार्टी का नाम	स्थान	उत्पादन का नाम	उत्पादन क्षमता (लाख टन में)	विनियोजन (लाख रु.में)	रोजगार (व्यक्ति)	आशय पत्र प्राप्त होने की तिथि
1—	मैसर्स दिग्विजय सीमेंट क. गुजरात।	ब्यावर (अजमेर)	पोर्टलैण्ड सीमेंट (एन. यू.)	4	2600—00	800	26—4—1978
2—	मैसर्स के. के. सोमानी, बम्बई।	किदरली (सिरोही)	पोर्टलैण्ड सीमेंट (एन. यू.)	5	1505—00	935	26—4—1978
3—	मैसर्स वूटा प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली	बनास (सिरोही)	पोर्टलैण्ड सीमेंट	4—18	1500—00	575	15—6—1978
4—	मैसर्स युनाल्द मेजर मिल्स, केरल।	नीम का थाना (मांडवा) (सीकर)	सीमेंठ प्लान्ट	3	900—00	813	11—5—1978

उन स्थानों के नाम जहां मिनी सीमेंट उद्योग लगाने की सम्भावनाएं हैं एवं भारत सरकार द्वारा आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं

खनिज विभाग उन स्थानों का पता लगा रहा है जहां खनन् पट्टे मिनी सीमेंट कारखानों के लिए उपलब्ध कराये जा सकते हैं अब तक खनिज विभाग ने राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. जयपुर को 10 स्थान सुझायें हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है —

1 ग्राम जमीरा, जिला उदयपुर।
2 ग्राम हायरों, जिला उदयपुर।
3 पलाना, जिला उदयपुर।
4 जैतपुरा (छन्न), जिला सवाई माधोपुर।
5 घनवाब, आबूरोड जिला सिरोही।
6 ग्राम परसोली, जिला चित्तोड़।
7 ब्रिजपुरा, किशनगढ़, जिला अजमेर।
8 ग्राम कलिनजरा, जिला बांसवाड़ा।
9 संजूरिया, बीकरनो, तहसील उदयपुर।
10 खुश्ला, जैसलमेर।

राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि. जयपुर को मिनी सीमेंट कारखाने लगाने के लिए निम्न स्थानों के लिए आशय पत्र प्राप्त हुए

1 नीम का थाना (सीकर)
2 बिलाड़ा (जोधपुर)
3 बहरोड छपरा केवरली (सिरोही)
4 कोटपूतली (जयपुर)
5 रास (पाली)

राज्य में 5 मिनी सीमेंट कारखानों की सूची (मिनी सीमेन्ट के लिए मिले आशय पत्र के सम्बन्ध में विवरण)

क्र. सं.	पार्टी का नाम	स्थान	उत्पादन का नाम	उत्पादन क्षमता	विनियोजन (लाख रु. में)	रोजगार (संख्या)
1.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम जयपुर।	जैतारण (पाली)	मिनी सीमेन्ट प्लान्ट (एन. यू.)	33 हजार टन	230-00	160
2.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर।	कोटपूतली (जयपुर)	मिनी सीमेन्ट प्लान्ट	33 हजार टन	230·00	160
3.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर।	किवरली (सिरोही)	मिनी सीमेन्ट प्लान्ट	33 हजार टन	230-00	160
4.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर।	नीमका थाना	मिनी सीमेन्ट प्लान्ट	33 हजार टन	230-00	160
5.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, जयपुर।	बिलाड़ा (जोधपुर)	मिनी सीमेन्ट प्लान्ट	33 हजार टन	230-00	160

कोलियारी से फलासिया सड़क का निर्माण कार्य

378. श्री लालूदास (फलासिया): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या उदयपुर जिले के कोलियारी से फलासिया, सोम तक कच्ची सड़क निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उसको कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं। कोलीयारी से फलासिया सोम सड़क निर्माणाधीन नहीहै। छठी पंचवर्षीय योजना में उदयपुर से सोम वाया साडोल सड़क के अन्तर्गत यह सड़क प्रस्तावित है।

मकराना-बिदयाद एवं बोरावड रोड पर इण्डस्ट्रियल पर्पज लीज

380. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश नागौर ने कितनी इकाइयों को इण्डस्ट्रियल पर्पज को लीज मकराना बिदयाद एवं बोरावड़ रोड पर दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत से केसेज जिलाधीश नागौर के जेरे गोर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार मकराना के आसपास रिहायशी जमीन किस ओर छोड़ रही है ? कृपया आबादी और औद्योगिक भूमि का खसरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिलाधीश द्वारा जब तक मकराना बिदयाद एवं बोरावड़ रोड पर कुछ 141 इकाइयों को उद्योग हेतु लीज दी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है। उद्योग लीज के जो मामले विचाराधीन हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) मकराना शहर के पूर्व में मकराना मंगलाना सड़क पर आबादी विस्तार हेतु जमीन सुरक्षित रखने का मामला विचाराधीन है।

कस्बा मकराना में लीज आवंटनतियों की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम	लीज धारकों का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	वर्ष जिसमें लीज आवंटन हुई
1	मकराना	भेरुबक्स पुत्र लक्ष्मी नारायण लडा	697	2।।)	17-11-71
2	"	श्री रामकृष्ण पुत्र भागीरथ प्रसाद	699	2।।)	17-11-71
3	"	मदानाराम पुत्र घासीराम सोलंकी	626	1।।)	"
4	"	राधाकृष्ण, मिश्रीलाल वगेरा	697	2।।)	"
5	"	कल्याणमल पुत्र सूरजमल	692	2।।)	22-5-72
6	"	कुम्भाराम पुत्र कालूराम बलाई	748	1)	"
7	"	रामवलम पुत्र जेठमल मानकणोया	701	2।।)	"
8	"	जानकीलाल पुत्र राधा किशन	691	2।।)	"
9	"	मेरू फरीद अब्दुल रहमान वगेरा	708	2।।)	"
			697		
10	"	सूरजीदेवी पत्नी ओमप्रकाश श्रीनगर अजमेर	708 697	2।।)	"
11	"	शिवनाथ पुत्र रामाराम माली	767	2।।)	28-9-72
			———— 1		
12	"	सीताराम शिवबगस वगेरा	692	2।।)	21-10-72
13	"	मैसर्स अमाल गेमटेड कोल फील्डम	604	2।।)	13-11-72

(234)

1	2	3	4	5	6
14	मकराना	माइला पुत्र जान महमूद वगैरा	750	2ıı)	14-6-73
15	"	मैसर्स वामल सांगध्डे कोल फील्ड	604	12ıı)	30–10-73 (रद्द)
16	"	मोहम्मद गनी जुमा पुत्र नसीरुद्दीन	698 697 760	2ıı)	28-5-74
17	"	पाबूदीन सुलतान वगैरा	733	3ıı)	6-7-74
18	"	राधाकृष्ण रामबलम वगैरा	692	2ı)	9-7-74
19	"	लादूराम गंगाराम रामदेव वगैरा	731	3ı)	16-8-74
20	"	मैसर्स एम.डी. सेटीया एण्ड कम्पनी	698	2ıı)	19-10-74
21	"	कल्याणमल श्रीराम वगैरा	698	2ıı)	17-11-71
22	"	छोटू पुत्र हाजी उसमान	684	2)	9-1–75
23	"	देवीप्रसाद गुप्ता मैनेजिंग डाइरेक्टर	634	3)1	"
24	"	श्री मंसूर पुत्र नसीरुद्दीन	697 710	ııı)2	3–2-76
25	"	सुलेमान पुत्र नसीरुद्दीन	698 710	ııı)1	"
26	"	इब्राहीम पुत्र इशाक	697 710	ııı)2	"
27	"	आशाराम पुत्र मूलाराम वगैरा	760	3ıı)	10-10-76
28	"	सत्यनारायण पुत्र भेरुका लड़ा	697	2ıı)	21-5-76
29	"	जमनालाल पुत्र लादूराम वगैरा	697	2ıı)	12-10-76

1	2	3		4	5	6
30	मकराना	श्रीमती शकुन्तला पत्नी विजयपालसिंह प्रदीप पुत्र भीमसिंह	760	1।।।)		21-1-77
31	"	शाबुद्दीन पुत्र सुलतान व्यापारी	729	2)3		7-12-76
32	"	आई. एस. अग्रवाल	689 690	2।)		24-2-77
53	"	अहमद हुसैन पुत्र फेज-महमद	689	4)		16-7-77
34	"	वालूराम पुत्र गोरूराम कुमावत	746	2)		20-3-77
35	"	नन्दलाल पुत्र भेरुबगस वगैरा	697	1)3		3-9-77
36	"	आई. आर. पी. टी. सोनेल	760	4।।)		2-10-77
37	"	भवानीराम रामदीन वगैरा	726	2)		9-8-78
38	"	नौरतन लाल नगरदास	760	3)		2-9-78
39	"	अब्दुल करीम वगैरा	760	1।)2		10-10-78
40	"	जेठमल पुत्र रामपाल	692	3)		17-11-78
41	"	महावीर आईस एण्ड आयल इन्डस्ट्रीज मकराना	637	।।)		3-3-79
				103)4		

प्राम गुणावती में लीज दी गई जिनकी सूची

क0सं0	नाम ग्राम	लीज धारकों का विवरण	खसरा न0	रकबा	दर्जे जिसमें लीज
1	गुणावती	श्री हरीशचन्द्र पुत्र दौलतराम वगैरा	90	6ll	6-4-73
2	,,	रामरख पुत्र सीताराम महेश्वरी	,,	2ll	,,
3	,,	मोहमद हसन पुत्र अब्दुल रहमान	,,	5	4-9-73
4	,,	अमरूफअली पुत्र गनी अहमद	,,	2ll	18-6-74
5	,,	अब्दुल हमीद, सगीर अहमद वगैरा	,,	1ll	1-10-73
6	,,	शान्तिस्वरूप पुत्र चुन्नीलाल वगैरा	31	2l	29-5-74
7	,,	इमामुद्दीन घीसा मोहम्मद वगैरा	90	1ll)3	31-11-74
8	,,	शिवचरण पुत्र नारायण माली	,,	2ll	27-1-75
9	,,	रफीक अहमद पुत्र मोहम्मद इस्माईल	25	2ll	12-2-75
10	,,	भंवरलाल पुत्र जैनारायण सोनी मकराना	90	1ll	22-2-75
11	,,	प्यार मो0 पुत्र दाऊद वगैरा	90	3ll	,,
12	,,	अब्दुल हकीम अब्दुल गफ्फार	,,	3ll	,,
13	,,	गफ्फार मो0, मो याकूब वगैरा	26	2l	2-9-78
14	,,	कान्तीचन्द्र पुत्र किशनलाल	20	1ll	,,
15	,,	राधाकिशन, श्री किशन वगैरा	90	1l	25-11-78
16	,,	सुमेरसिंह गणपतसिंह वगैरा	102	ll	13-2-79
		योग		40lll)3	

ग्राम कोरावड़ में लीज दी गई की सूची

क्र0सं0	नाम ग्राम	लीज धारकों का विवरण	स0न0	रकबा	वर्ष जिसमें लीज आवंटन हुई	वि. वि.
1	बोरावड़	श्री गणपतलाल पुत्र मांगीलाल ओमदास	349	2||	1966	20-4-66
2	,,	श्री गोविन्दराम मालचन्द गेंद ओसवाल	,,	2||	,,	21-5-66
3	,,	जसकरण किशनाराम पुत्र बोदुराम अग्रवाल एण्ड सुनील कुमार गोरीशंकर	335|1	2||	,,	13-1066
4	,,	भंवरलाल रामदयाल मालपानी कुचामन	331	2||	1967	20-12-67
5	,,	ताराचन्द पुत्र वंशीधर अग्रवाल बोरावड़	,,	6)4		14-10-69
6	,,	गोविन्दराम पुत्र मालचन्द	349	2||		17-11-71
7	,,	सुशीलकुमार पुत्र गोरी शंकर अग्रवाल	335|1	2||		,,
8	,,	रामप्रसाद पुत्र हनुमानप्रसाद	335	2||		,,
9	,,	कासम अली पुत्र काबुलजी चांदमो0 पुत्र अब्दुल सबाउद्दीन बोरावड़	335|1	2||		,,
10	,,	चमनलाल पुत्र मोहनलाल शर्मा मकराना	331	2||		,,
11	,,	कन्हैयालाल पुत्र रूघनाथ माली छोटुराम पुत्र कानागूजर मकराना	327	2||		,,
12	,,	वंकटलाल पुत्र चांदमल बोरावड़	331	2||		,,
13	,,	मांगीलाल पुत्र हरकचन्द ,,	348|1	2||		,,
14	,,	रूपचन्द पुत्र मिश्रीलाल	331	2||		25-5-72
15	,,	श्रवणकुमार रामस्वरूप वगैरा	349	2||		,,

1	2	3	4	5	6
16	बोरावड	चम्पालाल पुत्र नोरतनमलचोरड़िया	331	2ıı	22–5–72
17	,,	छीतर. गनी, छोटू, वगैरा मि0 पिण्डरूजी तेली हरनावा	,,	2ıı	,,
18	,,	जवरीलाल, बोदूलाल छाजेड़ वगैरा मेसर्स चांदमल हस्तीमल मेहता बोरावड़	464/374	2ıı	23-5-72
19	,,	रामानन्द पुत्र चतुरभुज वगैरा	335	2ıı	28-9-72
20	,,	भंवरलाल पुत्र रामदीन जागीड़	327	2ıı	18-12-72
21	,,	अब्दुल सत्तार पुत्र अमरुद्दीन	464/374	1ııı	4-5-73
22	,,	लिछमणराम पुत्र चुनीलाल माली	464/374	2ıı	,,
23	,,	यूसुफ पुत्र हाजी मो. इब्राहीम गेमावत	329	2ıı	18-6-73
24	,,	रामकरण, भंवरलाल वगैरा	327	1ıı	11-9-73
25	,,	संतोषी देवी पत्नी भिवराम शर्मा	464/374	1ıı	
26	,,	मैसर्स महावीर मारबल इन्डस्ट्रीज	326	2ıı	8-1-74
27	,,	हुक्मीचन्द पुत्र लालचन्द महेश्वरी बोरावड़	375/1	2ıı	6-3-74
28	,,	ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप वगैरा	329	2	22-4-74
29	,,	रोशनमल पुत्र शक्तीमल माथुर	326	1ıı	9-7-74
30	,,	श्री गोपाल पुत्र मदनलाल महेश्वरी	349	3	21-1-75
31	,,	गुलाबचन्द पुत्र छीतरमल जाजू	327	1ıı	,,
32	,,	राधाकिशन पुत्र नथमल कावट	331	2ı	7-5-75
33	,,	हस्तीमल पुखराज वगैरा	326	2	3-2-76
34	,,	ओमप्रकाश पुत्र बालकिशन बंसल	320/3	5	17-2-76

1	2	3	4	5	6
35	बोरावड़	नेमीचन्द पुत्र पारसमल गिलड़ा	372/ 373	2॥)2	21-2-76
36	,,	गणपतलाल पुत्र मांगीलाल बगैरा जैन	372	2॥	6-2-76, 21-2-76
37	,,	सूरज परिहार मैसर्स ऐसोसियेटेड मार्बल	372	3	20-1-76 (रद्द)
38	,,	उम्मेदसिंह पुत्र पकिरमल जाट	372	3	16-11:76
39	,,	रूपाराम पुत्र भगादाराम जाट	330	2॥	21-5-76
40	,,	शफी मोहम्मद वगैरा	335, 335	1	,,
41	,,	मांगीलाल पुत्र कानाराम जाट	330	2॥	,,
42	,,	सीताराम पुत्र रामानन्द वगैरा सोमानी	335	2	,,
43	,,	बंकटलाल पुत्र चतरभुज वगैरा	344	2	,,
44	,,	नरेन्द्रकुमार पुत्र नोरतमल मेहता	335	2	6-12-76
45	,,	चैनसुखक पुत्र नन्दकिशोर वगैरा	326	2)4	13-1-77
46	,,	शंभू मार्बल (रामेश्वरलाल)	374	2	6112-76
47	,,	इकरामुद्दीन वगैरा मदीना मार्बल	335	1)2	19-7-77
48	,,	रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान अग्रवाल	335	1॥	,,
49	,,	मोहम्मद पुत्र फरीद शोरगर	335	॥।)3	,,
50	,,	चांदमल पुत्र बद्रीनारायण वगैरा	372	1	22-7-77
51	,,	भीवराज मांगीलाल वगैरा	326	2)1	3-9177
52	,,	मूलचन्द पुत्र भीवराज गुणावत	331	1)2	,,
53	,,	विमला देवी वगैरा	326	1)	,,
54	,,	छगनलाल पुत्र रुघनाथ मालपानी	335	3	,,
55	,,	प्रकाशचन्द्र वगैर	375/ 1	2॥।	,,

(240)

1	2	3	3	5	6
56	बोरावड़	रूपचन्द पुत्र मिश्रीलाल भंडारी	331	II	3-9-77
57	,,	बिली फीवर पुत्र नवरतनमल मेहता	335	2	13-9-77
58	,,	मोहनाराम पुत्र सुजाराम वगैरा	326	III)4	1-9-78
59	,,	लिक्ष्मण पुत्र रामनाथ वगैरा	331	3)4	8-9-78
60	,,	पारीक मार्बल	363	2II	11-9-78
61	,,	हिमतसिंह पुत्र भंवरलाल राजपुरोहित	346	2	,,
62	,,	मोहम्मद पुत्र मुश्ताक सिसोदिया	327	1II	,,
63.	,,	सत्यनारायण बालकिशन वगैरा जाजू	335	1II	15-9-78
64.	,,	उम्मेदचन्द पुत्र रतनचन्द वगैरा	331I3	2I)2II	,,
65.	,,	मेहता ब्रदर्स मकराना	327	1II	15-9-80
66.	,,	एस.एम. सादिक शेख	327	1)2	10-11-80
67.	,,	हीराराम पुत्र नानूराम वगैरा	333	2II	13-11-78
68.	,,	शिवराम पुत्र नारायण माली मैसर्स संजय मार्बल इ. मकराना	374	3	6-12-76
69	,,	मेजर भागीरथ सिंह पुत्र गिरधारीलाल पलाड़ा तह. नावां	335II	2II)4	13-5-77
70	,,	श्रीमती जानकी देवी पत्नी रामाकृष्ण गोयल मकराना	464I374	1IIII)	7-9-77
71	,,	नेमीचन्द पुत्र बालचन्द	333)3	1III	17-11-78
72	,,	सुगनाराम पुत्र सुखाराम	334	2II	23-11-78
73	,,	केलाराम पुत्र रामाराम वगैरा	323	2II	4-12-78
74	,,	जयनारायण पुत्र बम्सूजी माली	312	2II	15-12-78
75	,,	रामेश्वरलाल पुत्र कानाराम वगैरा	374	1	7-12-78
76	,,	सुरेशचन्द उत्तमचन्द वगैरा	327	2II	26-12-78
77	,,	ताराचन्द पुत्र बनवारीलाल	331	III)1	6-1-79
78	,,	मोहनाराम पुत्र कानाराम वगैरा	327	2	16-1-79

Page No. 241

1	2	3	4	5	6
79	बोरावड़	मोतीलाल रामलाल वगैरा	349।1	।।	15-1-79
80	"	रतनलाल पुत्र नारायणलाल माली	374	1।।	30-12-78
81	"	रामकल्याण पुत्र बन्शीधर	331	1।।	30-12-78
82	"	मुबारक हसन पुत्र मुराद वगैरा कोहेनूर एम्पोरियम मार्बल	335।2	2।।	13-12-78
83	"	मोहनलाल पुत्र किशोरीमल	331	1।।।)1	30-12-78
84	"	मोहनलाल लूणाराम वगैरा	327।3	1।।)1	13-2-79
		कुल	183)½		

242

औद्योगिक क्षेत्र हेतु विचाराधीन मामलों की सूची

क्र.सं.	आवेदक का विवरण	विचाराधीन का कारण
1	अपसरा मार्बल मकराना	उद्योग केन्द्र नागौर से औद्योगिक क्षेत्र के बारे में सूचना न आने से
2	श्री माणकचन्द रान्दड़ मकराना	ना. तह. मकराना से प्रतिवेदन प्राप्त न होने से
3	" पाण्डे मार्बल इण्ड. मकराना	संयुक्त निदेशक उद्योग केन्द्र से प्रतिवेदन प्राप्त न होने से
4	न्यू पाण्डे मार्बल उद्योग मकराना	" "
5	संतबाबा उदयसिंह मकराना	प्रार्थी द्वारा आवासीय भवन बिना अनुमति बनाये। कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन परिवर्तन शहरी क्षेत्र नियम, 1978 के तहत निर्णीत किया जाना है लेकिन जोन्स राज्य सरकार द्वारा नहीं बनाये जाने से पेंडिंग है।
6.	अब्दुल सत्तार शोकत अली सा. मकराना	गै. मुमकिन रास्ता होने से धारा 91 आर. एल. एक्ट के तहत कार्यवाही चल रही है।
7	मै. संग मार्बल फैक्टरी प्रा. लि. जयपुर	तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन मंगवाया जा रहा है
8	मै. भावना स्टोन जयपुर	" "
9	श्री रामप्रसाद काबरा मकराना	1 " " 2 उद्योग विभाग का एन.ओ.सी. प्राप्त न होने से
10	मै. विष्णु मार्बल इण्ड. परबतसर	तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन न आने से
11	श्री रामदीन सा. मकराना	" "
12	" अंशाकुमारी सा. नावां	" "
13	श्री राधेश्याम सा. नावां	" "
14	" श्याम सुन्दर सा. मकराना	" "
15	" किशन गहलोत सा. मकराना	" "
16	" गौरीशंकर सा. मकराना	" "

1	2	3
17	श्री देव संगमरमर उद्योग	सहकाश्त कारान की सहमति प्राप्त न होने
18	,, प्यारा मोहम्मद सा. मकराना	से राज्य सरकार से रेट्स निर्धारित न होने से
19	,, हनुमान मार्बल इन्ड. मकराना	उद्योग विभाग से एन.ओ.सी. न आने से राज्य सरकार से मार्ग दर्शन सरकारी भूमि
20	,, शमसुदीन s/0 ईदु रोशन अली-तेली सा. बोरावड़	शामिल होने से चाहे गये हैं।
21	श्री हाजी नूर मोहम्मद सा. मकराना	तहसीलदार से कमी पूर्ति हेतु उद्योग विभाग से एन.ओ.सी. न आने से उप खण्ड अधिकारी से जांच रिपोर्ट न आने से
22	अग्रसेन इण्ड बोरावड़	
23	श्री जुमा लुहार सा. मकराना	
24	न्यू इण्डिया मार्बल मकराना	तहसील से कमी पूर्ति करवाई जा रही है
25	श्री शोकत अली चौधरी मकराना	प्रार्थी से जवाब न आने से
26	श्री अहमद कायमखानी मकराना	तहसील से कमी पूर्ति करवाई जा रही है
27	,, मांगीलाल बोरावड़	,, ,,
28	,, बैंकटलाल मोर बोरावड़	,, ,,
29	,, नन्दकिशोर ,,	,, ,,
30	,, मोहम्मद इस्माईल सिलावट मकराना	,, ,,
31	,, गुलाब लौहार सा. मकराना	,, ,,
32	,, शेखफरीद टांक मकराना	,, ,,
33	,, माऊदीन रोदड़ मकराना	उप खण्ड अ. से प्रतिवेदन न आने से
34	,, मोमद उस्मान सा. मकराना	तहसीलदार से प्रतिवेदन न आने से
35	,, रमेशशरण मकराना	,, ,,
36	,, आनन्द मार्बल एण्ड बोरावड़	,, ,,
37	,, अहमद बख्श राठोड़ मकराना	,, ,,
38	,, सुशीलकुमार अग्रवाल	,, ,,
39	,, ओमप्रकाश बोरावड़	,, ,,
40	,, खत्री मार्बल इण्ड. मकराना	,, ,,

1	2	3
41	श्री उसमान भाटी मकराना	उद्योग विभाग से एन. ओ. सी. न आने से
42	,, जेठाराम जाट बोरावड़	प्रार्थी का जवाब न आने से
43	,, हनुमानसिंह राजावत	(1) क्रमांक 43 से 91 व 94 में राजस्व
44	वंकटेश मार्बल एण्ड बोरावड़	ग्रुप-4 विभाग जयपुर से 12
45	श्री हाफिज हाजी मकराना	(32) राज/75/9416 दि. 20-12-76
46	,, जय भारत इण्ड. बोरावड़	व 8086 दि. 2-11-76 तथा 65
47	श्री नैनू उसमान मकराना	दिनांक 15-2-76 से मार्ग दर्शन
48	सनराइज मार्बल मकराना	चाहा गया जो प्राप्त न होने से कार्यवाही
49	श्री अलानूर निवासी मकराना	रुकी पड़ी है।
50	,, गुलाब हुसैन मकराना	(2) नगर नियोजक जोधपुर द्वारा
51	,, गंगाधर मकराना	मकराना का मास्टर प्लान अभी तक
52	,, रतनलाल मकराना	तैयार नहीं किया है इससे अनाधिकृत
53	,, मोहम्मद अयूब मकराना	रूप से की गई फैक्ट्रियों की पत्रावलियों
54	,, हनुमान राय मकराना	में कार्यवाही रुकी पड़ी है।
55	,, नथमल मकराना	
56	,, हाजी मोहम्मद मकराना	
57	,, मोहम्मद हनीफ मकराना	
58	,, राम मिनरल्स मकराना	
59	,, फरीदबक्स ,	
60	,, मोडूराम मकराना	
61	,, बिलाल सिसोदिया मकराना	
62	,, फजलू सुभान मकराना	राजकीय भूमि
63	,, कमरूद्दीन	,,
64	,, हरीभाई मकराना	,,
65	,, इस्माईल	
66	,, रहमतुल्ला मकराना	
67	,, फरीद मकराना	
68	,, हाजी दोस्म मकराना	

1	2	3
69	श्री अब्दुल कयूम मकराना	
70	,, शोकत अली मकराना	जी लेन्ड (राजकीय भूमि)
71	,, रहीम बक्स मकराना	,,
72	,, कन्हैयालाल मकराना	जी.एल./एस.सी.(राजकीय व अनु. जाति की भूमि)
73	,, अब्दुल हनीफ मकराना	एस.सी. (अनु. जाति की भूमि)
74	,, सारज मारबल क. मकराना	,,
75	,, शोकत अली भाटी मकराना	,,
76	,, इस्माईल रोदड़ मकराना	,,
77	,, फरीदबक्स मकराना	,,
78	,, कादर रोदड़ मकराना	,,
79	,, गफ्फार लोहार	,,
80	,, अलानूर मकराना	जी.एस./एस.सी.(राजकीय व अनु. जाति की भूमि)
81	,, कुसम मार्बल मकराना	एस.सी. (अनु. जाति की भूमि)
82	,, गोविन्दराम स्वामी मकराना	,,
83	,, बंशी मकराना	,,
84	,, अब्दुल रजाक मकराना	,,
85	,, नवाब अली मकराना	,,
86	,, शोकत अली मकराना	,,
87	,, फकीर मोहम्मद मकराना	,,
88	,, शुभमारबल इण्ड. मकराना	जी एल सरकारी भूमि
89	,, जुम्मा चौधरी मकराना	,,
90	,, अब्दुल सत्तार मकराना	,,
91	,, उसमान भाटी मकराना	,,
92	श्री बिलाल लोहार मकराना	कमी पूर्ति तहसील से करवाई जा रही है
93	" मोहम्मद रमजान मकराना	,,
94	श्री हाजी दोला मकराना	—
95	" अब्दुल रशीद मकराना	तहसील से सूचना चाही जा रही है।

सेवा सदन ट्रस्ट भीलवाड़ा के अन्तर्गत चलने वाली संस्थायें

382. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सेवा सदन ट्रस्ट भीलवाड़ा के अन्तर्गत कौन कौन सी संस्थाएं चलती हैं ?

(2) सेवा सदन ट्रस्ट की कितनी चल और अचल सम्पत्ति है ?

(3) क्या यह सही है कि महिला आश्रम भीलवाड़ा तथा पावरहाउस के बीच की 3 बीघा भूमि श्री काशीनाथ जी भदादा ने श्री हुकमचन्द जी सुराणा के लिये दी थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अब सेवासदन का कब्जा है ? अगर है, तो राज्य सरकार इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) वह ट्रस्ट (सेवा सदन) राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास नहीं है। अतः अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(2) पंजीकृत प्रन्यास न होने के कारण सम्पत्ति का लेखा विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

राजस्थान नहर परियोजना में पाइपों की खरीद

382. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी-पार्क) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 78 में राजस्थान नहर परियोजना में पाइप की खरीद की गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये की और इनके खरीदने का उद्देश्य क्या था ?

(2) उक्त पाइप की खरीद के लिये किस किस फर्म के टेन्डर किस तिथि को खोले गये और कब इनकी स्वीकृति के आदेश दिये गये ? तिथि बताने की कृपा करें।

(3) इन पाइपों की सप्लाई किस तिथि को की गई थी और किस तिथि को भुगतान हुआ ?

(4) परियोजना में कितने पाइपों का इस्तेमाल हो चुका है और कितना पाइप अभी तक बच गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। पाइपों की खरीद की गई थी। उनका मूल्य रुपया 7459921-18 था। इनके खरीदने का उद्देश्य यह था कि राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण के वित्तीय निर्माण में उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उचित व्यवस्था

(राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री)

की जा सके ताकि नहर शाखाओं व वितरिकाओं का निर्माण कार्य सुचारु रूप से चलाया जा सके।

(2) निम्न फर्मों के टेन्डर दिनांक 10-3-78 को खोले गये :—

1) मै. हिन्दुस्तान स्टील्स लि. कलकत्ता।

2) मै. अजन्ता ट्यूब लि. नई दिल्ली।

3) मै. जैन ट्यूब कम्पनी लि. नई दिल्ली।

4) मै. जिन्दल पाईप्स प्राइवेट लि. नई दिल्ली।

5) मै. कलिंगा ट्यूब कम्पनी कलकत्ता।

6) मै. इन्डियन ट्यूब लि. नई दिल्ली।

7) मै. हरयाणा ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लि. हिसार।

8) मै. इन्डिया स्टील डेवलपमेंट कम्पनी कलकत्ता।

9) मै. भारत स्टील ट्यूब लि. नई दिल्ली।

10) मै. हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग वर्कस हिसार।

11) मै. मनोज एण्टर प्राइज नई दिल्ली।

12) मै. मनोहर ट्रेडिंग कार्पोरेशन लुधियाना।

13) मै. इसको स्टेशन पाइप एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी लि. नई दिल्ली।

14) मै. आर.सी. कोमल एण्ड सन्स कलकत्ता।

15) मै. जीतेन्द्र स्टील एण्ड ट्यूब लि. नई दिल्ली।

पाइपों की खरीद की स्वीकृति स्टोर पर्चेज कमेटी की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 21/3/78 को दी गई।

(3) स्वीकृति निविदा की शर्तों के अनुसार 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान दिनांक 31/3/78 को किया गया था कुछ रकम का भुगतान दिनांक 23/8/78 को किया गया था। शेष अभी करना है। इन पाइपों की सप्लाई अप्रेल, 78 के प्रथम सप्ताह में प्रारम्भ होकर अधिकांश सप्लाई माह मई, 78 में हो गई थी। परन्तु कुछ पाइप माह सितम्बर, 78 में प्राप्त हुये।

(4) अधिकांश पाइप (58,896 मी.) द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों के लिये जल वितरण व्यवस्था हेतु काम में लगाये जा रहे हैं। 5766 मीटर लम्बाई के पाइप को साइट पर ले जाया जा रहा है व अप्रेल-मई तक इनका भी उपयोग कर लिया जावेगा।

सूरतगढ़ चिकित्सालय में क्षय रोग के रोगियों के लिए अलग वार्ड

384. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

(1) सूरतगढ़, अनूपगढ़ व श्री विजय-नगर चिकित्सालयों में गत वर्षों में क्षय रोग से ग्रस्त कितने मरीज आये ?

(2) क्या इस संख्या को देखते हुए राज्य सरकार सूरतगढ़ चिकित्सालय में क्षय-रोग के लिये अलग से वार्ड बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़, अनूपगढ़ व श्री विजय-नगर चिकित्सालयों में गत वर्षों में क्रमश: 583.95 व 57 क्षय रोग से ग्रस्त मरीज आये।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय क्षय निवारण योजना के अन्तर्गत केवल जिला मुख्यालय स्थित अस्पतालों में ही क्षय रोग के वार्डों के बनाने की व्यवस्था की जाती है।

जयपुर जिले में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधा में वृद्धि

385. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिस अनुपात में जयपुर जिले की आबादी में वृद्धि हुई है उस अनुपात में चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि नहीं हो सकी है ?

(2) राज्य सरकार उक्त जिले के प्रत्येक पचायत क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा कब तक पहुंचा देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अक्टूबर, 1979 तक जयपुर जिले की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

राज्य में फिल्म स्टूडियो बनाने की योजना

387. श्री ईश्वर चन्द्र (पिडावा) क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में फिल्म स्टूडियो के निर्माण की कोई योजना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने फिल्म अभिनेता राजकपूर को इस बारे में भूमि निशुल्क देने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(3) क्या राज्य सरकार स्वयं के स्टूडियो निर्माण की योजना पर विचार कर रही है ताकि उसे किराये पर दिया जा सके ? यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(जन सम्पर्क मन्त्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-2-79)

हिन्द-पाक युद्ध के दौरान भारत आये शरणार्थी

15. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1971 में हिन्द-पाक युद्ध के दौरान आये हुए शरणार्थियों को बसाने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की मदद से क्या योजना बनाई है ? योजना की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर सन् 1971 से हिन्द-पाक युद्ध के शुरू होने से दिसम्बर सन् 1972 तक पाक से आये हुए व्यक्तियों को राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने शरणार्थी माना और उन्हें नियमों एवं कानून के अन्तर्गत केन्द्र से सुविधायें प्रदान की गई ?

(3) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मणसिंह सोढा एवं उसके साथ 40 परिवार जो कि सन् 71 के युद्ध के करीब 6 महीने पहले आये थे उन्हें तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने शरणार्थी नहीं माना क्योंकि वे शरणार्थी की परिभाषा में नहीं आते थे ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य की वर्तमान सरकार ने कुछ अधिकारियों द्वारा उनके बारे में गलत सूचना भेजने के कारण उन्हें शरणार्थी मान कर वैसा ही लाभ देना शुरू कर दिया है और उन्हें बसाने के लिये भी वही लाभ दिया है और दिया जा रहा है जो कि सन् 71 के पाक युद्ध से आये हुए शरणार्थियों को दिया गया है और दिया जा रहा है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त गलत कार्यवाही को रद्द करके दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) 5,600 परिवारों की योजना स्वीकृत हो चुकी है। प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ?

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(250)

Sub :—Scheme and the Scales of rehabilitation assistance for the settlement of 5600 families of Indo-Pak Conflict 1971 in the Districts of Barmer, Jaisalmer and Jalore in Rajasthan.

The scales of rehabilitation assistance to be given are indicated below :

1. **Land Allotment :**

Each displaced person family will be allotted land.

2. **Milch Cows/Sheep And Ram :—**

In addition to the allotment of land each family will be given 3 Milch cows or 30 sheep and one Ram to enable them to have supplementary income so as to make their occupation on agriculture and cattle breeding a viable unit. A maximum of Rs. 4000/– per family will be given in the form of loan. Before considering applications for the grant of loan, the State Government would ascertain the number of animals already available with the dp family and the financial assistance will be restricted to the extent necessary to augment their existing stock of animals so as to make up the shortfall in the strength of livestocks.

3. **Transportation Charges :—**

Each family will be given a flat rate of Rs. 10/- for moving from the camps to the rehabilitation sites.

4. **Journey Allowance :—**

Journey allowance will be admissible @ Rs. 2/- per person for reaching the rehabilitation site.

5. **Maintenauce Assistance :**

This will be for a period of 6 months. The State Government will declare in advance the date from which the agricultural season

in case of any group of displaced persons should be deemed to begin. This period should normally be reckoned from the month prior to the date of actul sowing, so as to include the period necessary for preparing the land for sowing. The scale of maintenance assistance will be the same as admissible to the displaced persons in the camps and the amount involved will be treated as grant. The expenditure on this account should not, however, exceed Rs. 150/- per family per month.

6. Construction of Jhompas :—

a) Grant : The dps families will be given a grant of Rs. 950/- for the construction of Jhompa.

b) Loan : In addition to the grant of Rs. 950/- each dp family will be advanced a sum of Rs. 550/- as loan for completing the construction of the Jhompas.

7. Fodder :—

A sum of Rs. 100/- in the form of loan will be given to each family for the purchase of fodder.

8. Purohase of Camel/Bullocks :

Each family will be given a maximum loan of Rs. 2500/- for the purchase of camel or bullocks for agricultural purpose. For this purpose also the State Govt. would take necessary census with regard to the bullocks camel already available with the dp families and loans will be advanced to them in case the animal is not already available with them.

9. Land Reclamation :

A loan of Rs. 1000/- per family will be given for land reclamation.

10. Seeds, Fertilisers, Inputs

Rs. 1000/- per family in the form of loan.

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 1-3-79)

वन विभाग की जमीन के नियमन का मामला

60. श्री हीरालाल आर्य (पिपल्दा) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि अभी वन विभाग की खसरा नं. 227, 228 तथा 230 की भूमि करीब 500 बीघा पर सीनोता ग्राम नायब तहसील इन्द्रगढ़ के गरीब अक्सर अनुसूचित जाति के लोग 10-15 साल से फसल करते आ रहे हैं, जिससे इनका निर्वाह हो रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग वाले उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर रहे हैं जो कि अनुचित है ?

(6) क्या राज्य सरकार इन गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर रहम कर इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उक्त भूमि को वन विभाग से मुक्त कर राजस्व में परिवर्तन कर वर्षों से ट्रेसपासर इन गरीब व्यक्तियों के नाम नियमन करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) सीनोता ग्राम के खसरा नं. 227 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। राजस्व रेकार्ड के आधार पर खसरा नं. 228 व 230 के कुछ भाग पर अतिक्रमण हुआ है जिस पर वन विभाग के आधिपत्य की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) वन विभाग से राजस्व विभाग में परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि अतिक्रमियों का कब्जा वन विभाग की भूमि पर इतना पुराना है कि वो नियमन किया जा सकता है तो नियमन किया जावेगा अन्यथा नहीं।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 7-3-79)

नगरपालिका क्षेत्र सागवाड़ा में अलाट की गई भूमि

187. श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि श्री भीखा भाई भूतपूर्व मन्त्री ने स्वयं के नाम या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में नेहरू पार्क के पास कोई भूमि भूतपूर्व शासन के समय ली थी ?

(2) यदि हां, तो इसका क्या क्षेत्रफल है तथा किस कानून के अन्तर्गत ली है या नाजायज कब्जा किया था ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बेरी आयोग के पास यह मामला भेजा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में साबिक खसरा नं.

(श्री लाल शंकर डेंडोर)

4488 की भूमि आबादी में परिवर्तन हुई है ? इस भूमि का क्या क्षेत्रफल था ?

(5) क्या यह सही है इस नम्बर पर होस्पिटल या प्रसूतिगृह का सरकारी भवन निर्माण किया जा चुका है ?

(6) क्या यह सही है कि नम्बर परिवर्तन के पूर्व या बाद में बदला गया है ? यदि हां, तो किस कानून से ? इस अनुचित काम के लिए क्या कार्यवाही की गई है और दोषी अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री भीखाभाई भूतपूर्व मन्त्री के नाम ग्राम सागवाड़ा के गत भू-प्रबन्ध के खसरा नम्बर 3424 रकबा 71) बीघा में से 21)4 (दो बीघा नो बीस्वा) भूमि आदेश क्रमांक 2409 दिनांक 5-12-49 के द्वारा नव तोड स्वीकृत हुई है। इस भूमि का वर्तमान खसरा नं.4488 है।

(2) भूमि का क्षेत्रफल 2बीघा 9बिस्वा किया है श्री भीखा भाई को कृषि प्रयोजन हेतु इसका आवंटन किया गया था। नाजायज कब्जा नहीं किया गया।

(3) यह मामला बेरी आयोग को नहीं भेजा गया।

(4) यह सही नहीं है कि साबिक खसरा नं. 4488 की कोई भूमि आबादी में परिवर्तन हुई है। सही स्थिति यह है कि वर्तमान खसरा नं. 4488 की भूमि आबादी में परिवर्तन हुई है जिसका क्षेत्रफल 1) 1 (एक बीघा एक बिस्वा है।

(5) जी हां, यह सही है कि श्री भीखा भाई को साबिक खसरा नं. 3424 में 2)9 (दो बीघा 9 बिस्वा) भूमि दी गई थी उसमें 1) 8 (एक बीघा आठ बिस्वा) पर प्रसूति गृह का राजकीय भवन बनाया गया है।

(6) भूमि उसी नम्बर की है जिसका आवंटन हुआ था। अतः नम्बर बदलने का पूर्व या बाद का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चौकडी तोपखाना का विकास

360. श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्षाकाल में जयपुर शहर में चौकड़ी तोपखाना हजूरी के पानी से चौ0 घाटगेट चौ0 रामचन्द्रजी प्रभावित होती है ?

(2) यदि हां, तो नगर परिषद इसके बारे में क्या ठोस कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या तोपखाना हजूरी का 3/4 भाग कच्चा है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विकास कब तक किया जावेगा।

(उत्तर)

(1) जी हां।

(2) वर्षा के पानी के निकास के लिये नाला बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) इस कार्य हेतु योजना है।

जैतारण उप खण्ड में जैतारण और निवाज में महाविद्यालय खोलने की मांग

361. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के जैतारण उपखण्ड में जैतारण में और निवाज में महाविद्यालय खोलने की मांग गत कई वर्षों से होती रही है परन्तु राज्य सरकार द्वारा दोनों स्थानों में से एक स्थान किस स्थान को चुना जाये इसका निर्णय लेने में कठिनाई आ रही है ?

(2) क्या जैतारण और निवाज के नागरिकों और विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जाकर निवाज और जैतारण के बीच एक उपयुक्त स्थान को चुना जाय और आवश्यक सभी जन सहयोग की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय तो राज्य सरकार महाविद्यालय खोलने का निर्णय लेने को तैयार है ?

(उत्तर)

(1) ऐसी कोई मांग राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) यू. जी.सी. व केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार अभी निश्चय तौर पर कुछ कहना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न सं. 354 की सूचना

बिन्दु संख्या–1 (000 में)

स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या (वर्ष 1977–78 अनुसार)

शालायें	लड़के	लड़कियां	योग
उच्च माध्यमिक	248	65	312
माध्यमिक	276	85	361
उच्च प्राथमिक	830	256	1086
प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक	1235	360	1595

बिन्दु संख्या :— 2

सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या

	लड़के		लड़कियां		योग	
	सरकारी	गैर सरकारी	सरकारी	गैर सरकारी	सरकारी	गैर सरकारी
उच्च माध्यमिक	188	60	41	24	229	84
माध्यमिक	248	28	64	21	312	49
उच्च प्राथमिक	772	58	120	136	892	194
प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक	160	1075	94	266	254	1341

बिन्दु संख्या :— 3

सरकारी एवम् गैर सरकारी संस्थाओं पर व्यय

शालायें	सरकारी स्कूलों पर व्यय लाखों में	गैर सरकारी स्कूलों पर व्यय (लाखों में)	कुल व्यय
उच्च प्राथमिक एवम् प्राथमिक	3,790-86 —	2,305-57 —	6,096-43 —
माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक	2,842-58	0,229-05	3,071-63

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न सं. 355 का विवरण

कार्यालय नगर पालिका नवलगढ़

परिशिष्ट "क"

विकास कार्य जो सन् 76-77 में तत्कालीन बोर्ड द्वारा करवाये गये

विकास कार्य का नाम	खर्चे की राशि	यदि कार्य अधूरे रहे तो कारण
[illegible] ...पेन्सरी ...ड का निर्माण ...गई 78)	9,739-27	कार्य पूर्ण हो चुके हैं
[illegible]	1,377-97	,,
[illegible]	,117,24	

[illegible] -78 में अप्रेल 77 से नवम्बर 77 तक [illegible] बोर्ड द्वारा करवाये गये

...का नाम	...की राशि	यदि कार्य अधूरे रहे तो कारण
...खुर्रे एवं बांध निर्माण	33,680-59	कार्य पूर्ण हो चुके हैं
... नालियों का निर्माण	17,240-04	,,
3. बावड़ी गेट सीमेन्टेड रोड	12,783-20	,,
4. कल्याण जी के मन्दिर से मालीराम भगेरिया तक डामर रोड का निर्माण	5,186-47	डामर खरीद कर ली गई थी किन्तु इस सड़कों को आगे बढ़ाने के विचार से कोलतार नहीं डलवाया गया
योग	68,890-30	

Page No. 258

258

कार्यालय नगर पालिका नवलगढ़ (राजस्थान)

परिशिष्ट "क"

वर्तमान प्रशासक श्री भंवर सिंह चारण (आर.ए.एस.) एवं अधिशासी अधिकारी श्री रमेश कुमार पारीक द्वारा गत वर्ष में जनवरी 78 से मार्च 78 तक करवाये गये निर्माण कार्यों का ब्यौरा

	विकास कार्य का नाम	खर्चे की राशि	यदि कार्य अधूरे हों तो कारण
1.	मण्डी गेट से जयपुरिया मन्दिर तक गन्दे पानी के निकास हेतु नाले का निर्माण	17,700-03	कार्य [illegible]
2.	बावड़ी गेट के बाहर बालाजी के मन्दिर से कूलवालों की हवेली तक नाली निर्माण	10,156-14	[illegible]
3.	श्री मांगीलाल महन्त के मकान से श्री भजन लाल झुन्झुनूं वाला की हवेली तक नाले का निर्माण	13,536[illegible]	[illegible]
4.	वार्ड नं. 9 में श्री किशना राम रैगर के मकान के पास खुर्रा निर्माण	2252-33	,,
5.	वार्ड नं. 10 में चूना-राम रैगर के मकान के पास खुर्रा निर्माण	1,192-68	,,
6.	श्री भोलाराम चौवदार के मकान से श्री शुभ-राज तेली के मकान तक नाले का निर्माण	17,170-52	,,

विकास कार्य का नाम		खर्चे की राशि	यदि कार्य अधूरे हो तो कारण
7.	सेक्सरिया कन्या पाठ-शाला से सब्जी मण्डी तक सीमेन्टेड रोड का निर्माण	8,004–47	कार्य पूर्ण हो चुका है
8	श्री सीताराम परसरामपरिया की हवेली से श्री हनुमान सुनार [illegible] के सामने तक नाली [illegible]	6,308-10	,,
[illegible]	[illegible] हाउस से [illegible]. स्कूल तक [illegible] का निर्माण [illegible]8)	8,488-95	,,
[illegible]	[illegible] की हवेली से [illegible] तक [illegible]	18,822-79	मेकेडम रोड बन चुकी है कोलतार डलवाया जाना अनुदान की राशि समाप्त होने व पालिका की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण शेष है। अब अनुदान राशि प्राप्त होते ही इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

कार्यालय नगरपालिका नवलगढ़ (राजस्थान)

परिशिष्ट 'स'

नगरपालिका नवलगढ़ में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की सूची

क. सं.	नाम कर्मचारी	पद	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4
1	ईस्माईल	स. क.	10-9-56
2	परसुराम	,,	5-9-56
3	मुरली	,,	[illegible]
4	सीताराम	,,	[illegible]
5	भगवानाराम	,,	[illegible]
6	कालूराम	,,	[illegible]
7	नागर मल	,,	[illegible]
8	श्रीमती मनोरी	,,	[illegible]
9	श्रीमती कौलती	,,	[illegible]
10	श्रीमती पति	[illegible]	[illegible]
11	श्रीमती घापली	[illegible]	[illegible]
12	श्रीमती नरबदी/सोहन	[illegible]	[illegible]
13	श्रीमती चौथली	[illegible]	[illegible]
14	श्रीमती रूकमणी/भंवर	[illegible]	[illegible]
15	श्रीमती किशनी	[illegible]	[illegible]
16	श्रीमती शान्ती	[illegible]	[illegible]
17	श्रीमती भंवरी	[illegible]	[illegible]
18	श्रीमती बसन्ती	[illegible]	[illegible]
18	श्रीमती नानुड़ी	,,	1-4-50
20	श्रीमती मणी	,,	19-9-63
21	श्रीमती कौलती	,,	5-1-68
22	श्रीमती दुर्गी	,,	1-9-70
23	श्रीमती कैसरी	,,	1-6-54
24	श्रीमती सुवटी	,,	28-7-60

1	2	3	4
25	श्रीमती नरबदी/माणक	स.क.	5-9-56
26	श्रीमती परमेश्वरी/सीताराम	,,	1-11-68
27	श्रीमती मोहनी	,,	23-9-56
28	श्रीमती बनारसी	,,	5-1-68
29	श्रीमती चीनकी	,,	1-11-70
30	श्रीमती पानी	,,	1-11-70
31	श्रीमती छोटी	,,	1-11.70
32	श्रीमती गीता/ओमप्रकाश	,,	1-4-75
33	श्रीमती गीता/मदन	,,	28-7-77
34	श्रीमती रूकमणी/भागीरथ	,,	1-9-56
35	श्रीमती लक्ष्मी	,,	1-4-75
36	श्रीमती गोदावरी	,,	1-4-75
37	श्रीमती तरबीणी	,,	1-4-75
38	श्रीमती यशोदा	,,	1-4-75
36	श्री लालाराम	,,	1-11-74
40	श्री बोदूराम	,,	1-9-70
41	श्री राधेश्याम	,,	1-11-72
42	श्री मानाराम	,,	1-11-70
43	श्री गोरूराम	,,	5-1-68
44	श्री बक्सा राम	,,	1-9-70
45	श्री रामलाल	,,	1-7-53
56	श्री राजू/गौरीशंकर	,,	1-4-75
47	श्री रामदेव	,,	1-11-70
48	श्री बोदूराम पुत्र गोकल	,,	1-2-76
49	श्री जयप्रकाश	,,	1-2-76
50	श्रीमती बिदामी	,,	1-2-76
51	श्रीमती दाखली	,,	1-2-76
52	श्रीमती गीता/सन्तु	,,	1-10-76

"

1	2	3	4
53	श्रीमती रतनी	स.क.	1-5-76
54	श्री गिरधारी	,,	28-7-77
55	श्री किशनलाल	,,	28-7-77
56	श्री फूलाराम	,,	28-7-77
57	श्री ग्यारसीलाल	,,	28-7-77
58	श्री कादर	,,	28-7-77
59	श्री मुन्नाराम	,,	28-7-77
60	श्री राजू/मोहन	,,	28-7-77
61	श्री हरिराम	,,	28-7-77
62	श्री रतनलाल	,,	28-7-77
63	श्री राजू/बैजनाथ	,,	28-7-77
64	श्रीमती भंवरी/गुलजारी	,,	28-7-77
65	श्रीमती गिन्नी	,,	28-7-77
66	श्रीमती मैना	,,	28-7-77
67	श्रीमती विमला	,,	28-7-77
68	श्रीमती नार्रासिंह	,,	1-2-76
69	श्रीमती परमेश्वरी/भगवाना	,,	1-2-76

कार्यालय नगरपालिका नवलगढ़

परिशिष्ट 'घ'

नगरपालिका नवलगढ़ की वर्ष 77-78 की वास्तविक आय एवं व्यय तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का विवरण—

आय		व्यय	
राशि	मद	राशि	मद
3,06,387-27	नगरपालिका की आवर्तक आय	5,96,574-25	नगरपालिका का आवर्तक व्यय
2,51,223-51	नगरपालिका की अनावर्तक आय	53,117-73	नगरपालिका का अनावर्तक व्यय
1,59,390-00	राज्य सरकार से प्राप्त सामान्य अनुदान	1,72,007-12	निर्माण विकास कार्य पर व्यय
1,00,000-00	राज्यसरकार से प्राप्त विकास कार्यों के लिए अनुदान		

परिशिष्ट-19 मार्च, 1979-परिशिष्ट

264

TOTAL EXPENDITURE INCURRED IN THE STATE (DISTRICT WISE) DURING SESSION 1978-79 FOR IMPROVEMENT OF HIGHER EDUCATION

S. No.	Name of District	Subject	Amount sanctioned	Population in lacks.	प्रति व्यक्ति व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	Ganganagar (Suratgarh)	English (P. G. Level) IInd Yr. TDC.	2.14	13-94	0-15
2.	Bharatpur (Deeg)	Pol. Sc. (PG Level) History (PG Level Home Sc. (Degree level) Labour Law IInd Yr. TDC	3.27	14.90	0.22
3.	Kota	Geography (PG Level	0,52	11.44	0.05
4.	AJMER (Kishangarh)	M.A. Final i) Hindi ii) History Drawing & Painting (PG lavel)			

1	2	3	4	5	6
	(Nasirabad)	1/Sanskrit (Degree level)	3.63	11.47	0.32
	(Ajmer)	Diploma in Labour law.			
	(Kekri)	IInd Yr. TDC			
	(Beawar)	Sanskrit (M.A. Final)			
5.	Bikaner	1) Sociology PG Level	0.22	5.73	.04
6.	Chittorgarh	1 Sanskrit (Degree Level) History Sociology (M.A. Final	2.70	9.45	0.29
	(Nimbahera)	IInd Yr. T.D.C.			
7.	Nagaur	1 Steno Typist (Degree Level) 1 Economics 2 Accountancy Bus. Statistics	1.09	12.62	0.09
8.	Sawai Madhopur	1 Urdu (Degree Lavel)			
	(Karauli)	1 Bus. Admn. 2 Pol. Sc. (M.A. Final)	4.46	11.95	0.38

1	2	3	4	5	6
	(Gangapur)	IInd Yr. T. D. C.)			
	(Hindaun City)	IInd Yr. TDC)			
9.	Sirohi	1 Sanskrit) 2 Steno Typist) (Degree Level) 1 Hindi) 2 History) (M.A. Final) IInd Yr.) T. D. C.)	3.07	4.24	0.72
10.	Sikar (Neem ka Thana)	1 Sanskrit) 1 E.A. & F.M.) 2 Accountancy&) Statistics) (M.A. Final)	0.94	10.45	0.09
11.	Alwar (Behror)	1 Labour Law) 1 English) 2 Sanskrit) (M.A. Final) IInd Yr.) T. D. C.)	2.73	13.91	0.20
12.	Tonk (Deoli)	1 Economics) 2 Urdu) (M.A. Final) IInd Yr. TDC)	2.48	6.26	0.40
13.	Bundi	1 Pol. Sc.) 2 Accountency) Bus. & Statistics) (M.A. Final)	0.72	4.49	0.16

1	2	3	4	5	6
14.	Jhalawar	Economics Administration (M.Com.) Final	0.72	6.22	0.12
15.	Pali	Economics Administration(M.Com.) Final	0.72	9.70	0.07
16.	Jaipur (Kotputli)	1 Accountancy & Bus. Statistics 2 Pol. Sc. (M.A. Final)	.96	24.82	0.20
	(Dausa)	1 Accountancy & Statistics (M.Com.Final) 2 Pol. Sc. (M.A. Final)			
	(Shahpura)	IInd Yr. T. D. C.			
	(Bandilmi)	IInd Yr. T. D. C.			
17.	Badmer	1 Accountancy & Statistics (M. Com. Final) 2 History (M.A. Final)	0.72	7.75	0.09
18.	Udaipur	1 Hindi 2 Music (M.A. Final)	0.72	18.04	0.04
19.	Dungarpur	Political Sc. (M.A. Final)	0.72	5.30	0.13

1	2	3	4	5	6
		E.A. & F.M.) (M.Com. Final)			
20.	Banswara	Bus. Admn.) (M. Com.) Final)) Sociology) M. A. Final)	0.72	6.54	0.11
21.	Churu	History) Pol. Sc.) (M.A. Final)	0.72	8.74	0.08
22.	Bhilwara	Geography) (M.A. Final)	0.52	10.55	0.05

Primary & Sec. Ed.

जिले वार संभावित व्यय 1978-79 का विवरण पत्र

बजट प्रावधान कुल व्यय मय विकास

क्र. सं.	जिले का नाम	राशि रु. (लाखों में)
1	सीकर	187.00
2	अजमेर	394.00
3	नागौर	262.00
4	जोधपुर	333.00
5	बांसवाड़ा	152.00
6	बीकानेर	277.00
7	गंगानगर	282.00
8	जालौर	50.00
9	चूरू	223.00
10	जैसलमेर	45.00
11	भीलवाड़ा	162.00
12	झालावाड़	134.00
13	भरतपुर	416.00
14	सवाई माधोपुर	272.00
15	उदयपुर	537.00
16	अलवर	337.00
17	डूंगरपुर	115 00
18	झुंझूनूं	263.00
19	जयपुर	678.00
20	सिरोही	107.00
21	बून्दी	121.00
22	पाली	330.00
23	बाड़मेर	103.00
24	टौंक	162.00
25	कोटा	284.00
26	चित्तौड़	192.79
		6418.79
	पंचायत समितियों से सम्बन्धित राशि	1892.13
	योग	8310.92

Technical Education

जिले की जनसंख्या के अनुपात में प्रति व्यक्ति खर्चा

अजमेर	रु0	4,31,831-07	0-36	रु0 प्रति व्यक्ति
अलवर	रु0	28,219-32	0-02	,,
भरतपुर	रु0	34,563-05	0-02	,,
भीलवाड़ा	रु0	7,908-64	0-07	,,
गंगानगर	रु0	9,626-26	0-06	,,
जयपुर	रु0	3,94,248-02	0-11	,,
जोधपुर	रु0	4,70,810-73	0-40	,,
खेतड़ी (झुन्झुनू)	रु0	10,928-12	0-01	,,
कोटा	रु0	3,31,266-51	0-28	,,
नागौर	रु0	40,271-86	0-03	,,
पाली	रु0	39,709-23	0-04	,,
सीकर	रु0	17,006-12	0-01	,,
उदयपुर	रु0	41,562-21	0-02	,,
बीकानेर	रु0	60,307-18	0-10	,,
रतनगढ़ (चूरू)		5,418-80	0-05	,,
बांसवाड़ा	रु0	3,59,017-97	0-52	,,
योग		22,82,775-89		

Sanskrit Ed.

वर्ष 1978-79 में संस्कृत विभाग द्वारा जिलेवार शिक्षा के विस्तार पर किये गये व्यय और प्रति व्यक्ति के औसत का विवरण—

क्र. सं.	नाम जिला	शिक्षा के विस्तार पर किया गया व्यय	प्रति व्यक्ति औसत व्यय
1	जयपुर	10,000/-	0-4 पैसा
2	अलवर	6000/-	0-4 पैसा
3	भरतपुर	—	—
4	सवाई माधोपुर	—	—
5	टोंक	—	—
6	बून्दी	—	—
7	कोटा	—	—
8	झालावाड़	—	—
9	बांसवाड़ा	—1,000/-	0-2 पैसा
10	डूंगरपुर	—	—
11	चित्तौड़गढ़	—	—
12	भीलवाड़ा	—	—
13	अजमेर	—	—
14	उदयपुर	3,000/-	0-1 पैसा
15	पाली	—	—
16	जालौर	—	—
17	सिरोही	—	—
18	बाड़मेर	—	—
19	जैसलमेर	—	—
20	जोधपुर	3,000/-	0-3 पैसा
21	नागौर	—	—
22	बीकानेर	—	—
23	गंगानगर	—	—
24	चूरू	—	—
25	झुन्झुनूं	3,000/-	0.3 पैसा
26	सीकर	6,000/-	0,5 पैसा

272

Primary & Sec. Ed.

जिलेवार प्रति व्यक्ति अनुमानित व्यय

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल व्यय मय विकास प्रति व्यक्ति व्यय रु.
1	अजमेर	32-83
2	अलवर	24-07
3	भरतपुर	27-73
4	जयपुर	27-12
5	झुंझूनूं	29-22
6	सीकर	17-00
7	सवाई माधोपुर	22-67
8	टौंक	27-00
9	बीकानेर	39-57
10	चूरू	24-78
11	गंगानगर	20-14
12	बाड़मेर	12-88
13	जैसलमेर	22-50
14	जोधपुर	27-75
15	जालौर	7-14
16	सिरोही	26-75
17	नागौर	20-15
18	पाली	33-00
19	कोटा	25-82
20	बून्दी	30-25
21	झालावाड़	22-33
22	बांसवाड़ा	21-71
23	भीलवाड़ा	14-73
24	डूंगरपुर	23-00
25	चित्तौड़गढ़	19-30
26	उदयपुर	29-83

परिशिष्ट-19 मार्च, 1979-परिशिष्ट

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न स० 359

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

सूची (क)

नागौर जिले में निम्नलिखित विद्यालयों में अध्यापकों के स्थान रिक्त है—

क्रमांक	नाम विद्यालय		रिक्त स्थान का दिनांक/माह	विशेष
1	2		3	4
	(द्वितीय वेतन श्रृंखला)			
1	रा. मा. वि. खजबाना	1 पद अंग्रेजी	सितम्बर, 78	
2	रा. मा. वि. लवाण	1 पद ,,	दिसम्बर 78	
3	रा. मा. वि. गगराना	1 पद ,,	सितम्बर 78	
4	रा. मा. वि. कोतिया	1 पद ,,	सितम्बर 78	
5	रा. मा. वि. आनियावास	1 पद ,,	सितम्बर 78	
6	रा. मा. वि बड़ा खाटू	1 पद ,,	सितम्बर 78	
7	रा. मा. वि. जसवंतगढ़	1 पद ,,	दिसम्बर 78	
8	रा. मा. वि. रत्ताउ	2 पद अंग्रेजी एवं गणित	सितम्बर 78	
9	रा. मा. वि. हरसोर	1 पद ,,	नवम्बर 78	
0	रा. मा. वि. रेण	1 पद गणित	सितम्बर 78	
1	रा. उ मा.वि. डेगाना	1 पद अंग्रेजी	दिसम्बर 78	
2	रा. मा. वि. मूण्डवा	1 पद अंग्रेजी	जनवरी 79	
	तृतीय वेतन श्रृंखला			
1	रा. मा. वि. वेरी	एक पद	25 जनवरी, 79	
2	रा. मा. वि. कुचेरा	,,	,,	
3	रा. उ. मा. वि. छोटा खाटू	,,	,,	
4	रा. उ. मा. वि. मकराना	,,	,,	
5	रा. उ. मा. वि. रोटू	,,	,,	
6	रा. उ. मा. वि. श्यामसर	,,	,,	

1	2	3	4
7	रा. मा. वि. नं. 5 लाडनूं	एक पद	25 जनवरी 79
8	रा. उ. मा. वि. लाडनूं	,,	,,
9	रा. मा. वि. रत्ताऊ	,,	,,
10	रा. मा. वि. निम्बी जोधा	,,	,,
11	रा. उ. प्रा. वि. तंवर	,,	,,
12	रा. उ. मा. वि. जसवन्तगढ़	,,	,,
13	रा. उ. प्रा. वि. खारडिया	,,	,,
14	रा. प्रा. वि. नम्बर, 6 लाडनूं	,,	,,

(275)

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न सं. 366 की सूची

नकल नामान्तरकरण पंजिका ग्राम देवली तहसील खारची जिला पाली राजस्थान

गत जमाबन्दी (खेवट खतौनी) में शुद्धि करने हेतु प्रस्तावित प्रविष्टी							नवीन अंकन जो वर्तमान के स्थान पर करना है						परिवर्तन की किस्म व तिथि विक्रय अवस्था में सक कीमत व धरोहर या धरोहर की वापसी की दशा में उसकी रकम	नामान्तरकरण शुल्क जो लेना है	प्रतिवेद एवं आदेश
प्रविष्टी क्रम संख्या	गत जमाबन्दी के खातों की संख्या	थोक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप-जागीरदार, मालगुजार, विस्वेदार या जमीदार) का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत के क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमिकर या राजस्व	नवीन (चालू) जमाबन्दी के खातों की संख्या	थोक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकारी, जागीरदार, उप-जागीरदार, मालगुजार या विस्वेदार या जमीदार का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत के क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमिकर या राजस्व			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
275	49		राजस्थान सरकार	गणेशमल वल्द हीराचन्द कौम ओसवाल सा. देह $\frac{1}{2}$ गिरधारी S/o हंसा $\frac{1}{8}$ राजीया S/o भीखा $\frac{1}{16}$ तारीया, पीथा, केसीया, पोकरि पि. गीगला $\frac{1}{16}$ उदीया s/o केरा सगराम s/o रामा नारायण दुर्गीया, जेतीया पि. नेमा चिमना s/o गजा $\frac{1}{16}$ रुघिया s/o बख्ता लालीया s/o पुखा $\frac{1}{16}$ नवला मोती पि. भगा $\frac{1}{16}$ कौम भावी सा. देह $\frac{1}{2}$ खातेदार	730 जाव 631 2 729 बेरा अलावा 3	261/1 चाहीदोयम 22।।।/1 ,, 49/2 168.37 ।।/3 गै. मु. 49।।।) 168.37			राजस्थान सरकार	गणेशमल वल्द हीराचंद कौम ओसवाल सा. देह खातेदार	730 जाव 731 2 726 बेरा अलावा 3	261/1 चाहीदोयम 22।।।/1 ,, 49/2 168.37 ।।/3 गै. मु. 49।।।) 168.37	R. T. A. धारा 19 के तहत म्युटेशन भरा गया		

नकल गिरदावरी संलग्न है तुलना की गई तो पाया गया कि श्री गणेशमल का काश्त कब्जा सं. 2012 से 2019 तक बराबर है। लगान भी श्री गणेशमल देता आ रहा है। यानि संमत 2012 से सं. 2024 तक बराबर आराजी पर काबिज है इसलिए नामान्तरकरण R. T. A. 19 के तहत भरा गया।
11-6-68

S/d
भूपालसिंह
निरीक्षक (भू. अभिलेख)
मण्डल राणावास (राज.)

धारा 19 R. T. A. के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है।

S/d
दयालचन्द
11/6/68
तहसीलदार, खारची

S/d
शफी मोहम्मद
पटवारी देवली
5—6—68

सही प्रतिलिपि
तहसीलदार (भू. अ.)
खारची (राज.)

असल से नकल की गई।

(276)

Page No. 276

नकल नामान्तरकरण पंजिका ग्राम देवली तहसील खारची जिला पाली राजस्थान

गत जमाबन्दी (खेवट खतौनी) में शुद्धि करने हेतु प्रस्तावित प्रविष्टी							नवीन अंकन जो वर्तमान के स्थान पर करना है								
प्रविष्टी क्रम संख्या	गत जमाबन्दी के खातों की संख्या	थोक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकारी (जागीरदार, उप-जागीरदार, मालगुजार, बिस्वेदार या जमींदार) का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत के क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमिकर या राजस्व	नवीन (चालू) जमाबन्दी के खातों की संख्या	थोक पट्टी या तरफ का नाम	भूमि अधिकारी, जागीरदार, उप-जागीरदार, मालगुजार या बिस्वेदार या जमींदार का नाम विवरण सहित	कृषक का नाम विवरण सहित	खेत के क्षेत्रफल व भूमि प्रकार का विवरण	भूमिकर या राजस्व	परिवर्तन की किस्म व तिथि विक्रय अवस्था में सक कीमत व घरोहर या घरोहर की वापसी की दशा में उसकी रकम	नामान्तरकरण शुल्क जो लेना है	प्रतिवेद एवं आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
276	369		राजस्थान सरकार	काना s/o सेरा] तिलोक s/o करता] $\frac{1}{2}$ भंवरीया पीथीया केसीया लालीया पोकरिया पि. गीगला राजीया वल्द भीका $\frac{1}{16}$ उदीया s/o केरा] सगराम s/o रामा] $\frac{1}{32}$ रुगा s/o बखता] लालीया s/o पुखा] $\frac{1}{32}$ चिमनिया s/o गजानारायण दुरगीया, जेता पि. नेमा $\frac{1}{32}$ नवला मोती पि. भगा $\frac{1}{32}$ गिरधारी वल्द हंसा $\frac{1}{16}$ कौम भांवी गणेशमल वल्द हीरा चन्द कौम ओसवाल $\frac{1}{4}$ सा. देह	725 जाव 726 वेरा पीपलिया ——— 36।।।)	$3\frac{6}{4}1$ $\frac{1}{5}$ ——— 136·75	चाहीदोयम 136·75 गै. मु. ———		राजस्थान सरकार	काना s/o सेरा] तिलोक s/o करता] $\frac{1}{3}$ कौम भांवी गणेश मल वल्द हीराचंद कौम ओसवाल सा. देह $\frac{1}{2}$ खातेदार	725 जाव 726 वेरा पीपलिया ——— 2	$8\frac{6}{1}1$ $\frac{1}{3}$ ——— 36।।।)	चाहीदोयम 136·75 गै. मु. ——— 136.75		R. T. A. धारा 19 के तहत म्युटेशन भरा गया S/d शफी मोहम्मद पटवारी देवली 5—6—68

तुलना की गई अंकन पत्रों के सही है। श्री गणेशमल का काश्त कब्जा सं. 2012 से 2024 तक बराबर है। लगान भी देता आ रहा है। इसलिए नामान्तरकरण R. T. A. धारा 19 के तहत भरा गया। नकल गिरदावरी संलग्न है। 11-6-68

S/d
भूपालसिंह
निरीक्षक (भू. अभिलेख)
मण्डल राणावास (राज.)

धारा 19 R. T. A. के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है।

S/d
दयालचन्द
11/6/68
तहसीलदार खारची

सही प्रतिलिपि
तहसीलदार (भू. अ.)
खारची (राज.)

असल से नकल की गई।
13/3/79

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न सं. 377 की सूची
प्रश्न के द्वितीय भाग की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत रु. लाखों में	विवरण
1-	भैर लाटोटी	28.95	वर्ष 77-78 में त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी थी।
2-	देवली हुआ-चन्डावल	5.19	
3-	वावागांव भावनगर	26.71	इस योजना के पार्ट-I में ग्राम पियोनाबा को रु. 5.26 लाख की लागत से वर्ष 78-79 में स्वीकृत किया गया एवं बजट भी आवंटित है।
4-	बैनपुरा-बिरानी	13.70	
5-	सियाट भैसाना	16.80	
6-	बैमूदड़ा खेतावास	26.28	इस योजना के ग्राम खामल, आगेसर, सोबानिया थैमूदड़ा तथा खेतावास को क्षेत्रीय भाकरीवाला पार्ट-III जिसकी लागत 18.80 लाख है, में स्वीकृत किया गया। एवं बजट भी आवंटित करके कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
7.	सोमेसर योजना	-	
8.	शिलपुर-पैरवा	-	
9.	खिबोढ़ा-सिवास-गजनीपुरा	-	

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न सं. 378 की सूची
प्रश्न संख्या एक की सूची

क्र. सं.	योजना	ग्राम का नाम	जनसंख्या 1971 के अनुसार
1.	क्षे. यो. बोलावास राजोला कलां	1. बिलावास	2817
		2. रुपवास	1303
		3. धांगवास	622
		4. चाँडवास	965
		5. नयागांव	767
		6. चौपड़ा	939
		7. राजोला कलां	942
		8. भानियां	644
		9. अवकाई की ढाणी	430
		10. लूनेरा	684
		11. जूपेलाव	703
		12. शियोपुरा	1298
		13. बनयाला	136
		14. घोटाला	432
		15. लूदवास	430
2.	क्षे. योजना बोलावास राजोला कलां का विस्तार	16. हुगांवास	445
		17. गागोडा	806
		18. धीनावास	1341
		19. अजीतपुरा	331
		20. बोरावास	211

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न सं. 385 की सूची

जालोर जिले में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों व चिकित्सालयों की सूची

1.	राजकीय	'अ' श्रेणी	आयुर्वेदिक	चिकित्सालय	जालोर
2.	"	"	"	"	बांसवाड़ा
3.	"	"	"	"	आकोली
4.	"	"	"	"	सियाना
5.	"	"	"	"	आलासन
6.	"	"	"	"	तीखी
7.	"	"	"	"	निम्बलाना
8.	"	"	"	"	विशनगढ
9.	"	"	"	"	आंकरा
0.	"	"	"	"	उम्मेदाबाद
1.	"	"	"	"	आहोर
2.	"	"	"	"	घाना
3.	"	"	"	"	भवरानी
4.	"	"	"	"	अदाजून
5.	"	"	"	"	मोरडा
6.	"	"	"	"	पादरली
7.	"	"	"	"	कवराडा
8.	"	"	"	"	गुढा आलेतान
9.	"	"	"	"	भीनमाल
!0.	"	"	"	"	नरता
:1.	"	"	"	"	कोटकारता
:2.	"	"	"	"	तवाब
:3.	"	"	"	"	बागसा
!4.	"	"	"	"	मोदरा
5.	"	"	"	"	चाडामाडवी
:6.	"	"	"	"	रानीवाडा
.7.	"	"	"	"	कलापुरा
:8.	"	"	"	"	कंमिकाल
:9.	"	"	"	"	जसवन्तपुरा

(280)

30.	राजकीय	'अ' श्रेणी	आयुर्वेदिक	चिकित्सालय	पूरण
31.	,,	,,	,,	,,	राजी का वा
32.	,,	,,	,,	,,	देवडा
33.	,,	,,	,,	,,	पुर
34.	,,	,,	,,	,,	सूथडी
35.	,,	,,	,,	,,	हाड़ेचा
36.	,,	,,	,,	,,	केरिया
37.	,,	,,	,,	,,	हेमागुडा
38.	,,	,,	,,	,,	सांकड
39.	,,	,,	,,	,,	झाब

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न सं. 386 (71 चि मं) की सूची

S. S. HOSPITAL

S. No.	Machines.	Year wince lying Idle.	Reparable or not	Replacement.	Approx. Cost. and Remarks.
1.	Part of the Central Air Conditsioning Plant. 3 Compressers	1956	No	Yes	Rs. 5 Lacks taken in the next year budget for its replacement/repair.
2.	Eye Operation Air Conditioning Plant.	1975	Yes	No	Rs. 12000 Estimate received and it shall be oat repaired in the current year.
3.	K Oil Autoclave in Operation Theatre.	1960	No	Yes	Replacement demanded in the next year budget.
4.	2 Air Conditioner Children Ward.	1970	No	Yes	New Air Conditioner required.
5.	Part of the Laundry Machine Washers, Druges Stores press.	1975	No	Yes	Replaced with new Laundry in the current financial year.
6.	Kachra Waist Burning Machine.	1957	No	Yes	New Plant may be asked in the next year budget 0.50 lacks.

1	2	3	4	5	6
7.	E. C. C. Machines "Burdic Machine.	1977	No	Yes	New Machines according to the requirement may be got purchased.
8.	Vertical Type Non Clegging pumps 4 Nos.	1977	No	Yes	1.25 Lacks required in the next year budget for their replacement they were repaired by the Water Works and now only two are working.
9.	Steam Hot Water Plant (Bottle) in operation theatre.	1972	No	Yes	Rs. 0.50 lacks are required for the bottles repalcement.
10.	Blanket Sterilizer Disinfactor.	1972	No	Yes	More than 0.50 Lacks are required for replacement.
11.	One lift	1965	Yes	Yes	Replacement is desriable.

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न सं. 389 की सूची

तालिका हत्या के अपराध जो थाना मावली पर जुलाई, 77 से जनवरी, 79 की अवधि में दर्ज हो निष्कासन हुए व सिलसिले विधान सभा प्रश्न सं 75/मु. मं. द्वारा नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी विधायक

क्र.सं.	मुकदमा नं/वर्ष/धारा/तारीख	नतीजा पुलिस	विशेष विवरण
1—	179/77 धारा 302/201 आई पी सी तरमीम जुर्म 304 201 आई पी सी दिनांक-9-9-1977	चालान नं. 102 दि. 17-10-1977	न्यायालय ने मुल्जिम के विरुद्ध जुर्म सबूत नहीं मान बरी किया है।
2—	118/78 धारा 147/148/302 ताहि दिनांक 23.7-78	चालान नं 58 दि. 16-8-78	न्यायालय द्वारा मुलजिम सोहनसिंह डिस्चार्ज किया गया है।
3—	124/78 धारा 302 आई पी सी दिनांक 30-7-78	एफ. आर. अदम पता नं 98 दि. 30-11-78	इस प्रकरण की तफतीश पुनः खोली जाकर पतारसे मुल: की जा रही है।
4—	126/78 धारा 302 आई पी: सी: दिनांक 2-8-78	एफ: आर: अदम वकूआ नं. 99 दि. 16-12-78	तफतीश से मृतक पुष्पेन्द्रसिंह द्वारा खुदकशी करना पाया जाने से एफ. आर. अदम वकू में कता की गई।

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 390 की सूची

वर्ष 1976, 77, 78 में जयपुर शहर में पंजिबद्ध हुये अपराधों की तालिका थाने वार

नाम थाना	डकैती			लूट			कत्ल			बलवे			नकबजनी			चोरी			दीगर आईपीसी			योग			गुण्डा एक्ट		
	76	77	78	76	77	78	76	77	78	76	77	78	76	77	78	76	77	78	76	77	78	76	77	78	76	77	78
1. कोतवाली	—	—	—	16	32	11	—	—	33	55	81	85	125	165	134	255	233	279	250	310	291	701	884	803	1	3	8
2. शास्त्रीनगर	-	-	-	—	5	1	·	1	3	4	16	17	6	36	41	12	42	54	22	72	105	44	172	231	-	-	2
3. माणकचौक	-	-	-	7	7	19	2	3	2	19	41	45	55	77	74	173	379	320	131	158	108	387	665	618	1	-	14
4. रामगंज	-	1	-	10	10	16	4	—	6	40	46	49	71	77	49	56	97	93	117	186	190	298	417	403	2	-	-
5. अशोक नगर	-	-	-	4	15	11	—	1	1	15	25	25	56	81	82	163	248	221	112	92	137	350	462	477	-	-	1
6. आदर्श नगर	-	1	-	4	9	12	3	-	1	18	29	68	45	63	55	141	107	176	109	176	153	320	385	465	-	-	4
7. गांधीनगर	-	-	-	-	4	7	-	-	-	5	26	38	30	34	36	61	106	127	70	77	94	166	245	302	-	-	1
8. मोतीडूंगरी	-	-	-	1	8	10	-	1	3	4	30	34	8	29	31	79	246	123	40	113	236	132	427	437	-	-	-
9. सदर	-	-	-	2	3	9	1	1	1	19	31	48	59	46	51	82	97	75	95	112	123	256	290	307	-	-	2
10. बनीपार्क	-	-	-	6	6	3	2	—	—	20	25	18	49	21	24	143	210	139	140	141	135	360	403	319	-	-	-
11. विधायकपुरी	-	—	1	5	15	7	—	—	1	3	22	31	20	68	91	64	212	218	44	132	124	136	440	473	-	-	3
12. झोटवाड़ा	-	-	—	—	6	1	—	—	—	1	30	20	7	38	31	7	52	36	31	58	62	46	184	149	-	-	2

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न सं. 391 की सूची

माह जून 1077 से फरवरी 1979 तक सर्किल कोटपूतली में तैनात पुलिस उप अधीक्षक व थाना कोटपूतली एवं प्रागपुरा में तैनात थाना प्रभारी के नामों की सूची

क्र.सं.	नाम थाना	थाना प्रभारी/सर्किल आफिसर का नाम	पदस्थापन की अवधि
1—	प्रागपुरा	श्री लीलाराम उप निरीक्षक	जून 77 से अप्रेल 1978 तक
2—	प्रागपुरा	श्री शिवदत्त शर्मा ,,	20 दिन केवल
3—	प्रागपुरा	श्री लोकेश कुमार ,,	जून, 78 से 10 फरवरी 79 तक
4—	प्रागपुरा	श्री चतर सिंह ,,	11 फरवरी 79 से
5—	कोटपूतली	श्री प्रभूदयाल, ,,	जून 1977 से 14 जनवरी 78 तक
6—	,,	श्री जगदीशप्रसाद ,,	14 जनवरी 78 से 19-10-78
7—	,,	श्री सुलतानसिंह, आर: पी: एस: (प्रोवेशनर)	20-10-78 से 25-11-78 तक
8—	,,	पूर्णप्रताप निर्मल, उप निरीक्षक	26-11-78 से 17-9-79 तक
9—	,,	श्री नृसिंह देव ,,	18-2-79 से
10—	सर्किल कोटपूतली	श्री चुन्नीलाल, उप पुलिस अधी.	जून 77 से 17-9-77 तक
11—	,,	श्री तुलसीराम ,,	18-9-77 से 25-7-78 तक
12—	,,	श्री मुराद अली ,, अबरा	25-7-78 से

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न सं. 392 की सूची

Sud: Scheme and the Scales of rehabilitation assistance for the settlement of 5600 families of Indo-Pak Conflict 1971 in the Districts of Barmer, Jaisalmer and Jalore in Rajasthan.

The scales of rehabilitation assistance to be given are indicated. belowe:

1—LAND ALLOTMENT:

Each displaced person family will be allotted land.

2—MILCH COWS/SHEEP AND RAM:

In addition to the allotment of land each family will be given 3 Milch cows or 30 sheep and one Ram to enable them to have supplementary income so as to make their occupation on agriculture and cattle breeding a viable unit. A maximum of Rs. 4000/- per family will be given in the form of loan. Before considering the applications for the grant of loan. the State Government would ascertain the number of animals already available with the dp family and the financial assistance will be restricted to the extent necessary to augment their existing stock of animals so as to make up the shortfall in the strength of livestocks.

3 -TRANSPORTATION CHARGES:

Each family will be given a flat rate of Rs. 10/– for moving from the camps to the rehabilitation sites.

4—JOURNEY ALLOWANCE:

Journey allowance will be admissible Rs. 2/- per person for reaching the rehabilitation site.

5—MAINTENANCE ASSISTANCE:

This will be for a period of 6 months. The State Government will declare in advance the date from which the agricultural season in

case of any group of displaced persons should be deemed to begin. This period should normally be reckoned from the month prior the date of actual sowing so as to include the period necessary for preparing the land for sowing. The scale of maintenance assistance will be the same as admissible to the displaced persons in the camps and the amount involved will be treated as grant. The expenditure on this account should not, however, exceed Rs. 150/- per family per month.

6—CONSTRUCTION OF JHOMPAS:

a) Grant : The dps. families will be given a grant of Rs. 950/- for the construction of Jhompas.

b) Loan : In addition to the grant of Rs. 95 0/- each dp family will be advanced a sum of Rs. 550/- as loan for completing the construction of the Jhompas.

7—FODDER :

A sum of Rs. 100/- in the form of loan will be given to each family for the purchase of fodder.

8—PURCHASE OF CAMEL/BULLOCKS :

Each family will be given a maximum loan of Rs. 2500/- for the purchase of camel or bullock for agricultural purposes. For this purpose also the state Govt. would take necessary census with regard to the bullocks/camel already available with the dp families and loans will be advanced to them in case the animal is not already available with them.

9—LAND RECLAMATION :

A loan of Rs. 1000/- per family will be given for land reclamation.

10—SEEDS FERTILISERS. INPUTS :

Rs. 1000/- per family in the form of loan.

——— —

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 398 की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	क्र.सं.	नाम गांव	क्षेत्रफल
1	सिरोही	1	भारजा	234-06 बीघा
2	,,	2	सावेला	90-01 ,,
		3		34-03 ,,
		4	बसन्तगढ़	72-02 ,,
		5	बालोरिया	260-06 ,,
		6	जाम्बूडी	20-97 ,,
		7	क्यारी	47-08 ,,
		8	उपरी बोर	62-14 ,,
		9	उपला गढ़	198-02 ,,
		10	बूझा	30-02 ,,
		11	जाखदासन	114-03 ,,
		12	बोरी बूझ	148-05 ,,
		13	निवली ओर	30-06 ,,
		14	टाकिया	347-19 ,,
		15	रणोरा	33-04 ,,
		16	निवलागढ़	5-01 ,,
		17	तलेटी	7[illegible]-02 ,,
		18	बहादुर पुरा	14-02 ,,
		19	सकोडा	3-16 ,,
		20	ब्लोक नं. 1	0.13 ,,
		21	आम्बाबेरी	9-15 ,,
		22	उपलोबजडा	5o-08 ,,
		24	निचलोखेजडा	16-09 ,,
		24	भमरीया	66-10 ,,
		25	पाबा	113-10 ,,
		26	दोतरा	97-01 ,,
		27	सुरपगला	118-90 ,,
		28	डेरी	100-05 ,,
		29	बोला	38-04 ,,
		30	मेन	161-15 ,,
		31	राडा	27-15 ,,

289

		बीघा विस्वा
...वाडा	लालावाड	4-18
	,,	2-15
	,,	5-12
	बोरकुण्डी	8-00
	बेरठ	13-00
	बाम्रीदौरा	15-00
		44-5 विस्वा
	बड़ी पानासी	5-10
	डकारकुण्डी (मजरे खडोर)	31-10
	टोमरवा	4-16
		41-16 विस्वा
	कुल	91-1 विस्वा